

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Raj.)**

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

ग्रेट ब्रिटेन का आर्थिक विकास

लेखक

एन० एल० कुलश्रेष्ठ, एम० ए०, एम० कॉम०, साहित्यरत्न,
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य विभाग,
टिप्पी कालेज, चिड़वा (राजस्थान),

(भूतपूर्व असि० प्रोफेसर ऑव कॉमर्स, सेठ जी० बी० पोंदार कालेज, नवलगढ़;

लेखक—'भारतवर्ष का आर्थिक भूगोल', 'मसार का आर्थिक भूगोल'
तथा 'भारत में सहकारी खेती')



रामप्रसाद एण्ड संस : आगरा

प्राक्थन

ग्रेट ब्रिटेन के आर्थिक विकास का अध्ययन भारतवर्ष में हमारे लिए अनेक दृष्टियों से रुचि का विषय है। सन् १९४७ तक इस देश पर ब्रिटेन का प्राधिपत्य रहा और उसकी नीतियाँ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उतनी ही महत्वपूर्ण समझी जानी चाहिएँ जितनी इतिहास और राजनीति में। स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपरान्त राष्ट्रकुल (कॉमनवेल्थ) का सदस्य होने के नाते भारत का ब्रिटेन के साथ सम्बन्ध सुदृढ रहा है और हमने आर्थिक सहयोग प्राप्त किया है। राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के तुरन्त पश्चात् ही भारतवर्ष को अपनी स्वतन्त्र आर्थिक नीति का विकास करने की आवश्यकता हुई। निश्चय ही इस दिशा में भारत ने ब्रिटेन से कुछ सीखा है। विभिन्न परिस्थितियों में ब्रिटेन ने जो नीति अपनाई और उसमें परिवर्तन किए उसकी सफलताओं और असफलताओं के प्रकाश में हम भारतीय आर्थिक नीति पर विचार कर सकते हैं। ब्रिटेन और भारत में समानता का आधार केवल यह नहीं है कि दोनों देशों में जनतन्त्रात्मक प्रणाली है बल्कि उद्योग, व्यापार तथा अनेक क्षेत्रों में हमने ब्रिटिश पद्धतियों का अनुकरण किया है—यह हमारे ऊपर है कि उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता की दृष्टि से हम आगे उन्हें अपनाए रहे या त्याग दें।

प्रस्तुत पुस्तक भारतीय छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है। प्रयत्न यह किया गया है कि इसमें उन्हें ब्रिटिश आर्थिक विकास की पूरी रूपरेखा संक्षेप में मिल जाए परन्तु कुछ अधिक महत्व की बातों पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया है। भाषा जान-बूझकर सरल रखी गई है ताकि सामान्य पाठक भी लाभ उठा सकें। इस पुस्तक के हरेक अध्याय में लेखक का यह प्रयत्न रहा है कि ऐसी बातें पाठक का ध्यान अवश्य आकर्षित करें, जिन्हें जानना सैद्धान्तिक दृष्टि से ही नहीं अपितु व्यवहार में इस देश में उपादेय हो सकता है। शीर्षको तथा उप-शीर्षको में विषय-सामग्री का विभाजन करने में इस बात का विशेष ध्यान रखा है।

छात्रों (और संभवतः प्राध्यापको का भी) काम सरल करने की नीयत लेखक की अवश्य रही है परन्तु प्राध्यापको का महत्व कम करने का उद्देश्य कदापि नहीं है। इस पुस्तक में बहुत कुछ ऐसा भी है जिसे मध्यम श्रेणी के छात्र अपने प्राध्यापक की सहायता के बिना समझने में शायद कठिनाई अनुभव करें।

प्रार्थिक विकास का अध्ययन मूल रूप में ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित होना आवश्यक है। इसलिए इस प्रयत्न में मौलिकता का दावा नहीं किया जा सकता। लेखक ने विद्वान् आन् लेखकों के अधिकारपूर्ण लिखे अधिक से अधिक ग्रन्थों, तथा सरकारी प्रकाशनों का लाभ उठाने का प्रयत्न किया है यथोत्तम उनका यथास्थान उल्लेख भी किया गया है। निश्चय ही, विषय-वस्तु के व्यक्तीकरण में लेखक के निजी ढंग के साथ उसकी कमजोरियाँ आना स्वाभाविक है। उन सभी लेखकों और प्रकाशकों के प्रति लेखक हृदय से प्रीति है जिनके ग्रन्थों से सहायता ली गई है। विषय के विस्तृत अध्ययन के लिए छात्रों को चाहिए कि वे अपने अध्यापको के निर्देशन में उन ग्रन्थों का अवलोकन करें।

मनुमान है कि यह पुस्तक छात्रों को उपयोगी होगी। पुस्तक को अधिक उपयोगी बनाने के लिए सुझावों के हेतु लेखक का सबको आमन्त्रण है।

विषय-सूची

अध्याय

पृष्ठ

१. औद्योगिक क्रान्ति से पूर्व ग्रेट ब्रिटेन की आर्थिक दशाओं का एक विहंगावलोकन १-२०

ब्रिटेन की प्राचीन अर्थ व्यवस्था की विशेषताएँ, ब्रिटेन का प्राचीन ग्राम संगठन, प्राचीन औद्योगिक प्रणालियाँ, गिल्ड प्रणाली का विकास, गिल्ड का संगठन, गिल्ड का प्रशासन, क्राफ्ट गिल्ड और आधुनिक व्यापारिक संगठन में अन्तर, गिल्ड प्रणाली के गुण-दोष, गिल्ड प्रथा का अन्त, घरेलू प्रणाली, घरेलू प्रणाली के लाभ, घरेलू प्रणाली के दोष, वाणिज्यवाद, प्रश्न ।

२. औद्योगिक क्रान्ति के प्रारंभ काल में आर्थिक दशाएँ २१-२६
कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य-व्यापार, प्रश्न ।

३. औद्योगिक क्रान्ति ३०-५३

क्या क्रान्ति शब्द उपयुक्त है ? औद्योगिक क्रान्ति का काल, क्रान्ति पहले ही क्यों नहीं हुई ? औद्योगिक क्रान्ति के कारण—सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में ही क्रान्ति क्यों हुई ? औद्योगिक क्रान्ति की विशेषताएँ, कारखाना प्रणाली के घीमे विकास के कारण, औद्योगिक क्रान्ति के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव, १९वीं शताब्दि में ग्रेट ब्रिटेन की महत्ता के कारण, प्रश्न ।

४. प्रमुख उद्योगों का विकास ५४-७४

आविष्कार और तकनीकी विकास, सूनी वस्त्र उद्योग, कोयला उद्योग (Coal Mining), लोहा-इस्पात उद्योग, प्रश्न ।

५. कृषि का विकास ७५-९५

समावरण आन्दोलन, कृषि क्रान्ति, कृषि क्रान्ति की विशेषताएँ, कृषि क्रान्ति का कृषकों पर प्रभाव, आगल कृषि-क्रान्ति से भारत के लिए सबक, कृषि क्रान्ति और औद्योगिक क्रान्ति का संबंध,

मन्न कानून (corn laws), सन् १८५० के बाद ब्रिटिश कृषि की दशा, उत्पादन, सरकारी कृषि नीति, प्रश्न ।

६. यातायात का विकास तथा वाणिज्य क्रान्ति ६६-१२७

वाणिज्य क्रान्ति, वाणिज्य क्रान्ति के सामाजिक प्रभाव, यातायात के विकास का इतिहास, सड़को का विकास, नाव्य नहरें, नहरों की प्रवृत्ति, रेल मार्गों का विकास, समुद्री यातायात, नौ-बहन सम्बन्धी कानून तथा नीति, वायु-यातायात, प्रश्न ।

७. श्रम आन्दोलन १२८-१३४

श्रम संघों का जन्म, प्रारंभिक कठिनाइयाँ, आन्दोलन की प्रगति, संगठन और समामेलन, नए एक्ट-पंजीयन की व्यवस्था, सन् १८७१ से १९०० तक बीसवीं शताब्दि में श्रम संघों के मुख्य कार्य तथा धर्मिकों की दशाओं पर उनका प्रभाव, प्रश्न ।

८. सामाजिक सुरक्षा का विकास १३५-१५०

निधेन सहायता का कानून, सामाजिक बीमा की आवश्यकता, सामाजिक बीमा का विकास, बीवरिज योजना, ब्रिटेन की वर्तमान सामाजिक बीमा व्यवस्था, पारिवारिक भत्ते, राष्ट्रीय बीमा, औद्योगिक क्षति बीमा योजना, राष्ट्रीय सहायता तथा कल्याण सेवाएँ, प्रश्न ।

९. औद्योगिक तथा व्यापारिक नीति १५१-१६६

वाणिज्यवादी नीति, अबाध व्यापार नीति, अबाध व्यापार नीति का पतन तथा रक्षणवादी नीति का विकास, द्वितीय विश्वयुद्ध तथा युद्धोत्तर काल में प्रयुक्त नीति, प्रश्न ।

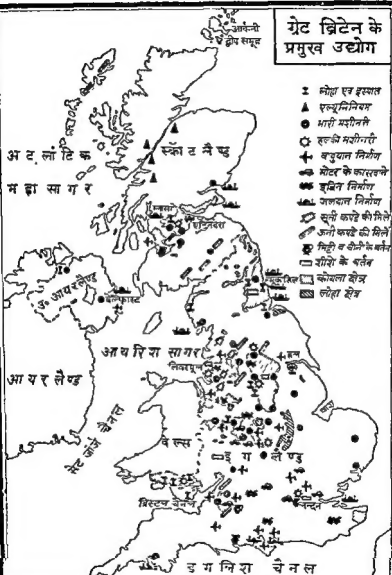
१०. अधिकोपण तथा राजस्व १६७-१८३

अधिकोपण प्रणाली का आरम्भ, बैंक ऑव इंग्लैण्ड की स्थापना, १८ वीं शताब्दी में ब्रिटिश अधिकोपण की विशेषताएँ, उन्नीसवीं शताब्दी के बैंकिंग अधिनियम तथा अधिकोपण का विकास, आधुनिक काल—बैंक ऑव इंग्लैण्ड, व्यापारिक बैंक, राजस्व, सरकारी आव-व्यय, प्रश्न ।

- ✓ ११. ब्रिटिश अर्थ व्यवस्था पर विश्व युद्धों का प्रभाव
 तथा द्वितीय विश्व युद्धोत्तर कालीन आर्थिक समस्याएँ १८४-१९०
 प्रथम महायुद्ध के प्रभाव, द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रभाव,
 युद्धोत्तरकालीन आर्थिक समस्याएँ, प्रश्न ।
 विस्तृत अध्ययन के लिए पुस्तकों की नामावली १९१-१९२

ग्रेट ब्रिटेन का आर्थिक विकास

ग्रेट ब्रिटेन के प्रमुख उद्योग



पहला अध्याय

औद्योगिक क्रान्ति से पूर्व ग्रेट ब्रिटेन की आर्थिक दशाओं का एक विहंगावलोकन

[ब्रिटेन की प्राचीन अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ, ब्रिटेन का प्राचीन ग्राम-संगठन, प्राचीन औद्योगिक प्रणालियाँ, गिल्ड प्रणाली का विकास, गिल्ड का संगठन, गिल्ड का प्रशासन, स्थापित गिल्ड और आधुनिक व्यापारिक संगठन में अन्तर, गिल्ड प्रणाली के गुण-दोष, गिल्ड प्रथा का अन्त, घरेलू प्रणाली, घरेलू प्रणाली के लाभ, घरेलू प्रणाली के दोष, बाणिज्यवाद, प्रश्न ।]

ग्रेट ब्रिटेन के आर्थिक विकास का इतिहास वृहद् और दीर्घकालीन है। ब्रिटेन की उन्नति अचानक एकदम अथवा अल्पकाल में ही नहीं हो गई थी। समृद्धि के शिखर पर पहुँचने में उसे कम समय नहीं लगा। ब्रिटेन की आर्थिक उन्नति की दिशा में जहाँ अनेक सुविधाएँ प्राप्त थी वहाँ कठिनाइयाँ भी थी। उन्नति के लिए उसे सतत संघर्ष करना पड़ा और, जैसा कि उसके आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन से विदित होगा, ब्रिटेन की उन्नति की ऊँची सीढ़ियों पर चढ़ चुकने के उपरान्त कालान्तर में नीचे भी उतरना पड़ा परन्तु उसने अपनी समृद्धि को पुनः प्राप्त करने के प्रयास का परित्याग नहीं किया। वस्तुतः जिन विभिन्न परिस्थितियों में होकर ब्रिटेन आगे बढ़ा तथा आगे चलकर जिनका भारतवर्ष के ऊपर भी प्रभाव पड़ा वही हमारे अध्ययन में अधिक रुचि के विषय हैं।

अनेक देशों के समान ब्रिटेन भी प्रारंभ में एक पिछड़ा देश था। उसकी जनसंख्या छोटे-छोटे गाँवों में बँटी हुई थी और जीविका का प्रमुख साधन कृषि था। कृषि के पूर्व वहाँ अंगुली शिकारी जातियों का आधिक्य था। मछली पकड़ना, शालेय करना और पशु-पालन कृषि के साथ-साथ चलता रहा।

ब्रिटेन की अर्थ व्यवस्था के विकास में प्रारम्भिक काल को हम स्वावलम्बन की अवस्था कह सकते हैं। उस समय ब्रिटेन में व्यापार नहीं होता था। देशी व्यापार का विकास भी बाद में ही हुआ था। अन्य देशों के साथ ब्रिटेन के

व्यापारिक संबंध और भी वाद में धीरे-धीरे हुए। यह सत्य है कि औद्योगिक क्रान्ति के पूर्व ही ब्रिटेन संसार का प्रमुख व्यापारी राष्ट्र बन गया था परन्तु पूँजीवादी पद्धति के विकास एवं औद्योगिक उन्नति के पश्चात् ही उसने यातायात, वाणिज्य और व्यापार में उन्नति की। वस्तुतः औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात् कृषि, यातायात, वाणिज्य व्यापार सभी दिशाओं में क्रान्ति हुई। प्रारम्भ में ब्रिटेन अपने निवासियों के साहसी स्वभाव, सामाजिक गुणों तथा राजनीतिक प्रभुत्व के कारण आगे बढ़ा और आगे चलकर पूँजी के प्रयोग तथा नई तकनीकी जानकारी इत्यादि उसकी उन्नति में अधिक सहायक सिद्ध हुए।

यहाँ यह कहना असंगत न होगा कि सभी सम्य देशों की प्राचीन आर्थिक प्रणालियों में एक समानता पाई जाता है। समय और विस्तार में पाये जाने वाले भेद ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं तथापि उनमें पाई जाने वाली समानता का महत्व कम नहीं है।

ब्रिटेन की प्राचीन अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ

अन्य अनेक देशों की भाँति ग्रेट ब्रिटेन की प्राचीन अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ अधोलिखित थी—

१. कृषि मुख्य पेशा था। अन्य पेशों का विकास अपेक्षाकृत बहुत कम हुआ था।

२. अधिकतर जनसंख्या गाँवों में रहती थी। प्रारम्भ में विकसित कस्बे गाँवों जैसे ही थे।

३. यातायात और आवागमन के साधनों का विकास नहीं हुआ था। अतः एव व्यापार और विनिमय अविकसित थे। ग्राम स्वावलम्बी थे। स्थानीय कृषि यच्छी होती तो उस गाँव में खुशहाली दिखाई देने लगती तथा फसलें अच्छी न होने पर दुर्भिक्ष की दशाएँ उत्पन्न हो जाती।

४. किसान निजी लाभ के लिए अपने ही श्रम और साहस से खेती करता था। उसके परिवार के सदस्य कृषि कार्य में हाथ बँटाते थे। पूँजी का प्रयोग बहुत सीमित था, सेत प्रायः छोटे, बिखरे हुए और खुले थे।

५. पेशे चुनने में स्वतन्त्रता नहीं थी, स्पर्धा का अभाव था। लगान, मजदूरियाँ और कीमतें परम्परा और प्रथाओं से सम्बद्ध थी। समाज में व्यक्ति का स्थान जन्म और जाति से निर्धारित होता था। उस समय समाज विच्छिन्न तो नहीं था परन्तु दोषण, विषमता तथा दास-प्रथा का बोलवाता था।

६. मुद्रा का प्रचलन नहीं था। अतः व्यापार जो कुछ होता था वह वस्तुओं

की बदला-बदली (barter) के रूप में था। आवश्यकताएँ सीमित थीं। आवश्यकता की अधिकांश वस्तुओं का व्यक्ति स्वयं उत्पादन करते थे। अतः जीवन-स्तर निम्न था। लगान प्रायः अनाज और श्रम द्वारा चुकाया जाता था। मजदूरियाँ वस्तुओं के रूप में दी जाती थीं।

७. उद्योग ग्रामोद्योगों के रूप में विकसित हुआ था। विशिष्टीकरण का अभाव था। विविध क्षेत्र ग्राम तक ही सीमित होने के कारण श्रम-विभाजन सीमित और अपूर्ण था।

८. उद्योग छोटे छोटे कारीगरों के हाथों में था। स्थानीय मांग के लिए ही उत्पादन किया जाता था। अतः उद्योगों में विकास की गुंजाइश उस समय नहीं थी। कारीगर अपनी बहुत थोड़ी पूँजी से काम करते थे। संगठन-व्यवस्था तथा साहस का विकास नहीं हुआ था।

९. अधिकोपेण, साक्ष तथा वित्त-व्यवस्था का भी विकास नहीं हुआ था। जब गाँव में लेन-देन का विकास हुआ तो सुदखोर साहूकार श्रेणी किसान का शोषण करने लगा।

१०. सामाजिक सुरक्षा का कोई साधन नहीं था। देहाती मजदूर और किसान सुरक्षा के लिए ग्राम के अधिपति पर ही निर्भर थे। राजकीय हस्तक्षेप तथा सहायता का अभाव था।

मध्ययुगीन ग्राम संगठन को सामान्यतया मेनोरियल प्रणाली (Manorial System) कहा जाता है।

ब्रिटेन का प्राचीन ग्राम-संगठन (Manorial System)

ग्राम संगठन की जो प्रणाली (manorial system) मध्य-युग में इंग्लैण्ड में प्रचलित थी वह वस्तुतः इंग्लैण्ड तक ही सीमित नहीं थी बल्कि पश्चिमी और मध्य योरोप में पाई जाती थी। यह प्रणाली इंग्लैण्ड में ग्यारहवीं शताब्दी से भी पूर्व स्थापित हो चुकी थी।

मेनर (manor) उस भू-सम्पत्ति को कहा जाता था जिसकी इकाई प्रायः एक ग्राम होता था। कालान्तर में इस भू-सम्पत्ति में एक से अधिक गाँव भी सम्मिलित होने लगे और कुछ दशकों में इसमें विभिन्न ग्रामों के भाग शामिल होने लगे। कृषि का संगठन सामंतवादी ढंग का था।

ग्राम-संगठन (manor) अथवा भू-सम्पत्ति के स्वामी को ग्राम का अधिपति (manorial lord) कहा जाता था। समस्त ग्रामवासी भूमि पर निर्भर

थे। ग्रामवासियों में दो प्रकार के व्यक्ति थे—एक तो स्वतन्त्र, और दूसरे कृषि करने वाले दास। यद्यपि गाँव के रूप में पाई जाने वाली भौगोलिक और प्राथिक इकाई में नर का पूर्ण स्वामी तो सम्राट् (king) ही था, परन्तु उसका प्रशासन ग्रामपति (manorial lord) के द्वारा ही होता था। ग्रामपति गाँव का नियंत्रण कारिन्दा (steward) और अमीन (bailiff) के द्वारा रखता था। गाँव में ग्रामपति की एक अदालत (court baron) होती थी जिसका अध्यक्ष कारिन्दा (steward) होता था। इस अदालत के मुख्य कार्य ये थे—(क) भूमिपति का सेवा रखना, (ख) ग्रामपति और कृषकों के बीच सम्बन्ध का निर्वाह जो प्रायः परम्परा के अनुकूल रखा जाना था, तथा (ग) विभिन्न अवसरों पर कर (taxes) तथा जुमने (fines) वसूल करना। सभी व्यक्ति परम्परागत प्रथाओं का पालन करने के लिए बाध्य थे। ग्रामवासियों के झगड़े भी अदालत द्वारा ही किये जाते थे।

ग्राम के स्वतन्त्र वर्ग के निवासियों में ग्रामपति, उसके कर्मचारी, सहकारी, पादरी, इत्यादि सम्मिलित थे। कृषक-दासों में सम्मिलित व्यक्तियों के दो वर्ग थे—एक आसामी (villein) कहलाते थे, दूसरे कुटीरवासी (cottar) कहलाते थे। इन दोनों में कोई वैज्ञानिक अन्तर नहीं था परन्तु आसामियों की आर्थिक स्थिति कुटीरवासियों से अच्छी थी। एक पूर्ण आसामी के पास खुले खेतों की प्रायः तीस एकड़ भूमि होती थी जब कि कुटीरवासी के पास पाँच एकड़ या उससे भी कम होती। दोनों प्रकार के किसानों (villeins and cottars) को ग्रामपति की भूमि पर कार्य करना पड़ता था। उनको सप्ताह में प्रायः तीन दिन ग्रामपति की निजी भूमि पर काम तो करना ही पड़ता था, फसल कटते समय अथवा विशेष आवश्यकता होने पर बेगार (boon work) के रूप में अतिरिक्त कार्य भी करना पड़ता था। कृषक-दास स्वयं कार्य करने के बजाय अपने सम्बन्धियों को भेज सकते थे। यों तो कुटीरवासियों (cottars) को भी आसामियों की भाँति ही ग्रामपति के लिए कार्य करने को कहा जा सकता था परन्तु उनसे प्रायः बहुत कम काम लिया जाता था। अतएव वे मजदूरी करके भी आय कमा सकते थे।

कृषक-दासों से थम लेने के अतिरिक्त ग्रामपति उनसे कर और जुर्माना भी वसूल करता था। उन्हें गाँव छोड़ने की स्वतन्त्रता नहीं थी। यदि वे गाँव छोड़ कर भागने लें उन्हें पकड़वा कर दण्ड दिया जाता था। ग्रामपति की आज्ञा लेकर वे गाँव को छोड़कर जा सकते थे और अपनी जमीन बेच सकते थे परन्तु ऐसा

करने के लिए उन्हें एक कर (chevage) देना पड़ता था। बिना ग्रामपति की आज्ञा आसामी अपने पशु भी नहीं बेच सकता था, सन्तान को पढ़ा नहीं सकता था। अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर आसामी (villein) को एक विशेष कर (merchet) देना पड़ता था। यदि वह मरता तो उत्तराधिकारी कर के रूप में उसका सर्वश्रेष्ठ पशु या अन्य कुछ ले लिया जाता था जिसे मृत्यु-कर (heriot) कहा जा सकता है। आसामी के लिए यह भी आवश्यक था कि वह त्यौहारों पर ग्रामपति को अण्डे इत्यादी भेंट करे। ग्रामपति उनके ऊपर कितना ही कर लगा सकते थे। आसामियों को अपने स्वामी के विरुद्ध सम्राट् के न्यायालय में भी अभियोग चलाने का अधिकार नहीं था। व्यवहार में दासों को भी परम्परा द्वारा ग्रामपति का संरक्षण प्राप्त था।

गाँव की भूमि अधिकार की दृष्टि से तीन प्रकार की थी। ग्रामपति की निजी भूमि को डेमीन (demesne) कहा जाता था। गाँव की एक तिहाई के लगभग भूमि ग्रामपति की निजी भूमि होती थी, शेष भूमि कृषक-दासों तथा स्वतन्त्र व्यक्तियों को समझी जाती थी।

ग्रामपति प्रसन्न होकर किसी भी दास को स्वतन्त्र घोषित कर सकता था। पादरी भी स्वतन्त्रता प्रदान कर सकता था। सिद्धान्त में द्रव्य देकर भी दास ग्रामपति से भू-स्वामित्व प्राप्त करके स्वतन्त्र हो सकता था। स्वतन्त्र व्यक्ति ग्रामपति को कर अथवा जुर्माना देने के लिए बाध्य नहीं थे। वे गाँव छोड़ने के लिए स्वतन्त्र थे। वे ग्रामपति के विरुद्ध राजा या सम्राट् की अदालत में मुकद्दमा भी चला सकते थे। व्यवहार में ये स्वतन्त्र व्यक्ति भी ग्रामपति को यदा-कदा उपहार देते थे और ग्रामपति से पट्टे पर भूमि भी लेते थे।

गाँव की भूमि प्रायः तीन प्रकार की पाई जाती थी—खेतिहर भूमि, परती जमीन और चरागाह। चरागाह जमीन का उपयोग गाँव के सभी निवासी कर सकते थे। चरागाहों तथा परती जमीनों से ईंधन (जलाने की लकड़ी) भी प्राप्त करने का अधिकार मिला हुआ था। परती जमीनों में तथा फसल कटने पर कृषि-भूमि में भी पशु चराये जाने थे।

कृषि बहुत पिछड़ी अवस्था में थी। पहले दो-खेत प्रणाली (two-field-system) के अनुसार खेती होती थी, जिसमें जोन का आधा भाग परती छोड़ दिया जाता था। इसका उद्देश्य भूमि की उर्वरा शक्ति बनाये रखना था परन्तु इसमें काफी भूमि व्यर्थ पड़ी रहती थी। बाद में तीन-खेत प्रणाली (three field system) का प्रचलन हुआ। इस प्रणाली में प्रतिवर्ष दो खेतों पर कृषि

होती थी और तीसरे को परती रखा जाता था। इस प्रकार तीन वर्षों के समय में प्रत्येक खेत को विश्राम मिल जाता था। कौन-सी फसल बोई जायेगी, कब बोई और कब काटी जायेगी, ये सब बातें परम्परा से निश्चित थी। रिवाज की प्रबलता इतनी थी कि लोग उसके विपरीत जाने का विचार भी नहीं करते थे।

हल चलाना बड़ा कठिन परन्तु महत्वपूर्ण काम था। बड़ा हल आठ घोड़ों या बैलों द्वारा तथा छोटा हल चार द्वारा खींचा जाता था। कृषि-भूमि की प्रवेक्षा परती भूमि पर हल अधिक जोना जाता था और उसकी मिट्टी साल में दो या तीन बार उलटी जाती थी। साधारण किसान के पास पशु अधिक नहीं होते थे अतः उसे खुताई के लिए दूसरे किसानों का सहयोग लेना पड़ता था। पशु बहुत निम्न कोटी के पाये जाते थे। खेतों की प्रति-एकड़ उपज बहुत कम थी। खेती हाथ से होती थी, आधुनिक यंत्रों का प्रयोग नहीं हुआ था। शसजम, भालू, जिमीकन्द इत्यादि फसलों की खेती नहीं होती थी। सिंचाई का उपयुक्त प्रबन्ध नहीं था।

आवागमन के साधनों के अभाव के कारण कृषि की उपज को बाहर भेजना और उसका विपणन सम्भव नहीं था। बाहर से केवल कुछ ही वस्तुएँ (लोहे की बनी वस्तुएँ, मसाले इत्यादि) आती थी। समय समय पर मेले-हाट इत्यादि होते थे। मजदूरी और लगान प्रायः वस्तुओं द्वारा चुकाये जाते थे। प्रसंविदा और स्पर्द्धा के बजाय रिवाज और परम्परा का ही प्रभुत्व था।

गाँव में ग्रामपति का मकान लकड़ी-पत्थर का बना होता था, गाँव में गिरजाघर, चक्की इत्यादि होने थे और जनसाधारण के घास-फूस के शोपड़े पाये जाते थे।

इंग्लैण्ड में पाई जाने वाली और अन्य अनेक देशों में फैली प्राचीन ग्राम संगठन प्रणाली (manorial system) के दोष बताना सरल है। मुख्य दोष ये बताये जाते हैं—

(१) दास प्रथा का पाया जाना और स्वतन्त्रता का अभाव। (२) रिवाज का इतना अधिक नियन्त्रण था कि व्यक्ति बुद्धिमानी और साहस का प्रयोग नहीं कर सकता था। (३) खुले खेतों की प्रणाली के भी अनेक दोष थे। सीमा सम्बन्धी झगड़े बहुधा होते थे। खेतों के बीच बहुत सी भूमि व्यर्थ हो जाती थी। अलसी व्यक्तियों के खेतों में घास-फूस उगते जो दूसरे व्यक्तियों के खेतों में भी फँस जाते थे, इत्यादि। (४) अम-विभाजन का अभाव था। एक गाँव के व्यक्तियों का दूसरे गाँव के व्यक्तियों से सम्पर्क नहीं हो पाता था। (५) अदलत बदली की प्रथा थी। मुद्रा के प्रचलन के अभाव में बचतों और पूँजी का निर्माण

सम्भव नहीं था। कुल मिलाकर उस समय इंग्लैण्ड में पिछड़ी हुई अर्थ व्यवस्था थी जिसमें प्रगतिशीलता के लिए गुंजायश कम थी। यह मानना पड़ेगा कि यह प्रणाली इंग्लैण्ड में चार शताब्दियों से भी अधिक रही और उसमें केवल दोष ही थे, यह बात नहीं है। वस्तुतः उस समय की परिस्थितियाँ ही ऐसी थी कि सुधार कठिन था, परन्तु रिवाज इतना प्रबल रहा कि यह प्रणाली अपनी उपयोगिता के काल से भी अधिक जीवित रही और उन्नति में बाधक बन गई।

ग्राम संगठन की इस प्राचीन प्रणाली (manorial system) का पतन पन्द्रहवीं शताब्दी में स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगा। उसके पतन के कई कारण थे, जिनमें मुख्य ये हैं—

- (क) मुद्रा का प्रचलन,
- (ख) कस्बों और नगरों का विकास,
- (ग) भूमि की घेरेबन्दी (enclosure movement),
- (घ) महामारियों और काली-मृत्यु (black-death), तथा
- (ङ) ग्रामीण न्यायालयों की समाप्ति।

१५वीं शताब्दी में उपर्युक्त कारणों पर आधारित इतने अधिक परिवर्तन हुए कि रूढ़ि और परम्परा पर आधारित मेनोरियल प्रणाली अन्ततोगत्वा टूट गई।

मुद्रा के प्रचलन का मुख्य प्रभाव यह हुआ कि दास प्रथा का अन्त हो गया। किसान अब ग्रामपति को लगान मुद्रा द्वारा चुकाने लगे और ग्रामपति उनसे बेगार लेने के बजाय नकद मजदूरियाँ देने में लाभ समझने लगा। ग्रामपति द्वारा आरोपित मनमाने करों तथा दण्डों और भारों के विरुद्ध किसान-वर्ग ने एक बहुत बड़ा आन्दोलन छेड़ा जिसके आगे रूढ़ियों को झुकना पड़ा। किसानों का यह आन्दोलन (Peasant Revolt) मई १३८१ में हुआ था। उनकी मुख्य माँग यह थी कि उन्हें साप्ताहिक और विशेष कार्य (weekly and boon work) में मुक्ति मिले और सेवाओं तथा लगान और मूल्यों की अदायगी वस्तुओं के बजाय द्रव्य में निश्चित की जाये। इस परिवर्तन को कम्यूटेसन (commutation) कहा गया। यह किसान और ग्रामपति दोनों के लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ परन्तु, कृषक दासों की सामाजिक स्थिति ऊँची हो जाने के कारण उन्हें अधिक सन्तोष हुआ।

छोटे छोटे नगरो और कस्बो का विकास भी १४वीं शताब्दी में ही होने लगा था जिनमें मजदूरों की भाँग बढ़ी । ग्रामपतियों को भी सुख सुविधा की दृष्टि से नगरो में रहना अच्छा लगा । उन्हें लगान मुद्रा में मिल जाने के कारण गाँव में रहना और अन्न वसूल करना आवश्यक नहीं रहा । ग्रामपति अपनी निजी भूमि (demesne) को भी लगान पर उठाने लगा । इस प्रकार डेमीन भूमि की समाप्ति हो गई । कृषि की अव्यवस्था न हो इस दृष्टि से ग्रामपतियों ने श्रमिकों को कानून के बन्धनों द्वारा गाँवों में रखने के प्रयत्न किये परन्तु स्पर्द्धा और प्रसंविदा के परे इन प्रयत्नों में सफलता नहीं मिल सकी ।

एक ओर नगरो और कस्बो में मजदूरों की भाँग बढ़ रही थी, गाँव में परम्परागत व्यवहार अग्रिथ था और दूसरी ओर महामारियों द्वारा श्रमिकों की पूर्ति घटी थी । १४वीं शताब्दी के मध्य में, इंग्लैण्ड में ही नहीं, योरोप के अनेक देशों में ऐसी प्लेग फैली जिसे काली मृत्यु (black-death) कह कर पुकारा जाता है । गाँवों में यह परिस्थिति अनेक वर्षों तक चलती रही जिसके कारण खेती के लिए श्रमिक दामों का मिलना कठिन हो गया । इस कठिनाई का एक हल यह निकाला गया कि किसानों को पट्टे पर भूमि दी गई और रिवाज के बजाय लगान स्पर्द्धा और प्रसंविदा पर निर्भर होने लगा ।

मेनोरियल प्रणाली के विनाश का चौथा मुख्य कारण यह था कि ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए ऊन की बढ़ती हुई माँग तथा श्रमिकों की कमी के कारण अपनी निजी भूमि को भेड़ें पालने के लिए घेरने लगे । चारागाहों को भी घेरा गया और किसानों को बेदखल करके उनकी जमीनों पर स्वामित्व प्राप्त करके उन पर भी भेड़ें पालना आरम्भ किया गया । १६वीं शताब्दी के इस समा-वरण आन्दोलन (enclosure movement) के कारण, जिसका विस्तृत विवरण अन्यत्र दिया गया है, गाँव किमानों से खाली होने लगे और मजदूरों पर भी दुरा असर पड़ा ।

मेनोरियल प्रणाली के टूटने का एक और कारण ग्रामीण न्यायालयों की समाप्ति था । ज्यों ज्यों किसान दास-वृत्ति से मुक्ति पाने की ओर अग्रसर हुए जमींदार (lord) को ग्रामीण अदालत लगाना लाभप्रद नहीं रहा । इंग्लैण्ड में केन्द्रीय शासन बढ़ रहा था । लोगों का यह असंदिग्ध अधिकार माना जाने लगा कि वे अपने मामलों राजकीय न्यायालयों में ले जा सकें । ग्रामीण अदालतों में जाने वाले भगदों में कमी होती गई और ये न्यायालय स्वतः ही बन्द होते गये ।

१५वीं शताब्दी के अन्त तक मध्ययुगीन जमींदारी प्रणाली (मेनोरियल प्रणाली) समाप्तप्रायः हो चुकी थी। खुले खेतों की पद्धति आगे भी चलती रही परन्तु कृषक-दासों का स्थान वैतनिक श्रमिकों ने ले लिया था। जमींदार की निजी जमीनें समाप्त हो गईं। अदस्ता-बदली (barter) की प्रणाली के बजाय मुद्रा-अर्थ व्यवस्था आ गई। व्यापार बढ़ा, रूढ़ियाँ टूट गईं और प्रतियोगिता-पूर्ण नए युग का विकास होने लगा।

प्राचीन औद्योगिक प्रणालियाँ

औद्योगिक क्रांति से पूर्व इंग्लैंड में उद्योग प्रणालियों का विकास चार सोढियों द्वारा आगे बढ़ा—

- (१) गृह उद्योग (household system),
- (२) गिल्ड प्रणाली (craft guild system),
- (३) घरेलू प्रणाली (domestic system) तथा
- (४) कारखाना प्रणाली (factory system)।

इनमें कारखाना प्रणाली का विकास और औद्योगिक क्रांति समान और समकालीन समझे जाते हैं।

गृह-उद्योग प्रणाली—स्वायत्तम्वन की अवस्था का ही एक अंग थी जिसमें व्यक्ति कृषि अथवा जीविका के अन्य साधनों, जैसे, पशु-पालन, मछली पकड़ना, आखेट करना, इत्यादि के साथ साथ ही आवश्यक वस्तुओं का गाँव में घर पर ही निर्माण करते थे, जैसे, वस्त्र, इत्यादि। गृह-उद्योग प्रणाली में पूँजी नाममात्र की थी और बाजार अत्यन्त सकुचित, केवल स्थानीय था।

गिल्ड प्रणाली का विकास

(Origin of the Craft Guild)

गिल्ड प्रणाली का जन्म १२वीं शताब्दी में हुआ। इस प्रणाली के उदय होने से व्यवसाय को कृषि से भिन्न आर्थिक क्रिया समझा जाने लगा। गिल्ड प्रथा सर्वप्रथम जुलाहों में अपनाई गई, तदुपरान्त अन्य धंधों में। गिल्ड एक व्यावसायिक संगठन का रूप था और इस संगठन को प्रायः वैधानिक मान्यता मिली हुई होती थी। गिल्ड का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक नियन्त्रण था।

गिल्ड के उद्देश्य प्रायः निम्नलिखित हुआ करते थे—

(१) व्यवसाय का नियन्त्रण—गिल्ड के अधिकारी देखते थे कि उनके व्यवसाय का काम उच्च कीटि का हो। मात की विस्म गिराने वाले अपराधियों को दण्ड देने की भी व्यवस्था थी। इसी दृष्टि से मजदूरों को रात

के समय काम नहीं करने दिया जाता था क्योंकि रात में काम घटिया होने की सम्भावना थी। गिल्ड के अधिकारी घूम फिर कर निरीक्षण किया करते थे। कारीगरी को प्रोत्साहन देने के लिए ट्रेनिंग और शिक्षा (apprenticeship) की व्यवस्था थी। कोई भी कारीगर गिल्ड का सदस्य बने बिना कोई शिल्प-कार्य आरम्भ नहीं कर सकता था।

(२) शिल्प संगठन का दूसरा मुख्य कार्य उस शिल्प में मजदूरों का वेतन निश्चित करना था। इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के हितों की रक्षा करना प्रतीत होता है, परन्तु वस्तुतः इससे एक ही प्रकार के शिल्प में वस्तु की उत्पादन लागत निश्चित और समान रह सकती थी।

(३) गिल्ड का तीसरा मुख्य कार्य वस्तु की कीमत निर्धारित करना था ताकि उपभोक्ता को उचित मूल्य पर वस्तु मिले। इस प्रकार गिल्ड केवल उत्पादकों का संघ नहीं था बल्कि मजदूरों तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा का, कम से कम आरम्भ में, ध्यान रखा गया था।

उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त गिल्ड प्रायः निम्नलिखित कार्य भी करते थे—

(४) वे धार्मिक उत्सवों की व्यवस्था तथा देखरेख करते थे।

(५) वे मंत्री समितियों की भांति कार्य, यथा दावतों और पार्टियों का आयोजन, भी करते थे।

(६) मजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भाग लेते थे।

(७) अपने सदस्य कारीगरों को बाहरी स्पर्धा से बचाते थे। उदाहरण के लिए नगर के बाहर के गिल्ड के मीर सदस्यों को नगर में माल नहीं बेचने देते थे।

(८) पंचायत कार्य (arbitration)—सदस्यों की आपस में कानूनी कार्य-वाही करने दी जाती थी। गिल्ड के सदस्यों में यदि कोई झगडा होता तो पहले गिल्ड के अधिकारी ही फैसला करने का प्रयत्न करते थे, परन्तु यदि यह सम्भव न होता तो उनकी आज्ञा लेकर मामला न्यायालय को ले जाया जा सकता था।

गिल्ड का संगठन

गिल्ड के सदस्य तीन प्रकार के हुआ करते थे—

(क) मिस्त्री (masters या master craftsman),

(ख) प्रशिक्षित श्रमिक (journeyman) तथा

(ग) शिषार्थी (apprentices)।

मिस्त्री (masters) उन कुशल कारीगरों को कहा जाता था जिनकी निजी दुकान या शिल्पशाला (workshop) होती, जिसमें वे अपनी सहायता के लिए वेतन पर प्रशिक्षित श्रमिक (journeymen) रखते थे और शिक्षार्थियों (apprentices) को ट्रेनिंग दिया करते थे। मिस्त्री अपनी कारीगरी में पूर्णतया कुशल होते थे। उनके निजी औजार होते थे तथा वे अपने सहायक कारीगरों (journeymen) को काम करने के लिए आवश्यक औजारों के प्रतिरिक्त प्रायः जगह भी देते थे। इस प्रकार वे एक ओर पूँजीपति और दूसरी ओर कुशल कारीगर थे।

प्रशिक्षित श्रमिक जिन्हें जर्नीमैन कहा जाता था, स्थायी या अस्थायी रूप से काम करने वाले मजदूर होते थे जो मिस्त्रियों के यहाँ वेतनभोगी (employees) रहकर काम करते थे। ये जर्नीमैन साधन जुट जाने पर स्वतन्त्र दुकानें या शिल्पशालाएँ खोल लेते थे अर्थात् मिस्त्री बन जाते थे।

शिक्षार्थी (apprentices) ऐसे तल्ले होते थे जो जर्नीमैन बनना चाहते थे। गिल्ड के नियमों के अनुसार मिस्त्री के लिए यह आवश्यक था कि वह उन्हें अपने पुत्र के समान समझे; उन्हें भोजन, वस्त्र, ठहरने के लिए स्थान दे तथा उन्हें सबकुछ सिखला दे, गुप्त कुछ भी न रखे। इसके बदल में शिक्षार्थियों को अपने मिस्त्री (master) का छोटे से छोटा काम भी करना पड़ता था। व्यवहार में शिक्षार्थियों से मिस्त्री प्रायः अवैतनिक मजदूरों की तरह काम लेते थे परन्तु इस शिक्षा-व्यवस्था में बुराइयों को रोकने के लिए गिल्ड और सरकार की ओर से देखभाल और नियन्त्रण रखने के कदम उठाए गए।

गिल्ड का प्रशासन (Administration)

क्राफ्ट गिल्ड का प्रशासन वार्डनो (wardens) के द्वारा होता था, जिनकी नियुक्ति या तो नगर के मेयर (mayor) के द्वारा होती थी या उनका चुनाव गिल्ड की सभा (जनरल असेम्बली) करता था। यह सभा (assembly) नियम और आदेश बनाती थी कि गिल्ड का कार्य उनके अनुसार चलता रहे। परन्तु इन नियमों और आदेशों के लिए पहले नगर के अधिकारियों अथवा जस्टिस ऑफ पीस (Justices of Peace) की स्वीकृति लेना आवश्यक था। कहीं कहीं गिल्ड की सभा नियम और आदेश बनाने के लिए एक कौंसिल (council) नियुक्त कर देती थी। यह कौंसिल प्रायः इस बात का निर्णय भी करती थी कि अपराधी कौन है अथवा गिल्ड अपनी अदालत स्थापित कर देते थे।

क्राफ्ट गिल्ड और आधुनिक व्यापारिक संगठन (Trade Union) में अन्तर

यद्यपि क्राफ्ट गिल्ड अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करते थे और उन्हें बाहरी स्पर्धा से बचाते थे परन्तु क्राफ्ट गिल्ड और श्रम संघों (trade unions) के बीच पर्याप्त अन्तर है। अन्तर की मुख्य बातें प्रयोजित हैं—

(१) गिल्ड पूरे व्यवसाय और उसमें लगे हुए सब व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए स्थापित होते थे, ट्रेड यूनियन प्रायः केवल मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए होते हैं।

(२) क्राफ्ट गिल्ड टैक्नीकल अधिकतर ट्रेनिंग की भी व्यवस्था करते थे परन्तु ट्रेड यूनियन अधिकतर मजदूरियों और काम की दशाओं पर ही ध्यान देते हैं। श्रम-संघों में अपने कार्यों का क्षेत्र बढ़ाया है परन्तु उनके मुख्य कार्य मजदूरियों तथा फैक्टरी में काम की दशाओं से ही सम्बन्धित हैं।

(३) इसके अतिरिक्त क्राफ्ट गिल्ड का कार्य प्रायः किसी एक नगर तक सीमित होता था, ट्रेड यूनियन का क्षेत्र प्रायः विस्तृत होता है।

(४) ट्रेड यूनियन के उद्देश्य बहुधा राजनीतिक होते हैं, क्राफ्ट गिल्ड इन उद्देश्यों से परे कार्य करते थे।

गिल्ड प्रणाली के गुण-दोष

श्रमिकों के लिए गिल्ड प्रणाली का मुख्य लाभ यह था कि इसके अन्तर्गत उन्हें काम की ठीक दशाओं, उचित वेतन तथा वृत्ति (employment) की वाछनीय निश्चितता की सुविधाएँ प्राप्त थीं।

गिल्ड वस्तु की ठीक किस्म और उचित कीमत पर ध्यान देते थे। अतः उत्पादक-विक्रेता एवं ग्राहक उपभोक्ताओं, दोनों के हितों की रक्षा होती थी।

गिल्ड व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करते थे, इस प्रकार सरकार को शिल्प-शिक्षा की दृष्टि कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ती थी।

गिल्ड प्रणाली की हानियाँ भी बताई जाती हैं। गिल्ड का मुख्य कार्य व्यवसायिक नियन्त्रण था। जब स्वतन्त्र व्यापार की धुम हुई तो इसे व्यक्ति के स्वतन्त्र व्यापार तथा साहस में बाधक समझा गया। यह भी कहा गया कि गिल्ड प्रथा औद्योगिक विकास को कुछ सीमा तक रोकती थी क्योंकि गिल्ड का व्यवहार स्थानीय एकाधिकार स्थापित करने जैसा था। वस्तुतः जैसा कि

लिप्सन ने कहा है, गिल्ड नियन्त्रण इङ्ग्लैण्ड के आर्थिक विकास में एक आवश्यक अवस्था थी।^१

गिल्ड प्रथा का अन्त

वस्तुओं के बाजारों के बढ़ने के साथ गिल्ड प्रथा चल न सकी। गिल्ड प्रथा का अन्त होने के मुख्य कारण निम्नांकित थे—

१. प्रशिक्षित श्रमिकों के शिल्प संघों (journeymen guilds) का विकास—मिस्त्री और प्रशिक्षित श्रमिकों में मजदूरी की दरों पर प्रायः झगड़ा हो जाता था। काम के घटों के लिए भी झगड़ा चलता था। अतः उन्होंने अपने अलग गिल्ड बना लिए परन्तु वे अधिक शक्तिशाली न बन सके।

२. गिल्ड की सामाजिक क्रियाओं का अन्त—गिल्ड के सदस्यों का सामाजिक क्रियाओं में उत्साह उन्हें परस्पर भैत्री और भ्रातृत्व के बन्धन में बांधे रखता था, परन्तु कालान्तर में गिल्ड की आन्तरिक क्रियाओं में शिथिलता आने लगी थी। सामाजिक क्रियाओं में सदस्य उदासीनता दिखाने लगे थे जिसके परिणामस्वरूप संगठन सूत्र कच्चे घागे की भाँति कमजोर पड़ गया।

३. शक्ति का दुरुपयोग और स्वार्थपरता—गिल्ड चलाने वाले अधिकारियों ने स्वार्थवश शक्ति का दुरुपयोग किया। उदाहरणार्थ, प्रशिक्षित श्रमिकों (journeymen) के मिस्त्री बनने पर रुकावट कर दी गई; सदस्यता शुल्क बढ़ा दिया गया जिससे शिल्प के विकास में बाधा पड़ी। बहुधा नये भर्ती होने वाले सदस्यों को गिल्ड के अन्य सदस्यों को दावत देने के लिए बाध्य किया जाने लगा जो बहुत खर्चीला होता था।

४. सरकारी हस्तक्षेप—विभिन्न कुराहियों आने पर देश की सरकार ने उनके लिए विविध कानून (सन् १४३७, १५०४, १५४७ में) बनाकर हस्तक्षेप किया। सरकारी नियन्त्रणों का भी यह परिणाम हुआ कि गिल्ड में शिथिलता आने लगी।

५. व्यापारिक कंपनियों का विकास (Rise of "Livery" Companies):—^२ गिल्ड के ही कुछ सदस्य अपना अलग वर्ग बना बैठे—व्यापारी वर्ग।

1. "Gild control was a necessary stage in economic development."—Lipson.

२. Livery विशेष पोशाक थी जो गिल्ड के केवल धनी और महत्त्वपूर्ण सदस्य ही पहिन सकते थे। इस प्रकार गिल्ड के सदस्यों में अन्तर पड़ गया। कालान्तर में धनी-मानी व्यक्तियों ने व्यापारिक कंपनियाँ बना ली।

उन्होंने अलग कम्पनियाँ खोल ली। १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ में ऐसी अनेक कम्पनियाँ वर्तमान थी। इस व्यापारी वर्ग को गिल्ड के सदस्य व्यवसायियों से ऊँचा समझा जाता था और शिल्प संघों की प्रतिष्ठा कम होने लगी।

६. कारीगरों से व्यापार का छिन जाना—“पोशाकी” कपनियों के विकास से संबंधित गिल्ड के सदस्यों पर प्रभाव डालने वाली बात केवल प्रतिष्ठा की हानि नहीं थी। कई कपनियाँ गिल्ड के व्यवसायियों को व्यापार कार्य नहीं करने देती थीं। उनका कार्य केवल निर्माण (manufacture) करना रह गया।

७. गिल्डों का एकीकरण (Amalgamation of Craft Gilds) प्रारम्भ में बड़े बड़े नगरों में अनेको गिल्ड होते थे परन्तु कालान्तर में इनका एकीकरण होने लगा और गिल्ड का नियन्त्रण पूँजीपतियों के हाथों में जाने लगा। सन् १४२३ में लन्दन नगर में १११ विभिन्न प्रकार के गिल्ड थे परन्तु सन् १५३१ में लन्दन में कुल ६० गिल्ड रह गये। पूँजीपतियों के नियन्त्रण होने के साथ ही घरेलू प्रणाली का विकास हुआ।

८. नये नगरों का विकास और उनकी रक्षा—मध्ययुग में कस्बों का आकार बहुत छोटा और उनकी संख्या बहुत कम थी। कस्बे वस्तुतः बड़े गाँव (manor) के समान थे। कालान्तर में व्यापार बढ़ने के साथ कस्बों का विकास हुआ। नये नगरों के विकास के कारण अनेक और विभिन्न थे। रोम-काल में रोम वासी ने जहाँ किले बनाये वहाँ प्रायः नगर बसे। सुरक्षा का लाग नगर विकास में मुख्य रूप से सहायक था। नदियों के संगम स्थान पर तथा सड़कों या सड़क-नदी के मिलने के स्थान पर व्यापार के लिए अनुकूल स्थिति मिल जाने से नगरों का विकास हुआ। समुद्र-तट से भीतरी भागों में नदियों के मुहानों पर जहाँ उत्तम बन्दरगाह बन सकते थे नगर बस गये। भीतरी और नगर बसने के दो मुख्य कारण थे—पहला तो यह कि समुद्र की ओर से एकदम आक्रमण का भय कम था, दूसरे, व्यापार के लिए भीतरी भागों से वस्तुओं का सभ्रह सुविधाजनक होता था। कई नगर मकान बनाने के सामान की सुलभता के स्थानों पर और अन्य कई बड़े गिरजाघरों के निकट ही बस गये। नये नगरों में सुरक्षा अधिक थी और निवासियों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे।

गिल्ड में जिन कारीगरों को सदस्यता नहीं मिल सकी अथवा प्रशिक्षित श्रमिकों को मिस्त्री बनने का अवसर हाथ नहीं लग सका वे नये नगरों में जाकर बस गए।

इस प्रणाली का प्रारम्भ सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र व्यवसाय में हुआ। व्यापारी साहसी कच्ची ऊन (raw wool) खरीद कर कातने वालों को देता, कतने पर उसे कातने वालों से लेकर बुनकरों को देता था। बुन जाने पर उसे देशी या विदेशी बाजारों में बेचता था। पहले पहल मशीनों का प्रयोग नहीं होता था और जब कुछ प्रारम्भ हुआ तो केवल मस्ती, सरल और साधारण मशीनें ही प्रचलन में आईं। ऊनी वस्त्र व्यवसाय में व्यापारी-पूँजीपति या मध्यवर्ती को कपड़ेवाला (clothier) कहते थे।

घरेलू प्रणाली के लाभ

घरेलू प्रणाली के विकास के कारणों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, परन्तु इस प्रणाली का उदय उसके कुछ लाभों तथा उसकी सुगमताओं के कारण भी हुआ सम्झा जाना चाहिए। इस प्रणाली के मुख्य लाभ निम्नलिखित बताये जा सकते हैं—

(क) खेतिहर अपने खाली समय में काम करके अपने परिवार की आय बढ़ा सकते थे, क्योंकि इन प्रणाली में घर बैठे ही काम मिल जाता था। उस समय (१५वीं और १६वीं शताब्दियों में) वहाँ के किसानों की ग्रामदनियाँ बहुत कम थी। इसमें परिवार के अन्य सदस्य भी काम में हाथ बटा सकते थे। इसके प्रतिरिक्त कारीगर का दर्जा (status) इस प्रणाली में निम्न नहीं समझा जाता था क्योंकि वह केवल मजदूरी पाने वाला श्रमिक नहीं, भूमि का स्वामी भी था।

(ख) आधुनिक औद्योगिक नगरों की गन्दगी, धुँआँ धक्कड़, भीड़ और बीमारियाँ उस समय नहीं थी। गिबिन्स ने अपनी पुस्तक औद्योगिक इतिहास में इस तथ्य पर प्रकाश डाला है।

(ग) घरेलू प्रणाली में श्रम विभाजन का विकास हुआ जिसके कारण श्रमिकों की कार्यक्षमता तथा उत्पादन में तो वृद्धि हुई ही, साथ ही इसने बढ़ते हुए बाजारों के लिए व्यवसाय की पूँजीवादी प्रणाली का विकास सम्भव बनाया।

(घ) गिल्ड प्रथा के नियमन (regulation) की अपेक्षा घरेलू प्रणाली में साहसी का कारीगरों के साथ सीधा सम्पर्क और काम की देख-भाल अधिक तबल और उपयोगी सिद्ध हुए।

(ङ) घरेलू प्रणाली ने गिल्ड प्रथा और उसके एकाधिकारों स्वभाव का प्रन्त करके बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास के लिए मार्ग खोल दिया।

घरेलू प्रणाली के दोष

घरेलू प्रणाली व्यावसायिक विकास के क्षेत्र में अमिश्रित आनीर्वाह नहीं थी। इनके कई दोष भी थे—

(१) सामान्य मन के विपरीत, घरेलू प्रणाली में कारीगर को स्वाधीनता नहीं थी। उसे कच्चे माल और औजारों के लिए मालिक (employer) पर आश्रित होना पड़ता था और इनो कारण कारीगर को मजदूरी कम मिलती थी, उनका शोषण होने लगा था।

(२) इस प्रणाली के अन्तर्गत कालान्तर में पूँजीपति और कारीगर का प्रत्यक्ष सम्पर्क समाप्त हो गया और दोनों के बीच का सम्बन्ध एजेंटों (agents) के द्वारा होने लग गया और सामाजिक अशान्ति प्रारम्भ हो गया।

(३) घरेलू प्रणाली में मालिक (employer) प्रायः किसी कस्बे या नगर में रहता था और मजदूर प्रायः गावों में। इन प्रकार सहर से गाँव में कच्चा माल लाने और गाँव से सहर का बना हुआ माल ले जाने में समय और श्रम का बुरा उपयोग होता था।

(४) मजदूरों में अधिक स्पर्धा होने पर उन्हें अधिक परिश्रम करना पड़ता था और वे अपना सब समय मजदूरी के काम में ही दे देते थे। कृषि का काम साधन-साधन खताना कठिन हो गया। अतः उनका या तो कृषि का काम छोड़ना पड़ा या कृषि की उपेक्षा की गई।

(५) इस प्रणाली में मजदूरों को मजदूरी में बहुत ही कम दिया जाता था। जो वस्तुएँ उन्हें दी जाती थी वे प्रायः घटिया किस्म की होती थीं।

(६) घरेलू प्रणाली का एक अत्यन्त अस्वस्थ प्रभाव यह देखने में आया कि बच्चों से भी काम कराना जाने लगा और उनकी शिक्षा की उपेक्षा हुई।

कृपया मनाकर यह कहा जा सकता है कि यद्यपि घरेलू प्रणाली के कुछ लाभों में सन्देह नहीं किया जा सकता तथापि इस प्रणाली में व्यावसायिक शोषण प्रारम्भ हो गया था और कई अवांछनीय उत्पन्न प्रवेश कर गये थे।

वस्तुतः, घरेलू प्रणाली की स्थिति निम्न प्रणाली और फॅक्टरी प्रणाली के बीच की थी। घरेलू प्रणाली में कारीगर की स्वतन्त्रता निम्न प्रणाली की अपेक्षा कम हो गई थी। अब कारीगर कच्चे माल और औजारों के लिए पूँजीपति का आश्रित हो गया था। दूसरी ओर, पूँजी का महत्व और प्रयोग बढ़ चले थे तथा श्रम विभाजन का विकास हो रहा था। मशीनों और बड़े पैमाने के उत्पादन का महत्व समझा जाने लगा था परन्तु घरेलू प्रणाली में

इनका प्रयोग सम्भव नहीं हो सका। अभी केवल साधारण औजारों (हथौड़े, धोकरनी इत्यादि) का ही प्रयोग हुआ था और विशेष टैकनीकल सुधार नहीं हुए थे। परन्तु जो परिवर्तन घरेलू प्रणाली में ही देखे जाते मगें वे उन्होंने औद्योगिक क्रान्ति द्वारा इंग्लैण्ड की औद्योगिक समृद्धि का मार्ग परिष्कृत कर दिया था।

वाणिज्यवाद (Mercantilism)

यह पहले बताया जा चुका है कि १५वीं शताब्दी के अन्त में मध्ययुगीन मेनोरियल प्रणाली का पतन हो गया। इस काल में कृषि में इतने परिवर्तन हुए, जिनमें भेड़ें चराने के लिए भूमि समावरण इत्यादि सम्मिलित थे, कि कृषि में इन्हें १६वीं शताब्दी की कृषि क्रान्ति कहा गया। जैसा कि पहले सकेत किया जा चुका है इन परिवर्तनों के गम्भीर परिणाम हुए। यह भी बताया जा चुका है कि १५वीं शताब्दी में औद्योगिक क्षेत्र में गिल्ड प्रणाली का पतन और घरेलू प्रणाली का विकास हुआ, ऊनी कपड़े का निर्माण, तथा उन ऊनी वस्त्र और अन्य वस्तुओं का व्यापार बढ़ा। इसके पूर्व अधिकांश विदेशी व्यापार विदेशियों के हाथों में था परन्तु ब्रिटेन के नागरिक इस बात को महत्त्व देने लगे कि विदेशी व्यापार का नियन्त्रण उनके हाथों में हो और उसमें वृद्धि हो।

१५वीं शताब्दी के अन्त की और ब्रिटेन के आर्थिक इतिहास में एक मोड़ आता है। यहाँ मध्ययुगीन अर्थव्यवस्था के क्षण्डहर पर वाणिज्यवाद (mercantilism) का भवन खड़ा किया। वाणिज्यवाद इस काल में अपनाई गई व्यापक आर्थिक नीति थी जिसकी यद्यपि बाद में भारी आलोचना हुई और वह तर्कपूर्ण सिद्ध नहीं हुई परन्तु वाणिज्यवाद का युग (era) ब्रिटेन के आर्थिक इतिहास में निश्चित अवस्था थी जिसका महत्त्व उपेक्षणीय नहीं है।

मध्यकालीन (medieval) आर्थिक जीवन का प्रत्येक पहलू कृषि उद्योग और वाणिज्य-नियंत्रित था। मनुष्य किसी संगठन, यथा, मेनर, गिल्ड अथवा कम्पनी की इकाइयों के रूप में कार्य करते थे।^१ आर्थिक प्रयत्नों का क्षेत्र स्थानीय था; धन की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्त्व दिया जाता था—वर्च शक्तिशाली संस्था थी; हर एक क्रिया में रूढ़ि और परम्परा पर अधिक जोर

1 Southgate : English Economic History, ch. 8, Mercantilism, p. 67.

दिया जाता था और राष्ट्रीयता की भावना देशों के बीच भेद पैदा करने वाली सीमा तक नहीं बढ़ पाई थी। पन्द्रहवीं शताब्दी में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक ऐसी घटनाएँ घटीं कि उनके परिणामस्वरूप नीति सम्बन्धी जो व्यापक परिवर्तन हुए, जिनका हर एक क्षेत्र में प्रभाव पड़ा, उन्हें बाद में 'वाणिज्यवाद' नाम दिया गया।

वाणिज्यवादी सिद्धान्तों का जोर १६ वीं और १७ वीं शताब्दियों में अधिक रहा। गिरजाघर के विरोध करने पर भी इस युग में धर्म को अधिक महत्त्व दिया जाने लगा। नैतिकता सिधिल हो गई। रुडियॉ दुर्बल पड़ गई। राष्ट्रीयता की भावना स्पष्ट और प्रबल हो गई।

वाणिज्यवादी युग की मुख्य विशेषताएँ ये थी—

(१) राज्य (state) को सर्वोपरि माना गया और देश के राजनीतिक मोहदे (status) को ऊँचा उठाने का भरसक प्रयत्न किया गया।

(२) विदेशी व्यापार और अनुकूल व्यापारान्तर को महत्त्व दिया गया। वस्तुतः "अनुकूल व्यापारान्तर" शब्द इसी युग की उपज थे। वाणिज्यवादियों की भ्रान्तिपूर्ण धारणा थी कि देश में धन की वृद्धि करने का एकमात्र उपाय यही था कि ब्रिटेन अन्य देशों को निर्यात अधिक करे और उन देशों में आयात कम करे, क्योंकि ऐसा करके वह स्वर्ण तथा अन्य बहुमूल्य धातुएँ प्राप्त कर सकता था। राष्ट्रीय कोष में उस समय स्वर्ण को अत्यधिक महत्त्व दिया गया। वाणिज्यवादियों ने स्वर्ण को एक वस्तु नहीं बल्कि विशेष सम्पत्ति माना और यह भूल की कि सभी देशों द्वारा वाणिज्यवादी नीति अपनाये जाने पर उनकी सब योजनाएँ विफल रहेंगी।

(३) कृषि की अपेक्षा व्यापार और पूँजी को अधिक महत्त्व दिया गया।

(४) कृषि, उद्योग, व्यापार इत्यादि सभी क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप को सिद्धान्तः महत्त्व दिया गया और व्यवहार में सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। राष्ट्र की समृद्धि और देश की स्वर्ण निधि में वृद्धि करने के लिए ऐसे साधनों को अपनाना भी उचित माना गया जिन्हें अन्यथा व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य में बाधक समझा जाता।

(५) राष्ट्र की शक्ति बढ़ाने के लिए मैनिफ और नौ सेना शक्ति बढ़ाने पर बल दिया गया।

१. इन घटनाओं में प्रमुख सम्बन्ध युद्ध, पुनर्जागरण (Renaissance), सामन्तों का पतन, भौगोलिक अन्वेषण तथा धार्मिक मुद्धार इत्यादि हैं।

इस युग में आवागमन के साधनों का विकास हुआ। राज्य द्वारा उद्योगों का नियन्त्रण किया गया। नौ-वहन (Navigation) पद्धति का विकास भी इसी काल में प्रारम्भ हो गया था। नियन्त्रणकारी कानून पास किये गये। नियन्त्रित आर्थिक जीवन तो मध्यकाल में भी था परन्तु बाणिज्यवादी युग में नियन्त्रणों का क्षेत्र स्थानीय नहीं रहा बल्कि पूरे देश में उन्हें लागू किया गया। औपनिवेशिक व्यापार और उसका स्वभाव बाणिज्यवादी सिद्धान्तों की उपज थी। १६ वीं शताब्दी में ऐसी अनेक कम्पनियाँ स्थापित हुईं जो या तो संपुक्त-पूँजी वाली कम्पनियाँ (joint-stock companies) थी या नियमबद्ध साझेदारियों के रूप में थी। ये दोनों प्रकार की कम्पनियाँ दूर दूर देशों के साथ व्यापार करने लगीं। ईस्ट इण्डिया कम्पनी जिम्ने भारत में ब्रिटेन का प्रभाव बढ़ाया और भारत के इतिहास को प्रभावित किया ऐसी ही एक कम्पनी थी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी को अपना सर्वप्रथम अधिकार पत्र (चार्टर) दिसम्बर सन् १६०० ई० में मिला था।

प्रश्न

1. Briefly describe the Manorial System of England. What were the main causes of its decline ?

2. Trace the origin of the Craft Guild System. Give a brief account of its working and administration. Why did the system break down ?

3. Discuss the merits and demerits of the Domestic system as compared to the factory system.

4. Discuss critically the essential features of the Manorial System and circumstances which led to its breakdown towards the middle of the fifteenth century.

दूसरा अध्याय अद्योगिक क्रान्ति के प्रारम्भ काल में आर्थिक दशाएँ

[कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य-व्यापार, प्रश्न ।]

अठारहवीं शताब्दी के मध्य तक, जिसके उपरान्त ब्रिटेन में भौतिक अभ्युदय के युग का प्रभात निकला और कृषि, व्यापार तथा व्यवसाय सभी दिशाओं में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए, ग्रेट ब्रिटेन मुख्यतया कृषिप्रधान देश था। उस समय नगरों की संख्या बहुत कम थी। प्राचुरिक नगरों की तुलना में उस समय के नगर बहुत छोटे थे।¹ लगभग अस्सी प्रतिशत जनसंख्या देहात में गाँवों में रहती थी। कृषि ही जीविका का प्रमुख साधन था। उद्योगों का शीघ्र काल था। उस समय तक वस्त्र, लोहा-इस्पात, इत्यादि निर्माण व्यवसायों (manufacturing industries) का या तो समारम्भ ही नहीं हुआ था या वे छोटे पैमाने पर देहाती क्षेत्रों में ही पाये जाने थे। उद्योगों का काम कृषि-श्रमिकों द्वारा कृषि कार्य के साथ साथ कुटीरों में किया जाता था। कृषि में दुर्भिक्ष की दशाएँ असामान्य नहीं थी और किसानों को आशिक बेरोजगारों का सामना करना पड़ता था। कृषि पिछड़ी दशा में थी और उद्योगों में नये यन्त्रों का प्रयोग प्रारम्भ नहीं हुआ था। व्यापार का विकास प्रगति पर था।

ग्रेट ब्रिटेन की अठारहवीं शती के मध्य की आर्थिक दशाओं का वर्णन नीम रीपों की के अन्तर्गत सुविधापूर्वक किया जा सकता है :—(१) कृषि, (२) व्यवसाय, (३) व्यापार एवं वाणिज्य।

कृषि

गाँवों के समीप की भूमि पहले सबकी सम्मिलित समझी जानी थी। यह विद्यने अध्याय में उल्लेख किया गया था कि १६वीं शती में भूमि का समा-

1. Southgate, op cit., ch. xiv, Industrial Revolution, p. 116.

बरण आन्दोलन आरम्भ हुआ था, परन्तु उसका उद्देश्य भेड़ें चराने के लिए भूमि घेरना था। इस आन्दोलन का एक गम्भीर अभाव यह पड़ा कि ग्राम्य समाज का समस्त दृष्टिकोण ही बदल गया था। खेती का उद्देश्य पहले जीवन-निर्वाह समझा जाता था परन्तु १६वीं शती की कृषि क्रान्ति के उपरान्त कृषि लाभ के लिये की जाने लगी। १८वीं शताब्दी में कृषि के क्षेत्र में जो क्रांति हुई उसमें व्यापक परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन सन् १७५० के पूर्व तक स्पष्ट नहीं हुए थे (कृषि क्रान्ति का वर्णन अन्यत्र किया गया है)।

१६ वीं शताब्दी में समावरण आन्दोलन (enclosure movement) जिस गति पर आरम्भ हुआ था उसकी गति सन् १६०० और १७५० के बीच मन्द रही। सन् १७१० से १७६० तक ३,३४,६७४ एकड़ भूमि घेरी गई जब कि सन् १७६० से १८४५ तक ७० लाख एकड़ के लगभग जमीन घेरी गई।

सत्रहवीं शताब्दी का और १८वीं शताब्दी का पूर्वार्द्धकाल अर्थात् डेढ़ सौ वर्ष का समय कृषि में स्थिरता का काल माना जाता है। पुराने ढङ्ग की खेती अब भी ब्रिटेन के जिलों में प्रचलित थी जिसमें खुले खेतों (open fields) और तीन-खेतों की प्रणाली (three-field system) मुख्यतया देखने में आते थे। त्रि-क्षेत्रीय प्रणाली में खेत के एक-तिहाई भाग को क्रम से खाली (fallow) छोड़ा जाता था। चरागाह भूमियाँ सबकी सम्मिलित समझी जाती थी। इस भूमि पर हरेक किसान अपने पशु चरा सकता था और उसमें से अपने लिए ईंधन (fuel) भी ले सकता था। फसलों की उपज (प्रति एकड़) बहुत कम थी। खादों का तथा शलजम जैसी फसलों का प्रचलन नहीं था। चारे की कोई फसलें नहीं उगाई जाती थी। खेत छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे हुए थे जिनके कारण धन और समय का अपभ्यस्य होता था और प्रायः झगड़े हो जाया करते थे। भेड़ों का पालन भी अधिक नहीं होता था और भेड़ें प्रायः कमजोर तथा गिरी हुई नस्लों की थी। खेती के औजार और ढङ्ग पुराने थे। सकड़ी के हल थे और अनाज ढोने के लिए पहिए वाली छोटी छोटी गाड़ियाँ थी। रियाजों का जोर था और परिवर्तनों के विषय में लोग सन्देह-पूर्ण थे। इस काल में कीमन स्तर भी प्रायः नीचा था जिसके कारण कृषि और पशु-पालन में कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकी।

कृषि में प्रगति की गति मन्द तो थी परन्तु एवदम रकी नहीं थी। चरागाह बनाने और कृषि सुधार दोनों दृष्टियों से कृषि भूमि का समावरण

(enclosure) जानू रहा। प्रारम्भ में समावरण आन्दोलन का इस आधार पर विरोध किया गया था कि भेड़-बकरियों के लिए भूमि घरे जाने से दरिद्रता और दुमिस्त की दशाएँ फैलती हैं, और जनसंख्या घटती है, बेकारी फैलती है, इत्यादि। ये तर्क अब अधिक प्रबल नहीं रहे थे क्योंकि खुले खेतों से होने वाली हानियों और बर्बादियों की तुलना में घिरे हुए खेतों में सुधार और अधिक उत्पादन को महत्व दिया जाने लगा था। रोजगार के नये क्षेत्र खुल गये थे और समावरण की प्रगति के परिणामस्वरूप अनाज का उत्पादन बढ़ा था जिससे से निर्यात भी होने लगा था। अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ब्रिटेन लगभग पाँच लाख क्वार्टर अनाज प्रतिवर्ष रूस, हार्लैण्ड, इत्यादि देशों को निर्यात करता था।

१७वीं शताब्दी में धीरान और बंजर पड़ी हुई भूमि को कृषि-योग्य (reclamation) किया गया। दलदली जमीनों में चरागाह बनाये गये और खेती प्रारम्भ हुई। १७वीं शती में नये आविष्कारों तथा नयी विधियों द्वारा 'वैज्ञानिक' खेती तो प्रारम्भ नहीं हो पाई थी परन्तु इस काल में कृषि की उन्नति के प्रयत्न प्रारम्भ हो गये थे। खुले खेतों की प्रणाली में कृषि सुधार सम्भव नहीं था परन्तु पट्टेधारी किसानों के घिरे हुए बड़े बड़े खेतों में कुछ प्रयोग किये गये। पशुओं की नस्ल सुधार की दिशा में भी ध्यान दिया गया। खादों तथा सलजम जैसी जहददार फसलों की खेती के प्रयोग प्रारम्भ किये, यद्यपि उनका विस्तृत प्रयोग १८वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध काल में हो पाया।

किसानों की दशा बुरी नहीं थी क्योंकि वे खाली समय में बटाई, बुनाई इत्यादि अन्य धन्धों का सहारा भी लेते थे। उनके पास भूमि भी दोम-तीस एकर के लगभग होती थी, जिस पर प्राचीन ढङ्गों में कृषि करके भी तत्कालीन मानदण्डों के अनुसार उसे एक परिवार के लिए पर्याप्त समझा जाता था।

ब्रिटेन की जनसंख्या निरन्तर बढ़ती जा रही थी, अतः इस बात की आवश्यकता पर सामंजस्य रूप में विचार किया गया कि कृषि-बन्ना में सुधार किया जाये। कृषि में वैज्ञानिक रीतियों का प्रयोग तभी सम्भव था जब खेत बड़े बड़े हों और उनमें पूँजी का विनियोग किया जाये। उस समय खेत प्रायः छोटे छोटे थे अतः बड़े बड़े चक्क बनाने के लिए चक्कवन्दी और समावरण की दिशा में कानून भी बनाये गये। किसानों में भी उत्साह था। कुछ उत्साही

व्यक्तियों ने प्रेस और प्लेटफार्म द्वारा “नयी कृषि” का विकास करने के लिए पर्याप्त प्रचार किया। जेयोटत, ब्लिथ, लॉड टाउन्सेण्ड, आर्थर यङ्ग तथा रॉबर्ट बेकवेल इत्यादि व्यक्तियों के परिश्रम और प्रयत्नों द्वारा कृषि में जो उन्नति हुई उससे आगे चल कर १८ वीं शताब्दी के उत्तरार्द्धकाल में ब्रिटेन की कृषि में क्रान्ति आ गई।

व्यवसाय

महान् काल व्यवसाय की धरेनू प्रणाली का था जिसमें कृषि के साथ साथ ही अन्य उद्योग-धन्धे भी चल रहे थे। ये उद्योग किसान अपने कुटीरों में खाली समय में करते थे और ये सहायक धन्धे के रूप में चल रहे थे। औद्योगिक नगरों का विकास नहीं हुआ था। शक्ति (power) का विकास नहीं हुआ था, जहाँ आवश्यक था दाकियानूसी ईंधन का उपयोग किया जाता था और प्राधुनिक यन्त्रों का कार्य अधिकतर हाथों से सम्पन्न होता था। मजदूरों को कच्चा माल और आवश्यक औजार प्रायः साहसी ही देते थे।

अठारहवीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटेन का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण व्यवसाय ऊनी व्यवसाय था। ऊनी माल का निर्यात बढ़ रहा था। सन् १७०१ में लगभग २० लाख पौण्ड मूल्य के ऊनी माल का निर्यात हुआ था और सत्तर वर्ष बाद दूने मूल्य के निर्यात हुए। यह निर्यात मुख्य कुल निर्यातों का एक चौथाई से अधिक था। ऊन की माँग बढ़ रही थी। भूमि का उपयोग भेड़ें पालने के लिए भी किया जा रहा था और भेड़ों की नस्लें सुधारने की ओर भी ध्यान दिया जाने लगा था। इस समय अच्छा ऊनी कपड़ा बनाने के लिए ब्रिटेन में स्पेन की ऊन काम में लाई जाती थी। सन् १७१०-६० में ऊनी व्यवसाय के प्रमुख क्षेत्र तीन थे—(१) नाविच (Norwich) के पूर्वी जिले (counties), (२) पश्चिमी इंग्लैण्ड में ड्रेडफोर्ड और समीपवर्ती क्षेत्र और (३) यार्कशायर का वेस्ट राइडिंग। ऊनी कपड़े का निर्यात इस समय भी काफी मात्रा में होता था परन्तु सन् १७६० के उपरान्त अधिक बढ़ा। इंग्लैण्ड और वेल्स का शायद कोई भी ऐसा जिला (काउन्टी) नहीं था जिसमें समय के कुछ भाग में किसान और कृषि श्रमिक ऊनी कपड़े का उत्पादन कार्य न करते हों।^१ सरकार की निगाह में ऊनी वस्त्र उद्योग इतना महत्त्वपूर्ण था कि उसके विकास के लिए कई कदम उठाये गये। उदाहरणार्थ, दन्धे ऊन के

1. Ashton, T. S. : The Industrial Revolution, ch. II the Earlier Forms of Industry, p. 29.

निर्यात और कुशल कारीगरों के प्रवास पर रोक थी; ऐसे ऊनी वस्त्र का आयात भी नहीं होने दिया जाता था जो ब्रिटिश ऊनी वस्त्रों में ब्रिटेन के बाजार में स्पर्धा ले। लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता था कि वे स्वदेशी वस्त्रों को ही पहिनें, बल्कि उन्हें इसके लिए विवश किया जाता था, यहां तक कि मुद्रों को भी उन के सिवाय किसी अन्य प्रकार के कपड़े में गाड़ने की आज्ञा नहीं दी जाती थी।^१ ऊनी वस्त्र का उत्पादन कई हाथों द्वारा होता था और उसमें तकनीकी प्रगति काफी हो चुकी थी, परन्तु आधुनिक यन्त्रों का प्रयोग उस समय तक नहीं हुआ था।

लोहा व्यवसाय ऊनी व्यवसाय के बाद आता था। उस समय लोहा पिघलाने और शुद्ध करने के लिए खान के कोयले का उपयोग ईंधन की तरह भी नहीं होता था, उसके बजाय लकड़ी के कोयले (charcoal) का उपयोग किया जाता था। लोहे का उत्पादन बच्चे लोहे के क्षेत्रों की समीपता के ऊपर नहीं, बल्कि वृक्षों की निकटता के ऊपर अधिक निर्भर था, क्योंकि कच्चा लोहा ढोने के बजाय लकड़ी या लकड़ी का कोयला दूर तक ढोना अधिक महंगा था। १६ वीं और १७ वीं शताब्दियों में इंग्लैण्ड के दक्षिणी भागों ससेक्स और केन्ट में लोह उद्योग विकसित हो चुका था परन्तु जहाज निर्माण और लोहा बनाने में इस क्षेत्र के जगल समाप्त प्राय होने पर इस प्रदेश में लोह-उद्योग मिरा और सन् १७०० के आस-पास ऐसे भागों में विकसित होने लगा जहाँ वृक्षों की बहुतायत थी। अठारहवीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटेन में भट्टियों की संख्या अधिक नहीं थी और लोहे का वार्षिक उत्पादन औसतन १७,३५० टन के लगभग था। उस समय ब्रिटेन लोहे का निर्यात नहीं करता था, आयात करता था। विकास सन् १७६० के बाद निरन्तर होता गया। सन् १७९० के पूर्व लोह व्यवसाय ब्रिटेन में वेल्स और इंग्लैण्ड के दक्षिणी भागों तक सीमित था परन्तु तदनन्तर स्वाटलैण्ड में भी विकसित हुआ।

लोहा गलाकर भाफ करने के लिए लकड़ी के कोयले का मिलना धीरे धीरे कठिन होता गया, खान के कोयले का उपयोग आरम्भ होने लगा। खान के कोयले का उपयोग सर्वप्रथम क्रिस्टन में अन्नाहम डरबी ने किया और सन् १७०६ में उसने कोक (coke) से पिघलाया हुआ अच्युटी क्रिस्म का टना लोहा (पिंग आयरन) बनाया। बेंजामिन हंट्समैन (Huntsman) ने लोह-

व्यवसाय में श्रान्ति लाने का कार्य सन् १७४० के लगभग एक दूसरी ही तराह में प्रारम्भ किया। उसने शेफील्ड में लोहे के साथ कोयला मिला कर धातु को साफ करने की तथा इस्पात बनाने की नई पद्धति निकाली। इस्पात बनाने के लिए अच्छी कोटि का लोहा स्वीडन से आयात किया जाता था और समीपता के कारण इस्पात बनाने का काम टाइन नदी पर न्यूकेसिल के आस-पास केन्द्रित हुआ। उत्पादन की लागत अधिक थी और इस्पात का उपयोग कटलरी, उस्तरे, तलवारें, बन्दूकें, घटियों के पुर्जे इत्यादि बनाने में सीमित था। लोहा बनाने में खान के कोयले का उपयोग बढ़ने पर लोहे की वस्तुएँ बनाने के उद्योग, जैसे, भोजार, ताले, बोरे, सांकल इत्यादि कोयला-क्षेत्रों के निकट विकसित हुए। टेम और स्टावर नदियों की घाटियों में दक्षिणी स्टेकडंशायर तथा उत्तर पूर्वी बसेंस्टरशायर लोहे की वस्तुएँ बनाने का सबसे बड़ा क्षेत्र था। बर्मिंघम हथियारों और धातु के हल्के बर्तनों के लिए क्वालिटी प्राप्त कर रहा था। शेफील्ड, दक्षिणी यार्कशायर और डर्बीशायर के समीपवर्ती क्षेत्रों में भी लोहे की वस्तुओं के निर्माण-कार्य में प्रगति हुई। लोहे की नई नई वस्तुएँ भी बनीं और कारीगरों की संख्या में भी वृद्धि हुई परन्तु उत्पादन की मात्रा कच्चे माल की उपलब्धता की मात्रा तक सीमित थी और अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध काल के पहले उत्पादन की रीतियों में विशेष विकास नहीं हुए।

खानों से कोयला निकालने का काम (Coal mining) बहुत कुछ कृषि से सम्बन्धित था और उस पर ग्राम्य स्वभाव की छाप थी। कोयले की खदानों का स्वामित्व और नियन्त्रण भू-स्वामियों के हाथों में था। खान खोदने वाले उन दिनों तो खानों पर काम करते थे, जब सेती का काम नहीं होता और फसल पकने पर खुदाई का काम छोड़कर चले जाते थे। खुदाई, खानों के भीतर से कोयला हटाने तथा ढुलाई की पद्धतियाँ पुरानी थी जिनमें मनुष्य श्रम सबसे अधिक होता था। खानों के गड्ढों में पानी भरने की समस्या विकट थी। सन् १६९८ में टॉमस सेबरी ने खानों का पानी निकालने के लिए एक पम्पिंग एजिन बनाया जिसमें वाष्प का प्रयोग होता था परन्तु इसमें क्षति बहुत बरबाद होती थी। सन् १७०८ में टॉमस न्यूकमैन (Thomas Newcomen) ने इस दिशा में एक नए एजिन का आविष्कार किया जिसमें बाद में उसने तथा अन्य व्यक्तियों ने और भी सुधार किये। यह एजिन खानों के अन्दर के पानी को बाहर निकालने के लिए ही था। कोयले का वार्षिक उत्पादन सन् १७००

मे लगभग २५ लाख टन था और सन् १७५० मे ४७½ लाख टन (बाद मे सन् १८०० मे उत्पादन लगभग १ करोड टन और आगे भी वृद्धि होती गई जिसका विवरण अन्यत्र दिया गया है)। यद्यपि सन् १७००-१७५० में भी कई प्रकार के उत्पादन कार्यों मे ईंधन के रूप मे कोयले का उपयोग आवश्यक रूप से होने लगा था परन्तु वस्तुतः १८वीं शताब्दी के बजाय १९ वीं शताब्दी को ही "कोयले का युग" कहा जा सकता है।

ऊनी व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य बरत्र व्यवसाय संशय कास मे थे। उनके लिए कच्चा माल न्यूनाधिक मात्रा मे आयात करना पड़ता था। कच्चा रेशम चीन, इटली, स्पेन और टर्की से; फर्निक आयरलैण्ड, वाल्टिक प्रदेश और उत्तरी अमेरिका से; तथा कपास लीबेंट और पश्चिमी द्वीप-समूह इत्यादि मे आयात किये जाते थे। उत्पादन कार्य ऊनी वस्त्र व्यवसाय के समान ही चलता था। सिल्क व्यवसाय का विकास कस्बो मे होने की प्रवृत्ति देखी गई, जैसे स्पिटलफील्ड्स, कान्ट्री, नॉर्विच और मेक्नेसफील्ड मे। लिनन और सूती वस्त्र उद्योग विस्तृत रूप मे विकसित हुए परन्तु लंकाशायर जिले मे और स्कॉटलैण्ड के निम्न प्रदेश मे स्थानीयकरण की प्रवृत्ति पाई गई। लंकाशायर जिले मे मानचेस्टर इत्यादि सूनी नगरो का विकास होने लगा था। होजरी व्यवसाय का विकास हो रहा था। प्रारम्भ मे मोजो की बुनाई कुटीरो मे हाथो द्वारा होती थी और विशेषतः स्कॉटलैण्ड और वेल्स मे मोजे बुनने का काम अधिक होता था। विलियम ली ने मोजा बुनने के एक फ्रेम (stocking-frame) का आविष्कार किया जिसके बाद यह उद्योग बहुत बढ़ा। डर्बी, नॉटिंघम और लीमिस्टर जिलो मे जहाँ मजदूर सस्ते मिलते थे यह काम फैला।

यद्यपि सूती वस्त्र व्यवसाय का विकास आरम्भिक अवस्था में ही था परन्तु १८ वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध मे इस उद्योग मे नए नए प्रयोग और विकासोन्मुख परिवर्तन हो रहे थे। सन् १७१७ मे टॉमस लोम्बे ने एक नए प्रकार की सिल्क फैक्टरी स्थापित की जिसका भाई इटली के मशीनो की डिजाईन लेकर आया था। सन् १७३३ मे लंकाशायर के एक घड़ा-साज जॉन ले (John Lay) ने करधे मे सुधार किया। सन् १७३८ मे बर्मिंघम के एक डाक्टर के पुत्र ल्यूइस पोल (Lewis Paul) ने कताई मे सुधार का नया विचार प्रस्तुत किया।

ऊपर जिन उद्योग धन्यो की सन् १७००-१७५० की स्थिति का उल्लेख किया है उनके अतिरिक्त अन्य धन्ये, जैसे मकान-निर्माण, जहाज-निर्माण, मछली पकड़ना, चमड़ा, कागज, छपाई इत्यादि भी थे, परन्तु उत्पादन प्रणाली और व्यावसायिक संगठन इत्यादि की दृष्टि से उनको स्थिति भी मिलती उलती थी।

वाणिज्य-व्यापार

उद्योगों का विकास न होने या विकास की गति धीमी होने के कारण केवल यही नहीं थे कि थम विभाजन और आधुनिक प्रकार के यन्त्रों का प्रयोग नहीं हुआ था, बल्कि यातायात, वाणिज्य और साख की संगठित प्रणाली का भी अभाव था। सन् १७६० के पूर्व आवागमन के साधनों की गिरी हुई अवस्था थी। जल मार्गों का उपयोग भी स्थल मार्गों की कमी के कारण किया गया था। नौकानयन कुछ नदियों में प्रारम्भ हुआ और सन् १७५५ में लिवरपूल के समीप एक १० मील लम्बी नौकानयन के लिए नहर खोदी गई जो प्रथम महत्वपूर्ण नहर थी। एक दूसरी ७ मील लम्बी नहर सन् १७६० में बर्सेल से मानचेस्टर तक बनाई गई। अधिक नहरों (Navigable Canals) का निर्माण सन् १७६० के उपरान्त ही हुआ।

समुद्री, और नदियों के जनमार्गों द्वारा सद्वर्तीय और अन्तःप्रदेशीय व्यापार का भी विकास हुआ। अठारहवीं शताब्दी के पूर्व देश का आन्तरिक व्यापार भी अविकसित था। कस्बा में छोटी छोटी मण्डियाँ होती थी परन्तु अधिक देशी व्यापार मेलों में होता था जो समय-समय पर यत्र तत्र होते रहते थे। कुछ घूमने वाले व्यापारी (travelling merchants) होते थे जो इन मेलों में और औद्योगिक केन्द्रों में सम्बन्ध स्थापित करते थे।

अधिकोपण (बैंकिंग) का अभी तक अधिक विकास नहीं हुआ था। बैंक ऑफ इंग्लैण्ड की स्थापना मर्यापि सन् १६९४ में हुई थी और सन् १७५१ से इसे राष्ट्रीय ऋण का पूर्ण प्रबन्ध सौंप दिया गया था परन्तु सन् १७५० के पूर्व तक अधिकोपण व्यवसाय प्रमुख रूप से लन्दन में सीमित था और सन् १७५६ के पूर्व तक २० पाउंड से कम मूल्य का कोई नोट नहीं निकाला गया था। अन्य बैंकों की संख्या सन् १७५० में लन्दन के बाहर एक दर्जन से अधिक नहीं थी जिसमें छः से अधिक साझेदार नहीं हो सकते थे। सन् १७७५ के पहले समाशोधन गृह (clearing house) की स्थापना नहीं हुई थी।

विदेशी व्यापार धीरे धीरे बढ़ रहा था। उस समय खाद्य सामग्री में ब्रिटेन आत्मनिर्भर था और सतुलन की दृष्टि से अनाज का निर्यातक था। ब्रिटेन विदेशों से इमारती लकड़ी, लोहा, सन इत्यादि जहाजों और मकानों के निर्माण के लिए, रेशम, रुई और रंग के पदार्थ वस्त्र व्यवसायों के लिए आयात करने के अतिरिक्त चीनी, चाय, शराब, तम्बाकू कहुवा इत्यादि भी मंगाता था। ब्रिटेन विविध प्रकार का बना हुआ माल निर्यात करता

था परन्तु निर्यातो में ऊली माल तथा लोहे और चमड़े की वस्तुएँ मुख्य थी। विदेशों से व्यापार करने के लिए कम्पनियाँ बन गई थी और यद्यपि अधिकांश व्यापार योरुप महाद्वीप के साथ ही होता था तथापि भारतवर्ष, पश्चिमी द्वीपसमूह, उत्तरी अमेरिका तथा अफ्रीका के दूरवर्ती देशों के साथ भी थोड़ी मात्रा में व्यापार हो रहा था। ब्रिटेन की गणना व्यापारिक देशों में की जाने लगी थी।

सन् १७५० तक ब्रिटेन में लोगों का जीवन-स्तर अन्य योरुपीय देशों की तुलना में तथा १८वीं शताब्दी के मध्य के अनुसार तो अच्छा था परन्तु आधुनिक युग की दृष्टि से बहुत गिरा हुआ था। “वास्तव में यह काल शीघ्र-गामी आर्थिक प्रगति का समय था” परन्तु औद्योगिक उन्नति की दशाएँ परिपक्व नहीं हो पाई थी।

प्रश्न

1. Give an account of the economic organisation of England before the advent of the industrial revolution.
2. Briefly describe the agricultural conditions in Britain in 1750.

तीसरा अध्याय औद्योगिक क्रान्ति

[क्या 'क्रान्ति' शब्द उपयुक्त है ? औद्योगिक क्रान्ति का काल, क्रान्ति पहले ही क्यों नहीं हुई ? औद्योगिक क्रान्ति के कारण—सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में ही क्रान्ति क्यों हुई ? औद्योगिक क्रान्ति की विशेषताएँ, कारखाना प्रणाली के धीमे विकास के कारण, औद्योगिक क्रान्ति के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव, अन्तीसवीं शताब्दी में ग्रेट ब्रिटेन की महत्ता के कारण, प्रश्न ।]

१८ वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध काल में और १९ वीं शताब्दी में ग्रेट ब्रिटेन में उद्योग, कृषि, यातायात और वाणिज्य चारों क्षेत्रों में महान् परिवर्तन हुए । इन परिवर्तनों की आर्थिक इतिहास के छात्र चार क्रान्तियों (औद्योगिक, कृषि, यातायात और वाणिज्य क्रान्तियों) के नाम से पुकारते हैं ।

क्या "क्रान्ति" शब्द उपयुक्त है ?

जिन औद्योगिक परिवर्तनों को हम 'औद्योगिक क्रान्ति' कहते हैं उसके विषय में कभी कभी यह आपत्ति उठाई गई है कि उन्हें 'क्रान्ति' कहना कहाँ तक उपयुक्त है ? यह सत्य है कि जिस काल में ये परिवर्तन हो रहे थे उस समय के अधिकांश ब्रिटिश नागरिकों का उन पर ध्यान भी नहीं गया । वस्तुतः उद्योग कृषि और वाणिज्य, इत्यादि क्षेत्रों में परिवर्तन पहले भी होते रहे थे । यदि दूसरी तरह से विचार किया जाये तो उद्योग की घरेलू प्रणाली का कारखाना प्रणाली (factory system) के रूप में पूर्णतया परिवर्तन हुआ ही नहीं । इसके प्रतिरिक्त कभी कभी यह समझा जाता है कि 'क्रान्ति' शब्द का प्रयोग हिंसात्मक आकस्मिक परिवर्तनों के लिए ही किया जाना चाहिए । फ्रांस में सन् १७८९ में और रूस में सन् १९१७ में क्रान्तियाँ हुईं । यद्यपि क्रैच और रूसी क्रान्तियों के उद्देश्य और ब्रिटिश औद्योगिक क्रान्ति के उद्देश्य लगभग समान ही थे—नव आर्थिक और सामाजिक जीवन का निर्माण—परन्तु फ्रांस और रूस में हुई क्रान्तियाँ हिंसापूर्ण रक्त से सनी हुईं और एक निश्चित

समय की थी। आग्ल औद्योगिक क्रांति धीरे धीरे होने वाली और शान्तिपूर्ण थी।

“औद्योगिक क्रांति” शब्द (term) को प्रयोग लाने का कार्य सर्वप्रथम ब्लान्की (Blanqui) द्वारा सन् १८३७ में हुआ, तत्पश्चात् जेवन्स, एन्जिल्स और कार्ल मार्क्स ने भी इस शब्द का प्रयोग किया परन्तु मामान्यतया यह समझा जाता है कि आरनोल्ड तोयनबी ने ही सन् १८८४ में इस शब्द का प्रयोग किया। जो कुछ भी हो, १८ वीं और १९ वीं शताब्दी में होने वाले ब्रिटेन के औद्योगिक परिवर्तनों के लिए ‘क्रान्ति’ शब्द का प्रयोग उचित और उपयुक्त है। उचित इसलिए है कि इससे लोग ब्रिटेन के नवकालीन महान् परिवर्तनों को समझने को महत्व दें। वे परिवर्तन इतने व्यापक और प्रभावपूर्ण थे कि एक ओर देश के भौतिक अम्युदय के रूप में और दूसरी ओर समाज के कतिपय वर्गों के पीड़न के रूप में उनके परिणाम स्पष्ट थे। उन्होंने निर्माण (manufacture) की विधियाँ को ही नहीं बदला बल्कि जीवन के ढंग, सामाजिक संगठन और दृष्टिकोण को ही बदल दिया। इसीलिए ‘क्रान्ति’ शब्द उपयुक्त है कि औद्योगिक संगठन और पद्धति में गम्भीर परिवर्तन हुए। वस्तुतः राजनीति में भी ‘क्रान्ति’ शब्द का प्रयोग हिंसा और आकस्मिकता की घटना के लिए किया जाना आवश्यक नहीं है। अहिंसापूर्ण राजनीतिक क्रांतियों के उदाहरण भी मिलते हैं। क्रांति चाहे औद्योगिक हो अथवा सामाजिक, राजनीतिक या और कोई, उसका अभिप्राय उस विशेष क्षेत्र में आधारभूत परिवर्तन लाना है। नोल्ले ने लिखा है कि ‘औद्योगिक क्रांति’ शब्द का उपयोग इसलिए नहीं किया जाता है कि परिवर्तन शीघ्र हुआ बल्कि इसलिए किया जाता है कि परिवर्तन हुआ तो वह मूलभूत था।

औद्योगिक क्रांति का काल

औद्योगिक क्रांति का निश्चित समय या अवधि बताना बहुत कठिन है। ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक परिवर्तन क्रांतिकारी अवधि में परन्तु वे शनैः शनैः हुए और उनके पूर्ण होने में एक शताब्दी के लगभग, बल्कि उसमें भी अधिक समय लगा। इस विस्तृत समय के सम्बन्ध में भी आर्थिक इतिहास के लेखक-गण एकमत नहीं हैं। सामान्यतया औद्योगिक क्रांति के आरम्भ का समय १८ वीं शताब्दी के मध्य के आसपास और पूर्ण होने का समय उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त की ओर माना जाता है। साउथगेट ने अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध (१७१०-१८१०) की अवधि को औद्योगिक

क्रान्ति का काल माना है^१। प्रो० टी० एस० एश्टन ने औद्योगिक क्रान्ति का काल सन् १७६० से १८३० तक का माना है।^२ नोल्स ने औद्योगिक क्रान्ति के दो चरण माने हैं। ब्रिटिश आर्थिक विकास का प्रथम काल सन् १७७० से १८४० तक और द्वितीय काल सन् १८४० से १९१४ तक माना गया है।^३ नोल्स ने लिखा है कि प्रथम चरण में विकास यातायात के अपर्याप्त विकास के कारण सीमित था; द्वितीय चरण में रेल मार्गों और वाष्प जलयानों के कारण मशीनरी और उत्पादन में विशाल रूप से विस्तार हुआ और श्रम-प्रान्दोलन तथा व्यापारिक संगठन में समानान्तर विकास हुए।

क्रान्ति पहले ही क्यों नहीं हुई ?

ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक क्रान्ति अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध के पूर्व ही क्यों नहीं हुई, इसके अनेक कारण थे। १८वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में भी प्रयास और कुशलता का अभाव नहीं था परन्तु उनके फलने फूलने में समय लगा। कुछ प्रारम्भिक आविष्कार अपूर्ण विचार के कारण असफल रहे तथा अन्य की असफलता के कारणों में उपयुक्त सामग्री का अभाव, श्रमिकों की दक्षता अथवा मशीनों को अपना लेने की कमी तथा परिवर्तनों के सामाजिक विरोध को सम्मिलित किया जा सकता है। पर्याप्त मात्रा में और उचित व्याज दर पर पूँजी मुलभ न होने के कारण औद्योगिक विकास रुका रहा। विकास के लिए एक विचार की आवश्यकता थी जो इने-मिने मस्तिष्कों में नहीं बल्कि अधिक लोगों के मनो में छा जाता, इसकी कमी थी। कठिनाइयाँ एकागी नहीं थी—कृषि का विध्वंसन, खानों का अपर्याप्त विकास, अच्छे

1. During the second half of the eighteenth century and the first half of the nineteenth British industry underwent great changes—changes so remarkable in character and so extensive that the term Industrial Revolution has been applied to them.”

—George W. Southgate
—English Economic History, ch. xiv, p. 115.

2. “About 1760 a wave of gadgets over England..... It was not only gadgets, however, but innovations of various kinds.....that surged up with a suddenness for which it is difficult to find a parallel at any other time or place.”

Prof. T. S. Ashton : *The Industrial Revolution, (1760-1830)*, chap. III, p. 58

3 Knowles, L.C.A : *Industrial and Commercial Revolutions, Part II*, p. 25.

कोयले की अपर्याप्त पूर्ति, कच्चे माल की कमी तथा यातायात, व्यापार और अधिकोपण में एकाधिकारियों के प्रभाव के कारण प्रगति की कमी आदि अनेक रुकावटें थी। इन्हीं कारणों से सन् १७६० के पूर्व उद्योग के ढाँचे, उत्पादन की तकनीकी अथवा लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में 'क्रान्ति' न आ सकी।

औद्योगिक क्रान्ति के कारण

सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में ही क्रान्ति क्यों हुई ?

ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक क्रान्ति के कारणों पर विचार करने के सम्बन्ध में यह बात उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण है कि औद्योगिक क्रान्ति सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में हुई। ग्रेट ब्रिटेन में क्रान्ति का सूत्रपात १८वीं शताब्दी के मध्य में हुआ जब कि फ्रान्स में और संयुक्त राज्य अमेरिका में १९वीं शताब्दी के मध्य के लगभग, जर्मनी में १८७० के बाद और रूस में तथा अन्य अनेक देशों में बीसवीं शताब्दी में हो सका। सन् १७६० के पूर्व ब्रिटेन में एक करोड़ से कम जनसंख्या थी जब कि उसी समय फ्रान्स में ढाई करोड़ से भी अधिक थी।^१ इस प्रकार फ्रान्स में बड़े पैमाने के उत्पादन की अधिक गुंजाइश सम्झी जा सकती है। फ्रान्स में पूँजी की भी कमी नहीं थी और अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध के आरम्भ में फ्रान्स के निर्यात और आयात ब्रिटेन के विदेशी व्यापार की तुलना में अधिक थे। उसका औपनिवेशिक और पुनर्निर्यात व्यापार भी विधाल था। तब क्या कारण थे कि औद्योगिक क्रान्ति फ्रान्स से भी पहले ग्रेट ब्रिटेन में हुई। इसके प्रमुख कारणों को तीन भागों में इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है :—

(क) राजनीतिक और सामाजिक कारण

१. सुरक्षा और शान्ति तथा प्रशासनिक स्थायित्व
२. वैयक्तिक स्वातंत्र्य-स्वतन्त्र-जनसंख्या
३. औपनिवेशिक साम्राज्य
४. कम जनसंख्या
५. साहसी स्वभाव
६. अनुकूल सरकारी नीति और सहायता

१. उस समय ब्रिटेन की जनसंख्या ६० लाख और फ्रान्स की २६० लाख के लगभग थी।

(स) आर्थिक कारण—

७. पूँजी सग्रह और व्याजदर में गिरावट
८. बड़े और विस्तृत बाजार
९. बड़े पैमाने के उत्पादन का अनुभव
१०. कुशल श्रमिकों की पर्याप्त पूर्ति
११. माल का स्वभाव और उपयुक्त व्यवसायों का चुनाव
१२. कर-प्रणाली
१३. जल मार्गों का विकास, जहाजी यातायात, आन्तरिक और बाह्य यातायात

(ग) भौगोलिक कारण—

१४. प्राकृतिक स्थिति—द्वीपीय, मध्यवर्ती
१५. उत्तम समुद्र तट और बन्दरगाह
१६. उत्तम जलवायु
१७. प्राकृतिक साधन और शक्ति

कारणों पर विस्तार में विचार करने के पूर्व यह कहना उचित होगा कि ग्रेट ब्रिटेन को अन्य देशों की अपेक्षा कुछ ऐसे राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक लाभ प्राप्त थे कि औद्योगिक विकास में वह अग्रगण्य राष्ट्र बन गया। विकास के मार्ग में एक रोड़ा जिस प्रकार अन्य कठिनाइयाँ भी पैदा कर देता है उसी प्रकार प्रगति का मार्ग खुलने पर उन्नति का व्यापक क्षेत्र भी मिल जाता है। ब्रिटेन के आर्थिक विकास में ठीक यही स्थिति थी।

औद्योगिक क्रान्ति सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में ही हुई इसका मुख्य कारण राजनीतिक थे। सन् १६८८ के पश्चात् ब्रिटेन का संविधान जिन सिद्धान्तों पर स्थापित किया गया था, योद्धा के अन्य देशों में उन्हें १९वीं शताब्दी तक स्वीकार नहीं किया गया। वालपोल (Walpole) की बुद्धिमत्तापूर्ण नीति के कारण देश को राजनीतिक क्षाति के अतिरिक्त वित्तीय स्थायित्व भी प्राप्त हुआ।^१ ग्रेट ब्रिटेन को १८वीं शताब्दी के अनेक युद्धों में भाग लेना तो पड़ा था परन्तु ब्रिटेन मालूमगुणों से बचा रहा था, वे युद्ध योद्धा के अन्य देशों छथवा समुद्रों में या अमेरिका इत्यादि में हुए थे। अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में फ्रान्स में हुई राजनीतिक क्रान्ति (१७८९) ने फ्रान्स के व्यावसायिक जीवन को

ऐसा तहस-नहस कर दिया कि उसे उसके पुनरुद्धार में चार दशान्दियाँ लगी । सन् १८७१ के पूर्व जर्मनी कई राज्यों में बँटा हुआ था और उसमें इतनी विभिन्न प्रथाएँ थीं कि वह उद्योग और व्यापार का विकास ही नहीं कर सका । संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस इत्यादि अन्य देश भी अपनी राजनीतिक विषम परिस्थितियों में फँसे हुए थे ।

ब्रिटेन के निवासी १६वीं शताब्दी से ही व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य का आनन्द भोग रहे थे जिसके अभाव में अन्य अनेक देश औद्योगिक विकास नहीं कर सके । जिस दासता का अन्त ब्रिटेन में सोलहवीं शताब्दी में हो चुका था, अधिकांश योरोपीय राज्यों में अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक दासता के बन्धन शिथिल नहीं हुए थे । श्रमिक मूमि से वैधानिक रूप से बँबे हो तो खानों और कारखानों में श्रम की पूर्ति होना सम्भव नहीं था ।

ब्रिटेन की उपनिवेशों और समुद्र-पार मण्डियों का साथ भी औद्योगिक क्रान्ति का महत्त्वपूर्ण कारण था । इतिहास के छात्रों को विदित होगा कि १७वीं और १८वीं शताब्दियों में ब्रिटेन, फ्रान्स, स्पेन, पुर्तगाल और हालैण्ड भारतवर्ष और सुदूर पूर्व तथा अन्य समुद्र पार देशों में मण्डियों पर अधिकार प्राप्त करने के प्रयत्न में संघर्ष करते रहे थे । ब्रिटेन विजयी हुआ और अपने उपनिवेशों तथा साम्राज्यगत देशों की मण्डियों पर उसने एकदम अधिकार पा लिया । इनमें ब्रिटेन अपना बना हुआ माल बेच सकता था (ब्रिटेन के राजनीतिक प्रभुत्व के कारण अन्य देशों को उनमें यह लाभ नहीं मिलने दिया गया) और वहाँ से कच्चा माल प्राप्त कर सकता था ।

पाठक भूले न होंगे, यह ऊपर कहा जा चुका है कि अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ब्रिटेन की जनसंख्या फ्रान्स की जनसंख्या की एक-तिहाई के लगभग थी । जनसंख्या की कमी औद्योगिक क्रान्ति में इस तरह सहायक सिद्ध हुई कि ब्रिटेन को अपने बढ़ते हुए विदेशी व्यापार के लिए मशीनरी का प्रयोग निरन्तर आवश्यक हो गया क्योंकि बड़ी हुई माँग को हाथ के काम से पूरा करना सम्भव नहीं था । फ्रान्स की जनसंख्या ब्रिटेन की तिगुनी के लगभग थी जबकि उसका विदेशी व्यापार सवा गुने से अधिक नहीं था । परिणामतः फ्रान्स उद्योग की धरेलू प्रणाली से शीघ्र ऊँचा नहीं उठ पाया ।

ग्रेट ब्रिटेन के लोगों का साहसी स्वभाव (enterprising nature) भी इस दिशा में सहायक सिद्ध हुआ अन्यथा वे समुद्र पार हजारों मील दूर वित्कुल भिन्न प्रकार के देशों में उत्पादन और व्यापार कार्य करने का विचार भी नहीं

करते। उनमें लगनशीलता थी, वे परिश्रमी और ईमानदार थे और उनमें यह दृढ़ विचार था कि वे अपने देश की समृद्धि में अवश्यमेव वृद्धि करेंगे।

ब्रिटेन की सरकारी नीति, जिसका विस्तृत वर्णन अन्यत्र किया जाएगा, सभी दिशाओं में इस प्रकार की थी कि देश के औद्योगिक और व्यापारिक विकास में प्रोत्साहन मिले।

आर्थिक कारण—उपयुक्त राजनीतिक और सामाजिक कारणों के प्रतिरिक्त आर्थिक कारण भी कम प्रभावशाली नहीं थे। आर्थिक कारणों में प्रमुख पूँजी की पर्याप्त पूर्ति थी। पूँजी के अभाव में औद्योगीकरण के मार्ग में भारत की तथा अन्य अनेक राष्ट्रों को जो कठिनाइयाँ रही हैं ब्रिटेन को नहीं थी। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रान्ति अनेक नये आविष्कारों के कारण हुई जिनके बिना वहाँ उद्योग के विकास की गति निश्चय ही धीमी रहती और ये आविष्कार बिना पूँजी साधनों के सम्भव नहीं थे और पूँजी की कमी की समस्या में बड़े पैमाने पर उनका प्रयोग भी सम्भव नहीं था। बचतों को नये प्रकार के जोखिम वाले व्यवसायों में लगाने की तत्परता के कारण ही यह सम्भव हुआ कि ब्रिटेन अपने परिश्रम का फल खल सका।

ब्रिटेन में पूँजी संचय के सम्बन्ध में बहुधा विरोधी मत दिये जाते हैं। वस्तुतः ग्रेट ब्रिटेन में पूँजी का विकास अनेक कारणों से हुआ था। वहाँ के नागरिकों ने कृषि के लाभों को उद्योग में विनियोग करना प्रारम्भ किया था और कृषि में पूँजीवादी पद्धति प्रारम्भ की गई थी। उपनिवेशों में आगल निवासियों ने कृषि करके लाभ कमाये थे। समुद्रपार देशों और उपनिवेशों के साथ व्यापार करके भी वे पहले से ही लाभ कमा रहे थे। कुछ लेखकों का यह कहना है कि प्राथमिक उद्योगों से पूँजी निर्मायक (manufacturing) उद्योगों की ओर बह रही थी परन्तु यह भी सत्य है कि यदि पूँजीपति उद्योगों में हुए लाभों को उद्योगों के विकास के लिये ही फिर न लगाते (जिसे "ploughing back" या "green manuring" industry कहा जाता है) तो उसके अभाव में विकास की प्रगति दृढ़ नहीं हो सकती थी। बैंकों का विकास भी इस दिशा में अनुकूल सिद्ध हुआ।

देश-विदेश में बाजारों के विस्तार के साथ साथ ध्वस्त-दर में गिरावट हो जाने से विनियोग के लिए प्रोत्साहन मिला।^१ यह पहले ही बताया जा चुका

है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रान्ति के पूर्व ही विदेशी व्यापार काफी बढ़ चुका था। उपनिवेशों और साम्राज्यगत देशों में ब्रिटेन को मंडियों की सुविधा पहले से ही प्राप्त थी। वस्तुतः अपने बढ़ते हुए व्यापार के कारण ही ब्रिटेन औद्योगिक क्रान्ति की ओर अग्रसर हुआ।

बड़े पैमाने पर कारोबार चलाने का अनुभव ब्रिटेन को पहले से ही था। ऊनी उद्योगों में वह बहुत प्रगति कर चुका था। अतएव अन्य वस्त्र उद्योगों के लिए पर्याप्त मात्रा में कुशल श्रमिक भी मिल गये और १६वीं शताब्दी के अन्त में ही मनोरियाल प्रणाली के पतन के उपरान्त गाँवों के बेरोजगार लोग शहरों में आकर बस गये थे और अकुशल (unskilled) श्रमिक सस्ती मजदूरियों पर सुलभ थे। घरेलू प्रणाली के उद्योगों में लगे मजदूर भी नगरों में आने लगे थे।

ब्रिटेन के व्यवसायियों ने अपने अनुभव से यह बात जान ली थी कि वस्त्र तथा अन्य वस्तुएँ सीधी-सादी भले ही हों परन्तु सस्ती होनी चाहिएँ। १८वीं शताब्दी में ब्रिटेन के नागरिकों की माली-हालत सामान्यतया ऐसी थी कि हाथ की बनी महँगी वस्तुओं की अपेक्षा सस्ती वस्तुओं की उन्हें आवश्यकता थी और यह खुला सत्य है कि हरेक व्यक्ति ऐसी वस्तुएँ जिनके ऊपर उसे धन का अधिक भाग व्यय करना पड़ता है सस्ती मिलने पर जीवन की अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के द्वारा लाभान्वित होता है—जिसे ऊँचा जीवन-स्तर कहते हैं। इसीलिए ब्रिटेन के उद्योगपतियों ने ऐसे व्यवसाय ही विकास करने के लिए चुने जिनमें बड़े पैमाने की बचतें मिलती हैं और जिनकी वस्तुएँ जनसाधारण की आवश्यकताएँ होती हैं। यह स्मरणीय है कि ब्रिटेन में जिस काल में औद्योगिक क्रान्ति हुई लगभग उसके साथ साथ कृषि में भी क्रान्ति हो रही थी, जिसके कारण कृषकों की स्थिति सुधरी और किमानों की आवश्यकताओं में वृद्धि हुई थी, जिसके लिए उद्योगों का विकास किया जा सकता था।

ब्रिटेन की कर-प्रणाली भी ऐसी थी कि उससे व्यापार और उत्पादन में बाधा नहीं, प्रोत्साहन मिला। ब्रिटेन में घरेलू व्यापार आन्तरिक करों से मुक्त था, जबकि फ्रान्स और जर्मनी में अनेक प्रकार के स्थानीय कर लगे हुए थे।

इसके अनतिरिक्त यह उल्लेखनीय है कि यदि ब्रिटेन में यातायात के क्षेत्र में विकास न हुए होते तो औद्योगिक विकास भी असम्भव था। ब्रिटेन में देशीय बाजारों का विकास नदियों, नहरों और स्थल यातायात में विकास

के कारण हुआ और अन्य देशों की अपेक्षा उसने समुद्री जहाजी यातायात में काफी प्रगति कर ली थी जिसके कारण विदेशी मण्डियों में उसकी पहुँच सरल हो गई थी। उसकी जहाजी नीति भी औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण रही। दासता का अन्त हो चुका था इसलिए गमनागमन पर रुकावटें भी नहीं रही थी।

भौगोलिक कारण— ब्रिटेन की औद्योगिक उन्नति में प्राकृतिक सुविधाओं का हाथ भी अधिक रहा है। ग्रेट ब्रिटेन की स्थिति द्वीपीय और मध्यवर्ती है तथा उसकी सीमा प्राकृतिक है। समुद्री यातायात का विकास उसकी द्वीपीय स्थिति और कटे-फटे समुद्रतट के कारण ही हुआ जिससे व्यापार तथा उद्योग के विकास का द्वार खुल गया। एक ओर उसे समुद्री शक्ति बढ़ाने में सुविधा हुई, दूसरी ओर सुरक्षा की। दोनों ही औद्योगिक समृद्धि में सहायक हुए।

ऊँचे अक्षांशों में समुद्र में स्थिति और गरम जलधारा (गल्फ स्ट्रीम) के संयोग के कारण ब्रिटेन की जलवायु भी उत्तम है जिसके कारण श्रमिकों की कार्यक्षमता, वस्त्र व्यवसाय, मछली उद्योग और कृषि पर अनुकूल प्रभाव पड़े हैं। ब्रिटेन का समुद्र और नदियों के जलमार्ग जमते नहीं हैं, मछलियाँ सड़ती नहीं हैं, घागा दूटता नहीं है और सजदूर परिश्रम से घबराने नहीं हैं।

इनके अतिरिक्त ग्रेट ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे प्रचुर प्राकृतिक साधन प्राप्त थे। यह आज सर्वविदित है कि लौह-उद्योग के विकास के बिना अन्य उद्योगों का विकास असम्भव नहीं तो बहुत कठिन अवश्य है। लौह-उद्योग के विकास के लिए उसके साधन पर्याप्त थे। लौह पिघलाने की शक्ति के लिए ब्रिटेन में पर्याप्त कोयला था, उसकी कोयले की और लोहे की खानें पास पास थी तथा वेल्स, नार्थम्बरलैंड और स्कॉटलैंड में समुद्रतट के समीप थी जिसके कारण यातायात में सुगमता थी। वहाँ मशीनें और वाष्प-एंजिन (Steam engines) बनाने के लिए पर्याप्त लोहा था और लोहा गलाने के लिए कोयले की कमी नहीं थी। और जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, इस सबके लिए साहस और पूँजी की भी कमी नहीं थी। तब क्या था, नये नये प्रयोग (experiments) हुए, आविष्कार किये गये।

१. संसार में सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुए आविष्कार तथा फ्रेंच क्रान्ति से सम्बन्धित फ्रांस का आर्थिक स्वतन्त्रता का विचार, ये दो महान् शक्तियाँ थी जिन्होंने १८वीं और १९वीं शताब्दी में ग्रेटब्रिटेन के आर्थिक विकास पर अत्यधिक प्रभाव डाला।

मशीनें बनी तो एक के बाद एक उद्योग विकसित होते गये ।

निस्सन्देह ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के किसी एक या दो कारणों को महत्व नहीं दिया जा सकता, सभी कारणों के सम्मिलित प्रभाव से ही वहाँ 'क्रांति' हुई जिसने ग्रेट ब्रिटेन को औद्योगिक राष्ट्रों का प्रमुखा और एक महान् राष्ट्र बना दिया ।

औद्योगिक क्रांति की विशेषताएं

औद्योगिक क्रांति के अन्तर्गत वे सब महान् परिवर्तन सम्मिलित किये जाते हैं जो इस आन्दोलन के कारण औद्योगिक संगठन प्रणाली और रीतियों में हुए । औद्योगिक क्रांति की विशेषताओं को उसके "परिणामों" से भिन्न समझने में कठिन ई आवश्यक होती है क्योंकि एक-दूसरे की परस्पर प्रतिक्रिया होने के कारण कारणों और परिणामों में अन्तर बतलाना कठिन होता है ।^१

जनसंख्या में वृद्धि, विज्ञान का उद्योग में प्रयोग, गहराई और विस्तृत रूप में पूँजी का उपयोग, ग्राम्य जनसंख्या का नगरी समुदायों में परिवर्तन तथा नये सामाजिक वर्गों का विकास, मुख्य रूप से ये परिवर्तन हैं जो प्रायः औद्योगिक क्रांतियों में सर्वत्र देखे गए हैं । परन्तु एशटन का कथन है कि भिन्न भिन्न स्थानों तथा समय सम्बन्धी परिस्थितियों के अनुसार आन्दोलन की गतिविधि प्रभावित हुई है ।^२ ग्रेट ब्रिटेन में कीमतों के उख, नीति सम्बन्धी परिवर्तनों और परिवहन (transport) में होने वाले सुधारों का भी इस प्रसङ्ग में ध्यान रखा जाना चाहिए । ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति मुख्यतया कोयले, लोहे और परिवहन की शक्ति से जुड़ी हुई थी । ज्योंही ब्रिटेन में बाष्प शक्ति का उद्योग में प्रारम्भ किया गया, विकास का द्वार खुलता गया ।^३

वाष्प (steam) के लिए कोयले की आवश्यकता हुई और कोयले का महत्व बहुत बढ़ गया । यही नहीं कोयला-क्षेत्रों के समीप जनसंख्या का घनत्व बहुत बढ़ गया । वाष्प शक्ति का प्रयोग लोहे की मशीनों में ही किया जा सकता था अतः इंजीनियरिंग और लौह उद्योगों का विकास हुआ । रसायनिक

1. "The Industrial Revolution is to be thought of as a movement, not as a period of time its character and effects are fundamentally the same."

—Prof. T. S. Ashton, op. cit., chap. VI, p. 142.

2. "But in each case the course of the movement has been affected by circumstances of time and place." —Ibid, p. 142.

3 Knowles : Industrial and Commercial Revolutions p.17

उद्योगों की स्थापना भी लगभग साथ-साथ ही हुई जिससे कोयले का महत्व और भी बढ़ गया। परिवहन की रीतियों में सुधार हुए बिना कोयला, लोहा तथा लोहे की भारी वस्तुओं को ढोना सम्भव नहीं था अतः यातायात के नये साधनों का विकास हुआ। वस्तुतः प्रारम्भिक विकास होने पर कोयला, लोहा, वाष्प, रसायनिक पदार्थ, मशीनरी और यातायात के सुधरे हुए साधन, सबका एक दूसरे की उन्नति पर प्रभाव पड़ा।

तोल्स के शब्दों में "तथाकथित 'औद्योगिक क्रांति' में छः महान् परिवर्तनों अथवा विकासों का समावेश हुआ जो एक दूसरे पर निर्भर थे।" ये परिवर्तन निम्नलिखित थे:—

१. इंजीनियरिंग का विकास—वाष्प एंजिन बनाने और उनकी प्रयोग करने के लिए, वस्त्र उद्योगों की मशीनें बनाने के लिए, खानों से कोयला निकालने की मशीनों तथा भोजारों और लोकोमोटिव इत्यादि के बनाने के लिए इंजीनियरों की आवश्यकता हुई और इंजीनियरिंग उद्योगों का विकास हुआ।

२. लोहा-इस्पात व्यवसाय का विकास—इंजीनियरिंग के लिए पर्याप्त मात्रा में अच्छी किस्म का लौह बनाने (iron making and smelting) की आवश्यकता थी। अतः लोहा बनाने में हुई क्रान्ति दूसरा विकास था जो लगभग मशीनें बनाने के पहले हुआ। यह स्मरणीय है कि लोहे के कारखानों का विकास शायद असम्भव था यदि पहले से होने या रड़े युद्धों के कारण लोहे की अधिक मांग न हुई होती और साथ ही वाष्प शक्ति और वाष्प-इंजन का विकास न हुआ होता।

३. वस्त्र व्यवसायों का विकास—तीसरा परिवर्तन या विकास तब हुआ जब वस्त्र उद्योगों में यन्त्रों की शुरुआत हुई। पहले कताई की मशीनें बनीं और जब सूत की अधिकता होने लगी तो उस सूत का उपयोग करने के लिए शनैः शनैः बुनने का यन्त्र प्रचलन में आया। पहले सूती वस्त्र उद्योग में मशीनों का प्रयोग हुआ और फिर ऊन, फ्लैक्स और सिल्क उद्योगों में।

1. "The so-called 'Industrial Revolution' comprised six great changes or developments all of which were interdependent."

—Knowles, L. C. A. - Industrial Commercial

Revolutions, Part II Industrial Revolution caused by Machinery, p. 20.

४. रसायनिक व्यवसायों का विकास—वस्त्र उद्योगों के विकास से चौथे प्रकार के विकास की आवश्यकता हुई। वस्त्र उद्योगों की प्रगति के समानान्तर धुलाई (bleaching), रङ्गाई (dyeing), फिनिश करने (finishing) और छपाई (printing) में उन्नति आवश्यक थी। इस प्रकार रसायनिक उद्योगों की रचना हुई। पहले से ही स्थापित और विकसित हो रहे इंजीनियरिंग उद्योगों से रसायनिक उद्योगों के विकास में सहायता मिली।

५. कोयले की खानों के काम का विकास (Coal Mining)—कोयले की खानों के काम का विकास औद्योगिक क्रान्ति में ममाविष्ट पाषाण मुख्य परिवर्तन था। कच्चा लोहा गलाने के लिए भट्टियों में कोक के रूप में कोयले की आवश्यकता थी, पिग आयरन से इस्पात बनाने के लिए और वाष्प उत्पन्न करने के लिए भी कोयले की आवश्यकता थी। अतः कोयले की खानों का विकास हुआ। यह भी सत्य है कि यदि खानों से पानी निकालने के लिए स्टीम पम्पिंग इंजन का आविष्कार न हुआ होता तो खान-उद्योग का इतना विकास सम्भव नहीं हो पाता। इन सबके लिए पूँजी की भी आवश्यकता थी। वस्तुतः सन् १६६४ में बैंक ऑफ इंग्लैण्ड की स्थापना के बाद विकास कार्य प्रारम्भ होने लगा था।

६. पास्तापात के साधनों में विकास—कारखानों में बड़े पैमाने पर मशीनरी का उत्पादन, स्टास्ट भट्टियों में लोहे का उत्पादन, इंजीनियरिंग उद्योगों और रसायनिक कारखानों की स्थापना और कोयले की खानों का कार्य सम्भव ही नहीं होता यदि परिवहन की रीतियों में भी साथ साथ सुधार न होता जिसके कारण कोयले और लोहे की खानों पर श्रमिकों के लिए भोजन पहुँचाने, कच्ची धातुएँ, ईंधन, कच्चे माल और अन्य सामग्री को ढोने की सुगमता हो गई तथा बने हुए माल के वितरण के ढंग में भी उन्नति हुई।

वस्तुतः, जैसा कि मोन्स ने लिखा है, दो अवधियों में परिवहन के साधनों की अवस्थाओं के अनुसार औद्योगिक क्रान्ति के दो युग थे।^१ औद्योगिक क्रान्ति के प्रथम युग या चरण में सड़कों और आंतरिक जलमार्गों का विकास हुआ। और वह मुख्यतः कोयला और लोहे की खानों, इंजीनियरिंग उद्योगों तथा कपड़े के कारखानों के प्रारम्भिक विकास से सम्बन्धित है। द्वितीय चरण में वाष्प से चलने वाले जलयानों और रेलों के चानू होने के साथ-साथ मशीनरी और

१. इसका संकेत पहले ही इस अध्याय में "औद्योगिक क्रान्ति का काल" शीर्षक के अन्तर्गत दिया जा चुका है।

उत्पादन में बहुत विस्तार हुआ। यातायात के विकास का व्यापारिक संगठन के स्वरूपों तथा श्रम आन्दोलन पर क्रमिक प्रभाव पड़ा जैसा कि निम्न तालिका से विदित होगा^१ :—

अवधि (Periods)	प्रभावित उद्योग (Trades affected)	व्यापारिक संगठन का स्वरूप	श्रम आन्दोलन (Unions)
(१) पक्की सड़कों और नाव्य नहरों का काल (१७७०-१८४०)	सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग और धातु संबंधी उद्योग, खनिज उद्योग, रसायनिक उद्योग,	एकाधिकारी व्यापारी या पारिवारिक फर्म। साम्भेदारी	स्थानीय सघ। मैत्री समितियाँ। श्रम संघ आन्दोलन में क्रांतिपूर्ण प्रारम्भ।
(२) रेलमार्गों तथा बाष्प जलयानों का काल (१८४०-१९१४)	अन्य उद्योगों में मशीनरी का विस्तृत प्रयोग। नये उद्योगों का विकास— पोत-निर्माण, रेलवेज, एसिड और बेसिक स्टील, बिजली के सामान।	संयुक्त पूँजी वाली कम्पनियाँ तथा संयुक्त पूँजी वाली बैंकें। एकीकरण और सम्मेलन का विकास: (क) राष्ट्रीय (ख) अंतराष्ट्रीय। मिलन (combinations) बैंकों में सम्मेलन।	एक-एक उद्योग में राष्ट्रीय श्रम सघ। विभिन्न उद्योगों के राष्ट्रीय फेडरेशन। अन्तराष्ट्रीय क्रिया।

इस प्रकार यातायात के विकास के प्रथम काल में औद्योगिक क्रांति अपूर्ण और विकास सीमित रहा और यातायात की क्षमता के दूसरे प्रहर में पूर्ण हुआ।

कारखाना प्रणाली के धीमे विकास के कारण (Slow Progress of the Factory System)

यह कहा जा चुका है कि औद्योगिक क्रान्ति के पूर्ण होने में एक शताब्दी से भी अधिक समय लगा। औद्योगिक क्रान्ति की विशेषताओं में सम्मिलित एक विशेषता यह भी थी कि उद्योग में पूँजी का अधिक प्रयोग, मशीनों, श्रम विभाजन तथा बड़े पैमाने का उत्पादन आरम्भ हुआ। संक्षेप में ये कारखाना प्रणाली की विशेषताएँ हैं। औद्योगिक क्रान्ति उद्योग में घरेलू प्रणाली (Domestic System) के स्थान पर कारखाना प्रणाली लाई।

ग्रेट ब्रिटेन में घरेलू प्रणाली के स्थान पर कारखाना प्रणाली की स्थापना इतनी धीरे धीरे हुई जितनी अन्य देशों में बाद में कहीं नहीं हुई। इसका मुख्य कारण यह था कि जहाँ ब्रिटेन ने अपने प्रयोग छोड़े वहाँ अन्य देश आरम्भ कर सके। उन्होंने औद्योगिक विकास का कार्य प्रायः रेल मार्गों के विकास के साथ साथ किया जिससे परिवर्तन शीघ्र सम्भव हो सके।¹ मॉल्स ने लिखा है कि यद्यपि परिणामतः औद्योगिक दशाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए परन्तु वे प्रचानक नहीं हुए।

कारखाना प्रणाली के धीमे विकास के कारण क्या थे? मॉल्स ने इसके चार प्रमुख कारण बताये हैं—

(१) श्रमिकों की घरेलू धर्मों की छोड़ने के प्रति उदासीनता—जैसा कि अन्यत्र बताया जा चुका है घरेलू प्रणाली का विकास मनोरिपल प्रणाली और गिल्ड प्रणाली के पतन के उपरांत हुआ था। इसके अन्तर्गत श्रमिक स्वच्छन्दता की साँस ले सकते थे। उसे पूँजीपात मालिक (employer) के स्थान पर बैठ कर काम नहीं करना पड़ता था बल्कि कृषि के साथ साथ खाली समय में अपने परिवार के सदस्यों का सहायता से अपनी इच्छा के अनुसार कम या अधिक काम कर सकता था। घरेलू प्रणाली के भी दोषों और कारखाना प्रणाली के भी अनेक गुणों की अपेक्षा श्रमिकों में उस समय घरेलू धर्मों के प्रति लगाव था। और जब कारखाना प्रणाली चालू हुई तो एक दम नहीं हो गई—पहले घरेलू औजारों में सुधार देखे गए जैसे कताई के लिए जैनों और बुनाई के लिए प्लाइम शटल, फिर जब कारखाने खुले तो वे छोटे छोटे थे

1. "In no country was the transition so slow as in this country. Other nations were able to begin where Great Britain left off in her experiments....."

—Knowles, L. C. A., op. cit., p. 78.

और उनमें धर्मिकों को ऐसे समूहों में रखा जाता था कि काम की देखभाल हो सके और धर्मिकों के लिए सामान चुराना सम्भव न हो, तब धर्मिकों की कमी की दशाओं में नये सुधरे हुए यन्त्र काम में आये और बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए।

(२) फैक्टरी उत्पादन की दिशा में मास्त्रिकों (employers) की उदासीनता—परेलू प्रणाली के अन्तर्गत थोड़ी सी पूँजी लगाकर भी पूँजीपति को धर्मिकों के ऊपर प्रभुत्व प्राप्त था और लाभ भी कम नहीं थे। दूसरी ओर कारखाना प्रणाली में महुँगी मशीनें खरीदनी पड़ती, काम के लिए फैक्टरी की इमारत ऊँची लागत पर बनवानी पड़ती भयवा भारी किराया देना पड़ता, कोयला, रोशनी, दुलाई इत्यादि की व्यवस्था करनी पड़ती और प्रायः बैंक से व्याज पर पूँजी उधार लेनी पड़ती। इस पर भी भारी जोखिम था—मजदूर काम पर ही न आते, काम बीच में ही छोड़ देते और भगड़े हो जाते। प्रारम्भ में उत्पादन की वह स्थिति तो थी नहीं कि पूँजी का शीघ्र उलटफेर सम्भव होता, अतः साहसी कारखाना प्रणाली की दिशा में उदासीनता धारण किये था। परन्तु साथ ही फैक्टरी प्रणाली के लिए प्रोत्साहन भी मिलते गये, यथा, धर्मिकों के साथ भगड़े होने पर सुधरे हुए यन्त्रों के प्रयोग के लिए। दुलाई के काम में पूँजीपति नई मशीनों का उपयोग करने में अधिक हिचकिचाते भी नहीं थे।

(३) जनसंख्या में वृद्धि—मशीनरी के उपयोग में आने में देरी का एक मुख्य कारण यह था कि १६ वीं शताब्दी में जनसंख्या में वृद्धि हुई जिससे सस्ते धर्मिक अधिक संख्या में सुलभ हो गये और मशीनरी की शुद्धता करने की आवश्यकता तीव्र नहीं रह गई। जनसंख्या में वृद्धि के अनेक कारण थे जिनमें प्रमुख ये हैं : (क) १६वीं और १७वीं शताब्दी में इंग्लैण्ड में फैली हुई अनेक महामारियाँ १८वीं शताब्दी में समाप्त प्रायः हो गई थी; (ख) गिल्ड प्रणाली के अन्तर्गत प्रशिक्षण काल (apprenticeship period) में विवाह पर प्रतिबन्ध था। विभिन्न कार्यों के अनुसार प्रशिक्षण काल २१ वर्ष से २४ वर्ष की आयु में समाप्त होता था जिसमें शिष्या (apprentices) विवाह नहीं कर सकते थे। सन् १७२० के बाद इस प्रथा का पतन होता गया और सन् १८१३ में प्रशिक्षण (apprenticeship) समाप्त कर दिया गया। (ग) बुद्धिमानी की दृष्टि से भी धर्मिकों के लिए विवाह करना और सतर्क होना बुरा नहीं था, क्योंकि प्रारम्भ में परिवार में जितने अधिक सदस्य होते माता-

पिता को उतनी ही अधिक मदद मिलती या सन्तानों को फैक्टरी में काम मिल जाने के कारण मजदूरियों से कुल आय अधिक होनी, (घ) फैक्टरी प्रणाली प्रारम्भ होने के साथ-साथ श्रमिकों को गाँवों की अपेक्षा शहरो और कस्बों में अलग-अलग मकान और छोटे परिवार होने से (privacy) भी अधिक मिली, (ङ) चिकित्सा विज्ञान में उन्नति और खाद्यान्नों की पूर्ति में वृद्धि के साथ साथ बच्चों की ही मृत्यु दरों में कमी नहीं हुई वरन् जीवन के दृष्टिकोण में ही आशा की किरण फूटने लगी थी। अनुमानतः ग्रेट ब्रिटेन का जनसंख्या सन् १७५० में साठ लाख के लगभग थी, सन् १८०१ की जनगणना के अनुसार यह ६० लाख हो गई, सन् १८५१ तक दुगुनी हो गई और सन् १९०१ तक उसकी भी दुगुनी हो गई।

(४) लौह इंजीनियरिंग तथा कोयला की खानों के उद्योगों में विकास की मन्द गति—यों तो युद्ध सामग्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोहे की वस्तुएँ पहले से ही बनाई जा रही थी परन्तु मात्रा की दृष्टि से तथा अनुद्धियों को दूर करने की दृष्टि से लौह उद्योग के विकास में काफी समय लगा। इस उद्योग में लकड़ी के बजाय कोयले का उपयोग अब्राहम डब्लो न ब्रिस्टल में सन् १७०६ में किया परन्तु सन् १७६० तक इसका अधिक प्रचलन नहीं हुआ और व्यावसायिक रूप में लोहे को शुद्ध करने में कोयले का सफल उपयोग सन् १७८३-८४ में कॉर्ट (Cort) के द्वारा ही हो पाया। अधिक मात्रा में लोहे का उत्पादन करने के लिए कोयले की आवश्यकता हुई परन्तु कोयला-खान उद्योग का विकास भी बहुत धीरे-धीरे हुआ। खान उद्योग का मुख्य समस्या गड्ढा में पानी भर जाने की थी और उनमें श्रमिक कृषि से बच हुए समय में हाँसलत थे। यातायात का अपर्याप्त विकास भी बहुत बड़ी काठनाई थी। इन सब कारणों से लौह उद्योग कोयला खान उद्योग के साथ ही धीरे-धीरे हो उठ सका। परिणामस्वरूप इंजीनियरिंग उद्योगों का विकास भी मन्द गति से हुआ। मशीनों का प्रयोग सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग में हुआ, अन्य उद्योगों में बहुत बाद में हुआ। स्टीम इंजन के प्रयोग और विकास में भी काफी समय लगा।

नोल्स ने औद्योगिक परिवर्तनों की धीमी गति के विषय में लिखा है, “मशीनरी के आगमन में मशीनों की कमी और उनका असन्तोषजनक होने से ही बाधा नहीं हुई बल्कि फैक्टरियों में काम करने के प्रति श्रमिकों की अधिक, उन व्यक्तियों द्वारा जो मशीनों से घायल हो जाने से डरते थे विद्रोह तथा

मशीनें तोड़े जाने की संभावना, जनसंख्या में वृद्धि होने से मजदूरों की संख्या में वृद्धि जो फैक्टरी की अपेक्षा घरेलू कार्य अधिक पसन्द करते थे, इन सबका समदिशाई प्रभाव हुआ।^१

सन् १८४० तक ग्रेट ब्रिटेन कृषि प्रधान देश की अपेक्षा एक औद्योगिक देश हो गया था। सन् १८४० वह वर्ष कहा जा सकता है जिसमें कोई व्यक्ति सन् १७५० वर्ष की दशाओं से तुलना करके अन्तर स्पष्ट रूप से समझ सकता था। मालगाड़ी द्वारा माल ढोने की मात्रा, खान खुदाई में गहराई और उत्पादन, भट्टियों के उत्पादन की मात्रा, वाष्प शक्ति का प्रयोग, बड़े पैमाने का उत्पादन, सभी दृष्टियों में सन् १८४० तक विकास की गति स्पष्ट हो गई थी और ग्रेट ब्रिटेन उस दिशा में कदम बढ़ा रहा था जिसमें अम्युदय, समृद्धि और महानता हाथ फैलाये हुए थे। उसकी प्रगति धीमी परन्तु दृढ़ थी।

औद्योगिक क्रान्ति के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव (Economic and Social Effects of the Industrial Revolution)

“औद्योगिक क्रान्ति” शब्द का उपयोग इसलिए नहीं किया जाता कि परिवर्तन की गति-विधि सीधे सी बल्कि इसलिए किया जाता है कि परिवर्तन हुआ तो वह मूलभूत था।^१ इस परिवर्तन के आर्थिक और सामाजिक परिणाम मुल्लया अधोलिखित हैं—

(१) नए उद्योगों का विकास—जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, नए व्यवसायों का जन्म हुआ, जैसे इंजीनियरिंग उद्योग, रसायनिक उद्योग, इत्यादि। बड़े-बड़े व्यवसायों के साथ साथ छोटे छोटे सहायक उद्योगों का भी विकास हुआ।

(२) बाणिज्य में क्रान्तिकारी परिवर्तन—उद्योगों के जन्म और विकास के साथ ही अथवा उसके परिणामस्वरूप बाणिज्य में महान् परिवर्तन हुआ।

1. ‘Not merely was the coming of machinery retarded by the deficiency of machines, their unsatisfactory nature, but the dislike of the hands to work in factories, the possibility of riots and machine-breaking by those who thought they would be injured, and the increase of population which provided a large number of hands always more ready to take up home work than factory work, all worked in the same directions.’
—Knowles, op. cit., p. 77.

2. Knowles, op. cit., p. 79.

ग्रेट ब्रिटेन बड़े पैमाने के उत्पादन और विश्व विनिमय का केन्द्र बन गया। ब्रिटेन कच्चे मालों के लिए समुद्रपार देशों पर निर्भर होने लगा जैसा पहले नहीं था। अब वह, उदाहरणार्थ, कपास और ऊन विदेशों में मँगाने लगा और अपने बने हुए माल की बिक्री के लिए उन देशों पर निर्भर होने लगा। उन्नीसवीं शताब्दी में वह भोजन सामग्रियों के लिए धीरे धीरे विदेशों पर निर्भर होता गया। बदले में उसने कोयला, निर्मित वस्तुओं तथा जहाजों और वित्तीय (Shipping and financial) सेवाओं का निर्यात किया। विनिमय का पैमाना इतना बढ़ा कि पहले स्वप्न में भी जिसकी कल्पना नहीं थी। नई नई और भारी भारी वस्तुएँ व्यापार में आईं और विदेशी व्यापार का एकदम नवीन स्वस्व दिखाई देने लगा। आयात निर्यात व्यापार में वृद्धि के कारण ही विदेशी विनिमय (foreign exchange) का विकास हुआ।

(३) नए जिलों का महत्त्व—सन् १७५० से पूर्व इंग्लैण्ड के दक्षिणी जिले घनी और महत्त्वपूर्ण समझे जाते थे परन्तु अब उत्तरी जिलों में नये व्यवसायों का विकास होने में उनका महत्त्व बढ़ गया। १८वीं शताब्दी के प्रारम्भ में अधिक महत्त्वपूर्ण जिले मिडिलसेक्स, सोमरसेट, डेवन, वैंस्ट राइडिंग, लिंकनशायर, नारफोक और नफोक थे। सन् १८०० तक लकाशायर और वैंस्टराइडिंग और यार्कशायर अधिक घने बन गये और सबसे अधिक घने प्रथम दो जिले समझे जाने लगे। स्काटलैण्ड में लनार्कशायर जिला नये रूप में विकसित हुआ। दक्षिण वेल्स में भी लौह उद्योग के विकास के कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई। इंग्लैण्ड के दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम के पुराने वस्त्र व्यवसाय के जिलों का महत्त्व घट गया।

(४) नगरों का विकास—लोहा और कोयला के क्षेत्रों में, नए औद्योगिक क्षेत्रों में तथा यातायात के केन्द्रों पर नये नगर बस गये परन्तु क्योंकि इन नगरों को बसाने की कोई पूर्व योजना नहीं थी, गन्दी बस्तियों (Slums) का जन्म हुआ। मकान खड़े बने, नालियाँ तथा सफाई की कोई व्यवस्था नहीं हुई। पीने के पानी का भी उचित प्रबन्ध सन् १८५० तक प्रायः किसी नए बसे नगर में नहीं हो पाया। परिणामतः गन्दगी फैली और अनेकों प्रकार की बीमारियाँ फैलने लगीं। इस सबका श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा, नगरों में मृत्यु दर भी बढ़ी।

(५) व्यवसाय की घरेलू प्रणाली का पतन और फँडरी प्रणाली का विकास—औद्योगिक क्रान्ति के पूर्व ब्रिटेन में उद्योग-धन्धे प्रायः कृषि के साथ

साथ किसान अपने घरों में ही चलाते थे (घरेलू प्रणाली का वर्णन पहले ही किया जा चुका है)। औद्योगिक विकास के साथ यह सम्भव नहीं रहा क्योंकि बढ़ते हुए उत्पादन के लिए श्रमिकों के पास यंत्र, कच्चा माल इत्यादि जुटाने के साधन नहीं थे। उद्योग शक्ति की सुसज्जता के स्थानों में केन्द्रित होने लगा। बड़े बड़े कारखानों की छतों के नीचे श्रमिक को काम करना आवश्यक होगया। यहाँ यह स्मरणीय है कि कृषि में भी छोटे किसानों का निर्वाह कठिन हो गया था क्योंकि उसमें भी स्पर्धा और पूँजी का प्रवेश हुआ। कृषि और उद्योग धंधे साथ साथ चलाना संभव न रहा। यन्त्रों का प्रयोग और निर्माण की नई विधियाँ कारीगर कारखानों में आकर सीखने लगे। बहुधा श्रमिक का कार्य नीरस होने लगा।

(६) पूँजीपति और श्रमिकों के सम्बन्धों में परिवर्तन—घरेलू प्रणाली में भी पूँजीपति और मजदूर थे परन्तु कारखाना-प्रणाली में उनमें पहले के स सम्बन्ध न रहे। मालिक और मजदूर (employer and employed) दो वर्ग हो गए। श्रमिक का व्यक्तित्व पहले जैसा न रहा। अब वह यन्त्रों के पहिए का पुर्जा बनकर रह गया—न उसके पास जमीन-जायदाद, न द्रव्य, न घर। काम की दशाएँ नीरसतापूर्ण हो गईं। मजदूरों की संख्या (पूर्ति) अधिक होने से मजदूरियाँ कम दी जाती थी और काम अधिक लिया जाता था। उनके प्रति दुर्भ्यवहार भी होता था। श्रमिक का शोषण और असन्तोष तथा श्रमिक और पूँजीपति का अप्रत्यक्ष सम्बन्ध इन सबके परिणामस्वरूप मजदूरों में वर्ग-चेतना प्रकट हुई और वर्ग संघर्ष का जन्म हुआ। धर्म सघों का विकास हुआ (जिन्हें प्रारम्भ में अर्बुध समझा जाता था)। यातायात के विकास के साथ साथ श्रम-आन्दोलन का क्षेत्र भी बढ़ा।

उपयुक्त मुख्य प्रभावों से ही सम्बन्धित कुछ अन्य प्रभावों पर भी दृष्टिपात किया जा सकता है :

(७) श्रम विभाजन के विकास, पूँजी और यन्त्रों के प्रयोग का कुल प्रभाव यह हुआ कि उत्पादन में वृद्धि हुई, लागत कम हुई, वस्तुएँ सस्ती मिलने के कारण जीवन स्तर ऊँचा हुआ।

(८) पूँजीपतियों के वर्ग के अतिरिक्त समाज में एक नये मध्यम वर्ग का जन्म हुआ। दुकानदार, बैबर, ठेकेदार, इत्यादि इस श्रेणी में सम्मिलित किए जा सकते हैं।

(६) व्यावसायिक संगठन के स्वरूप की दृष्टि में एकाकी व्यापारी या साहसी और सामेदारी के बजाय संयुक्त पूँजी वाली कम्पनियाँ अधिक प्रचलन में आईं और व्यवसायियों के संगठन, एकीकरण और सम्मेलन देखे जाने लगे, यद्यपि उनका अधिक विकास बाद में हुआ।

(१०) उद्योगों के स्थानीयकरण या केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति औद्योगिक क्रांति की विशेषता कही जा सकती है।

(११) प्रारम्भ में तो नहीं परन्तु औद्योगिक क्रांति के द्वितीय चरण में प्रति उत्पादन और औद्योगिक सकटों की घटनाएँ भी हुई जो उत्पादकों तथा श्रमिकों दोनों के लिए अहितकर थी।

औद्योगिक क्रांति के जो परिणाम हुए उनमें से बुरे प्रभावों पर जोर देने की प्रवृत्ति अधिक लेखकों की देखी जाती है। वस्तुतः हमने इनकार नहीं किया जा सकता है कि औद्योगिक विकास का युग माता के प्रभूतिकाल की भाँति दलों और कठिनाइयों से भरा हुआ था परन्तु यह कहना कि वे सब परेशानियाँ जो सन् १७६० के पश्चात् तथा १९वीं शताब्दी में देखी गई औद्योगिक क्रांति के ही कारण थी सत्य को मान्य करना होगा। सच तो यह है कि कठिनाइयाँ सन् १७६० के पहले भी कम नहीं थी परन्तु सन् १७६० के बाद श्रमिकों में और समाज में पहले से ही चली आ रही उन सब कठिनाइयों के प्रति जागरूकता और चेतनता पैदा हुई थी।

हानियाँ—औद्योगिक क्रांति की जिन हानियों की ओर ऊपर संकेत किया जा चुका है उनके अतिरिक्त मुख्य हानियाँ संक्षेप में ये थी : (क) धन के वितरण में असमानताएँ, (ख) कार्य के प्रति श्रमिक की शक्ति, सरसता और स्वच्छन्दता का लोप, (ग) स्त्रियों की पुष्टि की भाव पर निर्भरता, (घ) संक्रांतिकालीन सामाजिक विस्थापन तथा (ङ) दरिद्रता अथवा अकिंचनता में वृद्धि। साथ सामग्री की दृष्टि से ब्रिटेन अन्य देशों पर निर्भर हो गया।

लाभ—औद्योगिक विकास के प्रत्यक्ष लाभों के अतिरिक्त कुछ अप्रत्यक्ष लाभ भी हुए परन्तु वे निर्विवाद नहीं हैं। ऐसे लाभों में सम्मिलित किया जाने वाला पहला लाभ यह था कि बालकों के काम की दशाओं का नियमन प्रारम्भ हुआ और उनकी शिक्षा की ओर ध्यान गया। इसके अतिरिक्त निवास की जगह और काम की जगह पृथक् पृथक् हो जाने से मनुष्य सामाजिक मूल्यों को महत्त्व देने लगा। कारखानों में काम की दशाओं और सफाई इत्यादि पर ध्यान दिया गया; यंत्रों की सहायता और काम की दशाओं में सुधार होने से श्रमिकों की

कार्य क्षमता में वृद्धि हुई और उसकी मजदूरी भी बढ़ी। रोजगार के नए नए साधन खुल गए थे, वस्तुएँ सस्ती मिलने लगी थी। इनके कारण मजदूर सुखी और संपन्न तो होने लगे लगाने साथ ही वह अपनी दशाग्रो के प्रति सचेत भी हुआ।

ग्रेट ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के प्रभाव एकदेशीय नहीं थे। एक के बाद एक विश्व के अनेक राष्ट्र ग्रेट ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में लाभ उठा कर औद्योगीकरण की दिशा में प्रगति करने लगे। समस्त संसार परस्पर संपर्क में आया और एकाग्रता इसका प्रभाव आर्थिक सम्बन्धों में समानता लाने की दिशा में पड़ा। ग्रेट ब्रिटेन स्वयं एक शक्तिशाली महान् राष्ट्र बन गया और उस काल में अपनी ही नहीं यूरोप की भी रक्षा नेपोलियन से कर सका। प्रथम महायुद्ध में भी अपनी महान् शक्ति के कारण विजयधी उत्ती के पक्ष में रही। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक ग्रेट ब्रिटेन महान् शक्तियों में प्रमुखा देश और औद्योगिक दृष्टि से संसार का कारखाना (workshop) बन चुका था।

१९ वीं शताब्दी में ग्रेट ब्रिटेन की महत्ता के कारण
(Causes of the the Supremacy of Great Britain
during the 19th Century).

सन् १७८९ से १९१४ तक के समय में ग्रेट ब्रिटेन ने बहुमुखी महत्त्वा प्राप्त करली थी। संसार की मण्डियों में उसके बने हुए माल की माँग थी; औद्योगिक विकास के लिए विश्व के देश ब्रिटेन के ऊपर निर्भर थे; जहाजी, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के लिए भी वे उसके ऊपर आश्रित हो गए थे; और ग्रेट ब्रिटेन का साम्राज्य इतना बढ़ गया था कि, यह कहा जाने लगा था, उसमें कभी सूर्यास्त नहीं होता था। ग्रेट ब्रिटेन की इस प्रभुता के मुख्य कारण, औद्योगिक कारणों के अतिरिक्त (जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है), निम्नलिखित हैं—

(क) नई औद्योगिक तकनीकी में अग्रणी—ग्रेट ब्रिटेन में नये-नये आविष्कार हुए। यद्यपि इन आविष्कारों की लागत भी उसे अग्रतनी पड़ी और अन्य देशों को उनसे अपने औद्योगिक विकास में बहुत सरलता हुई परन्तु ब्रिटेन को अपने प्रथम आविष्कारों से एक स्थायी लाभ हुआ कि वहाँ दक्ष कारीगरों और कुशल श्रमिकों की एक सेना तैयार हो गई जो तकनीकी में निरन्तर सुधार और प्रगति करते गए तथा लाभ के साथ उसका उपयोग कर सके। उसकी मशीनें सभी

देशों को निर्यात होने लगी और अपने माल की अच्छी किस्म के लिए ब्रिटेन विख्यात हो गया ।

बड़े पैमाने पर मशीन-उद्योगों के विकसित होने के कारण ब्रिटेन में अनेकों सहायक उद्योग-धन्धे फले-फूले और अधिकोपण, वित्त इत्यादि में भी शीघ्र प्रगति हुई । प्रथम प्रारम्भ का वेग और उद्योग-वाणिज्य की विविध शाखाओं में उसका अनुभव प्रगति की दौड़ में उसे आगे रखना गया ।

(ख) कोयले की पर्याप्त पूर्ति तथा कोयला क्षेत्रों की उत्तम भौगोलिक स्थिति—प्रचुर मात्रा में कोयला मिलने का महत्व ब्रिटेन के लिए अत्यधिक था । ब्रिटेन को उसमें सस्ती शक्ति मिलती रही और अन्य उद्योगों के माथ ही उसे लौह उद्योग तथा रसायनिक उद्योगों के विकास में सरलता रही । ब्रिटेन के लिए कोयले का महत्व तब अधिक समझ में आ सकता है जब हम देखते हैं कि १९वीं शताब्दी में फ्रांस की औद्योगिक उन्नति कोयले की कमी और अधिक लागत के कारण रुकी रही । ब्रिटेन में लोहा गसाने के लिए कोयला अच्छी कोटि का उपलब्ध था और उसके 'कोयला-क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि उसे औद्योगिक केन्द्रों तक पहुँचना सरल था । अनेक उद्योग कोयला क्षेत्रों के समीप ही विकसित हो गये थे परन्तु ब्रिटेन में कच्चे लोहे के क्षेत्र भी समीप ही स्थित थे । 'कोयला-क्षेत्र प्रायः नदियों अथवा समुद्र तट अथवा दोनों के ही समीप थे, अतः जल मार्गों द्वारा कोयला ढोना न केवल सरल था बल्कि सस्ता भी था ।'

(ग) जहाजी वातावात का विकास—यों तो ब्रिटेन अनेक देशों से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कर चुका था परन्तु इस्पात के जलयानों के निर्माण में अग्रणी रहने से ब्रिटेन को दोहरा लाभ रहा । उसके जहाज अपना अपना मान बोलने के लिए सभी देश मांगते थे जिससे ब्रिटेन को विदेशी विनिमय (foreign exchange) का लाभ होता था । परन्तु इससे भी अधिक लाभ यह था कि विदेशों से जहाजी सम्बन्धों के कारण ब्रिटेन को अपना विदेशी व्यापार बढ़ाने तथा औद्योगिक विकास करने में बहुत लाभ रहा । ब्रिटिश जहाज जिन किसी देश का माल ढोकर माड़ा प्राप्त करने में ही रुचि नहीं रखते थे बल्कि ब्रिटेन के विदेशी व्यापार में वृद्धि करने के लिए कटिबद्ध थे । ग्रेट ब्रिटेन की जहाजी नीति का लक्ष्य भी यही था । ब्रिटिश जहाज स्वदेश का बना हुआ माल अन्य देशों को ले जाने थे और विदेशों में कच्चा माल ब्रिटेन को लाते थे ।

(घ) विश्व भर में उसके वित्तीय संबन्ध—फ्राम ही एक ऐसा देश था जिसका विदेशी व्यापार ग्रैंट ब्रिटेन के मुकाबले का था, अन्यथा १९वीं शताब्दी

मे ब्रिटेन का विदेशी व्यापार सब देशों से बढ़ा चढ़ा था । विदेशी व्यापार के सम्बन्धों के कारण विश्व भर मे ब्रिटेन के वित्तीय सम्बन्ध हो गए । ब्रिटेन के स्वीकृत बिल वाणिज्य मे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बन गए । 'लन्दन अधिग्रहण (banking) का केन्द्र बन गया और बैंकों की शाखाएँ अधिकांश देशों मे स्थापित हो गईं । इसके कारण सभी देशों से सौदों के भुगतान ब्रिटेन के लिए बहुत सरल हो गये और इस दृष्टिकोण से विदेशी व्यापार के मार्ग मे कोई रुकावट नहीं हुई ।)

(४) विदेशों मे ब्रिटिश पूँजी के विनियोग (investments)—
 ग्रेट ब्रिटेन मे पूँजी के संचय और विकास के कारणों पर भग्यत्र प्रकाश डाला जा चुका है । ' ब्रिटेन मे साहसियों की भी कमी नहीं थी । व्यापारिक सम्बन्ध जुड़ जाने से ब्रिटेन की पूँजी समुद्र पार दूर दूर देशों की ओर प्रवाहित हुई । विदेशों में ब्रिटिश पूँजी से कम्पनियाँ स्थापित हुईं जो उन देशों मे खानो, बागानों (plantations) मे ही नहीं रेल मार्गों, डॉक, बिजली के कारखानों, तारघरों, टेलीफोन इत्यादि अनेक प्रकार के कार्यों में पूँजी लगाकर विकास-कार्य करने लगी । एक दृष्टि से इससे ब्रिटिश पूँजीपतियों को लाभान्श और व्याज के रूप मे लाभ हुए परन्तु इससे भी अधिक ब्रिटेन के हितों को यों लाभ हुआ कि उसे विदेशी विनियम का लाभ होता था, उन देशों का कच्चा माल ब्रिटेन मे पहुँचाना और विदेशी मण्डियों मे ब्रिटेन का बना हुआ माल बेचना बहुत आसान हो गया था, एक प्रकार से उसे एकाधिकार ही मिल गया था । विदेशों मे स्थापित ब्रिटिश कम्पनियाँ केवल मशीनों के लिए ही नहीं, अन्य प्रकार के माल के लिए ब्रिटेन को ही आर्डर देती थी और अपने देश के ही इंजीनियर, डाइरेक्टर इत्यादि नियुक्त करती थी ।'

इस तथ्य का विस्मरण नहीं किया जा सकता कि १९वीं शताब्दी मे ब्रिटेन के बने हुए माल की किम्मे अपनी उत्तमता के लिए कोई समानी नहीं रखती थी परन्तु पूर्वं प्रारम्भ का लाभ, प्रचुर मात्रा मे कोयले की पूर्ति, जहाजी यातायात का विकास, विश्व भर मे उसके वित्तीय सम्बन्ध तथा विदेशों मे बढ़ी हुई मात्रा मे ब्रिटिश पूँजी के विनियोग, इन सब कारणों का सम्मिलित प्रभाव यह हुआ कि विगत शताब्दी मे ग्रेट ब्रिटेन की महानता का मुकाबला करने वाला और कोई देश नहीं था । उसकी क्षान को कोई छू तक नहीं गया था ।

प्रश्न

1. What do you understand by the term 'Industrial Revolution'? Why did the industrial revolution occur first in England?
 2. "The so-called 'Industrial Revolution' comprised six great changes or developments all of which were interdependent." Explain.
 3. What were the causes of the slow growth of the factory system in England?
 4. Discuss the economic and social effects of the Industrial Revolution in the nineteenth century in England.
 5. "The term 'Industrial Revolution' is used not because the change was quick but because when accomplished the change was fundamental." Elucidate this statement.
 6. What were the causes of the supremacy of Great Britain during the 19th century?
 7. Discuss the principal features of the Industrial Revolution in England.
-

अध्याय ४

प्रमुख उद्योगों का विकास

[आविष्कार और तकनीकी विकास, सूती वस्त्र उद्योग, कोयला खान उद्योग, लोहा-हस्तात उद्योग, प्रसन ।]

औद्योगिक क्रान्ति के पूर्व ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक दशाओ तथा प्रणालियों का संक्षिप्त परिचय दूसरे अध्याय में दिया जा चुका है। पिछले अध्याय में यह बताया जा चुका है कि सन् १७६० के पश्चात् ग्रेट ब्रिटेन में उद्योग में क्रान्ति-पूर्ण परिवर्तन हुए। पहले से ही स्थित उद्योगों की प्रगति, नए, नए और सहायक उद्योगों का विकास, उत्पादन की नई प्रणाली, संगठन के नए स्वरूप, उत्पादन की मात्रा में अतिशय वृद्धि, इत्यादि सभी दृष्टियों से ब्रिटेन में औद्योगिक विकास हुआ। विकास का मुख्य कारण (अथवा विशेषता) नये-नये आविष्कारों का प्रयोग तथा तकनीकी परिवर्तन था। इस अध्याय में नये आविष्कारों और तकनीकी परिवर्तनों का संक्षिप्त परिचय देकर ग्रेट ब्रिटेन में प्रमुख उद्योगों के एक ऐतिहासिक विकास एवं उनकी वर्तमान स्थिति का वर्णन किया गया है।

आविष्कार और तकनीकी विकास

आविष्कारों और तकनीकस परिवर्तनों का बोध सरकारीन पेटेण्टों (Patents) के पंजीयन से हो सकता है। सन् १७६० के पूर्व शायद ही कोई वर्ष था जिसमें स्वीकृत पेटेण्टों की संख्या एक दर्जन में अधिक हुई हो। सन् १७६६ में यह संख्या एकदम इकत्तीस (३१) हो गई और सन् १७९६ में ३६। तदनन्तर कुछ वर्षों में औसत संख्या इसमें कम रही। सन् १७८३ में पेटेण्टों की संख्या ६४ थी, बीच बीच में उच्चावचन हुए, परन्तु प्रवृत्ति वृद्धि की ओर ही रही। सन् १७९२ में यह संख्या ८१, सन् १८०२ में १०७, सन् १८२४ में १८० और उसमें अगले वर्ष २१० हो गई। कहा जाता है कि युद्धकाल में प्रायः नये आविष्कार होते हैं परन्तु ब्रिटेन में उपर्युक्त आविष्कार

शांतिकालीन थे।^१ टैक्नीकल प्रगति और नवीन विधियों का प्रारम्भ यद्यपि कृषि, लौह उद्योग, खानो, इंजीनियरिंग, रसायनिक उद्योग, यातायात तथा अन्य उद्योगों में बहुत कुछ साथ-साथ चल रहे थे परन्तु वस्त्र उद्योगों में परिवर्तन सबसे अधिक द्रुत गति से हुए।

वस्त्र व्यवसाय—वस्त्र उद्योग में सन् १७६० के पूर्व ही नई विधियों का आविष्कार और प्रयोग आरम्भ हो गया था। सन् १७६३ में लकाशायर के एक घड़ी साज ऑन के (John Kay)^२ ने करघे में एक साधारण महत्त्वपूर्ण सुधार किया और उसे फ्लाई शटिल (fly-shuttle) कहा गया। फ्लाई-शटिल द्वारा करघे पर बैठा हुआ अकेला बुनकर अब उतना कार्य कर सकता था जितना पहले दो करते थे। इसके प्रयोग में आरम्भ में कई कठिनाइयाँ आईं परन्तु सन् १७६० तक यह सामान्य चलन में आ गया। कताई के क्षेत्र में भी अनेक सुधार करने के प्रयत्न किये गये क्योंकि बुनाई के क्षेत्र में सुधारों के कारण सूत (yarn) की माँग बढ़ गई थी। इस दिशा में पहली व्यवहारिक सफलता ब्लेकबर्न के निवासी बुनकर वड्डे जेम्स हरग्रीव्स (Hargreaves) को मिली। उसने सन् १७६४ से सन् १७६८ के मध्यकाल में हाथ में चलने वाली कताई की एक साधारण मशीन बनाई जिसका नाम अपनी पत्नी के नाम पर उसने 'जेनी' (Jenny) रखा। 'जेनी' के द्वारा एक स्त्री (अथवा पुरुष) प्रारंभ में एक साथ ही छः सात और बाद में सौ १०० धागे तक कात सकती थी। हरग्रीव्स ने अपनी मशीन 'जेनी' को पेटेण्ट कराने से पहले ही बनाना और बेचना आरम्भ कर दिया था। इसलिए सन् १७७० में जब उसने पेटेण्ट कराया तो भी अदालतों का यह निर्णय रहा कि उसका कोई विनोदाधिकार नहीं हो सकता। 'जेनी' को पहले नाटिषम में और तदनन्तर लकाशायर में बहुत उत्साह में अपनाया गया। 'जेनी' की विशेषता यह थी कि यह कम स्थान घेरती थी, गृह उद्योग में भी उसका उपयोग सम्भव था क्योंकि उसे बुटिया में लगाना भी संभव था, वह सस्ती भी थी और कई गुना मूल उसके द्वारा उत्पादन करना सरल हो गया था। परन्तु उसका मूल पहले जैसा ही मोटा और कमजोर था।

१ Ashton, op. cit, p. 91.

२. Ibid, p. 33.

रिकार्ड आर्कराइट^१ (Richard Arkwright) ने कताई की महत्त्वपूर्ण विधि निकाली। उसने सन् १७६८ में 'वाटर-फ्रेम' (water-frame) का निर्माण किया जिसका पेटेण्ट उसे सन् १७६९ में मिला। उसका 'फ्रेम' प्रारम्भ में पानी की शक्ति से चलता था इसलिए उसे 'वाटर-फ्रेम' कहा गया, परन्तु बाद में अन्य प्रकार की शक्ति से चलाया गया। इससे घागा मजबूत बनता था और सस्ता भी पड़ता था परन्तु क्योंकि थमिक बिना शक्ति के उसका उपयोग नहीं कर सकता था इसलिए प्रारम्भ से ही उसका प्रयोग फैक्टरियो और मिलों में अधिक हुआ। आर्कराइट शीघ्र ही नॉटिंघम चला गया जहाँ होजरी व्यवसाय में सूत की माँग अधिक थी। उसने होजरी उद्योगपतियों की सहायता से सन् १७७१ में क्रोमफोर्ड में जल-चालित फैक्टरी स्थापित की जिसमें शीघ्र ही ६०० व्यक्तियों को रोजगार दिया जाने लगा। सन् १७७५ में आर्कराइट ने इस दिशा में और भी सुधार किया तथा नई रीति का पेटेण्ट कराया। डर्बीशायर और लकाशायर में नई मिलें स्थापित की और घीरे-घीरे अन्य जिलों में भी आर्कराइट की कताई की नई विधियाँ मिलों में अपनाई गईं।

सन् १७८५ के लगभग कताई में नये सुधार द्वारा स्थिति में पुनः परिवर्तन हुआ। बोल्टन के एक जुलाहे सेम्युअल क्रॉम्पटन (१७५१-१८२७) ने बहुत सुन्दर सूत बनाने में अपूर्व सफलता प्राप्त की। परन्तु आर्कराइट के पेटेण्ट की विस्तृत शर्तों के कारण क्रॉम्पटन को पेटेण्ट कराने में कठिनाई हुई। सन् १७८५ में आर्कराइट के दोनों पेटेण्ट अधिकार रद्द कर दिये गये। इसी वर्ष वाट (Watt) के वाष्प एजिन का प्रथमतः प्रयोग कताई में किया गया। सन् १७९० के बाद वाष्प द्वारा चालित बड़े-बड़े कारखाने कस्बों और शहरों में स्थापित हुए। देशी क्षेत्रों में भी औद्योगिक विकास रुका नहीं क्योंकि पानी से चलने वाली फैक्टरियों में अच्छा सूत काता जाता था परन्तु शहरी क्षेत्रों में विकास द्रुत गति से होता गया। सन् १७८२ में मानचेस्टर में केवल दो सूती मिलें थी, सन् १८०२ में ५२ बावन हो गईं। और सन् १८११ तक अवस्था यह हो गई कि लकाशायर में बने सूती माल का अस्सी प्रतिशत कस्बों में कते सूत द्वारा उत्पादन होने लगा।

1 Richard Arkwright (born in 1732, died in 1792) was a barber and wig maker of Preston in Lancashire, see Ashton op. cit. p. 71.

बुनाई के धन्धे में पहले में ही लाभ था। परन्तु सन् १७८० के बाद इस दिशा में भी परिवर्तन हुए। सन् १७८५ में एडमण्ड कार्टराइट (Edmund Cartwright) ने शक्ति-चालित करघे (power-loom) की रीति निकाली जिसे घोड़ों, जल-पहियों (water wheels) अथवा वाष्प-एन्जिनों द्वारा चलाया जा सकता था। यह करघा फैक्टरी उत्पादन के लिए अनुपयुक्त था और उसके विस्तृत उपयोग के पूर्व उसमें पर्याप्त सुधारों की आवश्यकता थी। विलियम रेडक्लिफ (Redcliffe) और टॉमस जॉन्सन ने सन् १८०३ और १८०४ में तथा कुछ वर्षों पश्चात् होरोक्स (Horrocks) एव रॉबर्ट्स (Roberts) ने करघे में अनेक सुधार किये तथापि सन् १८१३ में भी ब्रिटेन में शक्ति-चालित करघों की संख्या २,४०० से अधिक नहीं थी जबकि उसी समय हाथ-करघों की संख्या उसके सौगुने के लगभग थी। सन् १८२० में शक्ति-करघों (power-looms) की संख्या १४ हजार और सन् १८३३ में एक लाख हो गई। हाथ करघों पर काम करने वाले बुनकरों की दशा बहुत दयनीय हो गई।

कताई की मशीनों में भी सुधार होता गया। इनके दो मुख्य कारण थे : पहला यह कि लकड़ी के स्थान पर लोहे का प्रयोग होना गया ; दूसरे जल शक्ति की बजाय वाष्प शक्ति का उपयोग किया जाने लगा। कताई और बुनाई में ही नहीं, सूती वस्त्र उद्योग पर आधारित सहायक उद्योगों में भी तकनीकी प्रगति हो रही थी।

सूती वस्त्र उद्योग में कताई-बुनाई में होने वाले नये प्रयोग अग्न्य वस्त्र उद्योगों में भी किये गये परन्तु सूती उद्योग की तुलना में अग्न्य वस्त्र उद्योगों, जैसे, ऊन, रेशम, इत्यादि में तकनीकी प्रगति बहुत धीमी थी। रेशमी उद्योगों में नये तकनीकी प्रयोग अठारहवीं शताब्दी के अन्त में ही व्यावसायिक सफलता के स्तर तक पहुँच सके। ऊनी वस्त्र उद्योग में नई विधियों के उपयोग सर्वप्रथम बैस्ट्रार्डिंग में किये गये। 'जिनी' कताई यन्त्र यार्कशायर में सन् १७७३ में अपनाया गया परन्तु दक्षिण-पश्चिमी भागों में सन् १७६० तक पहुँच सका। सन् १८०० में यार्कशायर में कताई-बुनाई इत्यादि के लिए फैक्टरी प्रणाली विकसित होने लगी परन्तु पूर्वी और दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्रों में ऊनी कपड़ा बनाने में नई रीतियों को बहुत धीमी गति पर अपनाया गया।

खान व्यवसाय—खान उद्योग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण सुधार १८ वीं शताब्दी के अन्त में स्टीम पम्पिंग इंजनों का प्रारम्भ था। पहले खानों में पानी भरने से बचता, कच्चा लोहा इत्यादि खनिज खोद निकालना बहुत कठिन

था परन्तु वाट (Watt) के सुधार से वाष्प से चलने वाले पानी निकालने वाले इंजन काम में लाये जाने लगे। धीरे धीरे मानवी श्रम के स्थान पर खानो से खनिज पदार्थ निकालने का कार्य वाष्प यंत्रों द्वारा होने लगा। जॉर्ज रटिंग्सन ने सन् १८२० में दुलाई का यंत्र बनाया परन्तु उस समय छोटे लड़के कम मजदूरी पर मिल जाते थे इसलिए उसका विरतुत उपयोग नहीं हो सका। सन् १८४० के बाद खान सम्बन्धी कानूनों के पास हो जाने के बाद इस दिशा में सस्ते शिशु-श्रमिक मिलने बन्द हो गये। सन् १८६२ में सारो की रस्सियाँ दुलाई में सहायक होने लगी। लोह पटरियों का प्रयोग १७६७ में प्रारम्भ हुआ था। खानों में प्रकाश और हवा इत्यादि की धोर भी ध्यान दिया जाने लगा। खान उद्योग की तकनीकी में विकासो का कारण केवल यह नहीं था कि चतुर्मुखी विकास हो रहे थे बल्कि प्रमुख यह था कि कोयला तथा अन्य खनिज पदार्थों की माँग बढ़ती जा रही थी।

लोह-इस्पात उद्योग—सन् १७५६-६९ के युद्ध काल में युद्ध सामग्री की माँग बढ़ने के कारण लोहे के नये कारखाने स्थापित हुए जिनमें ब्रोसले (Broseley) और कैरन (Cairon) में स्थापित कारखाने मुख्य थे। कैरन धायरन वर्क्स की पहली मट्टी १ जनवरी १७६० में प्रज्वलित की गई थी। सन् १७८३-८४ में हेनरी कॉट (Cott) ने दो पेटेण्ट कराए। कॉट की नई रीतियाँ लोह उद्योग के लिए ही नहीं अपितु तकनीकी विकास के इतिहास में उल्लेखनीय घटना थी। उसकी रीतियाँ संक्षेप में ये थी कि पहले ढले हुए लोहे को कोक में गरम करके पिघलाया जाता था और लोहे को छड़ों से हिलाकर उससे कारबन तथा अशुद्धियों के अश को जलाया जाता था। अन्त में उसे लोहे के रोलर्स (rollers) के मध्य से दबाकर निकाला जाता था। हंट्समैन ने स्टील्ड में ढले हुए लोहे को शुद्ध करने की तरकीब पहले ही निकाली थी। वाट ने अपने स्टीम-एंजिन के द्वारा एक झुका हुआ हथौड़ा (tilt hammer) बनाया जो एक मिनट में ७३ हड़्डवेट भारी सिर से तीन सौ चोटें (blows) लगाता था। लोहा सस्ता भी था। उसका उपयोग बढ़ता गया। सन् १७७६ में पहला लोह पुरा बनकर तैयार हुआ था। रेल यन्त्रायाण के विकास के पश्चात् तो उसमें प्रगति होती गई और लोह उद्योग का महत्व बढ़ता गया। सन् १८५५-५६ में हेनरी बिस्मर (Bessemer) ने इस्पात बनाने की नई रीति निकाली जिसमें कॉट की विधि की प्रधूनन (puddling) क्रिया की आवश्यकता

नहीं रही। बाद में खुली भट्टी (open-hearth) की विधि और बिजली की भट्टी उपयोग में आई।^१

तकनीकी विकास और आविष्कारों का ऊपर जो संक्षेप में वर्णन किया है उससे ब्रिटेन के प्रमुख उद्योगों के विकास का परिचय प्राप्त करना सरल होगा।

सूती वस्त्र उद्योग (Cotton Textile Industry)

अठारहवीं शताब्दी के पूर्व सूती वस्त्र उद्योग ब्रिटेन में बहुत कम महत्व का था। यों तो १६ वीं शताब्दी के अन्त का आर इंग्लैण्ड में सूती कपड़ा बनाया जाता था परन्तु वह बहुत ही गिरी हुई कपड़ा प्रारम्भिक अवस्था में था। उस समय कई पश्चिमी द्वापसमूह तथा अन्य क्षेत्रों में आयात की जाती थी परन्तु पूर्ति अनिश्चित थी। कई के व्यापार में फ्रान्सीसी और डच व्यापारी भाग्य व्यापारियाँ स स्पर्धा करते थे। ब्रिटेन में वस्त्र उत्पादकों का ऊनी और रेशमी वस्त्र उद्योगों से अधिक लाभ था। विदेशों से सूती वस्त्र का आयात होता था। भारत का सूती माल इंग्लैण्ड में लोकप्रिय था।^२

यह उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन में सूती वस्त्र सजावट के लिए काम में आता था। वहाँ न तो रई का उत्पादन होता था और न ही सूती कपड़ा की अधिक माँग थी। यों भी सन् १७०० ई० के उपरान्त ग्रेट ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग का विकास होता गया। इसके कारण राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक इत्यादि अनेक थे।

सन् १७०० के पश्चात्, विशेषकर १८ वीं शताब्दी के मध्यकाल में, ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के विकास और उसका उन्नति के मुख्य कारण प्रयोजित थे—

✓ १. विदेशी सूती माल के आयात पर प्रतिबन्ध—सन् १७०० में भारतीय तथा पूर्वी देशों से आयात होने वाले कुछ प्रकार के सूती माल पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। यदि भारत से सूती माल का व्यापार स्वतन्त्र रूप से चालू रहता तो ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग का इतनी तीव्रता से विकास होना सम्भव नहीं था।^३ सन् १७२१ और १७३६ में प्रतिबन्ध और कड़े कर दिए गये।

१. बिजली भट्टी का प्रयोग सर्वप्रथम सन् १८७८ में सर विलियम सीमन्स ने किया था।

२. देखिए साउथगेट, पूर्व उद्धृत, अध्याय १५ पृष्ठ १२७, १

३. Ibid.

प्रतिबन्ध इस प्रकार के थे कि छोटे हुए सूती माल का बिलकुल आयात नहीं हो सकता था। मफेद सूती वस्त्र (वेलिको) और मनमन से स्पर्द्धा प्रभावहीन थी क्योंकि उनके आयात पर भारी कर लगे गये थे।

२. भारत में आन्तरिक अशान्ति—भारत सूती वस्त्र का प्रमुख उत्पादक था परन्तु सन् १७०७ में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात् भारत में जो अशान्ति रही और यहां प्रभुत्व स्थापित करने के लिए फ्रान्सीसियों और अंगरेजों में जो युद्ध होते रहे उनके कारण भारतीय सूती माल की पूर्ति रुक गई और आगल व्यापारी अपने व्यापार के लिए अपने देश के सूती वस्त्र उत्पादन का सहारा लेने लगे। कपास उत्पादक अन्य देशों में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हो नहीं पाई थी जो ब्रिटेन से स्पर्द्धा लेती।

३. समुच्चय राज्य अमेरिका की सस्ती कपास—ब्रिटेन के सूती वस्त्र उत्पादकों को यू० एस० ए० के दक्षिणी राज्यों में पर्याप्त मात्रा में अच्छी और सस्ती कपास मिलने से बहुत प्रोत्साहन मिला।

४. टैकनीकल और वैधानिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए सन् १७२१ में लगाई गई बन्दी सन् १७७४ में हटा दी गई। इसका प्रभाव यह पड़ा कि ब्रिटेन के वस्त्र उद्योग के विस्तार के लिए विवेकी टैकनीकल जानकारी सुलभ हो गई।

५. कताई-बुनाई के नये आविष्कार—इस अध्याय के प्रारम्भ में वस्त्रोद्योग सम्बन्धी तकनीकी विकास का उल्लेख किया जा चुका है। नये आविष्कारों से ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग को बहुत लाभ हुआ। नये यन्त्रों से उत्पादन अधिक होने लगा और लागत कम हुई।

६. सहायक उद्योगों का विकास—रसायनिक उद्योगों के विकास के कारण ब्लीचिंग, रंगाई और छपाई के कार्यों में प्रगति हुई। इजीनियरिंग उद्योगों के कारण यन्त्रों की सुलभता और मरम्मत सम्भव थी।

७. उपनिवेशों में बिक्री-क्षेत्र और कच्चे माल के स्रोत—ब्रिटिश साम्राज्य बढ़ता जा रहा था और साम्राज्यगत देशों तथा उपनिवेशों में ब्रिटिश सूती माल के लिए बिक्री-क्षेत्र (मण्डियाँ) मिले। साथ ही उन क्षेत्रों से कच्चे माल की सुविधा मिली।

८. रई के आयात में समुद्री यातायात की सुविधा—प्रारम्भ से ही ब्रिटेन व्यापार के लिए उत्तम सामुद्रिक जहाजों का स्वामी था। उसकी जहाजों नीति भी ऐसी थी कि कच्चे माल का आयात हो और निमित्त माल

का निर्यात हो। ब्रिटन की जिनिंग प्रक्रिया (ginning process) के आविष्कार से यह लाभ हुआ कि कपास का रई की गाँठों के रूप में आयात होने लगा।

६. भौगोलिक सुविधाएँ—ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए कुछ विशेष सुविधाएँ प्राप्त थी, जैसे, आर्द्र जलवायु, जलशक्ति और कोयले का सस्ता ईंधन इत्यादि। सूत को घुनाई के लिए ब्रिटेन में पहाड़ी नदियों का जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त है।

अन्य सुविधाएँ—उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी सूती वस्त्र उद्योग की उन्नति में सहायक सिद्ध हुए। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में उस समय ऊन का अभाव था अतः ऊनी वस्त्र उत्पादकों का ध्यान व्यापार की दृष्टि से सूती वस्त्रोद्योग की ओर गया। ऊनी वस्त्र उद्योग की प्राचीनता के कारण कुशल कारीगर भी मिले। समुक्त पूँजी वाला कम्पनियाँ और अधि-कोषण के विकास से सहायता मिली। विदेशी व्यापार पहुँच से हा बढ़ा हुआ था अतः विदेशी मंडियों में सूती माल बेचने के लिए उन्हें विनय प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं थी। ब्रिटेन में साहायसों की कमी नहीं थी। भवसर का लाभ उठाना वे जानते थे।

क्षेत्र—ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग मुख्यतया लंकाशायर तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में केन्द्रित है। 'लंकाशायर' चेष्टायर और डर्बीशायर में मिलाकर ब्रिटेन के सूती वस्त्रोद्योग में लगे हुए कारखानों का ८२ प्रतिशत के लगभग पाए जाते हैं। रोप का अधिकांश वेस्टराइडिंग और स्कॉटलैण्ड में है। सूती वस्त्र के प्रमुख केन्द्र बोल्टन, आल्डहम, रोचडाल (Rochdale) बर्नल, प्रिंस्टन, बरो, मान-चेस्टर स्टॉकपोर्ट, ली (Leigh) ब्लकवर्न, नल्सन, इत्यादि हैं।

लंकाशायर में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापनाकरण के प्रमुख कारण—भौगोलिक हैं। लंकाशायर में इस उद्योग के केन्द्रित हो जाने के मुख्य कारण ये हैं : (१) नम पछुआ हवाओं से इस प्रदेश को आर्द्रता मिलती रहती है जो कटाई के लिए आवश्यक समझी जाती है (यद्यपि आजकल शुष्क प्रदेशों में वातावरण में कृत्रिम साधनों से भी आर्द्रता उत्पन्न की जाने लगी है, परन्तु १८वीं शताब्दी में ये साधन अप्राप्त थे और यह तो मानना ही पड़ेगा कि कृत्रिम साधनों की कुछ लागत भी होती है)।

(२) लंकाशायर मररीकी बन्दरगाहों से समीप पड़ता है जहाँ से सस्ती कपास मुलभ भी।

(३) इस प्रदेश के समीप कोयला, लौहा, जल शक्ति, इत्यादि की सुविधाएँ प्राप्त थी। मध्य पेनाइन पर्वत श्रेणी से बहने वाली नदियाँ धुलाई और रमाई के लिए श्रेष्ठ जल प्रदान करती हैं। (इन नदियों से अब सस्ती बिजली की प्राप्ति भी होती है।

(४) इस प्रदेश के लिबरपूल बंदरगाह की स्थिति बहुत ही उत्तम है जिसे सन् १८६४ में मानचेस्टर शिप कैनल द्वारा मानचेस्टर से मिला दिया गया।

(५) अन्य कारण भी कम महत्व के नहीं हैं, जैसे, पंतुक कला प्राप्त दक्ष श्रमिकों की प्राप्ति, चेसायर प्रदेश से नमक की प्राप्ति, ओल्डहम इत्यादि नगरों से यन्त्रों की प्राप्ति, उत्साही और दूरदर्शी साहसी, इत्यादि, ये कारण उन कारणों के साथ साथ समझे जाने चाहिये जिनके कारण ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है।

उन्नति काल—सन् १७०० के उपरान्त ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग का निरन्तर विकास होना गया (कारणों पर पहले ही प्रकाश डाला जा चुका है)। भारतवर्ष जा पहले ब्रिटेन का बहुत अच्छा कस्म का सूती वस्त्र निर्यात करता था १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ में काफी मात्रा में सूती वस्त्र ब्रिटेन से मँगाने लगा। ब्रिटेन ने सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिए प्रारम्भ में संरक्षणवादी नीति अपनाई थी, यह स्मरणाय है। परन्तु बाद में उसने निवर्धनी नीति अपनाई क्योंकि उसके हित में यहाँ था।

ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग की उन्नति विविध पहलुओं से देखी जा सकती है, यथा (१) कारखानों की संख्या बढ़ी, (२) रोजगार में वृद्धि हुई, (३) सहायक उद्योगों का विकास हुआ, (४) कच्चे माल का आयात बढ़ता गया और (५) सूती वस्त्र के निर्यातों की मात्रा और मूल्यों में वृद्धि हुई। कपड़े और तकुआ की संख्या में वृद्धि हुई तथा कारखानों में शक्ति तथा यन्त्रों का उपयोग बढ़ा। वस्त्र की कस्म में निरन्तर सुधार होता गया और वस्त्र-उत्पादन की नई विधियाँ अपनाई गईं।

सन् १८०० से १८६० तक वस्त्रोद्योग सरलता से प्रगति करता रहा। सन् १८६० में संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ जाने के कारण अच्छी कोटि की सस्ती अमरीकी कपास ब्रिटेन के लिए दुर्लभ होगई अतः वह भारत-वर्ष और मिस्र से आयात करने लगा। भारतीय कपास अमरीकी कपास के

१. भारत के उद्योग के लिए यह नीति विपरीत सिद्ध हुई।

अभाव को पूरा नहीं कर सकी। सन् १८७५-७६ काल की मन्दी के कारण इस उद्योग को फिर हानि पहुँची। सन् १८८० में १८९३ तक उद्योग की उन्नति होती रही।

सन् १८९३ में ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग की स्थिति बहुत अच्छी थी। उस समय इस उद्योग में आठ लाख में अधिक शक्ति चरधे थे, तन्मूल्यों की संस्था ६ करोड़ में कुछ कम थी, छः लाख में अधिक मजदूरी का रोजगार इस उद्योग में मिला हुआ था; ब्रिटेन का सूती कपड़े का उत्पादन विश्व भर में सबसे अधिक था और उसके कुल निर्यात व्यापार का लगभग चतुर्थांश सूती वस्त्र का था।

प्रथम महायुद्ध काल : कठिनाइयाँ—यह स्मरणीय है कि ब्रिटेन का सूती वस्त्र-उद्योग मुख्यतया निर्यात व्यापार के कारण ही विकसित होता गया। इसी लिए सन् १९१४ में प्रथम महायुद्ध छिड़ते ही ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग को संकट का सामना करना पड़ा। जहाज युद्ध में लगे गये। जहाजों की कमी के कारण एक ओर तो वस्त्र माल के आयात सम्भव नहीं हो सके और दूसरी ओर कपड़े का निर्यात करना सम्भव नहीं था। अमेक और पूर्वी युद्ध सम्बन्धी व्यवसायों में लगे गये। इस प्रकार उत्पादन कम हुआ। युद्ध काल में वस्त्र के अभाव के कारण मूल्यों में वृद्धि होनी गई जिसे रोकने के लिए नियन्त्रण लागू पड़े।

युद्ध समाप्त हुआ तो ब्रिटिश माल की माँग फिर बढ़ी। इसका एक कारण यह भी था कि बाँझी के भाव ऊँचे हो जाने में पूर्वो देशों में अल्प शक्ति बढ़ गई थी। परिणामतः सन् १९१८ से १९२० तक ब्रिटेन में सूती वस्त्र उत्पादकों को पर्याप्त लाभ मिले। इन वर्षों में अधिक मात्रा युद्ध काल में रुकी हुई माँग के कारण भी थी। परन्तु अनेक देशों में, युद्ध काल में सूती वस्त्र का उत्पादन होने लगा था, यह ऐसा तथ्य था जिसका ब्रिटिश सूती वस्त्रोद्योग पर गम्भीर प्रभाव पड़ा।

सन् १९२० के पश्चात् ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग का पतन—सन् १९२० के पश्चात् इस उद्योग की अवनति होने लगी। सन् १९३० तक हालत बहुत गिर गई। द्वितीय विश्व-युद्ध छिड़ने के समय एक बार दशा कुछ सुधरी परन्तु प्रथम महायुद्ध की भी कठिनाइयाँ फिर आ गई, अन्तिम पहलू में भी अधिक मजदूरी का सामना करना पड़ा। सन् १९४५ में (अर्थात् युद्धोपान्त) निर्यातों में वृद्धि हुई, आयातों की कठिनाइयाँ भी कम हो गई और विकास हुआ परन्तु सन्

१९५१-५२ में मन्दी ने ब्रिटिश वस्त्र व्यवसाय को फिर हानि पहुँचाई। युद्ध पूर्व की दशाएँ तो अब आना सम्भव ही प्रतीत नहीं होता, यद्यपि ब्रिटिश सूती वस्त्र व्यवसाय में तकनीकी प्रगति होती रही है।

पतन के कारण—सन् १९२० के पश्चात् ब्रिटिश वस्त्र-उद्योग के पतन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं—

(१) जापान तथा अन्य पूर्वी देशों में वस्त्र व्यवसाय का विकास हुआ। युद्ध काल में (१९१४-१८ में) जब ब्रिटेन युद्ध को तैयारियों में लगा रहा, अन्य देशों ने औद्योगिक विकास किया। विशेष कर जापान ब्रिटेन का प्रतिद्वन्द्वी बन गया। बहुत अधिक मूल्यानुसार आयात कर चुकाने पर भी जापानी कपड़ा भारतवर्ष में ब्रिटिश कपड़े की अपेक्षा अधिक बिकने लगा था। भारत में भी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हो चुकी थी और प्रथम महायुद्ध काल में उसमें विकास हुआ था।

(२) युद्धों का प्रभाव—युद्ध काल में पूँजी और श्रम शक्ति युद्ध की दिशा में लगने के कारण व्यवसाय की प्रगति में खाई पड़ गई। आयात की सुविधाओं की कमी का भीषण प्रभाव पड़ा। युद्ध-काल में ग्रेट ब्रिटेन के कई प्राहक देशों की क्रय-शक्ति कम हो जाने से (युद्ध ने उन देशों पर विनाशकारी प्रभाव डाला था) युद्धोपरान्त भी ब्रिटेन का कपड़ा अधिक माँग में न रहा, विशेषकर द्वितीय विश्वयुद्ध से। ग्रेट ब्रिटेन का महान् दुर्भाग्य समझा जा सकता है जिसके कारण ब्रिटिश कारखाने भी नष्ट हुए थे। युद्ध कालों में अनेक देशों से व्यापारिक सम्पर्क बहुत कम हो गया और कपास का आयात भी न हो सका।

(३) मन्दी का आघात—सन् १९२९ से १९३३ की अवधि में संसार के अधिकांश देशों की भाँति ब्रिटेन के उद्योग को भी भारी क्षति पहुँची और सूती वस्त्र उद्योग उसके प्रभाव में बचा न रहा। सन् १९५१-५२ में मन्दी ने ब्रिटिश सूती उद्योग को फिर हानि पहुँचाई। (मन्दी का सामान्य प्रभाव यह पड़ता है कि वस्तुएँ सस्ती हो जाने से उत्पादकों को हानि होती है और बहुत से कारखाने बन्द हो जाते हैं।)

(४) विदेशों में सरक्षण कर—अनेक देशों ने ब्रिटिश सूती माल के आयात पर कर लगा दिये। कपास उत्पादक देशों ने भी बहुधा कपास के निर्यात पर कर लगाये। दोनों प्रकार से ब्रिटिश सूती वस्त्र व्यवसाय को हानि पहुँची।

(५) भारत में स्वदेशी-आन्दोलन अंगरेजी राज्य का मूलोच्छेदन करने के लिए भारत में 'स्वदेशी अपनाओ' आन्दोलन छेड़ा गया था। खादी और चर्खा स्वतन्त्रता सश्रम के मुख्य अस्त्रों के रूप में अपनाये गये थे। इसके कारण भारत में ब्रिटिश वस्त्र की माँग घट गई।

(६) बड़ी हुई लागत — ब्रिटिश सूती वस्त्र व्यवसाय की अवनति का मुख्य कारण यह था कि ब्रिटेन का कपड़ा विदेशी बाजारों में अन्य देशों के कपड़ों की अपेक्षा महँगा था क्योंकि उसकी उत्पादन लागत अधिक हो गई। एक तो यी ही ब्रिटेन को कच्चा माल (कपास) बाहर से मँगाने के कारण अधिक नहीं तो यातायात व्यय अधिक देना पड़ता, प्रायः कपास पर उन देशों द्वारा लगाया हुआ निर्यातकर तथा कपड़े पर आयात कर देना पड़ता। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन में अन्य देशों की अपेक्षा मजदूरियाँ अधिक हैं। इस कठिनाई की दशा में ब्रिटेन ने अपना ध्यान केवल उच्च कोटि के कपड़े के उत्पादन पर केन्द्रित किया है।

परिणाम यह हुआ कि सन् १९३७ की अपेक्षा सन् १९५७ में सूती वस्त्र उद्योग में रोजगार साठ प्रतिशत रह गया है। सन् १९५७ में उत्पादन सन् १९३७ के उत्पादन का पचास प्रतिशत था।

वर्तमान स्थिति — यद्यपि सन् १९२० में ब्रिटिश सूती उद्योग निरन्तर अवनति करता गया है परन्तु अब भी वह ब्रिटेन के उपभोक्ता वस्तु व्यवसायों में सबसे बड़ा है और निर्यात व्यापार की दृष्टि से उसका महत्वपूर्ण भाग है। सन् १९५७ में इस उद्योग में वहाँ २५६ हजार व्यक्तिों को रोजगार मिल रहा था। सन् १९५७ में इस उद्योग में ३३६ हजार टन कपास का उपभोग हुआ जिसका आधे से अधिक संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात किया गया था। दूसरा सबसे अधिक कपास सप्लाई करने वाला देश सूडान था। हाल में ब्रिटिश कपड़े के नये गुणों के कारण उसका महँगा कपड़ा भी विदेशों में दूर-दूर बिक जाता है। सन् १९५७ में ब्रिटेन ने ४५६० लाख वर्ग गज कपड़ा, जिसका मूल्य ६ करोड़ पाँच (£ 60 m.) था, विदेशों को भेजा था।

१. सन् १९३७ में ६३६ हजार टन कपास लगी थी।

सूत, धागा इत्यादि मिलाकर मूनी उद्योग के कुल निर्यात ६० मिलियन पौंड (६ करोड़ पौंड) मूल्य के थे।^१

ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग का भविष्य उज्ज्वल प्रतीत नहीं होता क्योंकि लगभग सभी कपास उत्पादक देशों में इस उद्योग की प्रगति हो रही है और उनमें उत्पादन की लागत अपेक्षाकृत कम है।

कोयला उद्योग (Coal Mining Industry)

ब्रिटेन में थोड़े से कोयला सात-सौ वर्ष पहले ही निकाला जाने लगा था परन्तु कोयला उद्योग का सत्रहवीं याताब्दी से संगठित व्यवसाय के रूप में विकास हुआ जबकि यूरोप के अन्य देशों में उसका विकास लगभग दो-तीन वर्ष बाद हुआ। अपने महत्व के कारण कोयला ब्रिटेन का काला हीरा (black diamond) समझा जाता रहा है।

घारम्म में कोयले का उपयोग घरेलू कामों में ही होता था। उस समय यातायात के यान्त्रिक साधनों के अभाव में कोयला डोना एक दुष्कर कार्य था। जब लोहा शुद्ध करने में कोयले का प्रयोग हुआ, वाष्प-एजिन का आविष्कार हुआ और शक्ति के रूप में कोयले का उपयोग बढ़ा तो उद्योग, यातायात और वाणिज्य में क्रान्ति आ गई। खानों से कोयला निकालने के लिए, खानों का पानी बाहर निकालने के लिए और कोयला डोने के लिए अनेक आविष्कार हुए जिनसे खान उद्योग को ही लाभ नहीं हुआ बल्कि अन्य उद्योगों का विकास होता गया। ज्यों-ज्यों औद्योगिक उन्नति होती गई, कोयला की माँग बढ़ती गई और कोयले की खानों का विकास हुआ। इसी आधार पर यह कहा जाता है कि इंग्लैण्ड का आर्थिक इतिहास उसके कोयला-खान-उद्योग की कथा है।

खान सम्बन्धी तकनीकी विकास का संक्षिप्त वर्णन हम अध्याय में पहले ही किया जा चुका है।

ब्रिटेन में कोयले का उत्पादन बढ़ने पर और ईंधन और शक्ति के रूप में संसार में कोयले का उपयोग बढ़ने पर ब्रिटिश कोयला जगत के अनेक देशों को निर्यात किया जाने लगा। सन् १९१० के लगभग तक संसार के कोयला

1. Source . Britain and Official Handbook, 1959 edition, p. 326.

बाजार में ब्रिटिश कोयले का ही प्रभुत्व था। सन् १९१३ में, जबकि ब्रिटेन में कोयले का उत्पादन उच्चतम शिखर पर था, कोयला उद्योग का उत्पादन २८७० लाख टन, निर्यात ६४० लाख टन और रोजगार ११०७ हजार व्यक्ति, था।^१

ब्रिटेन में कोयला खान व्यवसाय का विकास बहुत पहले ही हुआ, इस तथ्य का अर्थ यह हुआ है कि वहाँ की अन्धवी और ऊपरी खानों की प्रायः खुदाई हो चुकी है और अब घटिया और गहरी खानों में कोयला प्राप्त करना पड़ता है। ऐसी दशा में उत्पादकता बनाये रखने के लिए ऊँचे विनियोगों की आवश्यकता पड़ती है।

प्रथम महायुद्ध काल में विशेषकर मजदूरों तथा यन्त्रों एवं अन्य पूँजी साधनों की कमी के कारण कोयला खान उद्योग नीचे गिरा और सुधार नहीं किये जा सके। इसके अतिरिक्त अन्य देशों में शक्ति के अन्य साधनों का विकास होने तथा यूरोपीय देशों में सरसता कोयला मिलने के कारण ब्रिटिश कोयले के निर्यात भी गिरे। सन् १९२५ में ब्रिटेन ने केवल ६७० लाख टन कोयला निर्यात किया था।

समामेलन (amalgamation) द्वारा कोयला-उत्पादन के व्यय घटाने के प्रयत्न सन् १९१६ में सांकी आयोग (Sankey Commission) से प्रारम्भ हुए। सन् १९२५ में दूसरा प्रमुख कोयला आयोग नियुक्त किया गया जिसने इस व्यवसाय के सुधार के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं। सन् १९३० में एक एक्ट (Coal Mines Act) द्वारा उत्पादन की बढ़ी और कुशल इकाइयों का निर्माण करने के लिए कमिश्नर रखे गये। सन् १९३८ के कोयला कानून (Coal Act) द्वारा खनिज कोयले का स्वामित्व राज्य के हाथों में आ गया और कोयला आयोग का यह कानूनी उत्तरदायित्व हो गया कि व्यवसाय का सुचारु रूप से सगठन करने के लिए कोयला उत्पादन में लगी विभिन्न इकाइयों की संख्या और कम की जाय। इस दिशा में अधिक प्रगति नहीं हो पाई थी कि सन् १९३६ में द्वितीय विश्व-युद्ध छिड़ गया।

राष्ट्रीय कोयला बोर्ड (National Coal Board)—सन् १९४२ में सरकार ने इस उद्योग पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया परन्तु खानों का स्वामित्व

पूर्ववत् (of colliery undertakings) चालू रहा। १ मई १९४६ को कोयला उद्योग राष्ट्रीयकरण एक्ट को शाही स्वीकृति मिल गई। १ जनवरी १९४७ को कोयला उद्योग की कुल सम्पत्ति (assets) राष्ट्रीय कोयला बोर्ड के सुपुर्द कर दी गई। खानों का प्रबन्ध, वित्त-व्यवस्था, बिक्री व्यवस्था, श्रम-सम्बन्ध, सुरक्षा स्वास्थ्य-व्यायण तथा विकास और अनुसंधान की देखरेख करता है। बोर्ड का कार्य नौ विभागों (divisions) में बँटा हुआ है जिनके अन्तर्गत खानों का प्रबन्ध समूहों में पचास क्षेत्रों में किया जाता है।

उत्पादन—ब्रिटेन के प्रमुख कोयला क्षेत्र ये हैं: (१) यार्कशायर, डर्बीशायर और नाटिंगमशायर क्षेत्र, जिससे कुल उत्पादन का लगभग ४५ प्रतिशत प्राप्त होता है, (२) डरहम और नार्थम्बरलैण्ड क्षेत्र, (३) दक्षिण वेल्स क्षेत्र, और (४) स्कॉटलैण्ड के क्षेत्र। अन्य महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्रों में लंकाशायर और वेस्ट मिडलैण्ड्स (स्टैफर्डशायर तथा वारविकशायर) सम्मिलित हैं। उत्तरी प्रायरलैण्ड में कोई कोयला क्षेत्र नहीं है।

राष्ट्रीय कोयला बोर्ड के प्रयत्नों से सन् १९४७ से गहरी खानों का उत्पादन बढ़ा है। सन् १९४७ में गहरी खानों से प्राप्त कोयला १८७० लाख टन था, सन् १९५४ में २१४० लाख टन था। तब से उत्पादन लगभग स्थिर रहा है, सन् १९५७ में २१०० लाख टन था। इसके अतिरिक्त, खुली खानों का सन् १९५७ में १३६ लाख टन था। ब्रिटिश कोयला उद्योग में श्रमिकों की गंभीर कठिनाई रही है। सन् १९५७ में कोयला खानों में औसत रोजगार ७१० हजार था जिसमें से २८५ हजार मजदूर ऊपरी खानों पर थे।^१

यूनाइटेड किंगडम (U K) में कोयले के उपयोग का स्वरूप (pattern) संक्षेप में निम्न तालिका से जाना जा सकता है—

१. सन् १९१३ के उत्पादन और रोजगार के आँकड़ों से तुलना कीजिए। देखिए इस पुस्तक के इसी अध्याय का पृष्ठ ६७।

तालिका

यूनाइटेड किंगडम में सन् १९५७ में कोयले का उपभोग^१

(लाख टनों में)

गैस	२६४	लोहा-इस्पात	५६
बिजली	४६५	इंजीनियरिंग तथा अन्य	
रेलवेज	११४	उद्योग	३१६
कोक-भट्टियाँ	३०७	घरेलू तथा अन्य	६०७
		कुल	<u>२१३२</u>

कुल पूर्ति का पंचमाश से अधिक बिजली बनाने में उपभोग होता है।

समुद्री व्यापार—सन् १९१३ से कोयले का निर्यात व्यापार बहुत घट गया है, सन् १९३८ से भी कम हुआ है। अन्य कारणों के अतिरिक्त इसका एक प्रमुख कारण आन्तरिक उपयोग में वृद्धि होना भी है। सन् १९५७ में ६६ लाख टन कोयला निर्यात किया गया (सन् १९१३ में ६४० लाख टन रिया गया था)^२। सन् १९५७ में ब्रिटिश कोयला खरीदने वाले मुख्य देश डेनमार्क, आयरिश रिपब्लिक, फ्रान्स और नीदरलैंड्स थे। कान्वा ब्रिटेन में बाहर से मंगाया भी जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका से विभिन्न बरों में उसने कोयला आयात किया है। सन् १९५५ में ११५ लाख टन और सन् १९५७ में २६ लाख टन कोयला आयात किया गया था।

ब्रिटेन की अधिकतर कोयला खानों से अच्छी कोटि का कोयला मिलता है। दक्षिण वेल्स में एन्वैसाइट कोयला मिलता है जो जलाने में ज्वाला-शक्ति अधिक होने के कारण सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। नार्थम्बरलैण्ड और डरहम कोयला क्षेत्रों से भी एन्वैसाइट या अर्द्ध-एन्वैसाइट किस्म का कोयला मिलता है। मध्य स्काटलैण्ड में कैनल किस्म का कोयला पाया जाता है जो जलाने के लिए घटिया माना जाता है परन्तु गैस बनाने की दृष्टि से उत्तम होता है।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि ग्रेट ब्रिटेन में प्रत्येक महत्त्वपूर्ण कोयला क्षेत्र के समीप प्रायः किसी महत्त्वपूर्ण व्यवसाय का विकास हुआ है। उदाहर-

1. Britain : An Official Handbook, 1959.

2. Ibid.

एअर्थ, यार्कशायर (West Riding of Yorkshire) में ऊनी व्यवसाय, नाटिघम में रसायन और वस्त्र व्यवसाय, डर्बी तथा नाटिघम के कोयला क्षेत्रों के समीप शेफील्ड के लोहे के कारखाने स्थित हैं जो उस कोयले का उपयोग करते हैं। नार्थम्बरलैण्ड और डरहम कोयला क्षेत्रों के समीप पोत निर्माण, बन्दूक और रेल का सामान बनाने के कारखानों का विकास हुआ है। स्कॉटलैण्ड के कोयला क्षेत्रों के समीप लोहा इस्पात व्यवसाय और पोत निर्माण व्यवसाय विकसित हुए हैं। दक्षिण वेल्स में टिन प्लेट बनाने और कई प्रकार की धातुएँ गलाने का काम होता है। लन्काशायर के कोयला क्षेत्रों के समीप सूती वस्त्र, ईंजीनियरिंग तथा रसायनिक व्यवसायों का विकास हुआ है। कम्बरलैण्ड में लोहा-इस्पात, और स्टैफर्डशायर में मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग (Pottery Industry) कोयला क्षेत्रों के समीप विकसित हुए हैं।

लोहा-इस्पात उद्योग (Iron and Steel Industry)

ब्रिटेन की गणना विद्व के इस्पात उत्पादक देशों में तीसरी की जाती है। सत्रहवीं शताब्दी से ही यहाँ इस व्यवसाय का विकास प्रारम्भ हुआ था और उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक अपनी चरम सीमा तक पहुँच चुका था। ब्रिटेन प्रथम देश समझा जाता है जहाँ कच्चा लोहा पिघलाने के लिए कोयले का प्रयोग किया गया और ब्रिटिश आविष्कारकों के अनुसन्धानों द्वारा न केवल ब्रिटेन में लोहा-इस्पात उद्योग में वरन् समस्त भू-भाग में अान्तिकारी विकास हुए।

स्थानीयकरण—ग्रेट ब्रिटेन में लोहा इस्पात व्यवसाय के स्थानीयकरण पर मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों का प्रभाव पड़ा है—

- (१) कोयला क्षेत्रों की समीपता,
- (२) कच्चे लोह क्षेत्रों की समीपता,
- (३) भूना और भट्टियों के योग्य मिट्टी की सहज उपलब्धि,
- (४) नदियों और समुद्र-तट की समीपता,
- (५) यातायात की सुविधाएँ और ईंजीनियरिंग का विकास, इत्यादि।

कुछ क्षेत्रों में कच्चे लोहे के अभाव में आयात किये हुए कच्चे लोहे पर निर्भर होना पड़ता है।

कच्चे लोह के क्षेत्रों के समीप स्थित लिंकनशायर और नार्थम्पटनशायर लोहा-इस्पात व्यवसाय की दृष्टि में अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं जहाँ से ब्रिटेन का लगभग एक-तिहाई लोहा मिलता है। लोहा-इस्पात व्यवसाय के अन्य प्रमुख

क्षेत्र शेफील्ड, पश्चिमी और दक्षिणी यार्कशायर, लंकाशायर, डरहम, मिडलैण्ड, दक्षिणी वेल्स, क्लाइड नदी का बेसिन, लीसेस्टरशायर, कम्बरलैण्ड, वैंस्टमोर-लैण्ड, ग्राक्सफोर्ड और रटलैण्ड हैं।

विकास—औद्योगिक क्रान्ति के पूर्व लोहा बनाने का काम ब्रिटेन में बिखरा हुआ था। लोहा गलाने के लिए लकड़ी का कोयला काम में लाया जाता था। लकड़ी का अधिक उपयोग होते-होते लकड़ी की इतनी कमी अनुभव प्रतीत की जाने लगी कि उसके अभाव में लोह उद्योग की उन्नति रुक गई। लोहे की माँग बढ़ती जा रही थी और खानों में कोयले का उत्पादन भी बढ़ रहा था, अतः लोहा गलाने के लिए खान के कोयले को उपयोग में लाने की ओर ध्यान गया।

सन् १७५० तक लोहा-इस्पात व्यवसाय का जो विकास हुआ उसका वर्णन अध्याय दो में किया जा चुका है। इस अध्याय के 'तकनीकी विकास' खण्ड में लोहा-इस्पात व्यवसाय की तकनीकी प्रगति का परिचय दिया जा चुका है। लोहा-इस्पात व्यवसाय के विकास में उसे समझना आवश्यक है, उसे यहाँ दुहराया नहीं गया है। यह बताया जा चुका है कि अब्राहम डर्वी और बेंजायिन हड्समैन ने लोहा-इस्पात व्यवसाय में कोयले का उपयोग बढ़ाकर इस व्यवसाय की उन्नति में महान् कदम बढ़ाया। कोयलाखानों के विकास से मार्ग सरल हो गया।

लोहा गलाने की मट्टियो में सुधार हुआ। सन् १८२१ के पश्चात् रेलों का विकास होने और सन् १८५० के बाद जलयानों (ships) में लोहे का उपयोग आरम्भ होने में लोहा-इस्पात की माँग बहुत बढ़ गई। विदेशों में भी रेलवेज और पोत-निर्माण का विकास करने के लिए ब्रिटिश निर्मित माल की माँग बढ़ी। सन् १८७० में ब्रिटेन इस्पात उत्पादक देशों में प्रथम था, अन्य देश तो आरम्भ कर रहे थे जिसके लिए वे स्वयं ब्रिटेन की सहायता ले रहे थे।

सन् १७२० में ब्रिटेन का डूने हुए लोहे (पियग्रायरन) का उत्पादन लगभग १७ हजार टन था और सन् १८७१ में लगभग ६५ लाख टन हो गया था।

सन् १८५५ में हेनरी बिस्मिथ ने लोहे में कार्बन की मात्रा कम करके इस्पात बनाने में सफलता प्राप्त की जिसे बिस्मिथ प्रक्रिया कहा जाता है। इस विधि से डूने इस्पात को तेजाबी इस्पात कहा जाता था। इस प्रक्रिया का उपयोग

कासफोरस-रहित कच्चे लोहे में ही किया जाता था। इंग्लैण्ड में ऐसा कच्चा लोहा प्रायः नहीं मिलता था, अतः स्वीडन और स्पेन से मँगाना पड़ता था। कासफोरस-युक्त लोहे से इस्पात बनाने की प्रक्रिया का विकास टॉमस और गिलक्रिस्ट ने किया। तत्पश्चात् खुले-बूँदों की पद्धति का विकास हुआ और सन् १८७८ में सर विलियम सीमेन्स (Siemens) ने लोहा गलाने के लिए बिजली की भट्टी निकाली। तकनीकी प्रगति का क्रम रुका नहीं, प्रगति होती रही। सन् १८८० के पूर्व इस्पात का औसत वार्षिक उत्पादन ती लाख टन से कम था। सन् १९१३ में सत्तर लाख टन के लगभग हो गया। इस समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी ने भी पर्याप्त प्रगति कर ली थी। संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्पादन ब्रिटेन से बहुत अधिक हो गया था।

प्रथम महायुद्ध काल (१९१४-१८) में युद्धकालीन सामग्री के लिए लोहा-इस्पात की माँग बढ़ने के कारण लोहा-इस्पात के कारखानों को बहुत लाभ हुए, उत्पादक कंपनियों के अंशों के मूल्य बढ़ गये। परन्तु बाद में अमिकों की मजदूरियाँ भी बढ़ी, सरकार ने इस्पात के मूल्य पर नियन्त्रण लगाये और व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाये गये।

प्रथम महायुद्ध समाप्त होने के पश्चात् लोहा-इस्पात के निर्मित माल की माँग घटी। सन् १९२० से ब्रिटेन के लोहा-इस्पात उद्योग को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिनमें प्रमुख ये हैं—

१. इस्पात के मूल्य घटे। सन् १९२६ के बाद की मन्दी तो बहुत ही गम्भीर थी।

२. विदेशों में ब्रिटिश इस्पात माल की माँग घटी जिससे उसके निर्यात व्यापार को भारी क्षति हुई। इसके कई कारण थे : (क) अन्य देशों में लोहा-इस्पात का बढ़ा हुआ उत्पादन, (ख) युद्ध की ध्वसारमक क्रिया के कारण कई ग्राहक देशों की क्रय शक्ति में कमी, (ग) ब्रिटिश इस्पात का अपेक्षाकृत अधिक मूल्य, इत्यादि।

३. ब्रिटिश इस्पात का उत्पादन-व्यय संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी की अपेक्षा अधिक था क्योंकि इन देशों में प्राकृतिक सुविधाएँ अधिक उपलब्ध थी। दूसरे, उन्होंने इंग्लैण्ड के औद्योगिक सगठन के दोषों से सबक सीखकर उनका निराकरण आरम्भ से ही कर लिया था। उदाहरण के लिए उन्होंने उत्पादन की बड़ी इकाई (बड़े कारखानों) पर जोर दिया और भट्टियाँ प्राधुनिकतम प्रकार की बनाई, इत्यादि। तीसरे, उन देशों में उपलब्ध लोहा अच्छी

किस्म का था। चौथे, उन देशों में इंग्लैण्ड की अपेक्षा कीयता सस्ता था। इसके अतिरिक्त ग्रेटब्रिटेन में मजदूरी अधिक थी जबकि काम के घण्टे कम थे, ब्रिटिश उद्योग में पूँजी का विनियोग आवश्यकता से अधिक (over-capitalization) था।

१८ सन् १९२० तक ब्रिटिश लोहा-इस्पात उद्योग की हालत काफी गिर गई थी जिसका उपर्युक्त कारणों ने अतिरिक्त एक कारण यह भी था कि यूरोप के प्रमुख इस्पात उत्पादक देशों ने मिलाकर ऐसा संगठन बनाया था जिससे ब्रिटेन को विदेशी व्यापार में हानि हुई। विवश होकर ब्रिटेन को भी स्वतन्त्र-व्यापार नीति का परित्याग करना पड़ा।

सन् १९१० में इस उद्योग के विकास के लिए सरकारी तौर पर महत्वपूर्ण कदम उठाये गये। कीमतों को स्थिर रखने और निर्मात बढाने की ओर ध्यान दिया गया। सन् १९१४ में लोहा-इस्पात के व्यापार के पुनर्गठन की दृष्टि से ब्रिटिश आयरन एण्ड स्टील फ़ैडरेशन की स्थापना हुई। द्वितीय विश्व युद्ध (१९१६-४५) छिड़ जाने पर स्थानीय माँग बढने से आरम्भ में लाभ दिखाई दिये परन्तु निर्यात व्यापार की दृष्टि से तथा विध्वंसकारी प्रभावों से युद्ध का इस्पात उद्योग पर बुरा असर पड़ा। सन् १९४६ में लोहा-इस्पात की उत्पादन क्षमता बढाने के लिए पुनः प्रयत्न किये गये जिसमें सफलता मिली। आधुनिकीकरण और विकास का कार्य बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और यह योजना है कि सन् १९६३ तक इस्पात (crude steel) का उत्पादन लगभग २८० लाख टन हो जाये जिसमें से ५० लाख टन का निर्यात हो सके। सन् १९४६ में लोहा-इस्पात उद्योग कानून द्वारा सन् १९५१ तक इस उद्योग का अधिकांश सार्वजनिक स्वामित्व में ले लिया गया था परन्तु सन् १९५३ में नये कानून द्वारा निजी कम्पनियों को ही स्वामित्व लौटा दिया गया था।

वर्तमान स्थिति—इस समय ब्रिटेन संसार के चार प्रमुख इस्पात उत्पादक देशों में गिना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस का हरापान का उत्पादन ब्रिटेन से अधिक है। पश्चिमी जर्मनी ब्रिटेन के मुकाबले का है।^१

१. सन् १९५१ में विश्व के इस्पात उत्पादन का ४५ प्रतिशत संयुक्त राज्य अमेरिका में, १६ प्रतिशत सोवियत रूस में, ६ प्रतिशत यू० के० में तथा ६ प्रतिशत पश्चिमी जर्मनी से प्राप्त हुआ था।

ग्रेट ब्रिटेन विशेष रूप से अपने इस्पात की अच्छी किस्मों के लिए विख्यात है। सन् १९४६ में पिग आयरन का उत्पादन ७८ लाख टन और इस्पात का १२७ लाख टन था। सन् १९५७ में पिग आयरन का उत्पादन बढ़कर १४३ लाख टन और इस्पात का २१७ लाख टन हो गया। सन् १९५७ में लोहा-इस्पात के प्रत्यक्ष रूप से होने वाले निर्यात ३६ लाख टन थे जिसका मूल्य २१३० लाख पौंड था। अप्रत्यक्षतः होने वाले निर्यात लगभग ४४ लाख टन थे जो इस्पात-उपभोग करने वाले व्यक्तियों द्वारा निर्मित इस्पात के माल के रूप में थे। सन् १९५७ में लोहा-इस्पात में रोजगार पाने वाले व्यक्तियों की संख्या ४,६०,००० थी।

ब्रिटिश लोहा-इस्पात उद्योग की यह विशेषता है कि वह कोयला-क्षेत्रों के समीप केन्द्रित है जहाँ प्रायः अच्छी कोटि का कोयला सुलभ है परन्तु पहली कठिनाई तो यह है कि कच्चे लोहे के ब्रिटेन के भण्डारों के धीरे-धीरे समाप्त होते जाने से उसे कच्चा लोहा स्वीडन, उत्तरी अफ्रीका इत्यादि से मँगाना पड़ता है। दूसरी मुख्य समस्या श्रमिकों की कमी तथा उत्पादन व्यय की अधिकता है। यदि दूसरी समस्या का समाधान हो सका तो भविष्य में दीर्घ काल तक ब्रिटिश इस्पात उद्योग की उन्नति होती रहेगी क्योंकि सस्तर के अनेक नये स्वतन्त्र हुए राष्ट्र औद्योगीकरण की दिशा में प्रयत्नशील हैं।

प्रश्न

1. Estimate the services of Arkwright, Cartwright, Crompton and Kay to the British Industry.
2. Trace the growth and development of the Cotton Textile Industry in England. Why was this industry localised in Lancashire?
3. "The economic history of England can well be interpreted as the story of her coal mining." Discuss this statement.
4. Give a brief account of the historical development of the Iron and Steel of Great Britain. Write a few lines about its present position and examine its future prospects.
5. "Great Britain lost her leadership in one staple industry after another as modern industrialism spread over the world." Discuss.

अध्याय ५

कृषि का विकास

[समावरण आन्दोलन, कृषि ज्ञानि, कृषि ज्ञानि की विशेषताएँ, कृषि ज्ञानि का कृषि पर प्रभाव, आंग्ल कृषि ज्ञानि से भारत के लिए सशक, कृषि ज्ञानि और औद्योगिक ज्ञानि का सम्बन्ध, अन्न कानून, सन् १८५० के बाद ब्रिटिश कृषि की वृद्धि, उत्पादन, सरकारी कृषि नीति, प्रश्न ।]

अठारहवीं शताब्दी के मध्य तक ग्रेट ब्रिटेन की कृषि में जो विकास हुए उनका संक्षिप्त परिचय अध्याय एक और दो में दिया जा चुका है। वस्तुतः १८वीं शताब्दी तक ग्रेट ब्रिटेन एक कृषि प्रधान देश था परन्तु उसके बाद, यद्यपि कृषि में व्यापक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, कृषि गौण व्यवसाय रह गया और ग्रेट ब्रिटेन संसार का महान् औद्योगिक राष्ट्र बन गया।

कृषि की अपेक्षा उद्योग की अधिक उन्नति पर ध्यान देने के अनेक कारण थे। यह सर्वविधि है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयत्न किये जायें तो उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने लगता है जब कि निर्माण व्यवसायों में लागत घटती है। कृषि के क्षेत्र में ब्रिटेन की प्राकृतिक कठिनाइयाँ भी थी— ग्रेट ब्रिटेन की जनसंख्या अधिक थी और भूमि का क्षेत्रफल कम था। दक्षिण-पूर्वी भागों को छोड़कर देश की अधिकांश भूमि कृषि की फसलें उगाने के लिए कम उपयुक्त थी। ब्रिटेन में थमिकों की मजदूरियाँ भी अन्य देशों की अपेक्षा प्रायः अधिक रही हैं। इसके अतिरिक्त यूरोप के कुछ देशों तथा साम्राज्यगत देशों से, कम से कम आरम्भ में, सस्ता अनाज मिल जाने के कारण उसने औद्योगिक विकास की ओर अधिक ध्यान दिया। जैसा कि अन्यत्र बताया जा चुका है ब्रिटेन में औद्योगिक विकास के लिए परिस्थितियाँ भी अनुकूल थी।

सन् १७५० तक की ब्रिटिश कृषि की अवस्था तथा उसके विकास का विवरण अध्याय एक और दो में दिया जा चुका है। सन् १७५० के लगभग आंग्ल कृषि में जो विकास हुए उन्हें कृषि-ज्ञानि कहकर पुकारा जाता है।

कृषि क्रांति की अनेक विशेषताओं में एक प्रमुख विशेषता समावरण आन्दोलन (Enclosure Movement) की प्रगति थी। यहाँ पहले समावरण आन्दोलन के सम्बन्ध में समझ लेना सहायक सिद्ध होगा।

समावरण आन्दोलन (Enclosure Movement)

ब्रिटेन के आर्थिक विकास के इतिहास में जमीन घेरने का आन्दोलन (समावरण आन्दोलन) दो बार हुआ। पहली बार यह तेरहवीं शताब्दी में प्रारम्भ हुआ था जिसका प्रभाव पन्द्रहवीं शताब्दी तक अधिक स्पष्ट नहीं हो पाया था। दूसरी बार यह आन्दोलन अठारहवीं शताब्दी में हुआ जिसे कृषि क्रांति का मज्जा समझा जाता है।

प्रथम बार के भूमि समावरण आन्दोलन के द्वारा खुले खेतों की प्रणाली (open field system) का अन्त हो गया और किसान के ऊपर से सामुदायिक नियन्त्रण हट गया। यह समय मनोरियल प्रणाली के पतन का काल था। इस समय के समावरण आन्दोलन की चार मुख्य बातें थी—

१. बिल्वे हुए खेतों की चकबन्दी और बाड़ा बन्दी ;
२. कृषि योग्य भूमि का पशुचर भूमि की भाँति प्रयोग ;
३. भूमि के प्रति लगाव, अधिक भूमि के ऊपर स्वामित्व पाने के प्रयत्न,
४. व्यर्थ पड़ी हुई भूमि को उपयोग में लाना और संयुक्त अधिकारों (common rights) की समाप्ति।

तेरहवीं शती में प्रारम्भ होते वाले इस आन्दोलन का मुख्य कारण ऊन की बढ़ती हुई माँग थी। अधिकतर कृषि भूमि को पशुचर भूमि में बदल दिया गया क्योंकि कृषि की अपेक्षा भेड़ें पालना अधिक लाभदायक था। इसके अतिरिक्त भेड़ें पालने के काम में कृषि कार्य की अपेक्षा बाहरी मजदूरों की कम आवश्यकता होती थी अतः बढ़ती हुई मजदूरियाँ नहीं देने पड़नी थी। पुराने भू-स्वामियों (manorial lords) ने नये पूँजीवादी ढंग पर अधिकतर कृषि भूमि पर भेड़ें पालना प्रारम्भ कर दिया।

पहले शिकमी काश्तकार (tenant) को गाँव की सम्मिलित भूमि (common land) इस्तेमाल करने का अधिकार था परन्तु अब भूमि-समावरण आन्दोलन के उपरान्त उसका कोई अधिकार नहीं रहा। अतः उन्होंने इस आन्दोलन के विरुद्ध आवाज उठाई।

इस दिशा में कानून पाम किये गये। सन् १२३५ में एक कानून बनाया गया जिसके अनुसार यह स्वीकार किया गया कि भूस्वामी (lord) व्यर्थ जमीनो (waste lands) को निजी अधिकार में ले सकता है परन्तु यह आवश्यक कर दिया गया कि उसे अपने कार्तकारो के लिए पर्याप्त चरागाह छोड़ने पड़ेगे।

लगभग एक शताब्दी तक समावरण आन्दोलन अनुकूल वातावरण में चलता रहा। परन्तु तदुपरान्त जनना में इसके विरुद्ध भावनाएँ उठी और सरकार को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। सन् १४८६ में एक कानून बनाया गया और कृषि भूमि को चरागाह बनाना वर्जित कर दिया गया। सन् १५१४ में एक और एक्ट द्वारा इस उपाय को और भी अधिक दृढ़ कर दिया। सन् १५१७ और सन् १५४८ में इस विषय का अध्ययन करने के लिए आयोग (कमीशन) नियुक्त किये गये। परिणामस्वरूप सन् १५५२, १५५४, १५६२ और १५६२ में नये एक्ट बनाये गये परन्तु सन् १६२४ में उनको रद्द कर दिया गया।

भेड़ पालने के लिए जमीन घेरने के आन्दोलन का विरोध होने का मुख्य कारण निर्धनो की दुर्दशा थी। मजदूरों की माँग कम हो जाने से मजदूरियाँ कम हो गई थी। बेरोजगारी से पीड़ित श्रमिक रोजगार की तलाश में इधर-उधर फिरने लगे। उनकी कहीं पूछ नहीं थी। यदि वे कस्बों में नये विकसित हो रहे उनी वस्त्र उद्योग में काम पाने के लिए जाते तो शिल्प सङ्घ (craft guilds) उन्हें बुरी दृष्टि से देखने थे। इसके अनिश्चित उस समय ऊनी व्यवसाय में भी रोजगार देने की इतनी क्षमता नहीं थी कि कृषि से विस्थापित समस्त लोगो को रोजगार दिया जा सकता। देहात में कोई घन्घा नहीं था। अतः देहातों में शरीर से समर्थ भिखारियों और निर्धनो की संख्या बढ़ने लगी।

यह स्मरणीय है कि यद्यपि समावरण आन्दोलन को काफी महत्व दिया गया और उसका प्रभाव भी गम्भीर पड़ा परन्तु सत्रहवीं शताब्दी के अन्त तक इंग्लैण्ड की आधी भूमि में भी अधिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी पृष्ठभूमि में हम यह समझ सकते हैं कि दूसरी बार समावरण आन्दोलन किस प्रकार आरम्भ हुआ।

दूसरे आन्दोलन का काल १८वीं शती के मध्य में १९वीं शती के मध्य तक (१७५०-१८५०) समझा जाता है। इस समय समावरण आन्दोलन के लिए अनुकूल दशाएँ मुख्यतया निम्नलिखित थी—

(१) ब्रिटिश पार्लियामेण्ट में भूमिशक्तियों का अधिक प्रभाव था और वे भूमि के समावरण में रुचि रखने थे अतः कानून बनाना सरल था,

(२) आदम म्मिथ प्रभृति अर्थशास्त्रियों ने खुले खेतों की प्रणाली के दोषों तथा कृषि की वर्वादी को कम करने की दृष्टि से समावरण आन्दोलन का समर्थन किया,

(३) औद्योगिक क्रान्ति ने ब्रिटेन के निवासियों की आवश्यकताओं और दृष्टिकोण में अन्तर ला दिया था,

(४) कृषि में पूँजी लगाना प्रारम्भ हो गया था; और

(५) आधुनिक वैज्ञानिक कृषि का जन्म हो चुका था जिसके लिए बड़े बड़े खेतों की आवश्यकता होती है।

इन दशाओं का परिणाम यह हुआ कि समावरण आन्दोलन का नया स्वरूप प्रकट हुआ।

इस काल में भी छोटे-छोटे खेतों को बड़े खेतों में बदलने की क्रिया मुख्य थी। औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप ऐसी जनसंख्या अधिक हो गई जो खाद्यान्नों और बच्चे माल के लिए दूरगो पर आश्रित हो गई। यह बड़ी हुई माँग कृषि के पुराने तरीकों में पूरी होना सम्भव नहीं थी। कृषि-मुधार के लिए बड़े खेतों की आवश्यकता थी। छोटे खेतों पर खेती करने वाले बड़े पैमाने की खेती करने वालों की अपेक्षा लाभ भी कम पा सकते थे। नेपोलियन से होने वाले युद्धों के समय (सन् १७९३-१८१५) में कृषि की उपज की कीमतें बहुत बढ़ जाने से छोटे खेत भी चलने लगे।

छोटे-छोटे खेतों का बड़े खेतों में परिवर्तन पहले निजी (प्राइवेट) समझौतों के द्वारा हुआ। पीछे इन समझौतों का पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) माली अदालतों (Courts of the Exchequer) में होने लगा। जिन व्यक्तियों में निजी समझौते होते थे उनमें प्रायः झगड़े हो जाते थे इसलिए पार्लियामेण्ट द्वारा एक्ट (private acts) पास किये गये। इस प्रकार का एक्ट पास करने में पहले पार्लियामेण्ट कुछ कमिशनर (आयुक्त) नियुक्त करती थी जो नये समावरण की सीमा निश्चित करा दें। परन्तु ऐसा करने में और खेतों की सीमा पर दीवाल, भग्निपट्टियाँ इत्यादि लगाने में बहुत व्यय होना था। अतः प्रविधि (procedure) को सरल बनाने के लिए सन् १८०१ में एक सामान्य समावरण कानून (General Enclosure Act) पास किया गया जिसके अनुसार प्राइवेट एक्ट सीधेता और सरलता से पास हो जाते थे, और कुल व्यय में भी कमी हो गई।

सन् १८३६ में एक और एक्ट पास हुआ जिसके द्वारा यह अनावश्यक कर दिया गया कि पार्लियामेण्ट की सहमति ली जाये। यदि दो तिहाई सम्बन्धित व्यक्ति चाहें तो सम्मिलित भूमि (common land) का समावरण कर सकते थे। स्पष्ट है कि सरकार इस आन्दोलन के पूर्णतया पक्ष में थी।

समावरण आन्दोलन का प्रभाव मुख्यतः यह पड़ा कि कृषि श्रमिक का भूमि से सम्बन्ध छूट गया और कृषि का मंगठन आधुनिक पूँजीवादी ढंग पर होने लगा। कृषि में उत्पत्ति और कृषि कला में विकास के रूप में इस आन्दोलन के लाभ मिले परन्तु छोटे किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा। उनकी जमीनें छिन गईं, गाँव में उनको काम नहीं मिलता था, अतः वे विस्थापितों की भाँति रोजगारों की तलाश में नगरों की ओर बढ़े जहाँ प्रारम्भ में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

कृषि-क्रान्ति (Agricultural Revolution)

अठारहवीं शताब्दी के मध्यकाल में जिस समय ब्रिटिश औद्योगिक क्रान्ति की ओर प्रसरण हो रहा था लगभग उसी समय में उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक (१७५०-१८१०) यहाँ की कृषि में आमूल-मूल परिवर्तन हुए जिन्हें कृषि क्रान्ति कहा जाता है।

कारण—ब्रिटिश में कृषि क्रान्ति का जन्म अनेक कारणों से हुआ था। उस समय जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी और देश में खाद्यान्नों का अभाव था जिसके कारण उनकी कीमतें बढ़ रही थी। अतएव एक ओर तो कृषि में सुधार करने और उपज बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन मिला, दूसरी ओर बातावरण भी अनुकूल था। कृषि में सुधार करने और नई विधियों के प्रयोग के लिए डटकर प्रचार किया जा रहा था। पार्लियामेण्ट में भूमिपतियों का जोर था जिसके कारण अन्न कानून और समावरण कानून पास हुए। मुद्रा के प्रचलन में वृद्धि हुई थी और भूस्वामियों का दृष्टिकोण ही बदल गया था। उनका उद्देश्य कृषि से लाभ कमाना प्रमुख हो गया था। पूँजी निर्माण में वृद्धि हुई थी और पूँजीपति कृषि में अधिकाधिक पूँजी विनियोग करने में रुचि ले रहे थे। इस दिशा में तत्कालीन हुए यन्त्रों के आविष्कार और नई पद्धतियों के विकास के कारण सहायता मिली। कृषि और उद्योग अब साथ साथ चलाना सम्भव नहीं रहा था।

संक्षेप में, कृषि उपज की बढ़ती हुई माँग, कानूनी सहायता, पूँजी की

पर्याप्त प्रति, नये आविष्कार और कृषि सुधारको के सबल प्रयत्न कृषि-क्रान्ति के मुख्य कारण थे।

५. कृषि-सुधारक—“नवीन कृषि” की सिफारिश करने वालों में आर्थर यंग, जेम्स जेटल, लांड टाउनशेण्ड, रॉबर्ट बेकवेल तथा टॉमस कोक के नाम अधिक उल्लेखनीय हैं। आर्थर यंग ने अपने नये विचारों को पुस्तकाकार प्रकाशित कराया और एक पत्रिका ‘Annals of Agriculture’ निकाली जिसके द्वारा अपने अनुभवों और विचारों का प्रसार किया। जेम्स जेटल ने बीज बोने के लिए एक नये तरांके ड्रिल (Drill) का आविष्कार किया। उसके पहले बीज हाथ से बाएँ बाएँ बिखेर कर बोए जाते थे, यह प्रणाली मुहत्त से ख़री आ रही थी जिसमें बीज की बर्बादी होती थी और बीज समान रूप में ठीक दूरी पर नहीं गिरता था। ड्रिल के प्रयोग से बीज भूमि में गहराई पर गिरता था, बीज कतार में पड़ता था और कम ख़र्च था तथा पैदावार अच्छी होती थी। जेम्स जेटल ने खेत की गहरी जुताई पर जोर दिया, बीजों के चुनाव की सिफारिश की और बताया कि पौधा की जड़ों में दृढ़ता और अच्छी उपज के लिए बीज दूर-दूर बोना चाहिए। उसने मिट्टी को तोड़कर धीरे-धीरे करना अच्छा बताया और मिट्टी पोला करने के लिए अश्व चालित यंत्र निकाला। पशुओं के लिए चारे की फसलें उगाने पर भी उसने जोर दिया।

लांड टाउनशेण्ड ने एक नोरफोक पद्धति चलाई जिसकी विशेषता यह थी कि भूमि परती नहीं छोड़नी पड़ती थी, भूमि पर फसलें हेर फेर कर उगाई जाती थी जिसके अनुसार अनाज की फसल एक वर्ष छोड़कर बोई जाती थी और बीच के वर्षों में क्लोवर की फसल तथा ख़स-ख़स इत्यादि जइदार फसलें उगाई जाती थी जिनसे पशुओं के लिए चारा भी मिलता था और उर्वरता बनी रहती थी। यह चतुर्वर्षीय हेरफेर (rotation) की पद्धति थी। उसने उपयुक्त खादों पर भी जोर दिया।

रॉबर्ट बेकवेल ने भेड़ों, बैलों तथा अन्य पशुओं की नस्ल सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया जिसके परिणामस्वरूप भेड़ों का मांस और ऊन बढ़ा, गाय के बछड़ों और बैलों का वजन बढ़ा और संक्रामक रोगों में भारी कमी हुई। टॉमस कोक ने आर्थर यंग के विस्तृत अनुभवों और नये विचारों को व्यावहारिक रूप दिया। उसे उत्तराधिकार में होकम की जागीर मिली थी जिसकी अवस्था शोचनीय थी परन्तु उसने मिट्टी को हल्की भुरभुरी बनाने, खादों द्वारा उर्वरता में वृद्धि करने तथा अनेक नये उपायों के प्रयोगों

मे पाँच लाख पौण्ड में अधिक व्यय किये । उसने आसामियों को नए उपाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया । वस्तुतः उमे अपने जीवन में प्रयत्नों का उचित पारितोषिक मिला और उनकी जागीर पश्चिमी यूरोप में आदर्श समझी जाने लगी थी । उसने पशुओं के एक अच्छे चारे का प्रचार किया । उसने दोखम में एक प्रसिद्ध कृषि सम्मेलन बुलाया था ।

कृषि-क्रान्ति की विशेषताएँ II-

कृषि-क्रान्ति की मुख्य विशेषताएँ निम्नांकित थी —

कृषि में पूँजी का अधिकाधिक विनियोग—कृषि-क्रान्ति की मुख्य विशेषता यह थी कि कृषि में पूँजी का विनियोग बढ़ा । १८वीं सताब्दी में भूमि-स्वामिन्स का इंग्लैण्ड में काफी सामाजिक प्रतिष्ठा मिली । अतः बड़े व्यापारियों ने काफी भूमि खरीदी । इन व्यापारियों के पास साधनों की कमी नहीं थी । इन साधनों का प्रयोग उन्होंने भूमि की उर्वरता बढ़ाने, नई फसलें उगाने तथा नये वैज्ञानिक तरीकों के लिए किया ।

(२) गाँवों की अधिकतर जमीन छोटे छोटे कृषकों और भू-स्वामियों के हाथों से निकलकर बड़े जमींदारों (landlords) के हाथों में जाने लगी । इसका मुख्य कारण यह था कि छोटे किसान बड़े जमींदारों की स्पर्धा का मुकाबला न कर सकें और अपनी भूमि उन्हें बेचन को बाध्य हुए । पुराने भू-स्वामी परिवारों में नये पूँजीपति-कृषकों के विवाहों का भी सम-दिशाई प्रभाव पड़ा । परिणाम यह हुआ कि खेत बड़े बड़े होने लगे । सन् १८४५ में इंग्लैण्ड में खेत बहुत बड़े बड़े बन चुके थे । नेपोलियन के युद्धों, अन्न की भाँग बढ़ने, इत्यादि में किसानों में कृषि का भी यही प्रभाव हुआ ।

(३) समावरण आन्दोलन (Enclosure Movement)—आग्ल कृषि-क्रान्ति का तीसरा मुख्य पहलू जमीन घेरने के आन्दोलन का दुबारा जोर पकड़ना था । इसका प्रभाव भी यही पड़ा कि खेत बड़े-बड़े हुए । खुले खेतों की प्रथा समाप्त हो गई । आदम निम्न प्रभृति अनेक व्यंशस्थितियों ने खुले-विखरे और छोटे खेतों से होने वाली वर्षा-पानी को रोकने के लिए जमीन घेरने के आन्दोलन की विफारिश की । पार्लियामेण्ट में बड़े भूमिपतियों का प्रभाव होने के कारण कानून भी पास हो गये ।

यद्यपि जमीन घेरने के तरीकों में अन्तर था परन्तु प्रारम्भ में इस आन्दोलन की दो मुख्य विशेषताएँ थी : (१) कुल प्रभावित भूमि के ८० प्रतिशत मूल्य के भाग के स्वामियों की सहमति होनी आवश्यक थी तथा (२) पार्लियामेण्ट

द्वारा विशेष कानून पास किया जाना चाहिए था। सन् १८०१ में इस दिशा में कुछ और सरलता कर दी गई। सन् १८४५ में General Enclosure Act द्वारा Enclosure Commissioners समावरण आयुक्तों का एक बोर्ड बना दिया गया जिसको अधिकार दिया गया कि वह प्रस्तावित समावरणों के सम्बन्ध में निर्णय दे। इस बोर्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लागत कम करना तथा क्षीघ्रता में कार्य सम्पन्न सम्भव करना था। सन् १७०० से १७६० तक के समय में ३,१२,००० एकड़ जमीन घेरी गई जबकि सन् १७६० से १८४० ई० तक की अवधि में ५५ लाख एकड़ के लगभग भूमि घेरी गई।

(४) कृषि कला में सुधार—कृषि क्रान्ति की चौथी प्रमुख विशेषता यह थी कि कृषि कला में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए। सन् १७६० के पश्चात् मूल्यों में वृद्धि से इस दिशा में विशेष प्रोत्साहन मिला। औद्योगिक क्रान्ति के कारण नये नगरों का विकास हो रहा था जिनमें बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन-सामग्री की माँग बढ़ रही थी। अतएव नये तरीकों का प्रयोग हुआ : (क) सन् १८०० में नये मॉडल का हल काम में लाया गया। इसी समय घोड़े से चलने वाली घनाज निकालने की Threshing मशीन का प्रयोग प्रारम्भ हुआ। अन्य यन्त्र काम में आने लगे। (ख) कृषि कला में सुधारों का विवेचन करने और नये उपयोगी उपायों का प्रचार करने के लिए कृषि-संगठन स्थापित हुए। इनमें विशेष उल्लेखनीय संस्थाएँ सन् १८१८ में स्थापित शाही कृषि समिति (Royal Agriculture Society) और दूसरी सन् १८४२ में स्थापित कृषि रसायन साहचर्य (Agricultural Chemistry Association) थी जिनका सराहनीय कार्य रहा। (ग) व्यर्थ पड़ी हुई (waste land) तथा इसदली भूमियों को कृषि योग्य बनाने (reclamation) के प्रयत्न किये गये। (घ) कृषि में फसलें बदलकर बोलने (rotation of crops) की पद्धति प्रारम्भ की गई जिसके अनुसार, उदाहरणार्थ प्रत्येक चार वर्ष के समय में बारी बारी से गेहूँ, जौ, जई, राई, कानू, इत्यादि उगाए जायें। (ङ) भूमि की उर्वरता बढ़ाने तथा चारे की दृष्टि में शलजम जैसी फसलों की खेती में वृद्धि की गई।

(५) कृषि में व्यवसायीकरण (commercialisation) तथा विसिष्टीकरण (specialisation) की प्रवृत्ति बढ़ी।

(६) पशुओं की नस्ल सुधार के लिए भी वैज्ञानिक और नए तरीके अपनाये गये तथा पशु-प्रदर्शिनियाँ संगठित की गईं।

(७) दुग्ध व्यवसाय (Dairy Farming) और शाक-फल तरकारियों को खेती (Horticulture) का विकास हुआ। इस प्रकार कृषि का बहुमुखी विकास हुआ।

कृषि क्रान्ति का कृषकों पर प्रभाव ।

कृषि क्रान्ति का राष्ट्र को समूची अर्थ व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा। सामान्यतया कृषि-क्रान्ति द्वारा हुए परिवर्तन देश के हित में समझे जाते हैं परन्तु सन्नान्ति काल (transition period) में कई कठिनाइयाँ उत्पन्न हुईं। कृषकों पर मुख्यतः प्रयोजित प्रभाव पड़े :—

१. छोटे-छोटे किसानों को कृषि से हटना पड़ा। पूँजीपति व्यापारियों ने बड़े बड़े खेत खरीद लिए और कृषि सुधार किये तो उनकी स्पर्धा में छोटे किसान ठहर न सके। उन्हें बड़े बड़े नये भू स्वामियों को अपने खेत बेचने को बाध्य होना पड़ा।

२. कृषकों और कृषि-श्रमिकों को सहायक ग्रामोद्योगों में श्रम काम न मिलने में उन्हें गाँव छोड़ना पड़ा क्योंकि उद्योगों की घरेलू प्रणाली टूट रही थी, और श्रमिकों से कारखानों में ही काम कराना आरम्भ हो चुका था। किसान अब कृषि कार्य के साथ अन्य धन्धे नहीं चला सकता था।

३. कृषि में यन्त्रों के प्रयोग के कारण रोजगार देने की क्षमता कम हो गई थी और ग्राम निवासियों को रोजगार की तलाश में कस्बों और नगरों में भटकना पड़ा जिन्हें पहले कृषि में काम मिल जाता था।

४. समावरण आन्दोलन के पश्चात् गाँव के छोटे किसानों को जलाने के ईंधन और पशुओं के लिए चारे की तंगी हो गई।

५. ग्रॉग तथा शार्प लेखकों ने लिखा है कि कृषि क्रान्ति के परिणामस्वरूप किसानों के तीन वर्ग हो गये : भू स्वामी (landed proprietors) जिनके पास बड़े बड़े खेत थे परन्तु वे स्वयं खेती का कार्य नहीं करते थे, लगान पर अन्य कृषकों को जोतने के लिए दे देने थे। द्रव्य के अधिक प्रचलन तथा लगान नगदी में देने की प्रथा के विकास से यह सम्भव हो गया था। वे भू-स्वामी प्रायः गाँवों में नहीं रहते थे; (ख) कृषक (farmers) जो भूमि के स्वामी नहीं होते थे वरन् लगान पर भूमि लेकर पूँजीवादी पद्धति पर लाभ के लिए उद्योगों की भाँति साहसों का कार्य करते थे; तथा (ग) तीसरे वर्ग में वे कृषि श्रमिक थे जो न तो भूमि के स्वामी थे और न ही व्यवस्थापक, वे मजदूरों लेकर कार्य

करते थे। बेगार प्रथा समाप्त हो गई थी और मजदूरी द्रव्य में देने की प्रथा प्रारम्भ हो गई थी। ये तीन बर्ग अब भी पाये जाते हैं।

६. जिन छोटे किसानों का रोजगार छिना उन्हें अवश्य कठिनाई हुई परन्तु धन्य कृषकों और कृषि श्रमिकों को दशा सुधरी क्योंकि कृषि कला में विकास होने तथा उपज के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण उन्हें पहले की अपेक्षा अधिक आय होने लगी थी।

आगम कृषि-क्रान्ति से भारत के लिए सबक

यद्यपि इंग्लैण्ड की नत्कालीन तथा भारत की आधुनिक परिस्थितियों में हमें स्पष्ट अन्तर समझना पड़ेगा तथापि हम आगम कृषि-क्रान्ति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वस्तुतः इस दिशा में भारत पहले ही सही मार्ग पर चलने का प्रयत्न कर रहा है।

एक ओर भारत को विकास की अनेकों योजनाओं के लिए काफी मात्रा में विदेशी विनिमय की आवश्यकता है, दूसरी ओर स्वाश्रय के कारण हमें भारी मात्रा में अन्न का आयात करना पड़ता है। भोजन की कमी भारत की स्थायी समस्या बन गई है। खाद्यान्नों के ऊँचे मूल्य और भुखमरी इसके प्रमाण हैं। कई उद्योगों के लिए हम पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल भी नहीं उगा पाते और इसलिये हमें कच्चे माल का आयात करना पड़ता है। पोषण की दृष्टि से भी भारतीय कृषि की उपज बहुत पीछे है।

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है आगम कृषि क्रान्ति की विशेषताओं में मुख्य (क) पूँजी का विनियोग, (ख) कृषि कला में सुधार (ग) जेतों का बड़ा किया जाना, इत्यादि थी। भारतवर्ष में भी अर्थ व्यवस्था के सर्वाङ्गीण विकास की दृष्टि में कृषि सुधार के इन पहलुओं पर ध्यान दिया जाना परमावश्यक है।

भारत में कृषि के लिए वित्त के पर्याप्त साधन मुसम नहीं हैं। भारत में भूमि दण्डक बँकों और साख सहकारिता का विकास अभी तक प्रारम्भिक अवस्था में है। ब्रिटिश ढंग की पूँजीवादी कृषि पद्धति की भारतीय कृषि के लिए सिफारिश करना तो उचित प्रतीत नहीं होता परन्तु वित्त के पर्याप्त साधनों तथा पूँजी के विनियोग की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी।

टंकनिक की दृष्टि से भारतीय कृषि बहुत पिछड़ी अवस्था में है, जिसमें रखकर हम अपनी अर्थ व्यवस्था को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। शताब्दियों पुराने हमारे हल और दुबल बैल हमें पुरानी लीक पर

घसीटे चल रहे हैं। ट्रैक्टरों तथा समकक्ष यंत्रों का प्रयोग भारत की वर्तमान अवस्था में विवादग्रस्त है, परन्तु यह कहना अनुचित न होगा कि हमें अपने तरीकों में घोर औजारों में सुधार करना आवश्यक है। खादों, अच्छे बीजों, सिंचाई, खेतों की रखवाली, फसलों को बदलकर बोने (crop rotation), मिली जुली फसलें बोने (mixed crops) भूमि-संरक्षक इत्यादि की ओर हमारा ध्यान अवश्य जाना चाहिए। कृषि में विविधता, चारे की फसलें उगाने तथा पशुधर्मों के नष्ट सुधार की दशा में हमारे प्रयत्न ठोस और जोरदार होने चाहिए।

आर्थिक इकाइयों के अभाव में कृषि में सुधार करना और पूँजी का विनियोग करना निरर्थक है। इसके लिए भी हमें ब्रिटेन के तरीके तो नहीं परन्तु अपनी परिस्थितियों के अनुकूल उपाय अपनाने होंगे।

यह उल्लेख करना अनुचित न होगा कि भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त जनप्रिय सरकार ने उपयुक्त दिशामें योजनाबद्ध कार्यक्रम द्वारा पर्याप्त प्रगति करने के प्रयत्न किये हैं। ये प्रयत्न तृतीय योजना में तथा आगे भी जारी रहेंगे।

कृषि-क्रान्ति और औद्योगिक क्रान्ति का सम्बन्ध

औद्योगिक विकास के बिना ब्रिटेन में कृषि पशुओं का प्रयोग सम्भव न था। औद्योगिक क्रान्ति के साथ ब्रिटेन में नये नगरों का विकास हुआ और उनमें जनसंख्या बढ़ी, इसलिए खाद-पदार्थों की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए कृषि का विकास आवश्यक था। कच्चे माल के उत्पादन की दृष्टि से भी यह आवश्यक था। औद्योगिक क्रान्ति के कारण घरेलू प्रणाली समाप्त हो गई, छोटे किसानों की आय के सहायक साधन समाप्त होने के कारण वे गाँव छोड़कर नगरों में चले गये। यह कृषि-क्रान्ति और औद्योगिक विकास दोनों दृष्टियों में अनुकूल रहा।

कृषि-क्रान्ति के कारण गाँवों में लोगों की आयें बढ़ी और उनका जीवन-स्तर ऊँचा उठा जिसमें उद्योग निर्मित वस्तुओं (manufactured goods) की भी माँग बढ़ी और उद्योगों के विकास में अनुत्पत्ति हुई। औद्योगिक क्रान्ति ने कृषि क्रान्ति के लिए अनुकूल वातावरण और माधन उत्पन्न किये थे और कृषि-क्रान्ति औद्योगिक क्रान्ति के लिए न केवल सहायक वस्तु आवश्यक थी।

अन्न कानून (Corn Laws)

ब्रिटेन की कृषि के विकास तथा कृषि नीति के सम्बन्ध में अन्न-कानून का उत्प्रेष प्रासंगिक है। अन्न व्यापार का नियमन (regulation) इंग्लैण्ड

मे चौदहवीं शताब्दी से ही होता आ रहा था। सन् १६८६ में अन्न के निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से Corn Bounty Act (अन्न सहायता कानून) पास किया गया। जब जनसंख्या में वृद्धि हुई तो इस नीति में संशोधन करना पड़ा। यह समझा गया कि देश में अर्पयित उत्पादन के कास में अन्न के आयात को प्रोत्साहन दिया जाय तथा निर्यात को हतोत्साहित किया जाय। यह विचार सन् १७७३ से उठा आ तथा १७९३ तक अन्न के निर्यात पूर्णतया समाप्त हो गये।

नेपोलियन युद्धों के समय ब्रिटेन में अन्न का आयात सम्भव न हो सका। विदेशों में अन्न न मिलने के कारण अपनी पूरी माँग ब्रिटेन की अपने ही उत्पादन में पूरी करनी पड़ी। फलस्वरूप अन्न की कीमतें बहुत ऊँची हो गईं और यह स्थायी नक्शान प्रतीत होने लगा था। सन् १८१५ में नेपोलियन-युद्ध समाप्त होने अर्थात् शान्ति लौटने पर विदेशी अनाज के आयात की सम्भावना के कारण ब्रिटेन में अन्न की कीमतें गिरी। भूमिपतियों ने संरक्षण के लिए पार्लियामेंट में अर्पण की। सन् १८१५ में प्रसिद्ध "Corn Law" (अन्न कानून) पास हुआ। इस कानून के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि देश में अन्न का आयात तभी किया जाएगा जब इंग्लैण्ड के बाजार में गेहूँ का मूल्य ८० शिलिंग प्रति क्वार्टर हो जाए। इसी प्रकार राई, ज्वार, जई के मूल्य-सोमाएँ क्रमशः ५३ शिलिंग, ४० शिलिंग और २६ शिलिंग प्रति क्वार्टर निश्चित की गई। सन् १८१५ में गेहूँ का भाव ६१ शिलिंग प्रति क्वार्टर था। स्पष्ट है कि सन् १८१५ के 'अन्न कानून' का मुख्य दृष्टिकोण अन्न उत्पादकों को संरक्षण देने का था।

सन् १८१५ के अन्न कानून की कटु आलोचना हुई। इस ऐक्ट के मुख्यतया अधोलिखित दोष बताए गये :—

(१) यह कानून केवल एक वर्ग के हितों के लिए था। हमारे भूमिपतियों के अतिरिक्त अन्य लोगों तथा राष्ट्र के हितों का विचार नहीं रखा गया था। ऊँची कीमतें और निम्न जीवन स्तर भूस्वामियों के सिवाय सभी लोगों पर यही प्रभाव पड़ा।

(२) आयात करने के प्रयत्न उस समय किये जाते थे जब अन्न की कीमतें बहुत ऊँची हो जाती और आयात होने के समय तक अभाव की दशाएँ समाप्त हो चुकती।

(३) इस एक्ट के द्वारा यह उद्देश्य प्राप्त करने में भी सफलता प्राप्त

करना सम्भव नहीं था कि यूनाइटेड किंगडम अन्न में स्वावलम्बी हो जाय क्योंकि अन्न के मूल्यों में बहुत उच्चावचन हुए ।

(४) ब्रिटेन के व्यापारिक सम्बन्धों को भी ठेस पहुँची क्योंकि कई देशों से भोजन सामग्री मँगाकर बदले में उन्हें निमित्त वस्तुएँ (manufactured goods) बेचना सम्भव नहीं रहा ।

इन दोषों के कारण तथा इन आघातों पर सन् १८१५ के अन्न कानून को रद्द करने की माँग की गई । सन् १८२१ में लॉर्ड्स तथा कॉमन्स (Lords and Commons) की जाँच कमेटी ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि अन्न कानून में इसका विश्वास डिग गया था ।”

सन् १८२२ में संशोधित अन्न कानून पास हुआ जिसके अनुसार, गेहूँ, राई, ज्वार, जई के न्यूनतम मूल्य क्रमशः ७० शिलिंग, ४६ शिलिंग, ३५ शिलिंग और २५ शिलिंग प्रति क्वार्टर निश्चित किये गये तथा घटती हुई दर (sliding scale) पर आयात कर लगाये गये । उदाहरणार्थ, इसके अन्तर्गत ब्रिटेन में गेहूँ का भाव ६४ शिलिंग प्रति क्वार्टर से कम होने पर आयात कर २५ शि० ८ पेंस; ६४ शिलिंग से ६६ शिलिंग तक भाव होने पर १६ शिलिंग ८ पेंस तथा ७३ शिलिंग प्रति क्वार्टर से ऊपर होने पर केवल एक शिलिंग प्रति क्वार्टर आयात कर लगाया गया । इन आयात करों का उद्देश्य अन्न के आयात को पूर्णतया रोकना नहीं था बल्कि आवश्यकतानुसार आयात होने देना था तथापि ब्रिटेन में अन्न के मूल्यों में स्थिरता न आ सके ।

सन् १८३८ में संकाशायर के उद्योगपतियों के एक दल ने अनाज अधिनियम विरोधी संघ (Anti Corn Law League) स्थापित किया जिसकी घोषणा जनवरी १८३६ में की गई । एक पत्रिका 'Anti Corn Law Circular' भी निकाली गई तथा अन्न कानून विरोधी सभाओं, जुलूसों और भाषणों का देश भर में आयोजन किया गया । इसी उद्देश्य की नब्बे लाख से अधिक पुस्तिकाएँ चार वर्ष की अवधि में विनिरित की गईं । रिचार्ड कॉवडन, जॉन ब्राइट तथा चार्ल्स डिवियर्स इस आन्दोलन के प्रमुख नेता थे । इनका विश्वास था कि अनाज के स्वतन्त्र आयात में अनाज मस्ता होगा, मजदूरियाँ कम होंगी (क्योंकि सस्ते अनाज का अर्थ था कम जीवन-निर्वाह-व्यय), लागत कम होने में मस्ता निर्मित माल तैयार होने के कारण उद्योगपतियों की

प्रतिस्पर्धी-शक्ति बढ़ेगी और संसार के सब भागों में ब्रिटिश निर्मित माल की बिक्री की जा सकेगी ।

सन् १८४१ में रिचार्ड कॉब्डन पार्लियामेण्ट का सदस्य चुना गया तथापि बहुमत संरक्षणवादियों का था । अतः सन् १८४५ तक यो ही चलता रहा । सन् १८४४ और सन् १८४५ में प्रकालों के कारण खाद्य समस्या और भी जटिल हो गई । रॉबर्ट पोल, तत्कालीन प्रधान मंत्री, हठधर्मी नहीं था । उसने कहा कि अन्न कानून देश के लिए उसी समय तक हित में था जब तक अनाज का देशीय उत्पादन ब्रिटेन की जनसंख्या के लिए पर्याप्त था । उसने अन्न-कानून रद्द (repeal) करने का सुझाव रखा । पार्लियामेण्ट ने इसे मान लिया । सन् १८४६ में आयात कर की दर बहुत कम कर दी गई । १ फरवरी १८४६ से अन्न के आयात पर कर केवल एक शिलिंग प्रति क्वार्टर अर्थात् नाममात्र का रह गया और सन् १८६६ में वह भी हटाकर अनाज का आयात कर-मुक्त कर दिया गया ।

९ सन् १८५० के पश्चात् ब्रिटिश कृषि की दशा

सन् १८५० तक के सौ वर्षों में कृषिगत परिवर्तनों को कृषि-क्रान्ति के अन्तर्गत बताया जा चुका है । सन् १८४६ में ब्रिटेन में अन्न के आयात पर नाममात्र का कर रह गया था । इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ब्रिटेन में अन्न के आयात में वृद्धि होने अथवा उसकी सम्भावना से अन्न की कीमतें गिरेंगी परन्तु अन्न कानून रद्द हो जाने पर भी न तो आयात में वृद्धि हुई और न खाद्यान्न सस्ते हुए । इसके कई कारण थे : (क) उस समय तक संसार के किसी भी देश में गेहूँ इत्यादि खाद्यान्नों की बिक्री-योग्य इतनी अधिकता नहीं थी जिससे ब्रिटेन की मंडियों में अनाज की कीमतों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता, (ख) अमेरिका में देशीय यातायात तथा अमेरिका से ब्रिटेन तक के समुद्री परिवहन का पर्याप्त विकास नहीं हुआ था कि वहाँ की उपज को ब्रिटेन में शीघ्र पहुँचाया जा सकता, (ग) इसके अतिरिक्त समीपवर्ती यूरोपीय अनाज उत्पादक देशों में भी अन्न ढोने का खर्च सामान्यतया संरक्षण कर के बराबर सा था, तथा (घ) ब्रिटेन में कृषि के घन्धे में लगी हुई जनसंख्या में कमी हो रही थी परन्तु नये और विकसित औद्योगिक नगरों में जनसंख्या बढ़ रही थी जिसके कारण अन्न की माँग बढ़ रही थी । जनता की श्रम शक्ति भी बढ़ी थी ।

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से (सन् १८५० से) सन् १८७५ तक का समय ब्रिटिश कृषि के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है क्योंकि इस काल में कृषि का बहुमुखी विकास हुआ। आस्ट्रेलिया और कैलीफोर्निया में स्वर्ण की खोज, इत्यादि परिस्थितियों का कृषि उत्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। अनाज की मांग में निरन्तर वृद्धि हुई परन्तु ब्रिटिश कृषि उस समय इस बड़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए समर्थ नहीं रही।

सन् १८५० में १८७५ तक की अवधि में ब्रिटिश कृषि की उन्नति के मुख्य कारण ये थे :—

(१) देश में रसायनिक खादों का उत्पादन बहुत बढ़ा। उनके उपयोग से कृषि की उपज में वृद्धि हुई। कृषि रसायन शास्त्र में विकास हुआ था और उसके परिणामों का ब्रिटिश कृषि ने लाभ उठाया ;

(२) समाधारण आन्दोलन के फलस्वरूप खेत बड़े बड़े हो गये थे जिसका छोटे किसानों पर तो बुरा प्रभाव पड़ा परन्तु वैज्ञानिक कृषि का मार्ग खुल गया था ;

(३) कृषि के लिए पूँजी की कमी नहीं थी और नये नये कृषि यन्त्रों के अनुसन्धान होने से कृषि में श्रम की लागत कम करने के प्रयोग हुए ;

(४) कृषि-उपज की कीमतों में स्थिरता रही ;

(५) कृषि में अच्छा लाभ होने के कारण कृषि श्रमिकों के वेतन भी बढ़े, वस्तुतः सभी उद्योगों में मजदूरियाँ बढ़ रही थी ;

(६) कृषि के विकास का एक महत्वपूर्ण कारण रेलों का विकास था जिससे उपज को दूर की मंडियों में पहुँचाना, खाद मँगाना, बीज खरीदना इत्यादि सम्भव हो गया ;

(७) पशुधों को नस्ल सुधार से कृषि में दुग्ध उत्पादन, भेड़-पालन, मुर्गी पालन इत्यादि कृषि शाखाओं में भी उन्नति हुई ,

(८) राही कृषि समिति (Royal Agriculture Society) तथा प्रांतीय कृषि समितियों ने अनुसन्धान, कृषि पद्धतियों के विकास, सूचना प्रसार इत्यादि के द्वारा कृषि को अनेक लाभ पहुँचाए ; तथा

(९) कृषि प्रदर्शनियों और उपज प्रतियोगिताओं के आयोजनों का भी कृषि पर स्वस्थ प्रभाव पड़ा।

इस काल में यद्यपि छोटे किसानों को गाँव छोड़कर नगरों में विस्थापितों की भाँति रोजगार की तलाश में फिरना पड़ा परन्तु सामान्यतया रोजगार के

साधनों में वृद्धि हुई। उद्योगों और सहायक उद्योगों के अतिरिक्त रेलवे और इमारतों के निर्माण तथा सम्बन्धित धन्यों में धमिकों की माँग बढ़ी। यह सत्य है कि उद्योगपतियों और भूस्वामियों को जितने अधिक लाभ हुए, कृषि धमिकों को उसका एक अत्यल्प अंश ही मिला और मजदूरियों में वृद्धि बहुत धीमी गति से हुई, परन्तु देश की समृद्धि का लाभ सामान्यतया सभी को प्राप्त हुआ। इस काल में ब्रिटेन कृषि-उत्पादन में मुख्यतया स्वावलम्बी था।

नवी का काल (१८७४-१९१४)—उन्नीसवीं शताब्दी का अन्तिम, चतुर्थांश ब्रिटिश कृषि में घोर सकट का समय था। इस काल में एक घोर तो कृषि उपज के मूल्यों में भारी गिरावट हुई, दूसरी ओर अकाल और महामारियों के कारण कृषि का उत्पादन घटा। इसके अतिरिक्त कृषि भूमि के लगान में भी घोर कई बार भूमि परती पड़ी रह जाती थी, कृषि धमिक अधिक मजदूरियों की माँग कर रहे थे जबकि भूस्वामियों को भारी हानि हो रही थी—भू-स्वामियों और कृषि-धमिकों के झगड़ों का परिणाम प्रायः यह होता कि कृषि का काम पड़ा रहता।

कृषि उपज की कीमतों में तेजी के साथ गिरावट इस काल की प्रमुख विशेषता थी। सन् १८७७ में गेहूँ का भाव प्रति बर्गार्डर ५० शिलिंग से अधिक था, सन् १८८५ में ३२ शिलिंग और सन् १८९४ में १७ शिलिंग ४ पेंस तक पहुँच गया। मूल्यों में गिरावट के मुख्य कारण निम्नलिखित थे :—

१. 'समुद्रपार की नई भूमियों (virgin lands) की सस्ती उपज में ब्रिटिश बाजारों में अन्न के भाव गिरा दिये। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में गेहूँ का उत्पादन बहुत बढ़ा। इन देशों में बमने वाली जनसंख्या भीतरी क्षेत्रों में फैलकर खाली पड़ी हुई भूमि पर कृषि करने लगी थी।

२. सभी देशों में आन्तरिक यातायात का विकास हुआ था रेल मार्गों और महाद्वीपीय रेलों के विकास से अनाज का व्यापार बढ़ा। सन् १८८५ में कनाडियन पैसिफिक रेलवे बन जाने में अमेरिका के उपजाऊ मैदानों का गेहूँ ब्रिटेन को भेजना सम्भव हो गया था। परिवहन की सुविधाएँ सस्ती थी और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जहाज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। रूस, भारत, आस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से आयात होने वाले खाद्यान्न भी ब्रिटेन में बहुत सस्ते पड़ते थे।

३. इसी काल में स्वर्ण की खपत चाँदी के मूल्य गिर जाने से चाँदी

के सिवमे वाले (रजतमान) देशों का माल ब्रिटेन में बहुत सस्ता पडने लगा । उदाहरण के लिए भारतीय रप्प का स्टर्निंग मूल्य (विनिमय दर) गिर जाने से भारत के निर्यातक व्यापारियों को लाभ हुआ क्योंकि भारतीय अनाज ब्रिटेन में पहले की अपेक्षा सस्ता पडने के कारण अधिक खरीदा गया ।

४. सन् १८६६ में ब्रिटेन में अनाज का आयात कर मुक्त किया जा चुका था जबकि अन्य दवा में आयात कर लगे हुए थे, अतः सस्ते विदेशी गेहूँ की मांग बाजारों में भरमार हो गई ।

५. इस काल में प्रशानन विधि (refrigerating process) का विकास होने से दूरवर्ती देशों से जमाया हुआ गोश्त, डिब्बा में बन्द किए हुए मांस, मछलियाँ, सब्जियाँ, पनीर, फल इत्यादि ब्रिटेन में आयात होने लगे । प्रमुख निर्यातक देश न्यूजीलैण्ड, अर्जेंटीना और संयुक्त राज्य अमेरिका थे ।

इन कारणों से ब्रिटेन के कृषक एक तो यों ही घाटे में रहे परन्तु इसके साथ ही प्राकृतिक प्रकोपों ने कठिनाइयाँ और बढ़ा दी । सन् १८७५ से सन् १८८४ तक शीत और प्रति वर्षा के कारण फसलों को भारी हानि हुई और तदनन्तर अनावृष्टि (सूखा) के कारण फसलें अच्छी नहीं हुईं । इसी अवधि में पशुओं की बीमारियों और सक्रामक रोगों के कारण पशु-धन के नाश से पशुपालकों को भारी हानि हुई । परिणाम यह हुआ कि किसान कृषि में पूँजी हटाने लगे, वे गाँव छोड़कर नगरों की ओर जाने लगे । बहुत से कृषि-अधिक आस्ट्रेलिया और कनाडा इत्यादि देशों में जा बसे ।

१९वीं शताब्दी के अन्तिम चतुर्थांश की कठिनाइयों ने कृषि के स्वभाव पर गम्भीर प्रभाव डाला । ब्रिटेन की कृषि को बदलनी हुई दशाओं के अनुकूल होना पड़ा । कृषि में अनाज की फसलों के उत्पादन की प्रधानता के बजाय पशु-पालन और पशुओं से मिलने वाले पदार्थों के उत्पादन पर तथा फसलों में शाक-तरकारियों और फलों के उत्पादन पर अधिक ध्यान दिया गया । दूध और अंडों के उत्पादन तथा धूँकर-पालन में वृद्धि की गई ।

प्रथम महायुद्ध काल के वर्षों की छोड़कर जिनमें युद्धकालीन व्यवस्था के अन्तर्गत कृषि उत्पादन की ओर अधिक ध्यान दिया गया, सन् १८७२ से १९१६ तक ब्रिटेन का कृषि-क्षेत्रफल निरन्तर घटता गया ।^१ इस समस्त काल में ब्रिटेन में मुर्गीपालन तथा मांस और दुग्ध उत्पादन के घन्चों को आयात किए हुए खाद्य पदार्थों (feeding stuffs), चारे इत्यादि पर निर्भर रहना पड़ा ।

द्वितीय विश्वयुद्ध (१९३९) छिड़ जाने पर ब्रिटिश कृषि में परिवर्तन हुए। कारण यह था कि प्रथम युद्ध काल की भांति युद्ध छिड़ जाने पर जहाजों की कमी के कारण आयात करना बठिन हो गया और जनसंख्या के उपभोग के लिए देश में ही फसलों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता हुई। अतः ब्रिटेन में गेहूँ और आलू इत्यादि का उत्पादन बढ़ाया गया जिसके कारण दुग्ध के अतिरिक्त पशुओं से मिलने वाले अन्य पदार्थों (ऊन इत्यादि) के उत्पादन की तथा पशुपालन की उपेक्षा हुई। युद्धोत्तर काल में विद्वब्ध्यापी खाद्याभाव की समस्या अनुभव हुई और ब्रिटेन के सम्मुख भुगतान सतुलन (balance of payments) की विकट समस्याएँ थी। अतः ब्रिटेन के लिए यह आवश्यक हो गया कि देश में अनाज का उत्पादन बढ़ी हुई दर पर चालू रहे। सन् १९४७ के उपरान्त अनाज तथा अन्य फसलों के उच्च स्तरीय उत्पादन के साथ ही पशुओं (livestock) और उनसे मिलने वाले पदार्थों (livestock products), जैसे माँस, दूध, अंडों तथा पशुओं के लिए भोज्य पदार्थों (feeding stuffs) के उत्पादन को प्रोत्साहन मिला है।

उत्पादन

द्वितीय विश्व-युद्ध के पूर्व ब्रिटेन अपनी भोजन सम्बन्धी आवश्यकताओं का लगभग ३१ प्रतिशत ही उत्पादन करता था।^१ सन् १९५७ में यह बढ़कर ४० प्रतिशत के लगभग हो गया। मूल्य की दृष्टि से युद्ध के पूर्व उत्पादन कुल आवश्यकताओं का एक तिहाई में कुछ अधिक था जबकि सन् १९५७ में पचास प्रतिशत के लगभग हो गया। युद्ध के पूर्व भोजन और पशुओं के भोज्यपदार्थों के आयात (तिलों और तिलहनो को सम्मिलित करके) कुल आयातों के ४५ प्रतिशत थे, सन् १९५७ में ये ३८ प्रतिशत थे।

युद्ध (१९३९) के पश्चात् ब्रिटेन में मुख्य कृषि पदार्थों के उत्पादन का रुझान (trend) अगले पृष्ठ की तालिका से समझा जा सकता है।

यद्यपि युद्धकाल (१९३९) से कृषि में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या धीरे धीरे घटती गई, ब्रिटेन के कृषि उत्पादन में युद्ध-पूर्वकाल की अपेक्षा १९५६-५७ तक ६० प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई। दक्षिण-उत्प्रेषण में बहुत वृद्धि हुई है। उत्पादकता की वृद्धि में सहायक मुख्य कारण ये रहे हैं :

तालिका—यूनाइटेड किंगडम में कृषि उत्पादन
(वर्ष १ जून से ३१ मई तक)

उपज	इकाई	युद्ध-पूर्व काल का औसत		
		१९४६-४७	१९४६-४७	१९५६-५७
		१९३६-३८		
फसलों का उत्पादन				
गेहूँ	हजार टन	१,६५१	१,६६७	२,८४५
राई (Rye)	"	१०	३६	२५
जौ	"	७६५	८,६६३	२,८००
जई	"	१,६४०	२,६०३	२,४८६
मिश्रित अनाज	"	७६	३५०	४०७
धान	"	४,८७३	१०,१६६	७,५३३
शुक्लंदर	"	२,७४१	४,५२२	५,१६६
पशुओं से मिलने वाले पदार्थ:				
दूध	लाख गैलन	१५,६३०	१६,६५०	२३,५६०
अण्डे	हजार टन	३८५	३२२	६२८
ऊन	"	३४	२७	३१
गोश्त	"	१,२०८	८८६	१,६८७

(१) फसलों और पशुओं की किस्मों में सुधार, (२) उर्वरकों (fertilisers) का अधिकाधिक उपयोग, (३) फसलों के बीड़ों और बीमारियों के लिए नाशक पदार्थों का प्रयोग, (४) सुघरे हुए और अधिक यन्त्रों का कृषि में उपयोग, जिसके कारण थोड़ी कृषि जनसंख्या अधिक कृषि योग्य भूमि पर खेती कर सकी है। सन् १९२५ में यूनाइटेड किंगडम में ट्रैक्टरों की संख्या लगभग २१ हजार थी, सन् १९५७ में बढ़कर ४४४ हजार (२१ गुने से भी अधिक) हो गई। इस प्रकार यू० के० में ट्रैक्टर घनत्व एक ट्रैक्टर प्रति ३८ एकड़ कृषि योग्य भूमि था। ५) इसके अतिरिक्त ब्रिटिश कृषि की उत्पादकता में वृद्धि का महत्वपूर्ण कारण कृषि नीति की सफलता है जिसके अन्तर्गत आश्वासन, प्रोत्साहन, सलाहकारी सेवाएँ (advisory services), तथा नियंत्रण इत्यादि उपाय सम्मिलित हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व काल की अपेक्षा ब्रिटेन में फलों और शाक-तरकारियों के उत्पादन में भी बहुत वृद्धि हुई है। सन् १९५७ में यू० के० में

शाक-तरकारियों (vegetables) का उत्पादन २३-३६ लाख टन और फलों का ७-२५ लाख टन था।

९. सरकारी कृषि नीति

ब्रिटिश कृषि के इतिहास पर सरकारी नीति का प्रभाव स्पष्ट है। यह इस अध्याय में पहले बताया जा चुका है कि १८वीं शताब्दी में और १९वीं शताब्दी के मध्य तक सरकारी कृषि नीति मुख्यतया संरक्षणवादी थी। सन् १८४६ में संरक्षण समाप्त कर दिये गये थे। सन् १८७५ तक ब्रिटिश कृषि सभी दृष्टियों में उन्नति करती रही। सन् १८७५ से १९०० तक की अवधि में ब्रिटिश कृषि को घोर संकट का सामना करना पड़ा। (कारणों का उल्लेख इसी अध्याय में पहले किया जा चुका है।) इस काल की मन्दी के कारणों की जाँच के लिए सन् १८८२ में ड्यूक ऑफ रिचमण्ड की अध्यक्षता में एक शाही आयोग की नियुक्ति की गई। आयोग ने अपने प्रतिवेदन (रिपोर्ट) में प्राकृतिक प्रकोपों और पशुओं की बीमारियों के अतिरिक्त बाह्य स्पर्धा ऊँचे कर, लगान और रेलवे करों का अधिक भार, कृषि शिक्षा का अभाव मुख्य कारण बताए। सन् १८९३ में एक दूसरा शाही आयोग लॉर्ड एवरहैने की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया जिसने अन्त में एक भागों के अतिरिक्त चांदी के भाव में मिराबट के प्रभाव की ओर ध्यान आकृष्ट किया। आयोग ने बताया कि कृषि में फल और शाक-तरकारियों के उत्पादन, मुर्गी-पालन, पशु-पालन तथा घालू इत्यादि जड़-हार फसलों के उत्पादन का विकास किया जाना चाहिए। ये उपाय अपनाए गये और सुधार के चिह्न दृष्टिगोचर होने लगे। यद्यपि कृषि क्षेत्रफल घटा परन्तु पशुधर भूमि का क्षेत्रफल और फसलों के अतिरिक्त कृषि का अन्य शाखाओं में उत्पादन बढ़ा। इसी काल में भूमिहीन श्रमिकों को बसाने के लिए छोटे छोटे खेतों (small holdings) के सृजन में सरकारी तौर पर रुचि ली गई जिसके लिए सन् १८८७ में एक कानून पास करके स्थानीय अधिकारियों को बड़े भू-स्वामियों से भूमि खरीद कर अथवा पट्टे पर लेकर छोटे कुपकों को जोतने के लिए भूमि देने का अधिकार दिया गया। सन् १८८६ में कृषि मण्डल (Board of Agriculture) की स्थापना की गई। छोटी जोतों के सम्बन्ध में उठाये गये पिछले कदमों की अधिक प्रभावोत्पादकता न होने के कारण इस दिशा में सन् १९०८ में एक और कानून (Small Holdings and Allotment Act) पारित किया गया जिसके अनुसार नाउन्टी कॉमिटी के ऊपर कृषि मण्डल को अधिकार दिये जाने के कारण कानून प्रभावपूर्ण हो गया। पशु रोगों की रोक-

धाम, महकारिता के विकास, कृषि-शिक्षा इत्यादि की दिशाओं में भी यह महत्वपूर्ण कदम उठाये गये। कृषकों को वित्त सम्बन्धी सहायता भी दी गई। कृषि-उपज की जगहसी जानवरों में रक्षा करने के लिए भी अधिनियम बनाया गया।

प्रथम युद्धकाल (१९१४-१८) में सरकारी नीति—सन् १९१४ में युद्ध छिड़ने पर जहाजी यानायाज की दुर्लभता के कारण विदेशों से अन्न का आयात कठिन हो गया और यह भी समझा गया कि युद्ध काल में भोजन के लिए दूसरे देशों पर आश्रित होना खतरों में खाली नहीं था। अन्न-भोजन में स्वावलम्बन की अवस्था प्राप्त करने के लिए कृषि के विकास के भरसक प्रयत्न किए गये। खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन मिला परन्तु खाद्य-मामूरी की बहुत कमी होने के कारण सरकार ने नियन्त्रण जारी किये। सन् १९१६ में कानून बनाकर खाद्य विभाग की स्थापना की गई और उसका कार्य संभालने के लिए खाद्य-नियन्त्रक (Food Controller) की नियुक्ति की गई जिसका खाद्य-मामूरी के उत्पादन, संग्रह इत्यादि की स्थिति का पता लगाना और नियन्त्रण में रखना तथा कृषकों से खाद्य पदार्थों की प्राप्ति इत्यादि कार्य सौंप गये। प्रत्येक काउन्टी और जिले में देखभाल के लिए खाद्य-मामूरीयाँ स्थापित की गई। कृषि मण्डल को खाद्य-वितरण सम्बन्धी कार्य सौंपा गया। राशनिंग की व्यवस्था की गई और खाद्य पदार्थों के मूल्य निश्चित किए गए। सन् १९१७ में एक अन्न उत्पादन कानून (Corn Production Act) पारित हुआ जिसके अनुसार कुछ खाद्यान्नों के न्यूनतम मूल्य निश्चित कर दिये। धर्मिका के वेतन धार लगान भी निश्चित किये गये। परिणाम यह हुआ कि कृषि क्षेत्रफल में और खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि हुई।

सन् १९१९ में एक शाही आयोग की नियुक्ति की गई जिसका उद्देश्य तत्कालीन ब्रिटिश कृषि को उपज के मूल्य, उत्पादन लागत, मजदूरियाँ, काम करने का समय इत्यादि सम्बन्धी स्थिति को जांच करना था। सन् १९२० में एक नया कानून पास करके युद्धकालीन व्यवस्थाओं में परिवर्तन करके कृषि के क्षेत्र में स्थायी सुधार करने का प्रयत्न किया गया।

सन् १९२० के पश्चात् कृषि में भीषण मन्दो आ गई और सामान्य कीमत-स्तर में गिरावट हुई। अन्न-वृद्धि रूपों में रक्षणवादी नीति (protection) अपनाई गई और कृषि के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गई।

चुक्कन्दर, गेहूँ तथा गन्धुओं के लिए वस्तु आयोग (commodity commissions) स्थापित किये गये जिन्हें उन वस्तुओं के उत्पादन के लिए सरकारी सहायता (subsidies) अथवा अन्य प्रकार की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के प्रशासन का काम सौंपा गया। साथ ही, दूध, आलू, सुअर के गोस्त इत्यादि की बिक्री के नियमन के लिए उत्पादकों द्वारा नियंत्रित विपणन मण्डलों (Marketing Boards) की स्थापना की गई। सन् १९३७ में सरकार ने ओ और जई (oats) की कृषि को सहायता (subsidies) देने के लिए अधिकार प्राप्त किये।

९- द्वितीय विश्व-युद्धकाल तथा प्रारम्भिक युद्धोत्तर वर्षों में

कृषि उत्पादन और विपणन पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहा। सरकार के स्थानीय प्रतिनिधियों की भांति कार्य करने के लिए जिला युद्ध कृषि समितियाँ (County War Agricultural Executive committees) बनाई गईं जिनमें कृषि हितों के स्थानीय प्रतिनिधि सम्मिलित थे। ये समितियाँ प्रथम महायुद्ध काल में स्थापित समितियों के समान थीं। सरकारी नियन्त्रण के परिणामस्वरूप वस्तु आयोगों तथा विपणन मण्डलों (marketing boards) के कार्य बहुत कुछ स्पष्ट कर दिये गये। कालान्तर में इन संगठनों के अधिकार पूर्ववत् कर दिए गए अथवा उनके स्थान पर अन्य कुछ प्रबन्ध किये गये।

यूनाइटेड किंगडम की कृषि-नीति का मुख्य उद्देश्य जो सन् १९४७ के कृषि कानून (The Agriculture Act, 1947) के प्रथम भाग में दिया गया है यह है : 'यूनाइटेड किंगडम में स्थायी (stable) तथा कुशल कृषि व्यवसाय राष्ट्र की भोजन सम्बन्धी तथा कृषि उपज का इतना भाग उत्पादन करने में समर्थ हो सके जितना कि राष्ट्रीय हित में वांछनीय है, और यह उत्पादन न्यूनतम कीमतों पर हो परन्तु साथ ही कृषकों और कृषि-श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक और जीवन की दशाएँ तथा कृषि में लगी हुई पूँजी पर यथोचित प्रतिफल (return) मिल सकें।' इस उद्देश्य की प्राप्ति के हेतु लिये गये मुख्य सरकारी कदम निम्नलिखित हैं :—

(१) मुख्य कृषि पदार्थों की कीमतों की गारन्टी देना (guaranteed prices) अर्थात् कृषि उत्पादकों को अपने उत्पादन के लिए निश्चित कीमतों से कम न मिलने का आश्वासन दिया जाता है,

(२) लगान पर जोतने वाले कृषकों (tenant farmers) को निश्चित अवधि तक भूमि-स्वत्व प्राप्त रहना (security of tenure);

(३) भूमि-स्वत्व रक्षा के बढ़ने में कृषकों में कृषि-कार्य में कार्यक्षमता और उसकी समुचित व्यवस्था की आशा की जाती है। वस्तुतः कार्यक्षमता के स्तर बनाये रखने के लिए कृषि मन्त्रालय द्वारा देखभाल (supervision) और निर्देशन (direction) इत्यादि उपाय अपनाये जाते हैं और कृषकों द्वारा कृषि उचित ढङ्ग पर न होने की दशा में उनके अधिकार समाप्त किये जा सकते हैं ;

(४) कार्यक्षमता को बढ़ावा देने की दृष्टि में सरकार टैकनीकल सलाहकारी सेवाएँ प्रदान करती है; तथा

५. उत्पादकता में वृद्धि करने की दृष्टि से कृषकों और भू-स्वामियों को विभिन्न प्रकार की ग्रांट (grants) दी जाती है।

सन् १९४७ का कृषि अधिनियम (act) जिस समय पास हुआ था उस समय में ब्रिटेन में खाद्य की बहुत कमी थी, अतः उस समय सरकार द्वारा खाद्य पदार्थ खरीदने, कृषि के उत्पादन और विपणन (marketing) पर व्यापक नियन्त्रण, और खाद्य पदार्थों के राशनिंग की प्रणाली अपनाई गई थी। सरकारी कृषि नीति का प्राथमिक उद्देश्य उपज में वृद्धि करना था जिसमें युद्ध-पूर्व के स्तर को तुलना में सन् १९५२ तक लगभग ५० प्रतिशत की वृद्धि हुई। संसार की कुल खाद्य-पूर्ति में सुधार होने पर और ब्रिटेन के अपने कृषि उत्पादन और व्यापार सम्बन्धी दशा सुधरने पर ब्रिटिश सरकार ने शनैः शनैः खाद्य पदार्थों का व्यापार और उनका आयात निजी व्यापारियों (private businessmen) को वापस दे दिया। खाद्य पदार्थों के उपयोग पर से सब प्रकार का राशनिंग ३ जुलाई १९५४ को समाप्त कर दिया गया था।

अभाव का समय समाप्त हो चुकने पर ब्रिटिश कृषि नीति के उद्देश्यों के अन्तर्गत भिन्न प्रकार की बातों पर जोर दिया गया है। हाल के वर्षों में उत्पादन के विवेचनहीन विस्तार (indiscriminate expansion) की अपेक्षा जिन बातों पर जोर दिया है वे ये हैं—बाजार की दशाओं के अनुसार उचित कीमतों पर उत्पादन, टैकनीकल कुशलता में वृद्धि, आयात होने वाले पशुओं के भोज्य पदार्थों के उपयोग में मितव्ययिता, इत्यादि।

सन् १९५८ में कृषि के वार्षिक पर्यवेक्षण (review) के पश्चात् सरकारी दृष्टिकोण यह था कि कृषि का विकास निम्न दिशाओं में हो :—

(१) कृषियोग्य क्षेत्रफल वर्तमान आकार के लगभग समान बना रहे, परन्तु गेहूँ की अपेक्षा चारे की फसलों पर अधिक जोर दिया जाय;

(२) पशुओं के लिए देश में ही उत्पन्न चारे (feed) पर अधिक निर्भरता रहे ;

(३) बछड़ों और भेड़ों के बच्चों के गोشت (beef and lamb) की उस किस्म का अधिक उत्पादन जिसकी बाजार में अधिक मांग है ; और

(४) कम दूध, अंडों और सुअर के गोشت (piggmeat) का उत्पादन ।

ब्रिटिश सरकार का दीर्घकालीन लक्ष्य कृषि की स्वर्द्धा शक्ति में स्थायी सुधार करना है ।

प्रश्न

1. Point out the main features of the English Agrarian Revolution, and show how it affected the peasantry.

2. "The economic consequences of the agricultural revolution were brilliant while the social consequences were disastrous." Discuss

3. How did the Corn Laws in England affect the economic life of the country? What were the reasons for their repeal?

4. Describe clearly the factors which brought about the revolution in agriculture in England towards the close of the eighteenth century.

5. Contrast the agricultural situation in England in 1750 with that in 1850, and account for the change that came.

6. Briefly describe the British agricultural policy during and after the first world war.

7. Write notes on

(a) Corn Laws

✓(b) Enclosure Movement.

8. Give a short analysis of the leading features of British agricultural policy in post-war years-

यातायात का विकास तथा वाणिज्य क्रान्ति

(Developments in Transport And Commercial Revolution)

[वाणिज्य क्रान्ति, वाणिज्य क्रान्ति के सामाजिक प्रभाव, यातायात के विकास का इतिहास—सड़कों का विकास, नाव्य नहरें, नहरों की अवनति, रेल भागों का विकास, समुद्री यातायात, नौ-वहन सम्बन्धी कानून तथा नीति, वायु-यातायात, प्रश्न ।]

यातायात का विकास ग्रेट ब्रिटेन की औद्योगिक क्रान्ति का कारण भी समझा जाता है और उसका एक अंग भी । १८वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में सड़कों और नाव्य नहरों का विकास हुआ और तदनन्तर रेल-भागों और समुद्री यातायात के क्षेत्र में उन्नति हुई । सन् १८७० के उपरान्त यात्रिक यातायात के विकास के "सामान्य परिणाम क्रान्तिकारी थे ।"^१ वाष्प से चलने वाले जहाजों और रेलों का विकास सन् १८७० के उपरान्त ही अधिक हुआ । इस काल में यातायात में होने वाले विकास का ब्रिटेन के आर्थिक जीवन पर ही नहीं, समस्त संसार पर प्रभाव पड़ा ।

यातायात के विकास की मुख्य विशेषताएँ ये थी—

(१) गति (speed) में वृद्धि,

(२) सुरक्षा (safety),

(३) नियमितता (regularity),

(४) सस्तापन (cheap transport) और

(५) अधिक भारी वस्तुएँ, अधिक मात्रा में, बहुत दूर स्थानों को भेजना सम्भव होना ।

इतना ही नहीं, यात्रिक साधनों के द्वारा आवागमन के मार्गों में भौगोलिक बाधाओं, जैसे पर्वतों, जलवायु इत्यादि पर विजय पाने के प्रयत्नों में भी सफलता मिली है । इन सब विकासों का परिणाम यह हुआ कि व्यक्तियों

और वस्तुओं की गतिशीलता (mobility) में बहुत वृद्धि हुई जिसके कारण उद्योग और वाणिज्य में मूलभूत परिवर्तन और विकास सम्भव हो सके। मोल्स ने लिखा है कि १९वीं शताब्दी का ब्रिटिश साम्राज्य रेलों और स्टीमरों की सम्मिलित उपज थी।^१ वास्तव में साम्राज्य का स्थापन, संचालन और शासन इत्यादि यातायात के बिना सम्भव ही नहीं हो सकता था। यातायात के विकास के साथ साथ ही ब्रिटेन के विदेशी व्यापार में वृद्धि होती गई।

रेलों का विकास लोहा-इस्पात व्यवसाय के विकास के बिना सम्भव नहीं था। ग्रेट ब्रिटेन प्रथम देश था जिसमें रेलों का विकास हुआ, अतः उसके साथ साथ लोहा-इस्पात उद्योग का भी विकास हुआ। ब्रिटेन में बने हुए लोहे और इस्पात के माल की, विशेषकर लोकोमोटिव (रेलवे एजिन), रेलवे का सामान, इंजीनियरिंग का सामान इत्यादि की माँग संसार के अनेक देशों में की। इंग्लैण्ड संसार की भट्ठी बन गया।^२ वह संसार के अनेक देशों को लोहे और इस्पात की वस्तुएँ निर्यात करने लगा।

यान्त्रिक यातायात के विकास से केवल ग्रेट ब्रिटेन को ही लाभ नहीं हुआ अपितु अन्य देशों ने भी लाभ उठाया। यूरोप, अमेरिका, एशिया और अफ्रीका रेल यातायात के विकास के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था (world economy) में आ गये। उदाहरण के लिए, यूरोप में जर्मनी और रूस ने रेल यातायात के विकास के पश्चात् बहुत प्रगति की। जर्मनी में लोहा व्यवसाय और वस्त्र उद्योग पहले ही उन्नति पर थे, अतः वह शीघ्र ही कई वस्तुओं के निर्माण में इंग्लैण्ड का प्रतिद्वंद्वी (rival) बन गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी बिल्कुल यही हुआ। इन देशों से स्पर्धा बढ़ने पर ग्रेट ब्रिटेन को अपना आर्थिक आधार बदलने के लिए विवश हो जाना पड़ा। ब्रिटेन इन देशों से खाद्य सामग्री इत्यादि मँगाने लगा और मूल्य चुकाने के लिए डॉलर की बनी हुई वस्तुएँ तथा कोयला इत्यादि निर्यात करने लगा। जहाजी (shipping) तथा वित्तीय (financial) सेवाएँ विकसित की और सस्ती वस्तुओं का निर्माण अन्य देशों के लिए छोड़ दिया।

सन् १८६० में संयुक्त राज्य अमेरिका का जहाजी टन भार (shipping tonnage) ५२,६६,७५१ था जबकि यूनाइटेड किंगडम (U. K.) का

1. Ibid, p 183 "the new British Empire of the nineteenth century was equally a product of railway and steamer combined"

2 England became "the forge of the world."

४६,५८६८७ था। परन्तु लकड़ी के स्टीमरों के बजाय लोहे-इस्पात के स्टीमर प्रयोग में आये तो स्थिति एकदम भिन्न हो गई क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहा-इस्पात व्यवसाय का विकास अभी तक बाकी था। अतः ब्रिटेन को इस दिशा में बहुत लाभ रहा। जहाजी यातायात में उसका एकाधिकार था। ब्रिटेन के विदेशी व्यापार की यह भी एक विशेषता हो गई। ब्रिटिश साम्राज्यगत सभी देशों का व्यापार प्रायः ब्रिटेन के जहाजों द्वारा होता था, जैसे कनाडा का गेहूँ और निकेल (nickel), आस्ट्रेलिया का ऊन, भारत का कूट, अफ्रीका और मलाया का रबर, अफ्रीका का सोना इत्यादि ब्रिटिश जहाजों द्वारा ही भेजा जाता था। यदि यांत्रिक यातायात का विकास न होता तो ब्रिटेन के जहाजी विकास का यह रूप होना असम्भव था।

यातायात के साधनों में विकास होने से ससार के देश सम्पर्क में आये और व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हुए। अम-विभाजन की प्रवृत्ति आ गई। व्यापार बढ़ने पर जो स्पर्धा प्रारम्भ में देखी गई थी उतनी नहीं रही। प्रायः देशों ने अपनी परिस्थितियों के अनुकूल अलग-अलग उत्पादन क्रियाएँ अपना लीं। संचादवाहन के साधनों (तार, टेलीफोन इत्यादि) में विकास होने पर यह प्रवृत्ति और भी बढ़ गई।

यांत्रिक यातायात के साधनों के विकास का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव व्यापारिक संगठन में क्रान्ति के रूप में पड़ा। अब क्योंकि माल शीघ्र भेजा सकना सम्भव हो गया था, व्यापारियों को बहुत अधिक स्टॉक (stocks) रखने की आवश्यकता नहीं रह गई। बितरण के साधन-यातायात में विकास होने के कारण और व्यापार क्षेत्र में विस्तार होने से व्यापार का पैमाना भी बढ़ गया। व्यापार गृहों (business houses) के पास पूँजी में वृद्धि होने के कारण व्यापार में थम दबाने के साधनों (labour saving devices) यन्त्रों का व्यापार गृहों में प्रयोग होने लगा। तकनीकल रिमर्च के क्षेत्र में वृद्धि हुई। व्यापारियों में स्पर्धा बहुत बढ़ गई। अग्निशय-स्पर्धा (cut throat competition) के कुछ हद तक प्रतिकार के लिए समामेलन (amalgamation) और मयुक्तीकरण अथवा संयोग (combination) के उपाय अपनाये गये। रेलवे कम्पनियों और जहाजी कम्पनियों में भी स्पर्धा बढ़ चली थी, अतः समामेलन इत्यादि के उपायों का अवलम्बन इन दिशाओं में भी लिया गया।

यातायात के कारण मुख्यतः व्यक्तियों की गतिशीलता में वृद्धि होने तथा

अन्य प्रकार से भी सामाजिक जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। कस्बों और नगरों का विकास हुआ, नये धन्धों तथा श्रमिकों के नए वर्गों का उदय हुआ, स्त्रियों की अवस्था बदली तथा आवास-प्रवास में वृद्धि हुई।

अनुभव से यह मालूम हो जाने पर कि विदेशी सस्ते माल से देश के उद्योग को ठेस पहुँचती है और सरक्षण के द्वारा किसी व्यवसाय का विकास किया जा सकता है तो सरकारी प्रदुक्त नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, ममभौतो की नीति अपनाई गई और अधिकाधिक क्षेत्रों में राजकीय निपटणों के सम्बन्ध में विचार किया जाने लगा। ब्रिटेन में ही नहीं, सामान्यतया सभी देशों में राष्ट्रवादी भावनाएँ बढ़ी और सत्ता बढ़ाने के प्रयत्न किये गये।

वाणिज्य क्रान्ति (Commercial Revolution)

औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप ब्रिटेन में वाणिज्य-क्रान्ति भी हुई। उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन हो जाने के कारण व्यापार का ढाँचा ही बदल गया। स्थानीय माँग की अपेक्षा बड़े पैमाने पर दूरवर्ती देशों में स्थित बाजारों के लिए उत्पादन होने लगा था। कच्चा माल खरीदने और पक्का माल बेचने के लिए नये बाजारों की तलाश होने लगी थी। औद्योगिक क्रान्ति के पूर्व बाजार सकुचित थे तथा क्रय-विक्रय का कार्य प्रायः उपभोक्ता और उत्पादकों के बीच सीधा था। कुछ स्थानों पर कभी कभी मेले लगते थे जिनमें वस्तुएँ खरीदना बेचना सम्भव होता था। औद्योगिक क्रान्ति के उपरान्त व्यापार की प्रणाली बदली तथा मध्यवर्तियों (middlemen) की संख्या बढ़ी।

वस्तुतः वाणिज्य क्रान्ति यातायात के क्षेत्र में होने वाली क्रान्ति का परिणाम थी। रेल यातायात का विकास सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में हुआ। जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका इत्यादि देशों ने ब्रिटेन से लोकोमोटिव तथा रेल का अन्य सामान मंगाकर अपने देशों में रेल मार्गों का विकास किया और विदेशी व्यापार में ये देश ब्रिटेन के प्रतिद्वन्द्वी बन गये। इस अवस्था में ब्रिटेन में जहाजों (steamships) का निर्माण आरम्भ हुआ तथा वह इसमें आगे बढ़ा।

रेलो और जहाजों के कारण दुनिया के देश परस्पर निकट सम्पर्क में आने लगे और सभी देशों के आर्थिक जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। गति (speed), सुरक्षा (safety) नियमितता इत्यादि सभी दृष्टियों से यातायात में प्रगति हुई। देशों के भीतरी भागों में रेल मार्गों का प्रवेश होने के साथ साथ व्यापार में वृद्धि होती चली गई। नये व्यापारिक मार्ग खुले। अफ्रीकी और एशियाई तथा अन्य अविकसित राष्ट्रों से कच्चा माल बटोरने तथा

उनमें निर्मित माल बेचने के लिए यांत्रिक यातायात का विकास किया जा रहा था। १९वीं शताब्दी के अन्तिम प्रहर में (सन् १८७० के लगभग) जब ब्रिटेन में यातायात का विकास चरम सीमा की ओर बढ़ रहा था (यों विकास बीसवीं शताब्दी में भी चलता रहा), वाणिज्य के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे थे।

ब्रिटेन की वाणिज्यिक क्रान्ति की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थीं :—

(१) यों तो यातायात वाणिज्य का ही अङ्ग है इसलिए यातायात की प्रगति वाणिज्यिक क्रान्ति का महत्वपूर्ण पहलू समझा जा सकता है परन्तु इसकी एक विशेषता यह थी कि ब्रिटेन के जहाज अन्य देशों का माल ढोने लगे जिससे ब्रिटेन की विदेशी मुद्रा का साम हुआ। मुगलान संतुलन में यह मुख्य मद (item) हो गया।

(२) यातायात की प्रगति के कारण ब्रिटेन ने अपना साम्राज्य बहुत बढ़ा लिया था। साम्राज्यगत देशों तथा उपनिवेशों में ब्रिटेन की अपना माल बेचने के लिए मण्डियाँ मिल गईं जिसके कारण व्यापार की मात्रा में अप्रत्याशित वृद्धि हुई।

(३) व्यापारगत वस्तुओं की संख्या में वृद्धि हुई। ब्रिटेन का विदेशी व्यापार पहले समीपवर्ती देशों से थोड़ी वस्तुओं में होता था परन्तु १९वीं शताब्दी में व्यापारगत वस्तुओं की संख्या बहुत बढ़ गई। दूरवर्ती देशों से भारी वस्तुओं में भी व्यापार होने लगा। ब्रिटेन अपनी भोजन की पूर्ति कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेन्टाइना इत्यादि दूरवर्ती देशों से मँगाकर करने लगा। गेहूँ, जौ, भुवका, कपास, विनोला, पेट्रोलियम, कागज की छुगड़ी, कच्चा लोहा, कोयला, गन्धक, चूना, मशीनरी, मांस, दुग्ध पदार्थ, मछली, अण्डे, फल, चाय, तम्बाकू, चीनी इत्यादि के व्यापार का विकास हुआ तथा उसमें वृद्धि हुई।

(४) व्यापारिक सङ्गठन में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए। अब व्यापारियों को माल का स्टॉक (stock) कम रखना पड़ता था क्योंकि माल जल्दी जल्दी बँगलाना सम्भव हो गया था। अनुबद्ध गोदामों की संख्या बहुत अधिक पूर्तियों लगाने की आवश्यकता एक व्यक्तिगत विज्ञेता को नहीं रही। माल-खरीदने के लिए अब उन्हें बैंकों से अधिक साध (credit) की जरूरत नहीं रही। तार, टेलीफोन, केबिलग्राम द्वारा आर्डर दिये जाने लगे। मूल्य परिवर्तनों से अधिक हालि की आसंका भी अपेक्षाकृत कम हो गई। नमूने और प्रेड द्वारा क्रय-

विक्रय प्रारम्भ हो गया। मेलों का महत्त्व अब कम हो गया था। अन्तर्राष्ट्रीय मेले औद्योगिक प्रदर्शनियों के रूप में प्रारम्भ हुए। विज्ञापनों का महत्त्व बढ़ चला था।

(५) सट्टे द्वारा वस्तुओं के विनिमय केन्द्र (produce exchanges) प्रारम्भ हुए जिनके द्वारा हुए व्यापार की अनेक विशेषताएँ थीं। उदाहरणार्थ, नमूनों (samples), ग्रेड (grades) अथवा प्रमाणीकरण (standardisation) के आधार पर व्यापार होने लगा, धातु के सोदों का विकास हुआ, सट्टे की क्रिया में एक ओर जोखिम लेने वाले कूद पड़े, दूसरी ओर निर्मायकों (manufacturers) ने सुरक्षा के सोदों (hedging contracts) द्वारा अपने आपको जोखिम से मुक्त कर लिया। जिस सीमा तक सट्टे का प्रभाव कीमतों के स्थिरीकरण के रूप में पड़ा सामान्य रूप में व्यापारियों को लाभ हुआ क्योंकि कीमतों के अधिक उच्चावचनों (fluctuations) से होने वाली हानियाँ कम हो गईं।

(६) खुदरा व्यापार के नये तरीके अपनाये गये। प्रारम्भ में दुकानें जनरल स्टोर्स (general stores) के रूप में अधिक देखी जाती थीं। जहाँ अनेक प्रकार की वस्तुएँ बेची जाती थी परन्तु १९वीं शताब्दी में छोटी छोटी विशिष्ट दुकानें (specialised shops) खुली जिनमें एक ही प्रकार की वस्तु मिलती। सजावट (window dressing) की पद्धतियाँ अपनाई जाने लगीं। बड़ी दुकानों ने विभागीय भण्डारों (departmental stores) का रूप ग्रहण कर लिया। एक ही वस्तु या सख्या में सीमित वस्तुओं की विक्री का अधिक कस्बों में या अनेक क्षेत्रों में विकास करने के लिए शृङ्खला भण्डारों (chain stores or multiple shops) की पद्धति अपनाई गई। इस प्रणाली में दुकान का आकार तो वही रहा परन्तु विक्रेता फर्म या कम्पनी ने अधिक पूँजी लगाकर विक्री के नए क्षेत्र ढूँढ़ निकाले। एजेंसियों (commission agency system) तथा डाक द्वारा व्यापार (mail order business) का भी विकास हुआ।

(७) वाणिज्यिक क्रान्ति के पूर्व कारीगर अपनी उत्पादित या बनाई हुई वस्तुओं की विक्री स्वयं करता था परन्तु अब बाजार का विस्तार होने के कारण यह न तो सरल ही रहा और न लाभदायक ही। चूँकि व्यापारी और खुदरा व्यापारी पृथक्-पृथक् होने लगे। हरेक व्यापारी प्रायः भिन्न प्रकार का केवल एक ही काम करने की ओर प्रवृत्त हुआ। मध्यवर्तियों (Middle-

men) की संख्या बहुत बढ़ गई। सेल्समैन (salesmen) तथा व्यापारी यात्री (commercial travellers) की संख्या में वृद्धि हुई।

(८) जब उल्लिखित विशिष्टीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी तो वाणिज्य-गठन (commercial integration) की प्रवृत्ति का विकास भी साथ साथ देखा जाने लगा। इसके तीन रूप मुख्य थे—पहला लोगों की विभिन्न और विविध आवश्यकताओं के लिए बड़ी-बड़ी दुकानें स्थापित हुईं; दूसरा अनेक व्यापार गृहों (mercantile houses) ने उन वस्तुओं को, जिन्हें वे बेचते थे, निर्माण (manufacture) करना प्रारम्भ कर दिया; तथा तीसरे, अनेक व्यावसायिक फर्मों (industrial firms) ने अपनी खुदरा बिक्री की दुकानें (retail shops) स्थापित की अथवा उन वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानों का स्वामित्व प्राप्त कर लिया।

(९) प्रारम्भ में व्यवसायियों में तथा विक्रेताओं में प्रतिस्पर्धा स्पर्धा हुई थी परन्तु कालान्तर में स्पर्धा से होने वाली हानियों और बर्बादी से बचने के लिए उत्पादकों ने मिलन अथवा संयोगों (combinations) के अनेक प्रकार अपनाये। संयोगों के द्वारा उत्पादक आपसी समझौतों से मूल्य तथा कुछ प्रकार के समझौतों में उत्पादन की मात्रा तथा बिक्री-क्षेत्र इत्यादि निश्चित करके एकाधिकार पाने के प्रयत्न किये।^१ यो तो संयोगों के विविध रूपों का विकास हुआ; परन्तु उन्हें दो भागों में बाटा जा सकता है: पहले प्रकार के संयोग^२ ऐसे हुए जिनके अन्तर्गत किसी एक प्रकार के उत्पादन की सभी अवस्थाओं अर्थात् कच्चे माल के उत्पादन से लेकर वस्तु के उत्पादन (finished product) तक का नियन्त्रण एक ही व्यवस्था द्वारा हो। ऐसे संयोग चातु सम्बन्धी उद्योगों में अधिक हुए, जैसे इस्पात सम्बन्धी कच्चे लोहे, कोयला, इला लोहा, इस्पात इत्यादि उत्पादकों में। दूसरे प्रकार के संयोग क्षैतिज प्रकार के (horizontal combinations) हुए जिनके अन्तर्गत एक उद्योग के अनेकों कारखाने एक ही प्रबन्ध अथवा नियन्त्रण में आये—उदाहरणार्थ, स्निज नेल उत्पादकों ने आपसी समझौतों द्वारा विजय मूल्य निश्चिन किये, कार्टेल और ट्रस्ट स्थापित हुए। अन्तर्राष्ट्रीय संयोगों का भी विकास हुआ।

(१०) वित्तीय क्षेत्र में भी क्रान्ति (financial revolution) हुई।

1. Main types of combinations are pools, cartels or syndicates, trusts, holding companies, mergers, etc.

2. Vertical combinations.

पूँजी बाजार और शेयर बाजारों (Stock Exchanges) का विकास हुआ। प्रारम्भ में रेलवे कंपनियों में विनियोग का क्षेत्र सुता और अंशों (shares) की बिक्री की गई। इन अंशों पर तथा ऋणों पर ब्याज की गारंटी सरकार ने दी। धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में विकास हुआ। अधिकोषण, बीमा ऋण देने वाली और साखपत्र अगुनाने वाली संस्थाओं का विकास हुआ। संयुक्त पूँजी वाले बैंक खुले और संयुक्त पूँजी वाली औद्योगिक तथा व्यापारिक कंपनियाँ बढ़ती गईं। ब्रिटेन से पूँजी तथा वित्तीय सेवाओं का निर्यात भी प्रारम्भ हुआ।

वाणिज्य क्रांति के सामाजिक प्रभाव

(Social Effects of the Commercial Revolution)

वाणिज्य क्रांति के मूल में औद्योगिक क्रांति के कारण जो सामाजिक क्रांति हुई थी, वाणिज्य के क्षेत्र में हुए विकासों ने उसे आगे बढ़ाया। वाणिज्य क्रांति के मुख्य सामाजिक प्रभाव निम्नलिखित पड़े :—

(क) रेल यातायात और जहाजी यातायात के विकास के कारण व्यक्तिपों की गतिशीलता और व्यापार के विकास के परिणामस्वरूप नये नगरों और कस्बों (व्यापारिक केन्द्रों) का विकास हुआ। नोत्स के अनुसार यह उन्नीसवीं शताब्दी के विकास की प्रमुख विशेषताओं में से एक थी। प्रारम्भ में नगरों का विकास औद्योगिक क्रांति के कारण हुआ था। उदाहरणार्थ, ईंधन, शक्ति प्रयत्न कच्चे माल की सुविधा प्राप्त करने के लिए किसी स्थान पर कारखाने खोले गये, उनमें रोजगार पाने के लिए श्रमिक पहुँचे, सहायक उद्योग धन्धे विकसित हुए और रेल यातायात के विकास के कारण भोजन तथा जीवनोपयोगी वस्तुएँ मिलने लगी, व्यापार का विकास हुआ। शहरों में जनसंख्या की वृद्धि का मुख्य कारण यह नहीं था कि रेल यातायात के कारण वहाँ पहुँचकर रहना सम्भव हो गया था, बल्कि यह था कि शहरों में जीवन निर्वाह के साधनों के साथ साथ भोजन तथा उपयोग की अन्य वस्तुएँ उपलब्ध हुईं और जीवन की अधिक सुविधायें मिलीं।

(ख) नगरों के विकास के साथ साथ नए वर्गों का विकास हुआ। इन नए वर्गों में बँकर, छाड़तिये, दलाल, सेल्समेन, छोटे दुकानदार, यात्री, व्यापारी इत्यादि थे। यातायात में काम करने वालों का एक नया वर्ग विकसित हुआ। इस वर्ग में ड्राइवर, फायरमेन, क्लीनर, गाइड, टैंटर, स्टेशन मास्टर, वर्कशॉप

मॉपरेटर, मैकेनिक, कुली (पोर्टर), जहाज चालक, डॉक में काम करने वाले इत्यादि थे ।

(ग) यात्रिक यातायात के विकास का स्त्रियो की दशा पर भी प्रभाव पड़ा है ।^१ पहले उन्हें अपना अधिकांश समय भोजन की वस्तुएँ बनाने और बनाकर भविष्य के लिए रखने में देना पड़ता था । परन्तु यातायात और व्यापार के विकास के साथ साथ विस्किट, रोटी, अचार, रम, डिब्बों में बन्द गोश्त, नमक लगा मक्खन इत्यादि की फैक्टरियाँ बिकसित हुईं । धुलाई का काम लौन्ड्री (laundry) में कराया जाने लगा । उपभोग की वस्तुएँ अधिक मात्रा में सहेदीकर रखने के बजाय आवश्यकतानुसार जरूरत के समय प्राप्त करना सम्भव और सुविधाजनक हो गया । फलस्वरूप स्त्रियो की बहुत से घरेलू कार्यों में छुटकारा मिला गया और उन्होंने अधिक लाभदायक रोजगार (employments) अपना लिये ।

(घ) प्रकानो और मभावो की भासकाएँ कम हो गईं । एक ओर जीविका के साधनों में वृद्धि होने और दूसरी ओर दूरवर्ती क्षेत्रों और विदेशों में उत्पादित वस्तुएँ अपेक्षाकृत नीची कीमतों पर उपलब्ध होने में लोगों का जीवन स्तर सामान्यतया ऊँचा उठा और उनमें सुरक्षा की भावना भा गई, निश्चिन्तता के कारण कार्यक्षमता बढ़ी और वे भोजन एवं फसलों के उत्पादन में लगे रहने की अपेक्षा नये-नये अनुमन्वानी तथा उद्योगों की ओर घुमसर हुए ।

(ङ) स्थानीय जीवन की दशाएँ और स्वावलम्बन की अवस्था का लोप हो गया । विभिन्न देशों के निवासियों में परस्पर निर्भरता बढ़ने का लाभ ऊपर बताया जा चुका है परन्तु उन कारीगरों पर सन्नान्ति काल में बुरा प्रभाव पड़ा जो स्थानीय आवश्यकताओं की वस्तुएँ बनाते थे । बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास होने और सस्ती वस्तुएँ मिलने के कारण स्थानीय कारीगरों का काम छिन गया ।

(च) आवास-प्रवास—यातायात के विकास तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास के साथ-साथ ब्रिटेन में दूर-दूर देशों के व्यक्ति आये और ब्रिटेन के निवासी अनेक देशों में फैल गये । इसके अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्रभाव हुए । सम्यताओं के आदान प्रदान और सम्पर्क बढ़ने से मैत्री भावनाओं और व्यापारिक

सम्बन्धी का विकास हुआ। परन्तु देश के अन्य भागों और विदेशों के निवासियों के आगमन से स्थानीय प्रशासन की समस्याएँ उत्पन्न हुईं। नोन्स ने लिखा है कि बहुत से लोग काम एक जगह करते हैं और सोते दूसरी जगह है, और किसी भी जगह के स्थानीय कल्याण (local welfare) के दायित्व अनुभव नहीं करते।^१ चुनाव के रजिस्ट्रो में निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं। देश के नागरिकों के परदेशगमन से एक कठिनाई तो यह उत्पन्न होती है कि उनसे कर वसूल कैसे किया जाये। दूसरे, देश के नवयुवकों का जिनको शिक्षा इत्यादि पर व्यय किया जाता है विदेश चला जाना, जब तक अन्य दृष्टियों में लाभदायक न हो, देश के लिए घाटे की बात है।^२

(छ) सरकारी हस्तक्षेप की नीति और सरकारी उत्तरदायित्वों में वृद्धि—ऊपर आवास-प्रवास के कारण हुई जिन कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है उनके कारण सभी देशों की केन्द्रीय सरकारों ने हस्तक्षेप (interference) की नीति अपनाई। नगरों के प्रशासन के ऊपर व्यय बढ़ा। सरकारों को अन्य क्षेत्रों से आये हुए व्यक्तियों की क्रियाओं के प्रति सावधान होना पड़ा। साथ ही यातायात के साधनों के आवास-प्रवास सम्बन्धी एवं अन्य व्यापक प्रभावों की दृष्टि से रेल यातायात तथा जहाजी यातायात पर राजकीय नियन्त्रण की नीति अपनाई गई।

उल्लिखित ब्राह्मण्य क्रांति के महत्वपूर्ण प्रभाव थे। साथ साथ ब्रिटिश साम्राज्यशाही का विस्तार हो रहा था क्योंकि ब्रिटेन को अपने बने हुए माल की बिक्री के लिए तथा कच्चे माल के साधनों पर नियन्त्रण प्राप्त करने के लिए नये राज्य और उपनिवेश स्थापित करने पड़े। अफ्रीका में वर्गीय चेतना तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का विकास हुआ। वस्तुतः १८वीं शताब्दी में ब्रिटेन ने औद्योगिक विकास के कारण संसार में जो औद्योगिक नेतृत्व प्राप्त किया था ब्राह्मण्यिक क्रांति के द्वारा उसमें और प्रगति की। इस प्रकार ब्रिटेन संसार का अग्रणी, सबसे अधिक सम्पन्न और शक्तिशाली राष्ट्र बन गया।

1. Ibid "How can classes that are always changing their place of residence be governed ?..... many people work in one place and sleep in another, and feel no real responsibilities for the local welfare of either place."

2. Ibid "The nation that lets its citizens go in the pride of their youth and strength incurs a loss in productive power."

यातायात के विकास का इतिहास

अठारहवीं शताब्दी के मध्य तक ग्रेट ब्रिटेन में यातायात की दशा पिछड़ी हुई थी। नदनों पर लगभग सौ वर्ष की अवधि में अर्थात् १६वीं शताब्दी के मध्य तक सड़कों और नावों का विकास हुआ। स्टीम से चलने वाले जहाजों का विकास हुआ। सन् १८४० में १६१४ तक का समय रेलवे यातायात की उन्नति का काल था। इस काल में नहरों का महत्व घटा परन्तु अन्य प्रकार के यातायात के सभी माधनों का विकास हुआ। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चतुर्थांश की ओर राजकीय नियन्त्रण की दिशा में अधिक ध्यान दिया गया। ब्रिटेन के रेलवे यातायात और जहाजों यातायात के विकास की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि उनका विकास सरकारी महामयना में नहीं बल्कि निजी पूँजी में हुआ और राजकीय नियन्त्रण का प्रदत्त बहुत बाद में उठा। ग्रेट ब्रिटेन में यातायात के विकास का अध्ययन इन भागों में बाँटा जा सकता है :

- (१) सड़कों का विकास,
- (२) नावों नहरों,
- (३) रेल मार्गों का विकास,
- (४) समुद्री यातायात,
- (५) जहाजों नीति और नौ बहन का कानून, तथा
- (६) वायु यातायात।

१. सड़कों का विकास

ब्रिटेन में सड़कों का विकास बहुत कुछ बेइतरे तौर पर हुआ है। रोमन काल में सैन्य सड़क प्रणाली का निर्माण हुआ, परन्तु सन् ४१० ईसवी में रोमनों के ब्रिटेन छोड़ने के बाद शताब्दियों तक सड़कों का काम लगभग पूर्णतया स्थानीय आधार पर ही चला और अधिक दूरों के मार्गों पर बहुत कम ध्यान दिया गया। १८वीं शताब्दी के पूर्व ब्रिटेन में सड़कों की दशा बहुत गिरी हुई थी। आर्थिक विकास के लिए सड़कों का महत्त्व अत्यधिक था परन्तु परम्परा के अनुसार ब्रिटेन में सड़कों की देखभाल निजी हाथों में रही जबकि यह कार्य फ्रान्स में राजकीय प्रबन्ध में था। सन् ११५५ में ब्रिटेन में एक कानून द्वारा सड़कों के सुधार का कार्य पैरिस को (क्षेत्रों के प्रबन्ध में) सौंपा गया। १८वीं शताब्दी में टर्नपाइक ट्रस्टों (turnpike trusts) की स्थापना हुई जिनका

निर्माण स्थानीय क्षेत्रों के भू स्वामियों इत्यादि के द्वारा पार्लियामेंट का प्राइवेट एक्ट पास कराके किया जाता था। ये ट्रस्ट सड़कों की मरम्मत और उनका सुधार करते थे और इसके लिए धन एकत्रित करने के लिए उन्हें सड़क का उपयोग करने वालों से चुंगी (toll) वसूल करने का अधिकार मिला हुआ था। टर्नपाइक ट्रस्टों द्वारा नियन्त्रित सड़कों की दशा कुछ क्षेत्रों में अच्छी थी और कुछ में खराब थी। इसका एक कारण यह था कि उनकी धन (funds) सम्बन्धी स्थिति में अन्तर था परन्तु असतोषजनक दशा का एक मुख्य कारण यह भी था कि उस समय तक सड़क बनाने और मरम्मत करने की सामग्री (materials) उपयुक्त प्रकार की नहीं थी। परिणामतः तत्कालीन सड़कों पर यात्रा करना खतरों से खाली नहीं था।^१

उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में सड़कों की दशा में तीन बड़े सुधार हुए :

(१) जॉन मैक एडम ने सड़क टिकाऊ बनाने के लिए अनुसन्धान किए;

(२) टॉमस टेलफोर्ड ने सड़क इंजीनियरिंग का विकास किया, और

(३) टर्नपाइक ट्रस्टों का मिलना (combination) आरम्भ हो गया था जिससे अधिक क्षेत्रों में सड़कों के प्रबन्ध और सुधार में समानता (uniformity) आ गई थी, बड़े पैमाने पर काम होने के कारण ये ट्रस्ट बेतन पर अधिकारी नियुक्त करने लगे थे, काम अच्छे ढंग पर होने लगा था।

जिस समय सड़कों की दशा में वास्तविक सुधार आरम्भ हुए उसी काल में रेल यातायात के विकास का सड़कों पर बुरा प्रभाव पड़ा। रेल-स्पर्धा के कारण टर्नपाइक ट्रस्ट टूटने लगे। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में पास हुए कानून के द्वारा सड़कों का उत्तरदायित्व काउन्टी कीन्सिलों, जिला कीन्सिलों तथा नगरी कीन्सिलों को सौंप दिया गया। नई सड़कों का निर्माण लगभग पूरी सीमा पर बढ़ने वाले कस्बों तक सीमित रहा। यांत्रिक सवारियों (motor vehicles) का प्रयोग आरम्भ हुआ तो सरकार के लिए यह आवश्यक हो गया कि सड़कों का कार्य केन्द्रीय अधिकार में सौंपा जाये। अक्टूबर सन् १९०६ में एक एक्ट (Development and Road Improvement Funds Act, 1909)

1 "It is obvious that Travel would be attended with considerable danger to life and limb and it is not surprising that people who were adventurous enough to make 'tours' in England wrote of their adventures as if they had been to Central Africa."

—Knowles, L. C. A., op. cit., p. 238.

द्वारा सड़क बोर्ड (Road Board) की स्थापना हुई। सन् १९१६ में इस बोर्ड की जिम्मेदारियाँ नये रूप में प्रारम्भ हुए यातायात मंत्रालय (Ministry of Transport) ने ले ली।

द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त ब्रिटिश ग्रंथ व्यवस्था के सम्मुख अत्यधिक कार्य होने के कारण सड़कों पर होने वाला व्यय कुछ सुधारों तथा कुछ नई सड़कों के निर्माण तक सीमित रहा। परन्तु सन् १९५३ में नये कार्यों (works) पर अधिक जोर दिया गया है। इनमें सम्मिलित कार्यक्रम तीन प्रकार के हैं—पहले, आधुनिक ट्रंक सड़कों का निर्माण देश में शीघ्र में शीघ्र प्रारम्भ करना जिसके अन्तर्गत लन्दन से न्यूकैसिल, लन्दन से बर्मिंघम और यार्कशायर इत्यादि ट्रंक सड़कों को प्राथमिकता दी जायगी, दूसरे शहरी क्षेत्रों में सड़कों की भारी कमी दूर करने के लिए नई सड़कों द्वारा ट्रंक मार्गों में जोड़ा जाएगा, तीसरे, समस्त देश में अपेक्षाकृत छोटी सड़कों अधिक में अधिक सख्या में बनाए जाने के लिए प्रयत्न किये जायेंगे। सन् १९५७ में ग्रेट ब्रिटेन में १,६०,१५१ मील राजमार्ग थे जिनमें ८,२७१ मील ट्रंक सड़कों (trunk roads) तथा प्रथम कोटि की सड़कों १७,६०५ मील सम्मिलित थी। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के महत्वपूर्ण प्रयत्न किये गये हैं।

२. नाव्य नहरें

नहरी यातायात का विकास सड़कों की कमी के कारण तो हुआ ही जो इन नभ्य में प्रकट है कि प्रारम्भ में नहरें उन भागों में बनीं जिनमें सड़कों कम थी परन्तु, नहरों के विकास का मुख्य कारण अधिकाधिक परिमाण में कोयला और कच्चा माल टोने के लिए मस्ते यातायात की आवश्यकता थी।

ब्रिटिश नहरों का इतिहास दो कालों में बाँटा जाता है। सन् १७६० से १८३० का समय नहरी यातायात के प्रारम्भ और विकास का काल था जिनमें नहरें यातायात का बहुत महत्वपूर्ण अङ्ग रही और देश के औद्योगिक विकास में बहुत सहायक सिद्ध हुईं। सन् १८३० से १९१४ तक की अवधि में रेल यातायात और जहाजी यातायात में वृद्धि के कारण नहरों का अपेक्षाकृत पतन प्रारम्भ हुआ।

सन् १७६१ में पहली नहर^१ ब्रिजवाटर नहर जेम्स ब्रिड्जने ने पूरी की।

१. एक दस मील लम्बी नहर सन् १७५५ में लिबरपूल के समीप खोदी गई थी। देखिए इस पुस्तक का अध्याय २, पृष्ठ ३०।

इस नहर ने वर्सले की ब्रिजवाटर के ड्यूक की कोयले की खानों को मानचेस्टर से मिलाया। मानचेस्टर को समुद्र से मिलाने की आवश्यकता थी। ड्यूक ने दूसरी नहर मानचेस्टर से रनकोर्न तक बनाकर उसे लिवरपूल से जोड़ दिया। ग्रेट ब्रिटेन की अन्य महत्वपूर्ण नहरों में से अधिकांश सन् १८३० तक बन चुकी थी—सन् १७६३ से १७६७ तक की अवधि में बहुत सी नहरें बनीं। सन् १८४० के बाद बनी नहरों में सन् १८८८ से १८९४ के बीच बनी मानचेस्टर शिप कनाल ही अधिक उल्लेखनीय है।

सन् १७६० से १८३० तक का काल नहरों का स्वर्णयुग कहा जा सकता है। नहरों कम्पनियों के अंशों (shares) का बाजार कीमतों तथा उनपर दिए जाने वाले लाभांशों (dividends) से इसका समर्थन होता है।

ब्रिटेन में नहरें व्यक्तियों (अथवा प्राइवेट कम्पनियों) द्वारा निजी पूंजी (private capital) से बनाई गई थीं। सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से न तो उनके निर्माण के लिए कोई वित्तीय सहायता दी और न आरम्भ में उसका कोई नियन्त्रण था। स्कॉटलैण्ड में दो नहरों के सेडोनियन तथा क्लिनन का निर्माण और सुधार अवश्य सरकारों ग्रांट (grants) से हुआ। यह अपवाद के रूप में समझा जाना चाहिए। वस्तुतः इन नहरों का निर्माण समुद्रतटीय उच्च भूमि के खतरों से जहाजों को बचाने की दृष्टि से कराया गया था।

नहरों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों अथवा कम्पनियों का होने के कारण उनका उपयोग करने वालों से उनके द्वारा कर (toll) वसूल किया जाता था। नहरों के निर्माण के लिए भूमि का अधिकार प्राप्त करने के लिए पार्लियामेंट का एक एक्ट पास कराना पड़ता था और यह अधिकार देने के लिए पार्लियामेंट अधिकतम दूरे निश्चित कर देती थी और यह शर्त लगा दी जाती थी कि नहर का उपयोग करने के लिए उन निश्चित दूरों से अधिक महसूल (charges) नहीं लिये जा सकते। विभिन्न व्यक्तियों और कम्पनियों के स्वामित्व में होने के कारण नहरों की चौड़ाई, गहराई, मुराबे, पुल, लॉक (locks) इत्यादि में कोई समानता नहीं थी और महसूल की दरें भी भिन्न भिन्न थीं। उनके सुधार और वित्तीय प्रबन्ध के ढंग भी विभिन्न ढंगों के थे। माल एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने के लिए कोई यू प्रणाली नहीं थी, यदि उन स्थानों के बीच में दस नहरें थी तो सभी नहरों के चलन चलन असमान दरों पर महसूल चुकाने पड़ते थे।

ग्रेट ब्रिटेन में नहरों की असमान दरें और विभिन्न प्रबन्ध होने पर

भी नहरो यातायात के प्रभाव अत्यन्त महत्वपूर्ण थे। इनमें से मुख्य प्रभाव ये थे :—

(१) नहरों के विकास के पूर्व सड़क ने मान भेजने का भाड़ा बहुत अधिक था और समय बहुत लगता था। नहरों से मान भेजने में कम समय लगने लगा जिसके कारण मान की होने वाली क्षति न होता और साथ ही होने की लागत बहुत कम हो गई। परिणामस्वरूप, उद्योग और व्यापार में वृद्धि हुई क्योंकि कच्चा माल और भारी वस्तुएँ (जैसे कोयला, इमारती सामान इत्यादि) ढोना सम्भव हो गया था। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रान्ति में नहरों का योग महत्वपूर्ण था।

(२) नहरों के द्वारा साथ सामग्रियों के वितरण की सुविधाएँ मिलने के कारण कृषि के विकास में सहायता मिली। औद्योगिक विकास के लिए भी यह आवश्यक था कि औद्योगिक केन्द्रों में भोजन की पर्याप्त पूर्ति रहती।^१

(३) जनसंख्या के वितरण पर यह प्रभाव पड़ा कि अब भोजन सामग्रियों के उत्पादन क्षेत्रों से दूर नये नये उद्योग-धन्धों के स्थानों पर जाकर लोग रहने लगे।

(४) बन्दरगाहों के विकास की दृष्टि से नहरों का प्रभाव स्पष्ट था। नहरों ने उनके लिए वस्तुतः पृष्ठ-प्रदेश (hinterlands) खोल दिये थे।

(५) सड़कों का अपना नहर भाड़ा और समय का दृष्टि में अधिक सुविधाजनक था, यह तो ऊपर बताया जा चुका है, इसके साथ ही उनके नहरों के बीच दूरों कम हो गई क्योंकि तटाय मार्ग का अपेक्षा अब साथ मार्ग न यातायात सम्भव हो गया था, जैस, ब्रिस्टल से लंदन, लिबरपूल से हुल (Hull) व बाच में। इसका प्रभाव भी व्यापार के विकास के रूप में पड़ा।

(६) नहरों यातायात के विकास में नाविकों (navigators) के वर्ग का उदय हुआ। नहरों की खुदाई में ठेकेदारों और सर्वेक्षणकर्ताओं (Contractors and surveyors) की प्रशिक्षण मिली जिसके कारण बाद में रेलमार्गों तथा जहाजी यातायात के लिए कुशल कर्मचारी मिल गये।

(७) व्यापार का ढंग ही बदल गया। अरबों द्वारा हाने वाला व्यापार अब कर्मादिन यात्रियों (Commercial Travellers) के द्वारा सम्पन्न

1 . . . the 'great industry' could not have taken root in the North owing to the difficulties of the food supply and not merely the coal supply had it not been for improved transport by the canals."

(Samples and patterns) की सहायता से छुदरा व्यापारियों को बेचा जाने लगा—माल नहरों द्वारा बाद में भेज दिया जाता था ।

नहरों की अवनति

सन् १८३० के पश्चात् नहरों की अवनति होने लगी । यह समझना भ्रान्तिपूर्ण होगा कि सन् १८३० के पश्चात् नहरों ने माल डोना बन्द कर दिया था उसमें भारी कर्मा हुई अथवा नहरों यातायात का प्रब कोई महत्व नहीं रहा था । नहरों द्वारा ढाये जाने वाले माल का परिमाण घटा नहीं था ।^१ वस्तुतः नहरों की अवनति इस दृष्टि से हुई थी कि यांत्रिक यातायात के साधनों के विकास और उनका स्पर्धा के कारण नहरों को करों (toll) की दरें बहुत घटानी पड़ी ।^२ नहरों कम्पनियों को होने वाले लाभ घट गये, नहरों का सुधार रुक गया, कुछ अपवादों का छोड़कर नई नहरें बनने की दिशा में प्रगति बन्द हो गई तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखकर विचार किया जाय कि १९ वीं शताब्दी में ब्रिटेन के व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई तो यह कहा जा सकता है कि नहरों यातायात के परिमाण में होने वाली वृद्धि नगण्य और उसकी प्रगतिहीनता की सूचक थी । यातायात में होने वाली वृद्धि नये यांत्रिक यातायात के हाथों में गई ।

रेलमार्गों की तुलना में नहरों की प्रगतिहीनता के मुख्य कारण निम्न-लिखित थे :—

१. नहरों की अपेक्षा रेल मार्ग गति (speed) और समय की पाबन्दी (punctuality) की दृष्टि से श्रेष्ठतर थे । रेल कम्पनियों की दरें भारपार एक थी, उनके अफसरों का व्यवहार भी प्रच्छा था । रेल मार्गों से कम या अधिक कितने ही परिमाण में माल भेजा जा सकता था ।

२. नहरें और रेल मार्ग दोनों ही निजी स्वामित्व में थे अतः उनमें स्पर्धा थी और सरकार इस स्पर्धा को बनाए रखने में रुचि रखती थी ताकि भाड़े की दरें नीची रहें ।

३. समुद्री तटों पर चलने वाले स्टीमरों की संख्या में वृद्धि होने पर नहरों नौकाओं और पोतों से माल भेजने की अपेक्षा स्टीमरों से भेजा जाने लगा और नहरों की अपेक्षा तटीय मार्ग अपनाये गये ।

1. Knowles writes, "The canals actually carried in 1909 more goods than they had ever handled . . ."

2. Ibid, p. 250. "The canal tolls were reduced in some cases to as much as a seventh....."

४. नहरों के तामांश गिरने के कारण उनमें पूँजी का विनियोग करने की अपेक्षा पूँजीपतियों को रेलमार्ग (railways) अधिक आकर्षक थे। सरकार स्वयं उनमें पूँजी नहीं लगाना चाहती थी क्योंकि स्कॉटलैण्ड की केलेडोनियन नहर के स्वामित्व से ही हानि हो रही थी।

५. नहरों की स्पर्द्धा से बचने के लिए रेल कम्पनियों ने अनेको नहरें खरोद लीं, अनेक नहर कम्पनियाँ अपने अन्तर्धारियों (shareholders) को बचाने की दृष्टि में नहरें बेचने के लिए स्वयं तैयार हो गईं। परिणामतः एक-तिहाई में अधिक नहरें रेलवे कम्पनियों के स्वामित्व में आ गईं और नहरों का सुधार रूक गया। यदि सब नहरें रेलवे कम्पनियों के स्वामित्व में आ जाती तो उनके प्रवन्ध में एकता (uniformity) और कुशलता आना सम्भव था परन्तु यह भी नहीं हुआ। नहरें अनेको और विभिन्न प्रवन्धों में थी।

६. नहरों में सुधार करना इसलिए भी सम्भव नहीं हो सका कि उनके किनारों पर बहुत निकट तक इमारतें इत्यादि बनी हुई होने के कारण उन्हें चौड़ा नहीं किया जा सकता था।

७. कृषि और व्यापारगत विकसियों की दृष्टि में रेल यातायात अधिक अनुकूल था, यह नहरों की अवर्धन का मुख्य कारण समझा जा सकता है। कृषि में फसलों की अपेक्षा दुग्ध व्यवसाय पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। दुग्ध पदार्थ ढोने के लिए नहरें बहुत धीमी मिट्टी होनी थी, रेलों में उन्हें बाजारों में शीघ्र पहुँचाया जाता था। इसी प्रकार कोयले के व्यापार के लिए व्यापारी को यह सुविधा थी कि रेलवे बैगन को खान के मुख तक पटरियों पर खड़ा किया जा सकता था जब कि नहरों से कोयला भेजने के लिए यह सुविधा नहीं थी और उसमें बड़े बड़े गोदामों की भी आवश्यकता पड़ती थी।

सारांश यह है कि नये विवास्तों के लिए रेल मार्गों की अधिक उपयुक्तता, उनकी अधिक कुशलता, नहरों के प्रवन्ध में विभिन्नता, नहरों में होने वाले विनियोगों का अभाव, सरकारी सहायता की कमी इत्यादि कारणों का सम्मिलित प्रभाव यह पड़ा कि नहरें यातायात का पुराना साधन रह गईं और रेलों की होड़ में पीछे रह गईं। दुर्हसना न होना कि १८ वीं शताब्दी के मध्य से १९ वीं शताब्दी के मध्य के लगभग तक नहरों ने उद्योग, व्यापार और कृषि की उन्नति में अत्यधिक योग दिया परन्तु उसके पश्चात् अधिक महत्व का स्थान रेलों ने ग्रहण कर लिया।

प्रथम विश्वयुद्ध के समय रेलों के ऊपर सरकारी नियन्त्रण हुआ तो

उसके अन्तर्गत उनके स्वामित्व में आने वाली (railway-owned) नहरें भी आ गईं। ऐसी मुख्य नहरें जो रेलवे-स्वामित्व में नहीं थी सन् १९१७ में व्यापार मंडल (Board of Trade) की नहर नियन्त्रण कमेटी (Canal Control Committee) के नियन्त्रण में लाई गईं थी परन्तु युद्ध समाप्त होने पर उनके निजी स्वामियों को लौटा दी गईं। द्वितीय युद्ध काल में नहरों पर फिर सरकारी नियन्त्रण रहा और सन् १९४८ में नहरें सरकारी नियन्त्रण से सीधी ब्रिटिश यातायात आयोग (British Transport Commission) को सौंप दी गईं। सन् १९५५ में उनका प्रबन्ध प्रयक् रूप में आयोग के जलमार्ग भाग (Waterways Division) द्वारा होता है जिसे ब्रिटिश वाटरवेज (British Waterways) कहते हैं। सन् १९५८ में ग्रेट ब्रिटेन के कुल नाव्य आन्तरिक जलमार्ग २,६०० मील के लगभग थे।

३. रेल मार्गों का विकास

रेल यातायात का विकास विश्व में सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में हुआ। सड़कों और नहरों का विकास ब्रिटेन में पहले ही हो चुका था जिनका प्रबन्ध निजी व्यक्तियों के हाथों में था और उनमें सामंजस्य का अभाव था। रेलमार्गों ने यातायात के पूर्व विकसित साधनों की अनेक विशेषताएँ अपनाईं। ब्रिटेन की रेलवे प्रणाली अन्य देशों की प्रणालियों से अनेक बातों में भिन्न थी। उसकी मुख्य विशेषताएँ ये थी :

(१) ग्रेट ब्रिटेन में रेलमार्गों का विकास निजी (private) पूँजी से हुआ जबकि बाद में अन्य अनेक देशों जैसे फ्रान्स, जर्मनी में उनका निर्माण और विकास सरकारी पूँजी या सहायता से हुआ,

(२) ब्रिटिश रेलमार्गों के विकास का उद्देश्य सामरिक (military) नहीं था बरिक्त व्यावसायिक मात्र था;

(३) रेलमार्गों के विकास के लिए विनियोग करने के लिए ब्रिटेन में पूँजी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी जबकि भारतवर्ष और रूस इत्यादि देशों में उनका विकास विदेशी पूँजी की सहायता से किया गया,

(४) ब्रिटेन में गमनागमन और यातायात में पहले ही बहुत वृद्धि हो रही थी और रेलमार्गों का विकास बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए किया गया था, अन्य देशों में क्रम प्रायः यह था कि रेल यातायात के विकास के पश्चात् व्यापार और यातायात (Traffic) की वृद्धि हुई;

(५) ब्रिटेन में जिस समय रेलमार्गों का विकास आरम्भ हुआ उस समय नहरों का विकास रुक गया और उनकी अववृत्ति होने लगी, यूरोप के अन्य देशों में नहरों और रेलमार्गों का विकास साथ-साथ किया गया था;

(६) ब्रिटेन में रेलयातायात में एकाधिकार की दशाएँ नहीं थी क्योंकि रेलमार्गों का प्रबन्ध और स्वामित्व निजी और अनेक कम्पनियों के हाथों में था अन्य देशों में स्पर्धा का प्रभाव था;

(७) आरम्भ में ब्रिटेन में रेलवे लाइनें (पटरियाँ) इत्यादि बिछाने का काम कम्पनियाँ कर देती थी और जिस प्रकार नहरों का इस्तेमाल (नौका चलाने के लिए) कोई भी व्यक्ति कर सकता था और उसके लिए कर (toll) देना पड़ता था उसी प्रकार पटरियों पर कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी या बैगन ले जा सकता था जिसके लिए रेलवे कम्पनियाँ महसूल वसूल करती थी। कालान्तर में रेलमार्गों के स्वामी अपनी गाड़ियाँ चलाने लगे;

(८) ब्रिटेन में रेलवे महसूल की प्रणाली (system of rate charges) भी भिन्न प्रकार की थी;

(९) ब्रिटेन में छोटी छोटी रेलवे लाइनें बनाई गईं, जबकि यूरोप के अन्य देशों में बड़ी लाइनें बनीं। इसका मुख्य कारण यह था कि ग्रेट ब्रिटेन में कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जो किसी न किसी बन्दरगाह से नब्बे मील में अधिक दूरी पर हो।^१

(१०) इसके अनिश्चित ब्रिटिश रेलमार्गों पर अन्य सब देशों की अपेक्षा प्रति मील अधिक पूँजी लगानी पड़ी। इसके कई कारण थे। पहला कारण यह था कि आरम्भ में ब्रिटेन में रेल यातायात के विकास का विरोध ऐसे अनेक आधार पर किया गया जिन्हें आजकल हम अश्वन्त हास्यास्पद और मूर्खनापूर्ण कहेंगे।^२ इन विरोधों को दबाने में रेलमार्गों की लागत बढ़ी।

1 "The railway traffic of the continent necessarily consists of long hauls. In England . . . the hauls for domestic use or export are for short distances only" —Knowles.

2 "The country gentleman was told that the smoke will kill the birds as they passed over the locomotive . . . oats and hay would be no marketable produce . . . cows would cease to yield their milk . . . life and limb would be endangered . . .

—From Francis quoted by Knowles, op., cit., p. 256.

दूसरे, छोटे पैमाने पर अर्थान् छोटी दूरियों के लिए रेलमार्ग बनाये जाने के कारण लागत अधिक पड़ी । तीसरे, नहरों की स्पर्द्धा से बचने के लिए रेलवे कम्पनियों को नहरें खरीदनी पड़ी और इससे भी लागत बढ़ी । चौथे, ब्रिटेन के अधिकांश क्षेत्र में भूमि समतल न होने के कारण मार्ग बिछाने, सुरंगें बनाने तथा पुलों के निर्माण में लागत अपेक्षाकृत अधिक लगी । इसके अतिरिक्त यह स्मरणीय है कि ब्रिटेन को, रेलमार्गों के विकास का प्रथम देश होने के कारण, प्रयोगों (experiments) की लागत देनी पड़ी, जब कि अन्य देशों ने ब्रिटेन के अनुभवों से लाभ उठाया, जो गलतियाँ ब्रिटेन में रेलमार्गों के प्रारम्भिक काल में हुई थी उनमें से अधिकांश गलतियाँ अन्य देशों में नहीं होने दी गईं ।

रेलमार्गों के इतिहास को कुछ कालों (periods) में बाँटा जा सकता है । सन् १८२१ से १८४४ तक रेलमार्गों का प्रयोग काल (period of experiment) था । सन् १८४५ से १८७२ तक का समय रेलवे लाइनों का गठन काल (period of consolidation) कहा जा सकता है जिसमें बड़ी रेलवे कम्पनियों का निर्माण हुआ और नहरों की स्पर्द्धा समाप्त प्रायः हो गई । सन् १८७३ से १८९३ तक का काल राजकीय नियन्त्रण के विकास का था । सन् १८९४ से १९१४ तक की अवधि में रेलवे कंपनियों पर कई कारणों से बुरा प्रभाव पड़ा और उनके लाभार्थ घटे, व्यापारियों और श्रमिकों ने विरोध किये और राष्ट्रीयकरण का प्रश्न उठा ।

सोलहवीं शताब्दी के अन्त की ओर खानों और लोहे के कारखानों के समीप रेल पथों (पटरियों) का उपयोग होने लगा था परन्तु मान डोने वाले डिब्बों (trucks) मुख्यतया घोड़ों द्वारा खींचे जाते थे । उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में ब्रिटिश इंजीनियरों ने लोकोमोटिव (इंजनों) के उपयोग के सम्बन्ध में विचार रखे । रेलवे इंजन की सुधरी हुई डिजाइन का श्रेय जार्ज स्टीफेंसन को है । सन् १८२५ में स्टॉकटन से डालिङ्गटन तक पहला सार्वजनिक रेलमार्ग खुला जिस पर लोकोमोटिव चलने आरम्भ हुए । सन् १८३० में लिंथर पूल से मानचेस्टर तक रेलमार्ग बनकर तैयार हुआ जिस पर जार्ज स्टीफेंसन का प्रसिद्ध लोकोमोटिव 'रॉकेट' काम में लिया गया । सन् १८४२ के अन्त में ब्रिटिश रेलमार्गों की लम्बाई १,८५७ मील थी । इसके बाद रेलों में बहुत वृद्धि हुई, सन् १८४६ में एक बार अल्पकालीन स्थितिलता अवश्य आई थी, सन् १८५४ में रेलमार्गों की लम्बाई ८,९५४ मील हो गई ।

सन् १८४६ में सरकारी हस्तक्षेप आरम्भ हुआ और पार्लियामेण्ट के एक एक्ट द्वारा यह निर्धारित किया गया कि ग्रेट वैंस्टर्न रेलवे के विस्तार के अतिरिक्त सब नई लाइनें ४ फीट ८½ इंच गेज (gauge) की होगी। ग्रेट वैंस्टर्न रेलवे का गेज सात फीट का था। सन् १८४० के पश्चात् दो दशान्दियों (decades) में कुछ रेलवे कम्पनियों का सम्मेलन हुआ और कुछ कम्पनियों ने समझौता द्वारा सीधे गमनागमन (through traffic) की सुविधाओं की व्यवस्था की। सन् १८५४ में रेलवे तथा नहर यातायात एक्ट (Railway and canal traffic Act, 1854) कम्पनियों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया कि वे उचित सुविधाएँ प्रदान करें और उपयोग करने वालों में कुछ को अनावश्यक तरजीह (preference) न दें। सन् १८८८ में रेलवे एण्ड चैनल ट्रैफिक एक्ट द्वारा भाड़ों का वर्गीकरण कर दिया गया और भाड़ों की अधिकतम सीमा निर्दिष्ट कर दी। यह एक्ट सन् १८९३ में लागू हुआ। एक रेल-नहर आयोग (Railway and canal commission) की स्थापना हुई। कोई भी रेल कम्पनी किराये-भाड़ों में परिवर्तन इस आयोग की स्वीकृति के बिना नहीं कर सकती।

प्रथम विश्व युद्ध काल में समस्त रेलमार्गों केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में आगए और उनका प्रबन्ध रेलवे एक्जीक्यूटिव कमेटी को सौंपा गया। युद्धकालीन अनुभव से रेलमार्गों के नियन्त्रण और पुनर्गठन का महत्व प्रतीत हुआ। अतएव सन् १९२१ के रेलवेज एक्ट के द्वारा तत्कालीन १२३ रेल कम्पनियों का चार बड़े समूहों में सम्मेलन कर दिया गया। इन समूहों के नाम ये हैं :

- (१) लन्दन, मिडलैण्ड और स्कॉट्स,
- (२) लन्दन और नॉर्थ ईस्टर्न,
- (३) ग्रेट वैंस्टर्न और
- (४) सदर्न (इंग्लैंड)।

रेल-नहर आयोग के कार्य करने के लिए रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई जिसको किराये-भाड़े का वार्षिक पर्यवेक्षण का काम सौंपा गया।

प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच के काल (inter-war period) में रेलवेज को व्यावसायिक मन्दी और सड़कों की स्पर्धा में चोट पहुँची और उन्हें लाभ उचित दर पर नहीं मिल सका। सन् १९३८ में रेलों की स्थिति में सुधार करने के लिये प्रस्ताव रखे गये परन्तु सन् १९३९ में युद्ध छिड़ जाने

से उन्हें कार्यरूप में नहीं लाया जा सका। युद्ध काल में रेलमार्गों का नियन्त्रण गवर्नमेन्ट रेलवे एक्जीक्यूटिव कमेटी के हाथों में रहा। युद्धोपरान्त सन् १९४७ में ट्रान्सपोर्ट एक्ट पास हुआ जिसके द्वारा रेलमार्ग सार्वजनिक स्वामित्व में आ गये (उनका राष्ट्रीयकरण हो गया)। तब से ग्रेट ब्रिटेन के रेलमार्गों का प्रबन्ध एक इकाई ब्रिटिश रेलवेज के रूप में हो रहा है जिसके प्रादेशिक विभाग (रीजनल सब डिवीजन) छः हैं :

- (१) लन्दन मिडलैण्ड;
- (२) वेस्टर्न;
- (३) ईस्टर्न,
- (४) सदर्न,
- (५) नॉर्थ ईस्टर्न और
- (६) स्कॉटिश।

सन् १९५७ के अन्त में ब्रिटिश रेलवेज की रेल-सड़कें (railroads) १८,९६५ मील और रेलपथ (track) ५१,०७९ मील था।^१ ब्रिटिश रेलों ने सन् १९५७ में २७,४० लाख टन माल ढोया।

४. समुद्री यातायात

वाणिज्य-क्रान्ति लाने में जहाजों (steamships) का योग रेलों से कम नहीं था। लकड़ी के जहाजों का विकास तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भी लगभग उसी काल में हुआ जिसमें ग्रेट ब्रिटेन में हुआ परन्तु लोहे के स्टीमरों और जहाजों का विकास सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ और ब्रिटेन प्रथम देश था जिसने ससार के व्यापार में बड़े पैमाने पर स्टीमरों का प्रयोग प्रारम्भ किया।

कुछ ऊपर के नियमन को छोड़कर ब्रिटेन के जहाज राजकीय नियन्त्रण से मुक्त रहे। इनका एक कारण यह था कि उनके ऊपर नियन्त्रण प्रभावपूर्ण होना भी कठिन था।

ग्रेट ब्रिटेन में समुद्री यातायात का आरम्भ बहुत पहले ही हो चुका था क्योंकि प्रकृति ने ब्रिटेन को द्वीपीय स्थिति प्रदान की है। चौदहवीं शताब्दी के अन्त में वहाँ के शासकों ने जहाजी यातायात के विकास के लिए उपाय किये। पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त की घोर और उसके उपरान्त ब्रिटेन की जहाजी नीति और नौवहन कानून (navigation acts) द्वारा जहाजों यातायात की बहुत

उन्नति हुई। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में संरक्षण की नीति का परित्याग करके जहाजी यातायात को स्वतन्त्र स्पर्धा के लिए खुला छोड़ दिया (नीवहन विधान का संक्षिप्त परिचय इसी अध्याय में आये किया गया है)।

सन् १८१५ से १९१४ तक के सौ वर्षों में जहाजी उन्नति द्रुत गति से होती गई और पोत-निर्माण उद्योग में तथा माल ढोने में ब्रिटेन की सर्वोच्चता संसार में स्पष्ट थी। सन् १८५४ के पश्चात् सकड़ी के पाल वाले जहाजों के स्थान पर लोहे के और फिर इस्पात के जहाज प्रचलन में आये। पाल वाले जहाज हवा पर निर्भर रहते थे और उनकी गति धीमी थी। लोहे-इस्पात के जहाजों में वाष्प शक्ति का प्रयोग हुआ। तकनीकी (technique) में बहुत विकास हुआ। एंजिन में सुधार किये गये और जहाजों के आकार में वृद्धि हुई—वे पहले की अपेक्षा अधिक माल ढोने लगे। सन् १८६६ में स्वेज नहर खुलने के पश्चात् जहाजी यातायात में वाष्प शक्ति के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई क्योंकि पाल वाले जहाज स्वेज मार्ग के लिए अनुपयुक्त थे।

वाष्प से चलने वाले जहाजों (steamships) के दो प्रकार थे, एक लाइनर (liner) और दूसरे ट्रेम्प (tramp)। लाइनर निश्चित मार्गों से पूर्व निश्चित समय पर चलते थे और यात्रियों, डाक तथा ऐसे सामान को ले जाते थे जिन्हें शीघ्र पहुँचाना आवश्यक था क्योंकि लाइनर तेज चलते थे। ट्रेम्प माल ढोने का ही काम करते थे और मार्ग में रुकते हुए जाते थे और उनका कोई निश्चित मार्ग या समय नहीं था। नये स्थानों में व्यापार करने के लिए आरम्भ में ट्रेम्प काम में लाये जाते थे और व्यापार नियमित हो जाने पर उसे लाइनर ले लेते थे। जमाया हुआ मांस और तेल ढोने के लिए विशिष्ट प्रकार के जहाज काम में आने लगे। सन् १८८० में ब्रिटेन की सामुद्रिक शक्ति संसार में सबसे अधिक थी, पोत-निर्माण उद्योग में वह अग्रणी था और संसार का अधिकांश समुद्री व्यापार ब्रिटिश जहाजों द्वारा होता था।

सन् १८८० के उपरान्त जहाजी यातायात में ब्रिटेन को विदेशी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। सन् १८८१ में फ्रान्स में जहाजी यातायात के विकास के लिए सरकार ने अनेक रूपों में आर्थिक सहायता (subsidies) देना आरम्भ किया और सन् १८८५ में जर्मनी, इटली, आस्ट्रिया, हंगरी, जापान, रूस, डेन्मार्क, स्पेन, बेल्जियम और संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी सहायता दी जाने लगी। जर्मनी जहाजी व्यवसाय में ब्रिटेन का बहुत बड़ा प्रतिद्वन्द्वी बन गया।

सन् १८८० के बाद के वर्षों में विदेशी प्रतियोगिता का मुकाबला करने के लिए ब्रिटिश जहाजी कम्पनियों ने 'रिंग' (rings) अथवा कार्नेल्सो द्वारा जहाजी भाड़े निश्चित करने के लिए समझौते किए।^१ नये प्राधुनिकतम जहाज बनाए गए। एक नई प्रथा (deferred rebate system) अपनाई गई जिससे अन्तर्गत उन ग्राहकों को जो ब्रिटिश जहाजी कम्पनियों से ही नियमित रूप से माल भिजवाते थे, बाद में (छ. माह बाद) दस प्रतिशत की छूट दी जाती। विदेशी कम्पनियों से समझौते किये गये जिनके अनुसार जहाजी व्यापार के लिए प्रदेश (territories) बांटे गये परन्तु ये समझौते ठीक प्रकार नहीं चल पाने थे। ब्रिटिश जाहाजी कम्पनियों ने संयोग (combinations) और समामेलन (amalgamations) के द्वारा स्पर्धा क्षति बढ़ाई।

प्रथम महायुद्ध काल (१९१४-१८) में ब्रिटिश जहाजों की भारी क्षति हुई—मनेक जहाज नष्ट हो गए। दूर के व्यापार से ब्रिटिश जहाजों के हट जाने से जापान इत्यादि अन्य देश दूरवर्ती व्यापार को हथिया बैठे। युद्ध काल में ब्रिटिश जहाजों को सरकारी नियन्त्रण के कारण भी कम लाभ हो सके। सरकार ने जहाजी भाड़ों की दरें निश्चित कर दी थी और उनके ऊपर अतिरिक्त लाभ कर (excess profits tax) आरोपित कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका भी ब्रिटेन का प्रतियोगी हो गया। इस प्रकार युद्धोपरान्त काल में ब्रिटिश जहाजी यातायात को दो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, एक तो जहाजों की कमी और दूसरी जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की स्पर्धा। युद्ध काल में जहाजों की ठीक प्रकार मरम्मत भी नहीं हो सकी थी। परन्तु युद्धकाल में ब्रिटेन में पोत-निर्माण क्षमता (capacity) का सचय हुआ था जिससे युद्धोपरान्त काल में जहाजी टन भार में वृद्धि की जा सकी और दूसरा लाभ यह समझा जा सकता है कि जर्मनी की प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई।

सन् १९२० के उपरान्त विदेशी व्यापार में कमी के कारण एक भारी मन्दी शुरू हुई और सन् १९२६ तक चालू रही। उसके बाद हासत सुधरी। सन् १९२६ से १९३३ तक विश्वव्यापी मन्दी का काल था। जहाजी यातायात उसके प्रभाव से अधूता न रह सका। इस काल में जहाजी उद्योग को बहुत क्षति पहुँची।

१. पहली वार्न्डॉस सन् १८७५ में संगठित हुई थी और डेफर्ड रिबेट प्रणाली सन् १८७७ में आरम्भ हुई।

द्वितीय विश्वयुद्ध (१९३९-४५) काल में जहाजों उद्योग और जहाजी यातायात सरकारों नियन्त्रण में आ गये। इस काल में जहाज सम्बन्धी किसी भी प्रकार की हड़ताल अवैधानिक घोषित कर दी गई थी और शत्रु-देशों के साथ विदेशी व्यापार करने और उन्हें जहाज किराये पर देने को मनाही कर दी गई। अधिकतर जहाजों का बीमा करा दिया गया था परन्तु युद्धकालीन जोखिमों के कारण प्रीमियम की दरें बहुत ऊँची थी। युद्धकाल में जहाजी टन-भार की भारी क्षति हुई जिसे युद्धोत्तर काल के कई वर्षों में भी पूरा करना सम्भव नहीं हो पाया।

सन् १९४८ में लन्दन में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया जिसमें समुद्री यात्रा की सुविधा के प्रश्न पर विचार किया गया। युद्धोत्तर काल में पुराने जहाजों के सुधार और मरम्मत की समस्या के अनिश्चित धक्कट कठिनाई बन्दरगाहों पर कर्मचारियों की हड़तालों के कारण उत्पन्न हुईं जिनके कारण भारी क्षति हुई।

सन् १९५० में ब्रिटेन के व्यापारी जहाजों का टन^१ भार लगभग २०३ लाख था, सन् १९३९ में १७९ लाख था और ३० जून १९५७ को १९९ लाख था।^२ सन् १९५७ वर्ष के पुनर्गठन अनुदान में जहाजी यातायात का योग (net contribution) साठे ग्यारह करोड़ पाँच मूल्य का था।^३ जहाजों की संख्या ५,६२७ थी। व्यापारिक जहाजों के सम्बन्ध में एक आधुनिक प्रवृत्ति यह देखी गई है कि ट्रैम्प जहाजों में कमी हुई है और टैंकर (tankers) की संख्या और उनके आकार में वृद्धि हुई है। इन टैंकरों के लगभग दो तिहाई तेल कम्पनियों के हैं। नये प्रकार के विशिष्ट जहाज भारी माल, जैसे, कच्ची धातुएँ (ores), ढोने के लिए बनाये गये हैं।

५. नौवहन सम्बन्धी कानून तथा नीति (Navigation Acts and Policy)

ग्रेट ब्रिटेन में नौवहन सम्बन्धी एक के बाद एक कई एक्ट पारित हुए जिनका उद्देश्य ब्रिटेन के जहाजी व्यापार (shipping) तथा पोत-निर्माण उद्योग (Ship-building industry) को प्रोत्साहन देना था। प्रथम एक्ट सन्

1. Gross tons of merchant shipping.

2. Britain : An Official Handbook, 1959, p. 335.

3. Ibid.

१३८१ में पास हुआ था जिसके अनुसार यह आवश्यक कर दिया गया था कि ब्रिटेन के सभी आयात-निर्वात आगल जहाजों द्वारा लाये लेजाये जायेंगे। जहाजों की कमी के कारण यह कानून चल न सका और स्थगित करता पड़ा।

सन् १४८५ में यह कानून पास हुआ कि विदेशी शराब केवल इंग्लैण्ड के जहाजों में ही, जिनमें सब आगल कर्मचारी हों, आयात की जाएगी। सन् १५३२ और १५४० में भी इसी प्रकार की व्यवस्था हुई परन्तु उन्हें सन् १५५६ में रद्द कर दिया गया, तथापि आगल जहाजों को परोक्ष रूप से प्रोत्साहन दिया जाता रहा। सन् १५५६ के एक्ट के अनुसार इंग्लैण्ड के जहाजों के अतिरिक्त अन्य जहाजों द्वारा लाये गये माल पर अधिक ऊँचे कर (duties) निर्धारित किये गये थे। सन् १५६३ में सम्पूर्ण तटीय व्यापार (Coastal Trade) ब्रिटिश जहाजों के लिए सुरक्षित (reserve) कर दिया गया।

सत्रहवीं शताब्दी में उपनिवेशों तथा बागोचो (plantations) के विकास के साथ इंग्लैण्ड के जहाजों यातायात का नया युग प्रारम्भ हुआ। सन् १६५१ के नौवहन कानून (Navigation Act) में जो नीति प्रपनाई गई वह निम्नलिखित तथ्यों से प्रकट है :—

(१) इंग्लैण्ड और उसके उपनिवेशों के बीच होने वाला व्यापार केवल इंग्लैण्ड अथवा उपनिवेशों के जहाजों में ही हो सकता था।

(२) इन जहाजों के स्वामी, कप्तान तथा अधिकतर कर्मचारी आगल हों, या उपनिवेशों के हों, यह आवश्यक था।

(३) यह आवश्यक किया गया था कि आगल जहाजों द्वारा लाया गया माल (Cargo) इंग्लैण्ड लाया जायगा, किसी बीच के बन्दरगाह पर नहीं उतारा जाएगा।

(४) उपनिवेशों के लिए भी यह आवश्यक किया गया था कि वे आपस का व्यापार आगल जहाजों द्वारा ही करें।

(५) विदेशी जहाजों की व्यापार के कुछ सीमित क्षेत्रों में ही जाने की अनुमति थी।

इस एक्ट की कुछ व्यवस्थाएँ स्पेन के साथ युद्ध छिड़ जाने के कारण व्यवहार में न आ सकी। सन् १६६० में नया एक्ट बना। इसमें इंग्लैण्ड के समुद्रों में विदेशी जहाज पाये जाने पर सामान सहित जप्त किए जाने की व्यवस्था की गई। उपनिवेशों की कुछ उपजों (products) को परिगणित किया गया जिन्हें अन्य देशों को जहाजों द्वारा नहीं पहुँचाया जाता था। विदेशी

जहाजों द्वारा लाये गये माल पर सन् १९५१ के एक्ट की तरह उच्च कर (higher duties) चालू रखे गये ।

सन् १९६३ और १९७२ में सन् १९६० के एक्ट में संशोधन किये गये जिनके द्वारा पहले की अपनाई गई जहाजों नीति को और भी दृढ़ कर दिया गया और परिगणित वस्तुओं में कुछ रद्दोदत्त किये गये । उपनिवेशों में प्रतिनिधि शासक जहाजी नीति को क्रियान्वित करने का पूरा ध्यान रखते थे । उपनिवेशों में एडमिरैलिटी कोर्ट और कस्टम दफ्तर स्थापित किये गये ।

उपयुक्त एक्टों में अपनाई गई ब्रिटिश जहाजी नीति अपने उद्देश्यों में इस दृष्टि में सफल हुई कहीं जा सकती है कि इसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश जहाज दूर दूर तक माल ढोने लगे । ब्रिटेन महत्वपूर्ण वितरक देश बन गया और उसके विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई । यह कहने में शायद अशुक्ति न होगी कि बहुत कुछ नौ-वहन सम्बन्धी कानूनों के कारण ही ब्रिटेन ससार का श्रेष्ठ सामान वाहक, जहाज-निर्माता (ship builder) तथा प्रमुख व्यापारिक राष्ट्र बन गया ।

सन् १८४५ के आसपास ये कानूनी उपाय पुराने (obsolete) पड़ गये थे क्योंकि अमेरिका आश्रित नहीं रहा था और अनेक उपनिवेशों के अपने निजी जहाज हो गये थे । अतएव सन् १८४६ में तटवर्तीय व्यापार सम्बन्धी वाक्यांश (clause) को छोड़कर शेष अधिनियम को रद्द कर दिया गया । सन् १८५४ में जब अबाध व्यापार की नीति अपनाई जा रही थी तो तटवर्तीय व्यापार को भी खुला छोड़ दिया गया और कानून की पुस्तकों में से जहाजी सन्नियम के अन्तिम विह्व भी लुप्त हो गये ।^१

सन् १८५४ के बाद के जहाजी विक्रमों तथा नीति सम्बन्धी परिवर्तनों का उल्लेख इसी अध्याय में पहले ही किया जा चुका है ।

६. वायु यातायात (Civil Aviation)

ग्रेट ब्रिटेन की गणना उन देशों में की जाती है जिनमें वायु यातायात का विकास पहले पहल हुआ और डाक तथा यात्रियों के लिए नियमित हवाई यात्रा (regular service) आरम्भ की गई । ब्रिटेन में हवाई जहाज द्वारा डाक भेजने का काम सर्वप्रथम सन् १९११ में (सम्राट् जार्ज पंचम के सिंहासन

1. "The last trace of this great maritime code disappeared from the statute book."

समारोह के समय) हुआ। ब्रिटिश सिविल हवाई यातायात का उद्घाटन २५ अगस्त १९१६ को हुआ जब लन्दन (हैन्सली) से पेरिस (ली बुरगेट) के बीच एक कम्पनी एयरकाप्ट ट्रान्सपोर्ट एण्ड ट्रेविन लिमिटेड द्वारा यात्रियों के लिए दैनिक यात्रा (daily passenger service) की सुविधा प्रारम्भ हुई। सन् १९२३ तक हवाई यातायात की चार छोटी-छोटी कम्पनियाँ थीं। हवाई यातायात सहायता समिती (Civil Air Transport Subsidies Committee 1923) ने उनके एकीकरण (merger) की सिफारिश की जिसका दृष्टिकोण यह था कि समुद्रपार हवाईमार्गों का विकास हो सके। अतः अप्रैल १९२४ में चारों छोटी कम्पनियों को मिलाकर इम्पोरियल एयरवेज लिमिटेड की स्थापना हुई जिसकी दस वर्षों के लिए कुल दस लाख पाउंड को सरकारी वार्षिक सहायता (ग्रान्ट) मिली। संचालक मण्डल (Board of Directors) में सरकार का प्रतिनिधित्व रखा गया। सन् १९२७ में काहिरा और बसरा के मध्य एयर सर्विस चालू की गई और सन् १९२९ में इंग्लैण्ड को भारतवर्ष से मिला दिया गया। सन् १९३१ में मध्य अफ्रीका के लिए हवाई यातायात प्रारम्भ किया गया। लन्दन और आस्ट्रेलिया के बीच मेल सर्विस (डाक) सन् १९३४ में और पॅसिफिक सर्विस सन् १९३५ में प्रारम्भ हुई।

सन् १९३७ के पश्चात् अटलांटिक महासागर के पार हवाई यातायात प्रारम्भ हुआ। सन् १९३६ में एक विशेष अधिनियम (Act) द्वारा ब्रिटिश आवरसाज एयरवेज कॉर्पोरेशन (B. O. A. C.) की स्थापना हुई और सन् १९४० में इम्पोरियल एयरवेज लिमिटेड तथा ब्रिटिश एयरवेज लिमिटेड का प्रबन्ध बी० ए० सी० ने ले लिया।

युद्धकाल में बी० ए० सी० ने युद्ध सम्बन्धी आवश्यकताओं की दिशा में समुद्र पार हवाई सेवाएँ चलाईं। युद्ध समाप्त होने के समय सन् १९१६ की प्रेरणा हवाई यातायात से दूने अधिक यात्रा और तिगुने से अधिक माल ले जाया जाना लगा था। हवाई यातायात के विस्तार में बाधक बात यह थी कि हवाई जहाजों का कमी थी जिसकी पूर्ति मिलिट्री के वायुयानों और विदेशों से विमानों की खरीद करके की गई। बी० ए० सी० के अतिरिक्त दो अन्य निगमों (corporations) की स्थापना सन् १९४६ में सिविल एविएशन एक्ट द्वारा की गई : (१) ब्रिटिश यूरोपियन एयरवेज तथा (२) ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज (B. S. A. A.)। सन् १९४६ में बी० एस० ए० ए० को बी० ए० सी० में मिला दिया गया।

ब्रिटिश हवाई यातायात के विकास और देखभाल का उत्तरदायित्व ट्रान्सपोर्ट एण्ड सिविल एविएशन मन्त्रालय पर है। वायुमार्गों के उत्पादन तथा उसकी देखभाल का भार सप्लाय मन्त्रालय पर है।

प्रश्न

1. "The general results (of the growth of mechanical transport after 1870) were revolutionary." —Knowles

Briefly indicate these results and discuss the resulting changes in British foreign trade.

2. 'Canals, like water power, were a mere episode.' Discuss and point out the part played by them in England's economic development

3. How did England develop her mercantile marine in modern times?

4. "The spirit of the Medieval Age favoured regulation." Explain this statement, and illustrate it with reference to the enactment of a long series of Navigation Acts from 1533 upto the middle of the 19th century

अध्याय ७

श्रम आन्दोलन

(Working Class Movements & Trade Unions)

[श्रम संघों का जन्म, प्रारम्भिक कठिनाइयाँ, आन्दोलन की प्रगति, संगठन और सम्मेलन, नए एक्ट-पंजीयन की व्यवस्था, बीसवीं शताब्दी में, श्रम संघों के मुख्य कार्य तथा श्रमिकों की दशाओं पर उनका प्रभाव, प्रश्न ।]

ग्रेट ब्रिटेन के लगभग समस्त उद्योगों में न्यूनाधिक संख्या में श्रमिक व्यापारिक संघों (Trade Unions) में संगठित हैं। कुछ उद्योगों में तो लगभग सभी श्रमिक श्रम संघों के रूप में संगठित पाये जाते हैं। ब्रिटेन में श्रम आन्दोलनों का इतिहास दो सौ वर्षों में भी अधिक पुराना है। इस अध्याय में श्रम संघ आन्दोलन का संक्षिप्त परिचय दिया गया है।

श्रम संघों का जन्म

सई औद्योगिक प्रणाली के विकास के साथ १८वीं शताब्दी में पूँजी और श्रम के बीच मतभेद उत्पन्न हुए जिन्होंने कालान्तर में वर्ग संघर्ष का रूप ग्रहण कर लिया। मजदूर और मालिक (employer) के बीच निजो सम्पर्क समाप्त हो चुका था। दूसरी ओर, एक ही छत के नीचे काम करने तथा सम्पर्क की अनेक सुविधाओं के कारण मजदूरों में परस्पर सम्बन्धों के प्रबल बंधे। मजदूरों में वर्ग भावना जग रही थी। निम्न मजदूरियाँ, काम के अधिक घण्टे, जीवन निर्वाह की लागत में वृद्धि इत्यादि के कारण मजदूरों को संगठित होने और आवाज उठाने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार श्रम संघों (Trade Unions) का जन्म हुआ।

यह कहा जा सकता है कि श्रमिक संघ औद्योगिक क्रान्ति की उपज थे। "कारखाना प्रणाली के कारण संघ सम्भव हुए और कारखाने की दशाओं ने उसे आवश्यक कर दिया"^१ श्रमिकों का शोषण हो रहा था और श्रमिकों की

1. "The factory made the Union possible and the condition of the factory made it necessary."

—Shadwell : Industrial Efficiency.

शोचनीय दशा पराकाष्ठा पर पहुँच गई थी। काम की दशाएँ कारखाना-प्रणाली के पूर्व भी सम्भवतः बहुत अच्छी नहीं थी परन्तु औद्योगिक संगठन की नई प्रणाली में वर्गीय चेतना जाग उठी थी जिसे दबाने के प्रयत्न विफल हो गए।

प्रारम्भिक कठिनाइयाँ

प्रारम्भ में श्रमिक सघों को कॉमन लॉ (Common Law) के सिद्धान्तों के विरुद्ध माना गया। उन्हें पड्यत्र (conspiracy) तथा व्यापार में बाधक (in-restraint of trade) कहकर उनका विरोध किया गया। मुख्य प्रारम्भिक कठिनाइयाँ निम्नलिखित थीं :—

(१) सन् १७६६ में गैरकानूनी संगठनों (unlawful combinations) को रोकने के लिए एक एक्ट पार हुआ जिसको सन् १८०१ में और कड़ा कर दिया। इस कानून के द्वारा मजदूरों के लिये काम के घंटों में कमी, मजदूरी में वृद्धि इत्यादि के लिये मिनरर सम्झौते करना, मजदूरों के मालिकों से प्रसविदे करने में रुकावट डालना अथवा इन उद्देश्यों के लिए भ्रम इत्यादि करना अवैध घोषित कर दिया गया।

(२) श्रमिक निर्घन थे अतः मजदूरों का चन्दा देने में समर्थ नहीं थे जिसके कारण सङ्घ षोप में सघ के कार्यों के लिए आवश्यक रकम प्राप्त नहीं हो पाती थी।

(३) आवागमन के साधनों के पर्याप्त विज्ञान के अभाव में श्रमिकों के सङ्गठन का क्षेत्र सीमित रहा।

(४) सरकार और मिल-मालिकों की दमन-नीति का घातक प्रभाव पड़ा। मजदूरों और उनके नेताओं का कड़ी मजबूरी थी जानी थी तथा बड़े कानून थे। सन् १८१६ में इस दिशा में छः एक्ट पास हुये थे।

(५) श्रमिकों में नेताओं की कमी थी।

(६) नापाओं की तथा उद्देश्यों की विविधता के कारण श्रमिकों में पार्ष्वय बना रहता था।

आन्दोलन की प्रगति

उपरोक्त कठिनाइयों के पश्चात् भी श्रमिक सङ्घ आन्दोलन जोर पकड़ता गया। मजदूरों के गुप्त संगठन होने लगे। कभी कभी हिमापूर्ण हड़तालें हुईं। सन् १८२४ में एक एक्ट पार हुआ जिसके द्वारा हिमात्मक तरीकों को कानून-विरुद्ध और दण्डनीय अपराध बताया गया परन्तु मजदूरों बढ़ाने, काम के

घंटों में कमी कराने इत्यादि के उद्देश्य से किये गये मजदूरों के सङ्गठन कानून सम्मत (lawful) माने गये। सन् १८२५ में मालिकों (employers) ने इसका विरोध किया और उसे रद्द करा दिया तथापि काम की दशाओं के सम्बन्ध में परस्पर सलाह-मशविरा करने के लिये श्रमिकों के हित में सङ्गठनों को न्याय सम्मत माना गया। परिणामस्वरूप, श्रमिक मजदूरी की सहा में वृद्धि होने लगी। हड़तालें भी अधिक होने लगी, परन्तु बहुधा उनसे श्रमिकों को हानि हुई।

संगठन और समामेलन (Consolidation and Amalgamation)

इस अवस्था में सङ्घों को संगठित करने के लिये आन्दोलन हुआ। सन् १८२६ में मृत कातने वालों का एक राष्ट्रीय मजदूर संगठित किया गया। इसी वर्ष इमारतों का काम करने वालों (building workers) का संगठन स्थापित हुआ। सन् १८३० में लगभग डेढ़ सौ श्रम सङ्घों को मिला कर श्रमिकों की रक्षा के लिए 'नेशनल एसोसिएशन' बनाया गया। सन् १८३४ में जनरल ट्रेड्स यूनियन बनी जिसका नाम बाद में ग्राण्ड कन्सोलिडेटेड नेशनल ट्रेड्स यूनियन (Grand Consolidated National Trades Union) पड़ा। इसके सदस्यों की संख्या पाँच लाख में अधिक थी। भीतरी भगड़ों के कारण यह संगठन शीघ्रकाल में ही समाप्त हो गया।

ग्राण्ड श्रम-सङ्घों के इतिहास में सन् १८४५ के बाद का समय महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। कई राष्ट्रीय संगठन बने और प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों में व्यापारिक कौंसिलें (Trade Councils) बनाई गईं। (नगर के विभिन्न मजदूरों की स्थानीय शाखाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली समुक्त कमेटी ट्रेड कौंसिल कहलाती थी।) प्रथम ट्रेड कॉमिल सन् १८४८ में लिबरपूल में स्थापित हुई थी। तद्परांत सभी औद्योगिक नगरों में कौंसिलों की स्थापना हुई जिनके प्रतिनिधियों की वार्षिक राष्ट्रीय सभाएँ होने लगीं।

नये एक्ट—पजीयन की व्यवस्था

सन् १८६५-६६ में हड़तालें और ताताबन्दियाँ अधिक हुईं जिनमें मशीनों तथा सम्पत्ति की क्षति पहुँची। श्रम सङ्घों के पदाधिकारियों को इनका कारण समझा गया। सन् १८६७ में एक साही आयोग नियुक्त किया गया जिसकी सिफारिशों पर नए एक्ट पास किये गये जिनमें दशाएँ सरल कर दी गईं। श्रम

सह की परिभाषा अधिक व्यापक कर दी गई जिसके अनुसार कोई भी मिलन चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी, और जिसका उद्देश्य मजदूरों और मालिकों, अथवा मजदूरों और मजदूरों, अथवा मालिकों और मालिकों के बीच में सम्बन्धों का नियमन करना हो, अथवा किसी घन्वे या व्यापार के संचालन के विषय में प्रतिबन्धक दशाएँ आरोपित करना हो, ट्रेड यूनियन कहलायेगा।¹

थम सङ्घों के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई कि सङ्घ के कोई सात सदस्य उसके नियमों (rules) पर हस्ताक्षर करके उसका पंजीयन करा सकते हैं। व्यापार में बाधक होने के आधार पर अब थम सङ्घों को अवैध नहीं समझा जा सकता था। यह भी व्यवस्था हो गई कि षड्यन्त्र (conspiracy) का दोष लगाकर किसी भी व्यक्ति को अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता यदि वही काम उसके अकेले के करने पर अपराध न समझा जाय। थम सङ्घों को जायदाद रखने तथा कोष संचित करने के अधिकार भी दिये गये।

सन् १८७१ से १९०० तक

कानूनी प्रतिबन्धों के हट जाने से सन् १८७१ के उपरान्त थम संघों का काफी विकास हुआ। परन्तु सन् १८७१ से १८८० तक के वर्षों में व्यावसायिक मन्दो (अवसाद काल) के कारण और हटतालों में असफलताओं के कारण थम संघ आन्दोलन को घबका पहुँचा। एक दशाब्दी (दस वर्ष) पश्चात् फिर विकास आरम्भ हुआ। सन् १८९९ में थम संघों का एक फ़ेडरेशन (Federation) स्थापित हुआ जो थमिकों के सामान्य हितों का ध्यान रखे। थम संघों के गठन (consolidation) के कारण उनकी संख्या तो कुछ घटी परन्तु सदस्यता में वृद्धि हुई।

वीमबी दाताब्दी में

थम संघ आन्दोलन को सन् १९०१ में टैफ वैल अभियोग (Taff Vale Case) में बहुत आघात पहुँचा। मामला यह था कि वेल्श की टैफ वैल रेलवे कम्पनी के कर्मचारियों ने हड़ताल की और रेलवे कम्पनी की संपत्ति को भारी हानि पहुँचाई। कम्पनी ने रेलवे सर्वेंट्स की सम्मेलनवृत्त सोसाइटी (Amalgamated Society of Railway Servants) पर मुकद्दमा चलाया

1. "Any combination, whether temporary or permanent, for regulating the relations between workmen and masters, or between masters and masters, or for imposing restrictive conditions on the conduct of any trade or business . . ."

कि इस सोसाइटी ने ही कम्पनी के कर्मचारियों को भड़काकर कम्पनी की सम्पत्ति को हानि पहुँचाई। सन् १८७१ और १८७६ में पार्लियामेंट के अनुसार, जैसा कि सोसाइटी ने अपने बचाव के पक्ष में (in defence) कहा, संघ अपने सदस्यों के कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता और संघ के कोष (funds) मुआवजा देने के लिए इस्तेमाल नहीं किये जा सकते। परन्तु अदालत ने निर्णय दिया कि सोसाइटी को कम्पनी की हानि के लिए तेईस हजार पौण्ड हजनि के रूप में देने होंगे और कहा कि संघ को उसके सदस्यों के कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराना अनुचित नहीं है। इस निर्णय के विरुद्ध सोसाइटी ने अपील की परन्तु ऊँची अदालतों ने भी फैसला वही रखा। यह थम-थान्दालन कलिंग ईवी आपत्ति प्रतीत हुई क्योंकि यह समझा जाता था कि थम संघ मुकद्दमों के प्रभाव से दूर थे।

एक आन्दोलन द्वारा यह प्रयत्न किया गया कि कानून द्वारा थम संघों को मुकद्दमेबाजी के प्रभाव से बचाया जा सके। परिणामस्वरूप सन् १९०२ में एक एक्ट (Trade Unions and Trade Disputes Act) पास हुआ जिसके द्वारा पूर्व सम्मत कार्यों को तथा धान्निपूर्ण बिकेटिंग इत्यादि तरीकों को न्यायोचित माना और संघ द्वारा या संघ की ओर से किये गये हिमापूर्ण कार्यों पर भी अदालतों कार्यवाही करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया।

ओस्बोर्न अभियोग—थम संघों के इतिहास में एक और उल्लेखनीय घटना सन् १९०६ में हुई। सन् १९०६ के पूर्व थम संघों में यह प्रचलन था कि वे सघ के कोषों में न पालियामेंट के थम सदस्यों का समर्थन करने के लिए भी व्यय किया करते थे तथा इसने लिए सघ के सदस्यों में चन्दा इकट्ठा किया जाता था। रेलवे सर्वैण्ट्स की समावेलनइत सोसाइटी (Amalgamated Society of Railway Servants) की वाल्थमस्टन (Walthamston) शाखा के सेक्रेटरी वाल्टर व्ही ओस्बोर्न (Mr. Walter V. Osborne) ने इस प्रथा का विरोध करते हुए एक मुकद्दमा चलाया कि इन प्रथाओं नियमों में परे (ultra vires) घोषित कर दिया जाय। सार्डम की सभा (House of Lords) का अन्तिम निर्णय ओस्बोर्न के पक्ष में हुआ जिसके अनुसार यह तय हुआ कि “कोई भी व्यापारिक संगठन या थम संघ कानूनी तौर पर अपने सदस्यों में ऐसे कोषों के लिए जिसका उपयोग संमत्सदस्यों (M. P.S) के लिए किया जाय चन्दा वसूल नहीं कर सकता।” यह निर्णय थम संघों की राजनीतिक क्रियाओं के लिए बाधक था अतः इनको उलटने के लिए आन्दोलन छेड़ा गया।

सन् १९१३ में एक श्रम सघ कानून (Trade Union Act) पास हुआ जिसमें ट्रेड यूनियन की परिभाषा में उन समस्त मिलनों को सम्मिलित किया गया जिनके नियमों के अन्तर्गत उनके मुख्य उद्देश्य कानून सम्मत हो।^१ इस प्रकार परिभाषा काफी व्यापक कर दी गई। उद्देश्यों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करते हुए एक्ट में कहा गया कि वे व्यापार या घंघे (Trade) के नियमन तथा मदद्यों के लाभ के लिए होने चाहिए। कोषों के उपयोग के सम्बन्ध में कहा गया कि श्रम सघ (Trade Union) अपने कोषों (funds) का उपयोग ममस्त न्यायपूर्ण (lawful) उद्देश्यों के लिए कर सकता है परन्तु राजनीतिक कार्यों के लिए यदि उनका उपयोग किया जाए तो दो शर्तें पूरी होनी चाहिए :

(१) गुप्त मतदान (secret ballot) द्वारा यह प्रस्ताव पास हो जाना चाहिए कि कोषों का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए होगा,

(२) ऐसे कोषों में चन्दा देना सदस्यों के लिए अनिवार्य नहीं होना चाहिए। इस एक्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि जो सदस्य राजनीतिक कोष में कुछ न देने का विचार करें वे संघ को इसके सम्बन्ध में सूचित कर दें।

सन् १९२७ में पाम एक्ट के द्वारा राजनीतिक कोष में चन्दा देने वालों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि, चन्दा न देने वालों के दबाव में चन्दा देने की प्रपनी इच्छा को सूचना दें। सन् १९१३ और १९२७ के एक्टों में इस विषय में अन्तर यह था कि जबकि पहला एक्ट राजनीतिक कोष में चन्दा देने की क्रिया को सामान्य मानता था, सन् १९२७ के एक्ट में उसे असामान्य (exceptional) समझा गया। सन् १९२७ के एक्ट की व्यवस्था के अनुसार बहुत से सदस्य चन्दा देने से बच गये।

ब्रिटेन में श्रम-संघों (Trade Unions) के विकास में समय-समय पर अनेक बाधाएँ आने पर भी वहाँ के श्रम सघ आन्दोलन का इतिहास प्रगति का इतिहास कहा जा सकता है। सन् १८८६ में ब्रिटेन में श्रम संघों की कुल सदस्य संख्या १६,८८,५३१ थी, उत्तीसवीं शताब्दी के अन्त में २३,४७,४६१ हो गई तथा सन् १९५७ के अन्त में ६७ लाख के लगभग हो गई।

सन् १९५७ के अन्त में ग्रेट ब्रिटेन में १७ बड़े संघ थे जिनमें कुल के लगभग दो-तिहाई सदस्य थे। इन १७ संघों के अतिरिक्त ६४७ श्रम संघ और

1. "Any combination, whether temporary or permanent, the principal objects of which are, under its constitution, statutory objects"

थे। लगभग ८० श्रम संघ (ट्रेड यूनियन), जिनमें बड़े संघ सम्मिलित हैं, ऐसे हैं जिनके कोष लेबर पार्टी (Labour Party) का समर्थन (support) करने के लिए उपयोग किये जाते हैं।

इंग्लैण्ड और वेल्स में ५०० से अधिक ट्रेड कौंसिलें (नगर के विभिन्न संघों की स्थानीय शाखाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली संयुक्त समितियाँ) हैं जो २२ फ़ेडरेशनों (federations) में समूहीकृत हैं।

श्रम संघों के मुख्य कार्य तथा श्रमिकों की दशाओं पर उनका प्रभाव

श्रमिकों के लिए श्रम संघ आन्दोलन बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है। ब्रिटेन में श्रम का राजनीतिक दल की भाँति विकसित होना श्रम संघ आन्दोलन के अभाव में कदाचित् सम्भव हो नहीं था। श्रम संघों के प्रभाव के कारण फैक्टरी प्रणाली की अनेक बुराइयों का अन्त हो गया। सर्वत्र आठ घंटे के काम का दिन, सामाजिक बीमा की सुविधाएँ, बालकों से काम लेने की बुराई का अन्त इत्यादि सफलताओं का श्रेय श्रम संघ आन्दोलन को प्राप्त है। उनके आन्दोलनों के कारण श्रमिकों की मजदूरियों में वृद्धि हुई है तथा उन्हें कई प्रकार के भत्ते मिलने लगे हैं। श्रमिकों के कल्याण के अनेक कामों में प्रगति हुई है। इनके अतिरिक्त, ब्रिटेन में श्रम संघ आन्दोलन के द्वारा श्रमिकों की सामाजिक दशाओं में सुधार तथा शिक्षा का विकास हुआ है। संघों की ओर से ब्रिटेन में सदस्यों को उत्पादन, व्यवस्था इत्यादि के सम्बन्ध में तथा टैकनीकल शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल खोले गये हैं। समाजवादी प्रवृत्तियों के विकास के साथ श्रम संघ आन्दोलन से भविष्य को ऊँची आशाएँ हैं।

प्रश्न

1. Trace the growth of the Trade Union Movement in England discussing its main activities. How has it influenced the conditions of labour?

2. Describe the course of the Trade Union Movement in England in the nineteenth century, and state the changes in its objects and methods in the twentieth century.

3. Give a short historical sketch of the the working class movement in England during the nineteenth century.

अध्याय ८

सामाजिक सुरक्षा का विकास (Growth of Social Security)

[निर्धन सहायतायें कानून, सामाजिक बीमा की आवश्यकता, सामाजिक बीमा का विकास, बीवरिज योजना, ब्रिटेन की वर्तमान सामाजिक बीमा व्यवस्था, पारिवारिक भरो, राष्ट्रीय बीमा, औद्योगिक क्षति बीमा योजना, राष्ट्रीय सहायता तथा कल्याण सेवाएँ, प्रश्न ।]

समाज में मनुष्य बीमारी, दुर्घटना, बेरोजगारी और मृत्यु के संकटों से ग्रस्त होता रहता है। पिछली शताब्दी तक ब्रिटेन में ही नहीं, सभी देशों में सामान्यतया व्यक्तियों का यह विश्वास था कि मनुष्य अपने संकटों का कारण स्वयं है—अपने भालस्य, स्वभाव, कर्म अथवा भाग्य के फलस्वरूप उसे गरीबी तथा अन्य प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ना है। सामाजिक बीमा सेवाओं (social insurance) अथवा सामाजिक सुरक्षा का विकास बदलने हुए सामाजिक दृष्टिकोण का परिचायक है। औद्योगिक क्रान्ति के पूर्व सामाजिक संगठन कुछ इस प्रकार का था कि उस समय आधुनिक प्रकार के सामाजिक सुरक्षा के उपायों की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई थी, परन्तु कालान्तर में आर्थिक संगठन में होने वाले परिवर्तनों के साथ-साथ सामाजिक बीमा सेवाओं की व्यवस्था अत्यावश्यक हो गई।

सामाजिक सुरक्षा या सामाजिक बीमा का अर्थ उम्र प्रणाली में है जिसके अन्तर्गत व्यक्ति के लिए आपदा (जैसे बीमारी, बेरोजगारी, मरुतक की मृत्यु) के समय और वृद्धावस्था में ऐसी व्यवस्था रहे कि वह न्यूनतम जीवन स्तर से नीचे न गिरने पावे।

ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा को दिशा में टोले रूप में प्रयत्न बहुत पहले ही प्रारम्भ हुए थे और सोलहवीं शताब्दी में निर्धन सहायतायें कानून (Poor Law) द्वारा गरीब, वृद्ध, असहाय, अनाथ और विधवा इत्यादि के लिए सहायता की व्यवस्था की गई थी।

निर्धन सहायतार्थ कानून (Poor Law)

औद्योगिक प्रणालियों (industrial systems) में परिवर्तन होने पर कुछ जनसंख्या को भारी हानि उठानी पड़ी। निर्धनता और दुर्भाग्य से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता पहुँचाने की आवश्यकता सरकारी उत्तरदायित्व के रूप में सत्तार में सर्वप्रथम ब्रिटेन में अनुभव की गई।

प्रारम्भ में निर्धनों को सहायता या तो व्यक्ति निजी रूप से देने के अथवा गिरजाघरों (churches) में दान दिया जाता था। सोलहवीं शताब्दी में कृषि प्रणाली में परिवर्तन होने से निर्धनों की संख्या बहुत बढ़ गई और गिरजाघर इतनी क्षमतावाली सत्ता नहीं रही कि स्थिति संभाली जा सकती। देश में शान्ति और अनुशासन बनाये रखने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत हुई।

सन् १५३१ में एक एक्ट पास हुआ जिसमें अर्पाहिज निर्धनों (disabled poor) और आसक्तियों एवं बेकारों (able-bodied unemployed) में अन्तर बताया गया। पहले वर्ग के निर्धनों को जस्टिस ऑफ पीस (Justices of Peace) के द्वारा भीस माँगने के लिए अनुज्ञापत्र (Licences) दिये जाने की व्यवस्था इस अधिनियम के अन्तर्गत की गई। दूसरे वर्ग के भिक्षारियों को दण्ड देने की व्यवस्था की गई।

सन् १५३६ में एक एक्ट द्वारा भिक्षा माँगना और देना दोनों वर्जित कर दिये गये। इस अधिनियम द्वारा प्रत्येक क्षेत्र (Parish) में ऐसे कोषों की व्यवस्था हुई जिनमें लोग स्वेच्छा से धन राशि प्रदान करें और जिनसे अर्पाहिज निर्धनों को सहायता दी जाये। रोजगार पाने के इच्छुक सक्षम व्यक्तियों को काम देने, निर्धन बालकों को शिक्षा देने तथा आसक्तियों को सत्ता देने की व्यवस्था की गई।^१ सन् १५३६ का अधिनियम सन् १५३१ के अधिनियम की

१. सन् १५४७ में एडवर्ड षष्ठ के शासन काल में शरीर से समर्थ भिक्षुओं को एक अधिनियम द्वारा कठोर दण्ड देने की व्यवस्था की गई जिसके अनुसार स्वेच्छाचारियों को चिह्नित किया जाता और उन्हें बन्दी करने वालों के यहाँ दास के रूप में दो वर्ष तक काम करने के लिए बाध्य किया जाता था, यदि वह भागने का प्रयत्न करे तो मृत्यु दण्ड तक देने की व्यवस्था थी। परन्तु यह अधिनियम शीघ्र ही रद्द कर दिया गया।

अपेक्षा इस दृष्टि से उत्तम था, जबकि सन् १५३१ के एक्ट की मान्यता यह थी कि प्रत्येक समर्थ शिक्षुक आलसी था, सन् १५३६ में रोजगार पाने के इच्छुको को काम देने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त कोष में दिये गये दानों से अपाहिजों की सहायता इस दृष्टि से अन्धरी थी कि उनमें होन-भावना उत्पन्न न हो परन्तु स्वेच्छा दान की विधि चल न सकी।

इसी बीच निर्धनों की समस्या का हल कुछ नगरों में नये ढंग में निकालने का चल किया गया। सन् १५४७ में लन्दन में एक योजना स्वीकार की गई कि निर्धनों के सहायतार्थ घन राशि एकत्रित करने के लिए अनिवार्य कर लगाये जायें। अन्य नगरों में भी इस विधि का अनुकरण किया गया। अन्त में सन् १५७२ में सरकार ने भी इसे मान लिया और अनिवार्य कर आरोपित करने के आदेश दिये गये।

सन् १५७६ में न्यायाधीशों (Justices of Peace) को अधिकार दिया गया कि वे आधारा (स्वेच्छाचारियों) तथा बेरोजगारों की सहायतार्थ तथा उनको सुधारने के लिए उन्हें सुधार-गृहों (work houses) में काम दें। जो स्वेच्छाचारी उन स्थानों में रहकर काम करने को राजी न होते उन्हें पीटकर काम करने के लिए विवश किया जाता था।

सन् १६०१ में एक और एक्ट पास हुआ जिसमें निर्धनों की सहायता के लिए एक विस्तृत योजना रखी जिसके अनुसार निर्धन कानून (Poor Law) स्थानीय प्रशासन अधिकारी शान्ति न्यायाधीश (Justices of Peace) निश्चित रहे और प्रशासन की इकाई गिरजापर क्षेत्र (Parish) थे। इस क्षेत्र से अनिवार्य रूप से कर लगाकर जो राशि इकट्ठी होती उसे उस क्षेत्र का कोष समझा जाता था। निर्धनों के साथ अलग-अलग रूप में यथाचित व्यवहार किया जाना लगा। आवाग स्वेच्छाचारियों को या तो जेल भेज दिया जाता था या सुधार गृहों (work houses) में, वृद्धों को उन्हीं के घर पर सहायता प्रदान की जाती थी। काम करने की इच्छा रहने पर भी जो बेरोजगार थे उन्हें रोजगार देने का प्रयत्न किया जाना था। निर्धन बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था थी तथा किरी दरतवागों की शिक्षा दी जाती थी।

सन् १६६२ में पाबित अधिनियम का उद्देश्य यह था कि निर्धन क्षेत्रों के प्रकिचनों का घनी क्षेत्रों में जमघट न हो जाये। न्यायाधीशों को अधिकार दिया गया कि वे अपने क्षेत्र (parish) में बाहर ने आने वाले दरिद्रों को, यदि आवश्यक हो, जानीस दिन की अवधि में निकाल दें। इस एक्ट का

कुप्रभाव यह पड़ा कि श्रमिकों की गतिशीलता रुक गई। इस प्रकार अधिक माँग के क्षेत्रों में जाकर मजदूरों के लिए अधिक वेतन पाना सम्भव न रहा। दूसरी ओर कई स्थानों में श्रम की पर्याप्त पूर्ति न होने में व्यवस्था के विकास में बाधा हुई। १८ वीं शताब्दी में निर्धनों की सहायता बड़ी।

सन् १७२२ के अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था हुई कि प्रकिचनो को सहायता केवल कर्मशालाओं (work houses) में ही दी जावे। गिरजाघर क्षेत्रों (Parishes) को ऐसी शालाएँ बनवाने का अधिकार दिया गया जिनमें दरिद्रों को रखा जा सके और काम दिया जा सके और जो निर्धन उस शाला (house) में आना और ठहरना पसन्द न करे उमें कोई सहायता न दी जाय। केन्द्रीय नियन्त्रण के अभाव में इस व्यवस्था में अनेक दोष देखने में आये। अलग अलग स्थानों में निर्धनों को सहायता देने के तरीकों और सहायता की किस्म में भिन्नता थी। कई बार ऐसा होता था कि कोई व्यक्ति यह दायित्व ले लेता था कि वह कुछ निर्धनों को खाना देगा तो इसके बदले में वह उनसे काम लेता था। कभी उनसे कर्ताई (spinning) का काम कराया जाना तो कभी उन्हें समुद्र पर भेज दिया जाता था। निर्धनों को मिलने वाली सहायता अपर्याप्त थी और उनसे काम अधिक लिया जाता था। उनके साथ दुर्व्यवहार होता था। उनको मजदूरी कुछ नहीं दी जाती थी। कहा यह जाता था कि कि उन्हें सहायता दी जा रही है जबकि उनमें काम अधिक लिया जाता था। उनकी साधारण आवश्यकताएँ भी पूरी न होने और उसी दशा में अधिक काम करने में कार्यक्षमता का अभाव (inefficiency) स्वाभाविक था।

सन् १७८२ और सन् १७६५ में कुछ संशोधन किये गये। सन् १८३४ में एक निर्धन कानून आयोग (Poor Law Commission) नियुक्त किया गया। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की कि निर्धन कानून का प्रशासन केन्द्रीय नियन्त्रण में हो। इसके अनुसार स्थानीय अधिकारी रखे गए जिन्हें सरक्षक मण्डल (Board of Guardians) कहा जाता था। घूमने वाले निरीक्षक (travelling inspectors) भी रखे गये जो सन्दन में रहने वाले प्रायुक्तों (कमिश्नरों) के प्रति उत्तरदायी होते थे। ये कमिश्नर ही यह निश्चिन करने लगे कि निर्धनों की सहायता किस रूप में और कितनी दी जाय। प्रारम्भ में प्रणाली का विरोध किया गया परन्तु निर्धनों की दशा पर इसका प्रभाव अच्छा पड़ा। इस प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ ये थी : (१) मरदाको का स्थानीय क्षेत्र में चुनाव होना था और वे मनमानी नहीं कर सकते थे,

अधिकांश कार्यों के लिए उन्हें कमिश्नरों की अनुमति लेनी पड़ती थी, (२) अस्वस्थ व्यक्तियों अथवा साठ वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को छोड़कर अन्य सभी अकिंचनों को सहायता केवल वर्कशालाएँ (work houses) में ही दी जाती थी, बाहर नहीं। शरीर ने स्वस्थ व्यक्तियों को ये शालाएँ जेल के समान लगती थीं, (३) पूरे देश में एक ही प्रणाली लागू की गई, (४) निरीक्षण और अक्रेक्षण (auditing) का व्यवस्था की गई।

सन् १८४७ में एक यह सजाघन हुआ कि निधन कानून आयोग (Poor Law Commission) के स्थान पर एक मण्डल (Poor Law Board) निधन कानून का नियंत्रण करने लगा। मण्डल का अध्यक्ष पार्लियामेंट का कोई अवकाश प्राप्त सदस्य (sitting member) हो हा सकता था।

निधन कानून की प्रारंभिकता कई हटियों में की जा रही थी, अतः सन् १९०५ में उसकी जांच करने के लिए एक शाही आयोग की नियुक्ति हुई। आयोग ने निधनता के कारणों पर प्रकाश डाला और निधन-कानून (Poor Law) की कार्य-प्रणाली की त्रुटियाँ बताने हुए महत्वपूर्ण सिफारिशों का। आयोग की सिफारिशों के अनुसार श्रृद्धा और विधवाओं के लिए पेंशन इत्यादि की सुविधाएँ प्रदान की गईं। नये मिरों से वर्गीकरण करके अकिंचनता के साथ उचित व्यवहार करने के प्रयत्न किये गये। बकारी और बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सामाजिक बीमा का विकास हुआ तथा राजगार के दफ्तर (Labour Exchanges) खोल दिये। सन् १९२६ में स्थानीय प्रशासन अधिनियम पारित हुआ और निधन कानून का प्रशासन जिला-परिषद इत्यादि (County Councils and County Borough Councils) का सौंपा गया। सन् १९४८ के राष्ट्रीय सहायता अधिनियम (National Assistance Act) द्वारा व्यापक सुधार हुए हैं। यह उल्लेखनीय है कि गरीबी की समस्या मूल रूप में दोषपूर्ण सामाजिक संगठन प्रणाली का परिणाम है।

सामाजिक बीमा की आवश्यकता (Need of Social Insurance)

ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक तथा वाणिज्य क्रान्तियों के साथ-साथ अनेक समस्याएँ गम्भीर रूप में प्रकट हुईं। श्रमिकों का शोषण होता था—मजदूरियाँ कम दी जाती थीं और काम के घंटे अधिक थे। उन्हें गन्दी जगहों में काम करना पड़ता था। वे बीमार पड़ते तो उनकी बिक्रिता का प्रबन्ध भी नहीं होता और बीमारी के दिनों की मजदूरी भी उन्हें नहीं दी जाती थी। कभी कभी मशीनों से

दुर्घटनाएँ हो जाती थी। मजदूरों को चाहे जब निकाल दिया जाता था। बीमारी, मृत्यु और बेरोजगारी से सुरक्षा का कोई उपाय नहीं था। महिला श्रमिकों के लिए प्रसूति और शिशु कल्याण की कोई व्यवस्था नहीं थी। महिलाओं और बच्चों को भी काम पर रखा जाता था और उनको मजदूरियाँ बहुत कम दी जाती थी। श्रमिक यंत्रवत् काम में जुटे रहते थे और अत्याचार की चक्की अनवरत चल रही थी।

यह बात सरलता में समझी जा सकती है कि कम मजदूरी पाकर श्रमिक में यह सामर्थ्य नहीं था कि वह आपत्ति काल के लिए कुछ सपह या बचत कर पाता। अतएव सामाजिक बीमा की आवश्यकता अनुभव की गई।

सामाजिक बीमा वस्तुतः राजकीय हस्तक्षेप का एक उदाहरण है। सामाजिक बीमा वह तरीका है जिसके द्वारा मामूहिक रूप में श्रमिक विभिन्न जोखिमों से अपनी रक्षा कर सकें। यह तरीका इस तथ्य पर आधारित है कि यद्यपि जीवन की जोखिमें किसी एक व्यक्ति के लिए अत्यन्त भयङ्कर हो सकती हैं परन्तु किसी एक समूह में वे प्रायः सम रहती हैं और उनका अनुमान लगाया जा सकता है। मामूहिक रूप से उन जोखिमों को सहना कठिन भी नहीं होना।

प्रारम्भ में सामाजिक बीमा का कार्य ऐच्छिक (voluntary) था। उदाहरण के लिये ब्रिटेन में मैत्री समितियों (friendly societies) का उदय १८ वीं शताब्दी में हुआ था। कालान्तर में सरकारी हस्तक्षेप प्रारम्भ हुआ। सरकार की दृष्टि इस दिशा में उचित इसलिए भी समझा जा सकती है कि जोखिमों से श्रमिक की सुरक्षा होने से उनकी कार्यक्षमता और उत्पादन-शक्ति बढ़ जाती है और इस प्रकार राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। यो सामाजिक सुरक्षा समाज का दायित्व है। अब यह समझा जाने लगा है कि जन्म से मृत्युपर्यन्त (from the cradle to the grave) प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा का उत्तरदायित्व राज्य पर होना चाहिए।

सामाजिक बीमा का विकास (Growth of Social Insurance)

सामाजिक बीमा का शीर्गलेश सन् १८८०-८६ काल में जर्मनी में बिस्मार्क ने किया था। इससे पूर्व अन्य देशों में दुर्घटनाओं और बीमारी इत्यादि में सुरक्षा प्रदान करने के लिए सामाजिक बीमा की सुविधाएँ थीं तो सही परन्तु वे अनिवार्य नहीं थी, ऐच्छिक थीं। इसके अतिरिक्त ये सुविधाएँ देने वाली

संस्थाएँ प्रायः सार्वजनिक नहीं थी और उनमें समानता या नियमितता नहीं थी ।

ग्रेट ब्रिटेन में सार्वजनिक कोष में से सहायता देने के एकमात्र उपाय निर्धन कानून (Poor Law) से प्रथम अभियान सन् १९०८ में वृद्धावस्था पेंशने^१ देना प्रारम्भ करने के रूप में हुआ ।

श्रमिक क्षति-पूर्ति अधिनियम (Workmen's Compensation Act): सन् १८९७ में पास हुआ^२ जिसमें सन् १९०६ में संशोधन किये गये और सन् १९४८ में अनेक संशोधनों के पश्चात् The Industrial Injuries Insurance Scheme के रूप में लागू किया गया । वस्तुतः सन् १८९७ के क्षतिपूर्ति अधिनियम को राज्य प्रशासित बीमा योजना नहीं कहा जा सकता, जिसके अन्तर्गत काम के दौरान में दुर्घटनाएँ हो जाने के लिए मालिकों (employers) द्वारा क्षतिपूर्ति किये जाने की व्यवस्था की गई थी ।

सन् १९१२ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (National Health Insurance scheme) लागू हुई और इसी के साथ भ्रंशवान सिद्धान्त (contributory principle) प्रारम्भ हुआ, जिस पर बाद के सब उपाय (measures) आधारित किये गये हैं । थोड़ा सा साप्ताहिक चन्दा (contribution) लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीमारी के समय नि.शुल्क डाक्टरी चिकित्सा और कुछ नकद भुगतान (cash payment) की व्यवस्था की गई । आरम्भ में यह योजना कम मजदूरी पाने वाले कुछ श्रमिकों के लिए ही लागू की गई थी ।

सन् १९१२ ई० में बेकारी बीमा (unemployment insurance) भी चालू किया गया । इसका क्षेत्र सीमित था । सन् १९२० में उसका विस्तार करके रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के अधिकांश भाग को बेकारी बीमा की सुविधा प्रदान की गई । प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों के मध्यकाल (inter-war

१. Non-contributory, i.e., for which no contribution was required to be paid

२. श्रमिक क्षतिपूर्ति की दिशा में दुरुआत सन् १८८० में हुई समझी जा सकती है जब Employers' Liabilities Act पास हुआ जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि मालिक (employer) द्वारा गलती होने के कारण मजदूरों के घायल होने पर श्रमिकों की क्षतिपूर्ति के लिए मालिक उत्तरदायी होगा । इस अधिनियम का लाभ कुछ ही व्यवसायों तक सीमित था ।

period) में व्यापक बेरोजगारी की दृष्टि से बेकारी बीमा की व्यवस्था अत्यन्त महत्वपूर्ण थी ।^१

सन् १९२६ में अश्वदान पद्धति पर (अर्थात् जिसके लिए पहले चन्दे लिये जायें) वृद्धो, विधवाओं तथा अनाथों के लिए पेंशने प्रारम्भ की गईं ।

सन् १९२८ में ग्रेट ब्रिटेन उन कतिपय देशों में एक था जिनमें सामाजिक सेवाएँ सर्वोत्तम थी परन्तु उनमें सामंजस्य का अभाव था । इसका कारण यह था कि उनकी शुल्मात अधिकचरे रूप में हुई थी । उनका क्षेत्र व्यापक नहीं था ।

बीवरिज योजना (Beveridge Plan)

द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रभाव के अन्तर्गत, जब पुनोत्थर निर्माण के हेतु योजनाएँ बनाई जा रही थी, तत्कालीन मिली-जुली ब्रिटिश सरकार (National Coalition Government) ने देश की सामाजिक बीमा प्रणाली की जाँच करने के लिए सर विलियम बीवरिज^२ को आमन्त्रित किया गया । बीवरिज रिपोर्ट सन् १९४२ में प्रकाशित हुई । सामाजिक सुरक्षा के विकास के इतिहास में इस रिपोर्ट का महत्व अत्यधिक है । इस सरकारी प्रकाशन के द्वारा सामाजिक सेवाओं में न केवल सामंजस्य स्थापित करके उनको व्यापक रूप प्रदान किया गया बल्कि पहली बार इस सिद्धान्त का समावेश किया गया कि सामाजिक जोखिमों के निवारण के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यापक सुविधाएँ प्रदान करने में नागरिकों के सहयोग से राज्य (State) को स्वयं उत्तरदायित्व वहन करना चाहिए ।

बीवरिज रिपोर्ट में ब्रिटेन के सभी राजनीतिक दलों तथा समाज सेवियों ने रुचि दिखाई और उसकी सिफारिशों तथा उसमें निहित सिद्धान्तों का समर्थन किया । सरकार ने सामान्य रूप से यह मान लिया कि सामाजिक सुरक्षा का भावी विकास इस रिपोर्ट के आधार पर ही होना चाहिए । तब से बीवरीज योजना को व्यवहार में लाने के लिए कई अधिनियम पारित हो चुके हैं । नई सामाजिक बीमा प्रणाली सन् १९४८ से पूर्ण रूप में लागू है, जिसमें बाद के अधिनियमों द्वारा संशोधन भी किये गये हैं ।

1. सन् १९३४ में Unemployment Assistance Board की स्थापना हुई ।

2. Later Lord Beveridge.

ब्रिटेन की वर्तमान सामाजिक बीमा व्यवस्था (Present Social Security System)

ग्रेट ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था इनमें व्यापक है कि इसके अन्तर्गत देश के सभी नागरिकों के लिए सुविधा प्रदान की गई है तथा सुविधा केवल जन्मकाल से मृत्यु पर्यन्त ही नहीं बल्कि गर्भावस्था में तथा मृत्यु के उपरान्त अन्तिम संस्कार के लिए भी दी जाती है। सामाजिक बीमा की सुविधा दान (charity) के रूप में नहीं, बल्कि सम्मानपूर्वक अधिकार की तरह दी जाती है क्योंकि सुविधा पाने वाला व्यक्ति उनके लिए चन्दा या भंडादान (contribution) देता है। ब्रिटेन की वर्तमान सामाजिक बीमा व्यवस्था के मुख्य रूप निम्नलिखित हैं :—

(१) पारिवारिक भत्ते

जून १९४५ में पारित पारिवारिक भत्ते अधिनियम (Family Allowances Act) के अन्तर्गत अगस्त सन् १९४६ में राज्य द्वारा पारिवारिक भत्तों की व्यवस्था की गई है। इस योजना के अन्तर्गत पहलें या इकलौते बच्चे को छोड़कर परिवार के हरेक बच्चे के लिए एक निश्चित आयु तक भत्ता दिया जाता है। निश्चित आयु (age limit) उन बच्चों के लिए १५ वर्ष है जो इस उम्र में स्कूल छोड़ देते हैं, पिछड़े हुए बच्चों के लिए १६ वर्ष, तथा उन बच्चों के लिए १८ वर्ष है जो स्कूल में पढ़ते रहें अथवा शिष्याधीन (apprentices) हों। भत्ते प्राप्त करने के लिए योग्यता सम्बन्धी कोई शर्त नहीं है। यदि परिवार ब्रिटेन के नागरिक न हो तो भी, यदि वे निवास सम्बन्धी विशेष दशाएँ पूरी करते हों, भत्ते प्राप्त करने के अधिकारी हैं। पारिवारिक भत्ते राजकीय कोष में से दिए जाते हैं और उनका उद्देश्य पूरे परिवार को लाभ प्रदान करना है।

इस योजना के अन्तर्गत दो या दो से अधिक बच्चों वाले साठे बत्तीस लाख में भी अधिक परिवारों को साठे बावन लाख से भी अधिक भत्ते दिये जाते हैं।^१

भत्ते की दर सन् १९५२ के पूर्व प्रति बच्चा ५ शिलिंग प्रति सप्ताह थी, सितम्बर १९५२ में बढ़ाकर ८ शिलिंग प्रति सप्ताह कर दी गई। सन् १९५६ में पारित पारिवारिक भत्ते तथा राष्ट्रीय बीमा अधिनियम के द्वारा परिवार के तीसरे और उसके बाद हरेक बच्चे के लिए भत्ते की दर अक्टूबर १९५६ से १० शिलिंग कर दी गई।^२

1. Britain : An Official Handbook, 1959 edition, p. 130.

2. Ibid.

तालिका

राष्ट्रीय बीमा तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के हेतु साप्ताहिक चन्दों की दरें
सितम्बर १९५८

	पुरुष ^१			स्त्रियाँ ^१		
	राष्ट्रीय बीमा ^२	स्वास्थ्य सेवा	कुल	राष्ट्रीय बीमा ^२	स्वास्थ्य सेवा	कुल
	रि० पें०	रि० पें०	रि० पें०	रि० पें०	रि० पें०	रि० पें०
प्रथम वर्ग रोजगार प्राप्त व्यक्ति : रोजगार में लगे व्यक्ति में— (Paid by the employee)	८-०३	१-१०३	९-११	६-७३	१-४३	८-०
रोजगार देने वाले से— (Paid by employer)	७-९३	०-५३	८-३	६-३३	०-५३	६-९
जोड़	१५-१०	२-४	१८-२	१२-११	१-१०	१४-९
द्वितीय वर्ग निजी धंधों में लगे व्यक्ति (Self employed persons)	९-१०	२-२	१२-०	८-४	१-८	१०-०
तृतीय वर्ग रोजगार में न लगे व्यक्ति (Non-employed persons)	७-५	२-२	९-७	५-११	१-८	७-७

१. १८ वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति पुरुष और स्त्रियाँ। इसमें कम आयु के लड़के और लड़कियों से चन्दों की दरें कम हैं।

२. राष्ट्रीय बीमा की दरों में प्रथम वर्ग के व्यक्तियों के लिए Industrial Injuries Insurance के चन्दों भी सम्मिलित हैं जिनकी दरें पुरुष के लिए employee से ८ पैसे तथा employer से ९ पैसे, और स्त्री के लिए employee से २ पैसे तथा employer से ६ पैसे हैं।

(२) राष्ट्रीय बीमा

सन् १९४६ का राष्ट्रीय बीमा अधिनियम पूर्ण रूप में ५ जुलाई सन् १९४८ में लागू हुआ। राष्ट्रीय बीमा योजना में सन् १९४८, १९४९, १९५२, १९५३, १९५४, १९५५, १९५६ और १९५७ में मंजोर्जन हुए। राष्ट्रीय बीमा योजना स्कूल छोड़ने की आयु के उपरान्त सामान्यतया ग्रेट ब्रिटेन में रहने वाले हरेक व्यक्ति के लिए लागू है।

राष्ट्रीय बीमा योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने का अधिकार पाने के लिए हरेक व्यक्ति को चन्दा देना पड़ता है। चन्दा की दरें निश्चित करने के लिए व्यक्तियों की आय वगैरों में विभाजित किया गया है। कुछ विशेष दशाओं के अतिरिक्त सामान्यतया सितम्बर १९५८ में साप्ताहिक चन्दे की जो दरें थी वे पृष्ठ १४४ पर दी गई तालिका में दी हुई हैं :

राष्ट्रीय बीमा में सरकारी कार्य का अदान (contribution) सामान्य करों से प्राप्त राशि में से दिया जाता है। निवृत्त (retire) होने पर अथवा सामान्यतया निवृत्त हान की आयु के उपरान्त व्यक्ति को चन्दा नहीं देना पड़ता। परन्तु यदि कोई व्यक्ति निवृत्त हान के पश्चात् भी रोजगार प्राप्त व्यक्ति (employed person) के रूप में कार्य कर तो Industrial Injuries का चन्दा उमर देना पड़ेगा, रोजगार देने वाला (employer) को तालिका में दी हुई दर पर पूरा चन्दा देना पड़ेगा।

राष्ट्रीय बीमा के अन्तर्गत बीमारी, बेराजगारी, प्रसूति तथा वैधव्य की अवस्था में मुविधा (benefit) प्रदान करने तथा सुरक्षक के भत्ते, रिटायर होने पर पेंशन एवं मृत्यु के समय अनुदान (grants) की व्यवस्था है। प्रथम वर्ग के व्यक्तियों को सभी लाभ (benefits) दिए जाते हैं। द्वितीय वर्ग के व्यक्तियों को बेराजगारी का अवस्था में तथा उद्योग में घायल (industrial injuries) पर मिलने वाली मुविधाओं के अतिरिक्त अन्य सब लाभ दिए जाते हैं। तृतीय वर्ग के व्यक्तियों का बीमारा, बेराजगारी तथा घायल हान की अवस्थाओं में दी जाने वाला मुविधाएं तथा प्रसूतिकालीन भत्ता नहीं दिए जाते, अन्य लाभ दिये जाते हैं।

लाभों (benefits) की दरें सन् १९५८ के मध्य में बढ़ाकर इस प्रकार कर दी गई थी :—

(क) रोगावस्था में (Sickness Benefit)

बीमारी के समय १८ वर्ष की आयु से ऊपर पुरुष और अविवाहिता स्त्री को सामान्यतया ५० दिवस प्रति सप्ताह दिए जाते हैं। यदि उसका कोई

प्रौढ़ आश्रित हो तो उसके लिए ३० शि० प्रति सप्ताह और दिये जाते हैं; पहले और इकलौते बच्चे के लिए पारिवारिक भत्ते की आयु सीमा के अन्तर्गत १५ शि० प्रति सप्ताह तथा इसके साथ साथ प्रत्येक बाद के बच्चे के लिए पारिवारिक भत्ते के अतिरिक्त ■ शिशु प्रति सप्ताह और दिये जाते हैं। विवाहिता स्त्री को बीमारी के समय ३४ शिशु प्रति सप्ताह की दर पर लाभ (benefit) दिया जाता है परन्तु यदि उसका पति काम करने योग्य नहीं (invalid) है अथवा वह पति से अलग हो गई है और उससे कोई आर्थिक सहायता नहीं पा सकती तो उसे, ३४ शि० साप्ताहिक के बजाय, ५० शिशु प्रति सप्ताह दिये जाते हैं।

रुग्णावस्था में दी जाने वाली सहायता (Sickness benefit), यदि प्रथम और द्वितीय वर्ग के सहायता पाने वाले व्यक्ति ने १५६ साप्ताहिक चन्दे नहीं दिये हैं तो, एक वर्ष तक ही दी जाती है। परन्तु यदि १५६ साप्ताहिक चन्दे दिये जा चुके हैं तो यह सहायता बीमारी भर चालू रहेगी, बीमारी बाहे कितनी ही लम्बी अवधि तक रहे।

(ख) बेकारी की अवस्था में (Unemployment Benefit)

बेरोजगारी में सहायता की दर वही रखी गई है जो रुग्णावस्था में है। पहली बार बेकारी सहायता तीस सप्ताह तक दी जा सकती है परन्तु यदि हान के वर्षों में इस प्रकार की सहायता ली न गई हो और चन्दे चुकाता रहा हो तो बेरोजगारी सहायता अधिक से अधिक १६ उन्नीस माह तक चालू रखी जा सकती है।

(ग) प्रसूति लाभ (Maternity benefit)

चन्दा देने की कुछ शर्तें पूरी हो जाने पर बच्चा होने के समय १२ पौण्ड १० शिलिंग का प्रसूति अनुदान दिया जाता है, इसके अलावा हरेक अतिरिक्त बच्चे के जन्म पर, यदि बच्चा जन्म से १२ घंटे बाद जीवित रहे तो, १२ पी० १० शि० और दिये जाते हैं। यदि जच्चा बच्चे के जन्म के समय किसी ऐसे स्थान पर न रहे जो सार्वजनिक कोष से चलाया जाना हो तो घर पर बच्चा होने क लिये (home confinement grant) पाँच पौण्ड दिये जाते हैं। चन्दे की आवश्यक शर्तें पूरी होने की अवस्था में आर्थिक महिलाओं को शिशु-जन्म के लगभग ११ सप्ताह पहले से ५० शिलिंग प्रति सप्ताह की दर पर १८ सप्ताह तक प्रसूति भत्ता दिया जाता है।

(घ) वधव्य सहायता (Widow's Benefit)

मृत पति के बाका के आधार पर ही उसकी विधवा को तीन प्रकार के

लाभ दिये जाते हैं। वैधव्य भत्ता ७० शिलिंग प्रति सप्ताह की दर पर १३ सप्ताह तक दिया जाता है, जिसके अतिरिक्त इस अवधि में पहले और भकेले बच्चे के लिए निश्चित आयु सीमाओं में २० शिलिंग प्रति सप्ताह तथा उसके बाद दूसरे एवं हरेक बच्चे के लिये पारिवारिक भत्ते के अतिरिक्त १२ शि० प्रति सप्ताह और दिये जाते हैं। तेरह सप्ताह तक वैधव्य भत्ता मिलने के पश्चात् यदि विधवा के कोई बच्चा है जिसकी आयु निश्चित सीमाओं में हो तो उसे विधवा माँ का भत्ता दिया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि विधवा की आयु उसके पति की मृत्यु के समय ५० वर्ष या अधिक हो और उससे उसका विवाह कम से कम तीन वर्ष पूर्व हो चुका हो तो विधवा की पेंशन दी जाती है।^१ वैधव्य भत्ता तथा विधवा माँ का भत्ता समाप्त होने पर विधवा को बीमारी या बेकारी की अवस्था में सहायता देने के सम्बन्ध में विशेष नियम है।

(ङ) सरक्षक का भत्ता (Guardian's Allowance)

सरक्षक का भत्ता उस व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसके परिवार में कोई ऐसा बच्चा हो जिसके माँ-बाप (अथवा सीतेले माँ-बाप) मर चुके हो जिनमें से किसी एक का राष्ट्रीय बीमा अधिनियम के अन्तर्गत बीमा हो चुका हो। भत्ते की दर २७ शि० ६ पें० प्रति सप्ताह है और भत्ता तब तक चल रहा है जब तक वह बच्चा पारिवारिक भत्ता अधिनियम की निश्चित आयु-सीमा में आता है।

(च) कार्य-निवृत्त होने पर पेंशन (Retirement Pension)

जबकि सम्बन्धी आवश्यक शर्तें पूरी हो चुकी हो तो नियमित रोजगार से निवृत्त होने पर पुरुषों को ६५ वर्ष की आयु में और स्त्रियों को ६० वर्ष की आयु में पेंशन दी जाती है। ७० वर्ष की आयु होने पर पुरुष को और ६५ वर्ष की आयु होने पर स्त्री को, वह रिटायर न हो तो भी, पेंशन देय है। इस आयु के पूर्व (अर्थात् पुरुष के लिए ७० वर्ष तथा स्त्री के लिए ६५ वर्ष) पेंशन पाने वाले व्यक्ति कमाने लगे तो उनकी आयो के अनुसार निश्चित दरों पर पेंशन में से कमी कर दी जाती है। विवाहिता स्त्री अपने पति के बीमा के आधार पर पेंशन ३० शि० प्रति सप्ताह की दर पर पा सकती है।

1. For details see Britain : An Official Handbook, 1959 edition, p. 133.

पुरुषों और स्त्रियों को न्यूनतम आयु पर रिटायर न होने के लिए प्रोत्साहन देने की दृष्टि से यह व्यवस्था की गई है कि जो व्यक्ति काम करने रहें और चन्दे देते रहे उन्हें निश्चित दरों पर बढ़ी हुई पेंशने दी जाती है।

(ख) मृत्यु होने पर (Death Grant)

चन्दे की आवश्यक दायें पूरी होने पर प्रौढ व्यक्ति की मृत्यु होने पर २५ पौण्ड तक, बच्चे की मृत्यु पर कुछ कम, अनुदान (Death Grant) दिया जाता है।

(३) औद्योगिक क्षति बीमा योजना

(Industrial Injuries Insurance Scheme)

श्रमिकों को क्षति प्रति योजना के बजाय औद्योगिक क्षति बीमा योजना जुलाई १९४८ में लागू हुई जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि यदि किसी व्यक्ति को रोजगार के दौरान में और उसके कारण हुई दुर्घटनाओं से चोट (injuries) पहुँचे, एवं रोजगार का स्वभाव ऐसा हो कि उसके कारण निर्धारित बीमारियों में से कोई बीमारी हो जाए तो अघोसिबिन लाभ (benefits) दिये जाते हैं :—

घायल होने पर (Injury Benefit)

औद्योगिक दुर्घटना अथवा बीमारी में यदि कोई व्यक्ति काम करने योग्य न हो तो उस दुर्घटना या रोग हो जाने के समय से अधिक से अधिक २६ सप्ताह तक सुविधा (benefit) प्रदान की जाती है जिसकी दर प्रौढ व्यक्ति के लिए ८५ शिलिंग प्रति सप्ताह है, यदि उसका कोई प्रौढ आश्रित है तो उसके लिए ३० शि०, निर्धारित आयु सीमाओं में पहले और इक्वलिटे बच्चे के लिए १५ शि० तथा उसके बाद हरेक बच्चे के लिए जो सहायता पाने का अधिकारी है ७ शि० प्रति सप्ताह और दिए जाते हैं। यह सुविधा पारिवारिक भत्ते के अतिरिक्त दी जाती है।

अपाहिज होने पर (Disablement Benefit)

अपाहिज होने पर दी जाने वाली सुविधा उस समय दी जा सकती है जब पहले प्रकार की सुविधा (injury benefit) मिलना बन्द हो जाए। अपाहिज होने पर दी जाने वाली रकम इस बात पर निर्भर है कि अधिक रितना अपाहिज हुआ है जिसका निर्णय एक मेडिकल बोर्ड करता है। यदि अधिक इलाज अपाहिज हो जाय कि कुछ भी कर सकने के लिए समर्थ न रहे तो ८५ शि० प्रति सप्ताह दिये जाते हैं। २० प्रतिशत अग्रमर्षता (disablement) को १२५

में १७ शि० प्रति सप्ताह दिये जाते हैं। यदि असमर्थता २० प्रतिशत से भी कम है तो रकम सामान्यतया एकमुश्त (gratuity) के रूप में अधिक से अधिक २८० पौण्ड तक दी जाती है।

असमर्थता की दशा में दी जाने वाली सुविधा (Disablement Benefit) निम्नलिखित परिस्थितियों में बढ़ाई जा सकती है :—

(क) अस्पताल में रहकर चिकित्सा होने की दशा में शत प्रतिशत सुविधा दी जा सकती है, साथ ही आर्थिकों के लिए भी सहायता दी जायगी।

(ख) यदि शत प्रतिशत सुविधा दी जा रही हो और बीमागुदा (insured) व्यक्ति की देखभाल करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता हो तो निरन्तर सेवा का भत्ता अधिक से अधिक ३१ शि० प्रति सप्ताह (बहुत विनोद दशामों में ७० शि० प्रति सप्ताह तक) दिया जा सकता है।

(ग) यदि बीमागुदा व्यक्ति काम करने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य (unfit) हो गया है तो उसे बेरोजगारी के लिए १० शि० प्रति सप्ताह और दिये जा सकते हैं, साथ ही उसके आर्थिकों के लिए भत्ता दिया जायगा।

(घ) यदि बीमागुदा व्यक्ति अपना पहले वाला या वैसा ही काम करने के योग्य न हो सके तो विनोद भत्ते के रूप में ३४ शिलिंग बढ़ाये जा सकते हैं परन्तु कुल दी जाने वाली रकम ८५ शि० प्रति सप्ताह में अधिक नहीं होगी।

मृत्यु हो जाने पर (Death Benefit)

यदि दुर्घटना से अथवा बीमारी से मृत्यु हो जाए तो बीमागुदा व्यक्ति के आश्रितों को सहायता दी जाती है। रकम कितनी दी जाएगी यह इन बातों पर निर्भर है कि मृत व्यक्ति से आश्रित का कितना समीप का सम्बन्ध था और आर्थिकों को मृत व्यक्ति अपने जीवन-काल में किस सीमा तक सहायता देता था।

विधवा को जो अपने पति की मृत्यु के समय उनके साथ रहती थी वैध-व्यकाल के पहले १३ सप्ताह तक ७० शि० प्रति सप्ताह पेंशन देय है। तत्पश्चात् उसे २० शि० प्रति सप्ताह तथा कुछ दशामों में ५६ शि० प्रति सप्ताह पेंशन पाने का अधिकार है। बच्चों और आश्रित माता-पिता इत्यादि के लिए अनिश्चित व्यवस्था है।

(८) राष्ट्रीय सहायता तथा कल्याण सेवाएँ

(National Assistance and Welfare Services)

राष्ट्रीय सहायता अधिनियम १९४८ जिसने अन्तर्गत निर्धन व्यक्तियों को -

आर्थिक सहायता दी जाती है, १५ जुलाई, १९४८ से लागू हुआ। इस अधिनियम के अन्तर्गत उन लोगों को सहायता प्रदान की जाती है जो अन्य सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के क्षेत्र में नहीं आते अथवा बीमा लाभ अपर्याप्त हो। इस अधिनियम द्वारा निर्धन कानून (Poor Law) का अन्त करके और उसके दोषों का निवारण करके विस्तृत आधार अपनाने का प्रयत्न किया गया है। राष्ट्रीय सहायता का प्रशासन राष्ट्रीय सहायता बोर्ड द्वारा किया जाता है।

ग्रेट ब्रिटेन में वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के आवास के लिए गृहों की व्यवस्था की गई है। वृद्धों के कल्याण-कार्य प्रायः सामाजिक संस्थाओं द्वारा किये जाते हैं।

एक अधिनियम (The Children Act, 1948) द्वारा ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय संस्थाओं के लिये यह आवश्यक कर दिया गया है कि १८ वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चों की, जिनके माता पिता या संरक्षक न हों, अथवा त्रिनका त्याग कर दिया गया हो, अथवा जिनके माँ बाप अस्थायी या स्थायी रूप से उनकी सहायता करने में असमर्थ हो, स्थानीय संस्थाएँ अपनी देख-भाल में रखें।

प्रश्न

1. Give an account of the various forms of social insurance prevailing in England and point out its main features.

2. What do you mean by Social Insurance? What is its necessity and how has it been provided in England?

3. The movement of social insurance is said to have started in England with the Old Age Pensions Act of 1908. Trace the history of this movement from this period to the present day.

4. Write a full note on the Poor Law in England.

5. Give a brief appraisal of the Social Insurance schemes undertaken in Great Britain after the first world war.

अध्याय ६

औद्योगिक तथा व्यापारिक नीति

[वाणिज्यवादी नीति, अबाध व्यापार नीति, अबाध व्यापार नीति का पतन तथा रक्षणवादी नीति का विकास, द्वितीय विश्व-युद्ध तथा युद्धोत्तर काल में प्रशुल्क नीति, प्रश्न ।]

पिछले अध्यायो में ग्रेट ब्रिटेन के आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं पर जो प्रकाश डाला गया है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि ब्रिटेन में सरकारी नीति का आर्थिक क्रियाओं पर प्रभाव बहुत अधिक पड़ा, साथ ही यह सत्य भी सम्मुख आता है कि आर्थिक क्रियाओं के विकास के अनुकूल ही ब्रिटेन में सरकारी नीति का विकास हुआ। अध्याय तीन में यह बताया जा चुका है कि ब्रिटेन किस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी में भौतिक उन्नति के उच्च-तम शिखर पर पहुँचा गया था। उन्नीसवीं शताब्दी में नीति के परिवर्तनों और तत्कालीन उन्नति के आधार पर १८वीं शताब्दी तथा उसमें पूर्व की नीति में त्रुटियाँ छूटना असंगत होगा। यह ठीक है कि १८वीं शताब्दी तक अपनाई गई नीति उस शताब्दी के अन्त की ओर अनुपयुक्त हो गई थी परन्तु १९वीं शताब्दी में जिन नीति को व्यापक रूप में अपनाया, परिस्थितियाँ बदलने पर उसका परित्याग करना पड़ा।

मध्ययुग में व्यक्ति-स्वातंत्र्य का अभाव था, आर्थिक क्रियाओं पर नियमन था। उत्पादन स्थानीय आवश्यकताओं के लिए किया जाता था। आर्थिक विचारधारा स्पष्ट नहीं थी, उस पर नीतिशास्त्र का प्रभाव था। राष्ट्रीयता की भावनाएँ मध्ययुग में प्रायः सुप्त रूप में थी परन्तु मध्ययुग के अन्त की ओर उनका विकास हुआ।

मध्ययुग के बाद की ग्रेट ब्रिटेन की औद्योगिक तथा व्यापारिक नीति के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन तीन समूहों में किया जा सकता है :—

- (१) वाणिज्यवादी नीति (Mercantilism),
- (२) अबाध-व्यापार नीति (Laissez-faire), तथा
- (३) रक्षणवादी नीति (Protectionist Policy)।

वाणिज्यवादी नीति

वाणिज्यवाद के सम्बन्ध में पहले अध्याय में बताया जा चुका है। वाणिज्यवादी नीति का प्रभाव सोलहवीं शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी तक रहा। यह द्रव्य और राष्ट्रीयता के विकास का काल था। वाणिज्यवादी नीति का सबसे अधिक प्रभावशाली तत्व अथवा उद्देश्य राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना था। राष्ट्रीय सत्ता बढ़ाने की धुन में हरेक क्षेत्र (sphere) में राष्ट्रीय क्रिया का संगठन हुआ। राज्य के हितों की अपेक्षा स्थानीय तथा व्यक्ति और वर्गों के हितों को गौण रखा गया।

सत्ता के आर्थिक आधार के रूप में वाणिज्यवादी नीति के मुख्य उद्देश्य ये प्रपनाये गये : (क) सम्पत्ति को अत्यधिक महत्व दिया गया, (ख) बहुमूल्य धातुओं, मुख्यतः स्वर्ण, को सम्पत्ति का मुख्य रूप समझा गया; (ग) उद्योगों तथा उत्पादन में अधिक विदेशी व्यापार को महत्व दिया गया; (घ) व्यापारान्तर अनुकूल रहने पर जोर दिया गया तथा (ङ) इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए औद्योगिक तथा वाणिज्यिक नियन्त्रण की नीति अपनाई गई।

ऊपर कहा जा चुका है कि वाणिज्यवादी क्रिया ने हरेक क्षेत्र को प्रभावित किया। इसका प्रमाण इस काल में पारित अधिनियम हैं।^१ कृषि के सम्बन्ध में समावरण अधिनियम (Enclosure Acts) तथा अन्न कानून (Corn Laws) पास हुए। सामुद्रिक शक्ति बढ़ाने के लिए नौवहन कानून (Navigation Acts) पास किये गये। मछली उद्योग के विकास के लिए प्रयत्न किये गये। उद्योग में स्वार्थीय प्रकृति के शिल्प-संगठन की बजाय केन्द्रीय नियन्त्रण बढ़ चला था। उदाहरण के लिए, सन् १५६३ में एक कानून (The Statute of Artificers) द्वारा कृषि तथा औद्योगिक श्रमिकों की वृत्ति की सामान्य दशाएँ निर्धारित की गईं। रोजगार देने वालों, मजदूरों तथा उपभोक्ताओं के कुछ सीमा तक विरोधी हितों में नियमन द्वारा संतुलन स्थापित करने का प्रयत्न किया गया। जनसंख्या की समृद्धि और रोजगार सम्पन्नता राष्ट्रीय सत्ता की मुख्य दशा प्रतीत हुई।^२ मृदा सम्बन्धी सुधार किये गये। निर्धन-

१. इन अधिनियमों का परिचय यथास्थान दिया जा चुका है।

2 Meredith, H O. Economic History of England, Pitman, London, 1949, p. 95. "a well-nourished, regularly employed and prosperous population seemed one main condition of national power."

कानून संहिता (Poor law Code) का विकास हुआ।^१ समुद्रपार व्यापार बढ़ाने के लिए बड़ी-बड़ी व्यापारिक कम्पनियों का निर्माण हुआ, उन्हें एकाधिकार दिया गया। देश के स्वर्ण कोषों में वृद्धि करने के लिए व्यापार के नियमन की पद्धति इस काल की प्रमुख विशेषता थी। इसके अन्तर्गत ड्यूटी (duties), बन्दी (prohibition) तथा उत्पादन और व्यापार बढ़ाने के लिए सरकारी आर्थिक सहायता (bounties) के उपाय मुख्य रूप से अपनाये गये। ऊनी वस्त्र उद्योग की उन्नति के हेतु निजी जीवन और उपभोग पर प्रभाव डालने वाले कानून बनाए गए। उदाहरण के लिए सन् १६७८ में सान के कुछ महीनों में ऊनी वस्त्रों का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया था। सन् १६९६ में एक विशेष कमेटी ने विदेशी निर्मित माल के आयात को बन्द कर देने देश के कच्चे माल का निर्यात बन्द कर देने, तथा उन कच्चे मालों पर से आयात कर हटा देने के लिए सिफारिश की थी जो आन्तरिक उद्योगों के लिए आवश्यक थे। इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए अधिनियम पारित हुए।

सत्रहवीं शताब्दी के आरम्भ से ही उपनिवेशों को देश की सम्पत्ति समझकर उनसे लाभ उठाने को महत्त्व दिया गया।^२ देश के हित में उपनिवेशों के साथ होने वाले व्यापार का नियमन किया गया। जहाजी कानूनों में भी यही नीति बरती गई।

वाणिज्यवादी नीति की आलोचना बाद की परिस्थितियों में तो होनी स्वाभाविक थी, उस समय भी हुई जब यह नीति अपनाई गई थी। वस्तुतः वाणिज्यवाद का आर्थिक आधार गलत था क्योंकि उसका दृष्टिकोण एक-देशीय था। परन्तु व्यक्ति-स्वातन्त्र्य के आधार पर अथवा अत्यधिक नियमन के विरोध की दृष्टि में बहुत आलोचना प्रायः तत्कालीन परिस्थितियों पर बिना

१. यह पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि निर्धन कानून ने न केवल अकिंचनों के लिए प्रतिबन्ध लगाये बल्कि दान देने के सम्बन्ध में तथा निर्धनों की सहायता के प्रशासन के लिए भी नियम बनाये गये।

२. “... the colonies were regarded as estate to be worked for the mother country.” —Bair, Dr. B. S., and Pradhan, N. S.: *Modern Economic Development*, p. 123.

विचार किये हुए की जाती है। 'वाणिज्यवाद' शब्द तो बाद का गढ़ा हुआ है, सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी में ब्रिटेन में जिस नीति का विकास हुआ वह एक प्रणाली के रूप में नहीं परन्तु ब्रिटेन की उन्नति के लिए उस समय की परिस्थितियों के अनुसार शर्तें : अपनाई गई थी जिसका बीजारोपण बहुत पहले ही चौदहवीं शताब्दी में हुआ समझा जाना चाहिए। यदि ब्रिटेन की मध्ययुगीन दशाओं पर विचार किया जाय,^१ मेनोरिपल प्रणाली तथा व्यापक शान प्रथा की घुराइयों को कम करने के लिए अपनाई गई नीति का औचित्य समझा जा सकता है। बहुत अधिक स्थानीय प्रतिद्वन्द्वों के स्थान पर राष्ट्रीय नियमन उन्नति की महत्वपूर्ण अवस्था थी। पार्लियामेण्ट ने देश के हित में अधिनियमों को पारित करके जो कुछ किया उसका महत्व इस दृष्टि से भी समझा जाना चाहिए कि समूचे राष्ट्र के हित में पार्लियामेण्ट द्वारा उन अधिनियमों को रद्द किया जा सकता था।^२

अबाध व्यापार नीति

सन् १७७६ में एडम स्मिथ का प्रसिद्ध ग्रन्थ "दी वैल्थ ऑफ नेशन्स" (The Wealth of Nations) प्रकाशित हुआ था। आर्थिक और सामाजिक कुछ दिशाओं में अबाध व्यापार सिद्धान्तों का चलन ग्रेट ब्रिटेन में एडम स्मिथ के उल्लिखित ग्रन्थ के प्रकाशन के बहुत पूर्व ही आरम्भ हो चुका था^३ परन्तु एडम स्मिथ के विचारों ने इन सिद्धान्तों को तर्क शक्ति प्रदान की। वस्तुतः पूर्ण रूप में ये सिद्धान्त कभी भी लागू नहीं हो सके (होने भी नहीं चाहिए थे) परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी के अधिकांश भाग में ब्रिटेन में जिस नीति का प्रभुत्व रहा उसे स्वतन्त्र व्यापार नीति और अबाध नीति (Laissez faire) कहकर सम्बोधित किया जाता है।

उद्देश्य—अबाध व्यापार नीति का दार्शनिक आधार यह विचार था कि यदि व्यक्तियों की स्पर्धा पर कोई प्रतिबन्ध न लगाया जाये तो हरेक व्यक्ति इस प्रकार की क्रिया में लगेगा कि उसका अधिकतम हित हो। इस प्रकार सभी व्यक्ति अपने अधिकतम लाभ के लिए कार्य करेंगे जिसके कारण पूरे

१. देखिए इस पुस्तक का अध्याय १।

२. "The solution of national for local regulation, of legal discipline for class servitude, mark important stages on the road to freedom. What Parliament did for the whole country could be undone for the whole country by Parliament."

Meredith, op. cit., p. 100

३. Southgate, G W, cit., p. 344

समाज का भी अधिकतम हित होगा। इस आधार पर राज्य द्वारा आर्थिक क्रियाओं का नियम राष्ट्र के हितों के विरुद्ध बनाया गया।

यहाँ यह उल्लेख करना अप्रासंगिक न होगा कि अवाध व्यापार नीति के आधार मूलक विचार एक सिरे के (extremist) थे, उनमें सत्य का जग था तो सही परन्तु उसे इतना बड़ा चड़ा कर कहा गया कि वास्तविकता के अन्य पहलुओं की उपेक्षा की गई। अवाध व्यापार नीति के कट्टर विद्वानों भी बाद में यह मानने लगे थे कि स्पर्द्धा करने में श्रमिक और नियोक्ता (employer) की स्थिति समान नहीं थी। वस्तुतः अब यह समझा जाने लगा है कि बन्धन-हीन स्पर्द्धा से कुछ व्यक्तियों का लाभ भले ही हो परन्तु अन्य व्यक्तियों को हानि होती है—तुलनात्मक रूप से देखा जाय तो नियमन की अपेक्षा बन्धन-हीन प्रतियोगिता में समूचे समाज की अधिक समृद्धि की आशा करना निमूलक है।

अवाध व्यापार नीति की दिशा में प्रगति—सन् १७८३ के पश्चात् विलियम पिट (Pitt) ने अवाध व्यापार की ओर रुचि दिखाई। पिट इस नीति को भागे बढ़ाने में सफल न हो सका क्योंकि एक तो उद्योगपतियों ने पूरा साथ नहीं दिया, दूसरे, उसने जो कार्यक्रम चालू किया, सन् १७९३ में फ्रान्स के साथ युद्ध छिड़ जाने के कारण, वह भागे न बढ़ सका। परन्तु यह भुलाया नहीं जा सकता कि एडम स्मिथ तथा अन्य अर्थशास्त्रियों के अवाध-नीति पौषक विचारों का सरकारी नीति पर कई दिशाभ्राम प्रभाव पड़ा था। उदाहरण के लिए श्रमिकों की वृत्ति सम्बन्धी दशाओं के लिए कानून लागू नहीं रहा; प्रारम्भ में जो कारखाने खुले उसके ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाये गये, यहाँ तक कि फैक्टरी इमारतें वेडगी बनी, उनमें सफाई, प्रकाश, हवा इत्यादि का कोई ध्यान नहीं रखा गया, श्रमिकों के आवास की भी ठीक व्यवस्था नहीं थी, निमोक्ता मनमाने ढंग पर गन्दा बस्तियों की रचना करते और श्रमिकों की दशाओं की अपेक्षाहीन अधिक किराया वसूल करते थे; यातायात के क्षेत्र में भी सरकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं था, सड़कें और नहर तथा वाद में रेल-मार्गों का विकास व्यक्तियों तथा निजी कम्पानियों द्वारा हुआ, स्वामित्व और प्रबन्ध उन्हीं का था। सरकार ने न तो वित्तीय दायित्व लिया और न उनके विषय में हस्तक्षेप किया। विदेशी व्यापार के क्षेत्र में भी एकाधिकार का अन्त हो गया और प्राचीन औपनिवेशिक प्रणाली के बन्धन शिथिल किये गये।

सन् १७६३ से १८१५ तक की अवधि में युद्ध होते रहे। इस काल में ब्रिटेन की जनसंख्या में बहुत वृद्धि हुई। जनसंख्या की वृद्धि के कारण तथा युद्ध के प्रभाव के अन्तर्गत वस्तुओं की कीमतें बढ़ी। इसलिए सामान्यतः उत्पादन को प्रोत्साहन मिला—कृषि की बहुत उन्नति हुई और उद्योगों का भी विस्तार हुआ। नैपालियन आग्ल निर्यात व्यापार को नष्ट करना चाहता था परन्तु कठिनाइयों की स्थिति में भी ग्रेट ब्रिटेन का निर्यात व्यापार कम नहीं हुआ बल्कि उसमें वृद्धि हुई। युद्धकालीन समृद्धि की सामान्य दशाओं के साथ साथ समाज में अस्वस्थ दशाएँ उत्पन्न हुई थी। इस काल में सम्पत्ति और सम्पन्नता वृद्धि का लाभ पूरे समाज को नहीं बल्कि भूस्वामियों और मिल मालिकों या पूँजीपतियों को ही अधिक हुआ। श्रमिकों और निम्न वर्ग के व्यक्तियों की दशा शोचनीय हो गई।

युद्धोपरान्त की मन्दी (१८१५-१८३०) में स्थिति बहुत गिरावट और दशाएँ अगहनीय हो गईं। युद्धकाल में यूरोपीय देशों में क्रय शक्ति नष्ट हो जाने का यह प्रभाव पड़ा कि ब्रिटिश मात की माँग कम हो गई। देश में भी माँग गिरी। अतः व्यापार घटा और उत्पादन भी गिरा। बहुत से कारखाने बन्द हो गए। युद्धकालीन उद्योगों में तथा सेनाओं में तो छँटनी का कुदाल चला ही, अन्य उद्योगों में उत्पादन घटने के कारण मजदूरों में बेकारी फैली। मजदूरियाँ गिरी। युद्धकालीन राष्ट्रीय ऋण पर व्याघ्र देने और कालान्तर में ऋण चुकाने के लिए कर-भार बढ़ाया गया।^१ अन्न-कानून के बावजूद कृषि की दशा असन्तोषजनक थी; सरक्षण के कारण खाद्यान्नों के मूल्यों में बहुत कम गिरावट हुई। परन्तु इससे श्रमिकों और निर्धनों पर और भी बुरा प्रभाव पड़ा।

ऊपर जिन सफटों का उल्लेख किया गया है उन्हीं के मध्य अर्थ व्यवस्था के पुनर्बुद्धार की दशाएँ उत्पन्न हो गई थी। शांति स्थापित होने तथा राजनीतिक स्थायित्व के कारण एक तो यो ही अच्छा प्रभाव पड़ा,^२ साथ ही सस्ते मजदूरों तथा मशीनों के प्रयोग में आने से उत्पादन की लागत कम होने के कारण

१ सन् १८१५ में आयकर (Income Tax) समाप्त कर दिया गया था अतः परोक्ष कर लगाये गये और वस्तुओं पर कर बहुत बढ़ गये। परोक्ष कर की मुख्य बुराई यह है कि निर्धन के ऊपर उसका भार अधिक पड़ता है।

२. इसका अर्थ यह नहीं समझा जाना चाहिए कि समाज की स्थिति सन्तोषपूर्ण थी, वस्तुतः उस समय राजनीतिक तथा सामाजिक असन्तोष व्याप्त था।

निम्न मूल्यों पर भी उत्पादन किया जाने लगा और निर्यात सम्भव हुए। मुद्रा प्रणाली में भी स्थायित्व आ गया। इसके अतिरिक्त सम्पत्ति और धातु पर कर भार निम्न होने के कारण उद्योगों के विकास के लिए पर्याप्त पूँजी उपलब्ध थी। तथापि श्रमिकों की दशा में सुधार नहीं हुआ।

इस अवस्था में स्थिति के सुधार के लिए नीति सम्बन्धी दो भिन्न दृष्टिकोण रखे गए। स्वतन्त्र नीति (*laissez faire*) विचारका, जिनमें जेरेमी बेन्थम प्रमुख थे, का मत था कि सरकार की स्थाित अबाध व्यापार नीति के सिद्धान्तों के कारण उत्पन्न नहीं हुई थीं बल्कि उनके प्रयोग का अपूर्णता के कारण थी। उनका मत था कि स्वतन्त्रता में बाधक सभी कानूनों को रद्द कर देना चाहिए, बल्कि राज्य का अपना भा प्रकार का भार प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए और यथासम्भव कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए।¹

दूसरा समूह मानवतावादियों का था जिनका अग्रणी लॉर्ड शफ्ट्सबरी (Lord Shaftsbury)² इनका विश्वास था कि विशेषकर ऐम व्यक्तिगतों के हित में कुछ प्रतिबंध लगाने चाहिए जो अपने लिए स्वतन्त्रतापूर्वक सोदा करने के लिए अयोग्य हों, समाज का दशा को उठाने और लोगों को रोकने के लिए ठोस (positive)³ प्रयत्न होने चाहिए।

बेन्थमवादियों को कई कानूनों को रद्द कराने में सफलता मिली जो स्वतन्त्र प्रसविदा तथा स्वतन्त्र व्यापार के मार्ग में बाधक थे। अबाध व्यापार नीति की पृष्ठभूमि में यह बात ध्यान देने योग्य है कि ग्रेट ब्रिटन संसार का प्रमुख और प्रथम औद्योगिक राष्ट्र था। दशाय व्यापार में उसे अन्य देशों से स्पर्धा का भय नहीं रहा था। उसका औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा था और उसके उद्योग-पतियों को कच्चा माल पाने और अपना निर्मित माल बेचने के लिए विदेशी बाजारों की तलाश थी⁴। अतः उद्योगपति स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में थे दूसरों

1. Knowles, L. C. A., op cit., p. 128.

2. दाना दृष्टिकोण धार्मिकता त्रिय हुए थे।

3. बेन्थमवादियों का दृष्टिकोण नकारात्मक (Negative) माना जाता है।

4. "The laissez-faire party believed that the Lord had endowed certain peoples with certain aptitudes and that mere man had no right to try and hinder them in the exercise of their faculties by putting man-made restrictions in the way of the exchange of goods or utilization of their opportunities."

—Knowles, op. cit., p. 127

और भूमिस्वामी अन्न में स्वतन्त्र व्यापार के विरुद्ध थे। उद्योगपतियों और भूमिपतियों के व्यापारिक नीति सम्बन्धी विरोधी विचार चलते रहे। अन्न में स्वतन्त्र व्यापार विचारको की विजय हुई।

सन् १८२४-२५ के उपरान्त कई दिशाओं में राजकीय नियमन (state regulation) समाप्त कर दिया गया। सन् १८२५ में व्यापारिक संघों (trade unions) को एकबारगी स्वीकृति मिल गई। इसी वर्ष प्रवास (emigration) सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटा लिए गए तथा मशीनरी निर्यात करने के लिए भी स्वीकृति दी गई।

स्वतन्त्र व्यापार नीति के सम्बन्ध में हस्किंसन (Huskisson) रॉबर्ट पील (Peel) तथा ग्लेडस्टन (Gladstone) के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। व्यापार मण्डल (Board of trade) के प्रेसीडेंट के पद पर आसोन हस्किंसन ने सन् १८२१-२७ की अवधि में कुछ आयातकर कम कर दिए तथा कुछ विदेशी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध हटा दिये। नौ बहन कानून में भी उसने सुधार प्रारम्भ किये। उन देशों के जहाजों पर से प्रतिबन्ध हटा लिये गये जो ब्रिटिश जहाजों को समतुल्य छूट देने को तैयार हो गए। आयात-निर्यात-प्रचुलक तालिका (Tariff Schedule) में अनेक परिवर्तन किड़े गए।

रॉबर्ट पील की सफलता अधिक उल्लेखनीय है। सन् १८४५ से १८५५ की मध्यविधि में आयात करों में इतनी अधिक कायापलट हुई कि वस्तुओं पर जो आयात कर लगे थे, उनकी संख्या ११५० से ५६० रह गई। सन् १८४६ में अन्न कानून को रद्द करके अन्न का आयात स्वतन्त्र कर दिया गया। सन् १८४६ के पश्चात् नौ-बहन कानून के प्रतिबन्धक अद्य समाप्तप्रायः कर दिए गए। निर्यात करों तथा उत्पादन करों में बहुत कमी कर दी गई।

पील के बचे हुए कार्य को ग्लेडस्टन ने पूरा किया। सन् १८५५ में चीनी तथा सन् १८६० में शराब के विदेशों तथा उपनिवेशों से होने वाले आयातों पर करों की दर समान कर दी गई। आयात कर केवल ४८ वस्तुओं पर रह गए। सन् १८५४ में नौ-बहन प्रतिबन्ध तृतीय व्यापार से भी समाप्त कर दिये गये। आयात करों के उन्मूलन अथवा उनमें की गई कमी के कारण होनेवाली सरकारों आय की कमी को पूरा करने के लिए पील और ग्लेडस्टन ने कर प्रणाली में व्यापक परिवर्तन किये।

मानवतावादियों के प्रयत्नों के परिणाम—जिन बात में बोन्यमवादियों ने स्वतन्त्र व्यापार नीति को दिशा में सफल प्रयत्न किये, तमाम उद्योगों में

लॉर्ड शेफ्टसबरी ने प्रभावशाली व्यक्तित्व के नेतृत्व में टोड़ी मानवतावादियों ने सरकार द्वारा व्यावसायिक दशाग्रो के नियमन और सुधार हेतु प्रयत्न किये जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। सन् १८३३ से १८५० तक की अवधि में कई कारखाना अधिनियम (Factory Acts) पारित हुए। सन् १८३३ के प्रथम प्रभावपूर्ण फैक्टरी ऐक्ट की एक नवीनता यह थी कि निरीक्षण की व्यवस्था की गई और इन्स्पेक्टरों की नियुक्ति की गई।^१ सन १८३३ में शिक्षा के लिए सरकारी अनुदान (grants) की व्यवस्था प्रारम्भ का^२ जिसमें बाद में वृद्धि की गई। सन १८४२ में एक अधिनियम द्वारा स्त्रियों और बच्चों से खानों के भीतर काम कराना वर्जित कर दिया गया। सन १८४८ में स्वास्थ्य मण्डल (Board of Health) की स्थापना हुई जिसमें लॉर्ड शेफ्टसबरी भी एक सदस्य के रूप में सम्मिलित थे।

सन १८५० में १८७५ तक का समय सभी दृष्टियों में समृद्धि का काल था जिसे ब्रिटिश आर्थिक इतिहास में 'स्वर्ण युग' कहा जाता है। इस अवधि में कीमते बढ़ी और साध-माय मजदूरियों में भी वृद्धि हुई। धन संधा ने प्रगति की और फैक्टरी अधिनियमों का कांक्षित अर्थिका की दशाएँ सुधरी थी। परिवहन के साधनों में बहुत विकास हुआ। घरेलू तथा विदेशी व्यापार में असाधारण वृद्धि हुई। ब्रिटेन में जहाज निर्माण उद्योग तथा जहाजी व्यापार में विकास हुआ। लोहा-इस्पात तथा अन्य अनेक उद्योगों में बहुत प्रगति हुई। अन्य यूरोपीय देशों तथा अमेरिका में असाधारण के कारण ब्रिटेन की स्थिति इस प्रकार की हो गई कि उसका कोई मुकाबल का प्रतिद्वन्द्वा न रहा और उसे एकाधिकार के स्वभाव के लाभ मिले। पूँजी की शक्ति बहुत बढ़ रही थी (जिसके सुधार के लिए चार आन्दोलनों—सहकारी आन्दोलन, धर्म सभ आन्दोलन, कारखाना कानून और मूर्तिनसपल कार्यों का विकास हुआ।

अवाध-व्यापार नीति के समर्थकों का कहना था कि इस काल में (१८५०-१८७५) समृद्धि इसलिए हुई कि आर्थिक क्रियाओं का राजकीय नियमन हटा

1. "... The starting of inspectorate is therefore epoch-making, at only meant at first State control of certain industries to prevent breaches of the law, it gradually extended its scope....."
—Knowles, op cit., p 125

२. सन् १८३३ के पूर्व शिक्षा की व्यवस्था पूर्णतया निजी और दातव्य साहस पर छोड़ी हुई थी।
—Southgate, op. cit., p. 350.

दिया गया था परन्तु मानवतावादियों का विचार था कि उनके प्रयत्नों के परिणाम राष्ट्र की समृद्धि में बाधक सिद्ध नहीं हुए थे बल्कि सरकारी कार्यवाही वांछनीय थी ;

अबाध व्यापार नीति का प्रभाव—यह ऊपर बताया जा चुका है कि विनोद सन् १८२५ के पश्चात् राजकीय नियमन तथा प्रतिबंधों को कम करने की दिशा में अनेक परिवर्तन हुए । अबाध व्यापार नीति ब्रिटेन के लिए उस समय बहुत अनुकूल सिद्ध हुई । मुख्य आर्थिक प्रभाव निम्नलिखित दिशाओं में पड़े :—

१. विदेशी व्यापार में बहुत वृद्धि हुई । सन् १८४६ में ब्रिटिश निर्यातों का मूल्य ६,४० लाख पौण्ड था, सन् १८७० में यह २०,०० लाख पौण्ड हो गया था ।

२. औद्योगिक समृद्धि में वृद्धि होती गई तथा अनेक नये उद्योग विकसित हुए ।

३. निर्यातों की संख्या में वृद्धि हुई तथा विदेशी व्यापार के स्वभाव में परिवर्तन हुआ । व्यापार का क्षेत्र भी बढ़ा ।

४. जहाजी आय में बहुत वृद्धि हुई ।

५. कृषि-पदार्थों के मूल्यों में गिरावट तथा विदेशी से स्वर्द्धा के कारण कृषि की उन्नति करना अनिवार्य हो गया । गहरी खेती होने लगी ।

६. खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं की कीमतें कम होने के कारण श्रमिकों की वास्तविक मजदूरियाँ बढ़ी ।

७. सरकारी आय को स्थिर रखने के लिए आयकर तथा परोक्ष कर लगाये गये ।

अबाध व्यापार नीति का पतन तथा रक्षणवादी नीति का विकास

सन् १८७५ में मन्दी ने आ धेरा जिसका प्रभाव ब्रिटेन पर ही नहीं संसार के अधिकांश देशों पर पड़ा । यह मन्दी सन् १८८६ तक चलती रही, बल्कि

१. वस्तुतः ये प्रभाव केवल अबाध व्यापार नीति के ही नहीं थे बल्कि कई अनुकूल दशाओं के सम्मिलित प्रभाव समझे जाने चाहिएँ, तथापि अबाध व्यापार नीति का प्रभाव इन्हीं दिशाओं में था । अन्य अनुकूल दशाओं के अन्तर्गत यातायात में विकास, सन् १८६६ में स्वेज नहर का खुलना इत्यादि थे ।

उद्योगोसयी शताब्दी के अन्तिम चतुर्थांश का पूरा भाग ब्रिटिश अर्थ व्यवस्था का महान् मकट काल माना जाता है। इस काल की मुख्य विशेषताएँ ये थी :

(१) कीमतों में सामान्य गिरावट हुई,

(२) कृषि पर सस्ते विदेशी गेहूँ और मांस के आयात का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। रेलों और जहाजों यातायात के विकास के कारण तथा प्रशीतन विधि इत्यादि के विकास के कारण आयात बहुत बढ़ गये थे।

(३) जर्मनी और संयुक्त राज्य की तथा अन्य देशों की स्पर्धा का ब्रिटिश उद्योगों पर गम्भीर प्रभाव पड़ा; लोहा इस्पात उद्योग में मन्दी का एक कारण बिसीमर पद्धति भी था जिसके कारण काफी हानि उठा कर पुनर्गठन किया गया।

(४) नौवहन (shipping) पर भी कुपभाव पड़ा। इस्पात के जहाजों में वृद्धि हुई थी और ब्रिटिश जहाजों का एकाधिकार समाप्त हो गया था, स्वेज नहर खुलने के पश्चात् नये प्रकार के जहाजों का विकास हुआ।

(५) बेरोजगारी व्यापक रूप में फैली।

(६) स्वेज नहर खुलने तथा रेलमार्गों के विकास के कारण व्यापारिक मार्गों में परिवर्तन का ब्रिटेन के व्यापार पर प्रभाव पड़ा। यूरोपीय देशों का व्यापार ग्रेट ब्रिटेन की भारभक्त होने के बजाय सीधा होने लगा। भूमध्यसागरीय बन्दरगाहों का महत्व बढ़ चला था। जर्मनी की प्रतिद्वन्द्विता का ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर सर्वां क्षेत्रों में प्रभाव पड़ा।

इस दुःखान्त कथा में दो तथ्य प्रकट हुए। पहला तो यह कि जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका इत्यादि देशों में उसी समय सरकारी महामता द्वारा उद्योग, वाणिज्य एवं कृषि की उन्नति की जा रही थी जब कि प्रवाच व्यापार नीति में विश्वास करने वाले ब्रिटेन में आर्थिक क्रियाओं को प्राकृतिक नियमों के सहारे अथवा यों कहिए कि दैवी प्रकोप सहने के लिए छोड़ा हुआ था।

दूसरा यह कि सस्ते विदेशी माल की स्पर्धा का सबसे अधिक बुरा प्रभाव ब्रिटेन पर पड़ा क्योंकि सन् १८५० के उपरान्त ग्रेट ब्रिटेन ने विदेशी व्यापार की राह की रक्षादलों को समाप्त करके अपने द्वार खुले छोड़ दिये थे जबकि अन्य देश प्रशुक्त की ऊँची दीवारों के भीतर सुरक्षण अपनाये हुए थे, अतः उन देशों में माल बेचना तो सरल नहीं था, ब्रिटिश मण्डियों में सस्ता विदेशी माल घड़ाघड़ प्रवेश पा रहा था। इसी प्रसङ्ग में यह उल्लेखनीय है कि अमरीका का ग्रान्डीनन ग्रेट ब्रिटेन में जोर पकड़ता जा रहा था।

ऊपर जो कुछ बताया गया है उसके आधार पर यह समझना सरल है कि अबाध व्यापार नीति ने प्रति ब्रिटेन में लोगों का विश्वास डिग गया और उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। परिणाम यह हुआ कि सन् १८८६ के पश्चात् अबाध व्यापार नीति का पतन होने लगा। अनेक क्षेत्रों में सरकारी कार्यवाही आवश्यक समझी गई और अनेक अधिनियम पारित किये गये। सरकारी हस्तक्षेप के लिये अन्य कारण भी उपस्थित हुए :

(१) मास्टू लिया, फ्रान्स तथा इटली ने ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता भङ्ग कर दिया,

(२) सन् १९१४-१८ के महायुद्ध काल में उत्पन्न परिस्थितियों में सुरक्षा की दृष्टि से कदम उठाने आवश्यक थे;

(३) ब्रिटेन का व्यापार सन्तुलन प्रतिकूल बढ़ता जा रहा था,

(४) सन् १९२९-३० की मन्दी ने ब्रिटिश अर्थ व्यवस्था को कमर ही तोड़ दी और नीति में परिवर्तन की आवश्यकता एकदम सम्मुख आ गई।

इसी प्रसङ्ग में निम्नलिखित परिस्थितियाँ उल्लेखनीय हैं :—

१. ब्रिटेन ऐसा देश था जो विदेशी व्यापार पर अधिक निर्भर था, मत. उसे अन्य देशों की अपेक्षा अधिक हानि हुई।

२. युद्धकाल में जहाजों (Shipping space) की तंगी थी। उस काल में ऐसे देशों ने, जो युद्ध में लगे हुए नहीं थे, अपने समुद्री व्यापार के लिए अपने जहाज बना लिये। इसका ब्रिटिश जहाजी व्यापार तथा जहाज-निर्माण उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा।

३. युद्धकाल में कोयले के उपयोग में वृद्धि कराने का प्रयत्न किया गया था। युद्धोत्तर काल में (१९१८ के पश्चात्) अन्य ईंधनों के प्रचलन के कारण ब्रिटिश कोयला उद्योग को धक्का पहुँचा।

४. युद्ध में प्रभावित देशों में जनता की क्रय-शक्ति कम हो गई थी, अतः उन देशों में ब्रिटिश माल की माँग घटी।

५. पूर्वी देशों में औद्योगीकरण की दिशा में प्रगति हुई थी। अतः उन देशों में तो ब्रिटिश निर्मित माल की माँग घटी ही, साथ ही वे ब्रिटेन के प्रति-द्वन्द्वी बन रहे थे।

६. ब्रिटिश उद्योग की प्रतिযোগिता सामर्थ्य घटी थी क्योंकि अन्य देशों की अपेक्षा ब्रिटेन में श्रमिकों को मजदूरियाँ बढ़ी थी तथा काम के घंटों में घटोत्तरो किये जाने से लागत बढ़ी थी।

परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश उद्योगों की उत्पादन क्षमता गिरी। सन् १९३० में १९२९ वर्ष की तुलना में आयातों में १३८ प्रतिशत और निर्यातों में २१०८ प्रतिशत की गिरावट हुई। सन् १९३० में बेकारों (unemployed) की संख्या २५ लाख हो गई। पांच सौ में अधिक कम्पनियों के लाभों में १८ प्रतिशत के लगभग गिरावट हुई। इस प्रकार व्यापार में गिरावट, लाभों में कमी तथा बेरोजगारी का सम्मिलित प्रभाव यह हुआ कि देश का आर्थिक सन्तुलन नष्ट हो गया।^१ अतः अर्थव्यवस्था के और अधिक पतन को रोकने के लिए ब्रिटेन ने रक्षणवादी नीति अपनाई।

अबाध व्यापार नीति का पतन वाणिज्यवाद (mercantilism) की पुनः स्थापना की ओर कदम नहीं था जिसमें व्यक्तियों का समृद्धि की अपेक्षा राष्ट्र की सत्ता बढ़ाना प्रमुख ध्येय था। रक्षणवादी नीति में राजकीय कार्यवाही का महत्व नियमन एवं नियन्त्रण का अपेक्षा सहायता, महारे और सुरक्षा के लिए समझा गया था।

राजकीय कार्यवाही और रक्षणवादी नीति की प्रगति—जैसा कि इस अध्याय में पहले बताया जा चुका है कि सन् १८८६ के उपरान्त अबाध व्यापार नीति की प्रतिक्रिया हुई। अनेक दिशाओं में सरकारी कार्यवाही हुई।

(१) श्रमिकों के हितों में कई अधिनियम पारित हुए। उदाहरण के लिए, सन् १८९१ में फैक्टरी तथा वर्कहाउस अधिनियम पास हुआ जिसके अनुसार १२ वर्ष से कम आयु वालों से कारखानों में काम कराना वर्जित कर दिया गया। सन् १८९३ में शॉप आबर्स एक्ट (Shop Hours Act) तथा सन् १८९५ में एक और फैक्टरी एक्ट पास हुआ। सन् १८९६ के उपरान्त सामाजिक बीमा की दिशा में प्रगति होती गई।^२ सन् १८९६ के पश्चात् औद्योगिक झगड़ों के हल के लिए भी कानूनी उपाय अपनाये गये।^३

(२) कृषि की दशाओं की जाँच के लिए आयोग नियुक्त किए गए तथा अधिनियम पारित किए गए। सन् १९३१-३२ में कृषि की सहायता के लिए विशेष उपाय अपनाए गए।

1. "Thus shrinkage of trade, unemployment and loss of profits combined thoroughly to shake the economic equilibrium of the country."

२. विस्तार के लिए 'सामाजिक सुरक्षा का विकास' अध्याय देखिए।

३. सन् १८९६ में Conciliation Act पास हुआ था।

(३) सन् १८७० के उपरान्त, विशेषकर सन् १८८७ से तथा सन् १८९५ में कोलोनियल पद पर चेम्बरलेन के आजाने के पश्चात् औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन हुआ और रचनात्मक साम्राज्यवाद की दिशा में प्रयत्न किये गये।

(४) व्यापार के क्षेत्र में भी कुछ अधिनियम पारित किये, व्यापार मण्डल का कर्माक्षियल इन्टेलीजेन्स विभाग खोला गया और एक जर्नल निकाला गया, समुद्रपार व्यापार के लिए एक पृथक् विभाग खोला गया। सन् १९३१-३२ में मेम्बरन्स व्यापार का परित्याग कर दिया गया और साम्राज्यगत अधिमान (Imperial Preference) की नीति को मान्यता दी गई।

(५) रेल यातायात तथा जहाजी यातायात के क्षेत्र में भी राजकीय सहायता प्रदान की गई। सामाजिक सेवासो का विकास हुआ।

सन् १९१५ में सिने फ़िल्मों, घड़ियों, मोटर गाड़ियों इत्यादि पर ३३½ प्रतिशत यथा मूल्य कर लगाकर ब्रिटिश उद्योगों को संरक्षण दिया गया। सन् १९२१ में उद्योग संरक्षण अधिनियम स्वीकृत हुआ जिसके अनुसार सैकड़ों वस्तुओं पर ३३½ प्रतिशत यथामूल्य कर (ad Valorem duty) लगाया गया। सन् १९३१ के पश्चात् ब्रिटेन विश्व का प्रसिद्ध रक्षणवादी देश बन गया। तत्कालीन मिली जुली सरकार (Coalition Government) ने कई वस्तुओं पर ५० प्रतिशत से १०० प्रतिशत तक की दर पर आयात कर लगा दिये। परन्तु उपनिवेशों तथा साम्राज्यगत देशों के माल को कर-मुक्त रखा गया प्रथम। उस पर बहुत कम कर लगाया गया।^१ सन् १९३२ के छोटावा समझौते के अनुसार सभी अधिराज्यों के लिए आपसी रियायत करना अनिवार्य हो गया।

रक्षणवादी नीति के लाभ—रक्षणवादी नीति अपनाने से ब्रिटेन को निरचय ही लाभ हुए। रक्षणवादी नीति मुख्यतया निम्नलिखित उद्देश्यों से अपनाई गई थी जिनमें सफलता मिली :—

(१) आयातों में कमी तथा निर्यातों में वृद्धि करके व्यापारान्तर (Balance of Trade) का सुधार किया।

१. बात यह थी कि उपनिवेशों और साम्राज्यगत देशों में निर्माण उद्योगों का इतना विकास नहीं हुआ था कि वे ब्रिटेन से स्पर्द्धा करने के योग्य होंगे और ब्रिटेन उनमें अपना निर्मित माल बेचने के लिए क्षेत्र सुरक्षित रखना चाहता था।

(२) प्रतिकूल व्यापारान्तर के कारण स्टलिग का विनिमय मूल्य गिरा था, रक्षणवादी नीति के द्वारा गिरावट रकी ।

(३) आयात निर्यात प्रशुल्क का उद्देश्य यद्यपि देश के उद्योग और व्यापार को संरक्षण प्रदान करना था परन्तु साथ ही सरकारी आय में वृद्धि हुई ।

(४) अबाध व्यापार नीति अपनाने का अर्थ सभी उद्योगों को समान समझना था । यह उचित नहीं था । रक्षणवादी नीति के द्वारा विभिन्न उद्योगों की आवश्यकताओं में वैज्ञानिक आधार पर भेद करना सम्भव हुआ ।

(५) जिस सीमा तक संरक्षण से निर्यातों को प्रोत्साहन मिला, उत्पादन और वितरण के श्रेष्ठतर तरीके अपनाना सम्भव हुआ ।

(६) अबाध व्यापार नीति सभी विदेशी राष्ट्रों को समान मानती थी, रक्षणवादी नीति के आधार पर समान और पारस्परिक लाभों की दृष्टि से कुछ देशों के माल को अधिमान (preference) देना सम्भव था जिसके आधार पर अन्य देशों से समझौते किये जा सकने थे ।

यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विशेष आर्थिक परिस्थितियों से बाध्य होकर ब्रिटेन को अबाध व्यापार नीति का त्याग करके रक्षणवादी नीति अपनानी पड़ी । हरेक देश में राष्ट्रीयता की भावनाओं के विकास तथा औद्योगिक प्रगति के साथ ब्रिटेन में रक्षणवादी नीति अपनाना उचित और उसके लिए हितकारी सिद्ध हुआ ।

द्वितीय विश्व-युद्ध तथा युद्धोत्तर काल में (ब्रिटेन की प्रशुल्क नीति)

द्वितीय विश्व युद्ध काल में आयात नियन्त्रण किश गया तथा सरकार द्वारा ही खरीद हो सकती थी, अतः प्रशुल्क द्वारा संरक्षण देने का मूल्य बहुत कम हो गया । सन् १९४६ में जब आयात नियन्त्रण सम्बन्धी प्रतिबन्ध पर्याप्त ढीले कर दिये गये तो संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रशुल्क (tariff) पुनः महत्वपूर्ण भूमि हो गया ।

ब्रिटेन की प्रशुल्क नीति अब भी रक्षणवादी है परन्तु द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् व्यापार और प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौते (GATT—General Agreement on Trade and Tariff) के अनुसार संरक्षणात्मक प्रशुल्क में काफी परिवर्तन किये हैं । राष्ट्र कुल (Commonwealth) के देशों के तथा औपनिवेशिक पदार्थों पर अधिमान चालू है ।

सन् १९५७ में पारित एक अधिनियम (The Customs Duties—Dumping and Subsidies Act) द्वारा व्यापार मण्डल को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी प्रकार के ऐसे आयात होने वाले माल पर छपूटी लगावे जिसका ब्रिटेन में डम्पिंग किया जाये अथवा जिसे आर्थिक सहायता (Subsidy) प्राप्त करके विक्रय के लिए भेजा जाए। सन् १९५८ के आयात कर अधिनियम (Import Duties Act) द्वारा सरस्राणुत्मक प्रशुल्क सम्बन्धी कानून को एकत्रित करके अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित रूप में ला दिया गया है।

प्रश्न

- 1 Give an idea of the various stages through which commercial policy in England has passed.
 2. Discuss critically why England adopted protection in 1932
 3. Examine by reference to the agricultural and industrial legislation from 1880 to 1914, the important change that occurred in the economic policy of England as a result of the great depression of 1873-86.
 4. Describe the growth of Free Trade in England after 1800. What causes led to it at the time, and what gave it a setback about the end of the nineteenth century
 5. Describe the rise and fall of Mercantilism in England.
-

अधिकोपण तथा राजस्व

(Banking and Finance)

[अधिकोपण प्रणाली का प्रारम्भ, बैंक ऑफ इंग्लैण्ड की स्थापना, सत्रहवीं शताब्दी में ब्रिटिश अधिकोपण की विशेषताएँ, उन्नीसवीं शताब्दी के बैंकिंग अधिनियम तथा अधिकोपण का विकास, आधुनिक काल—बैंक ऑफ इंग्लैण्ड, व्यापारिक बैंक; राजस्व, सरकारी आय-व्यय, प्रश्न ।]

सत्रहवीं शताब्दी तक ग्रेट ब्रिटेन में अधिकोपण (banking) व्यवसाय शायद था ही नहीं, आधुनिक अर्थ में तो निश्चय ही नहीं था। ब्याज लेना बहुत निन्दनीय समझा जाता था। सूदखोरी बर्जित कर दी गई थी। सत्रहवीं शताब्दी में इंग्लैण्ड में मत बदला और यह समझ जाने लगा कि किसी व्यापारी से, जो लाभ कमाने के लिए ऋण लेना है, ऋण पर ब्याज लेना अनुचित नहीं था। सन् १५४५ में एक अधिनियम पारित हुआ जिसके अनुसार सूदखोरी तो नहीं, ब्याज लेना गैरकानूनी न रहा। सन् १६२४ के एक अधिनियम द्वारा ब्याज की अधिकतम दर आठ प्रतिशत निश्चय हुई। सन् १६५२ में यह सीमा ६ प्रतिशत कर दी गई।

अधिकोपण प्रणाली का प्रारम्भ

सत्रहवीं शताब्दी में अधिकोपण प्रणाली का प्रारम्भ हुआ समझा जा सकता है जब स्वयंसेवा ने ब्याज पर पूँजी उधार देने के लिए जमाएँ (deposits) स्वीकार कीं। मुनारी के पास पूँजी थी परन्तु अन्य प्रकार के व्यापारी की तरह उनके व्यापार में अधिक पूँजी विनियोग करने का क्षेत्र न था। अतः वे अपने सबी हुई पूँजी उधार देने थे। अन्य व्यापारियों की सुविधा के लिए वे अन्य देशों की मुद्राओं का विनियम भी करने लगे। कालान्तर में वे अपने ग्राहकों में द्रव्य सुरक्षित रखने के लिए स्वीकार करने लगे। वे ऐसी जमाओं की माँगने ही देने की प्रतिज्ञा करते थे। अनुभव में वे यह सीख गये

कि उनके पास जमा की हुई धन राशियाँ किसी एक समय पर सबकी सब नहीं माँगी जायेंगी। अतः वे उनमें से उधार भी देने लगे जिसके लिए ब्याज लेते थे। धीरे धीरे इन सुनारों पर लोगों का विश्वास बढ गया और वे परिवर्तनीय नोटों का निर्गम करने लगे। जब उनका यह व्यवसाय बढा तो वे जनता की अधिक जमाएँ (deposits) आकर्षित करने के लिए ब्याज देने लगे।

स्वर्णकारों के अधिकोपण व्यवसाय पर आरम्भ में कोई नियमन या सरकारी नियन्त्रण नहीं था। वे ऋण लेने वालों से ब्याज ऊँची दर पर लेते थे। जिन उद्योग-धन्धों के लिए ऋण लिए जाते थे उनमें भी अनिश्चितता थी, अतः इस दृष्टि से अधिक ब्याज लेना बहुत अनुचित प्रतीत नहीं होता। स्पष्ट है कि ऋण लेने वालों की स्थिति अनिश्चित होने के कारण तत्कालीन अधिकोपण व्यवसाय भी सुरक्षित नहीं था। कालान्तर में सम्राट् भी स्वर्णकारों से ऋण लेने लगे।

सन् १६७२ में चार्ल्स द्वितीय ने स्वर्णकारों से लिए हुये ऋणों के सरकारी कोष से होने वाले भुगतान स्थगित कर दिए, केवल ब्याज चुकाने का दायित्व लिपा।^१ इस कार्यवाही का स्वर्णकारों की स्थिति पर गम्भीर प्रभाव पड़ा। वे अपनी दैनदारियों को चुकाने में असमर्थ हो गये और सकट में पड़ गए। कई दृष्टियों से जनमत उनके विरुद्ध हो रहा था। ऐसी अधिकोपण संस्था की माँग थी जिस पर जनता का अधिक विश्वास हो सके तथा उद्योग और व्यापार के लिए अपेक्षाकृत निम्न ब्याज दर पर ऋण प्राप्त हो सकें। जो कुछ भी हो, यह कहा जा सकता है कि अधिकोपण प्रणाली का जन्म हो चुका था।

बैंक ऑव इंगलैण्ड की स्थापना

सत्रहवीं शताब्दी के अन्त की ओर ग्रेट ब्रिटेन की अर्थ व्यवस्था सन्नान्ति लाने वाली अनेक परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जिनके कारण १८वीं शताब्दी में नई आर्थिक प्रणाली का जन्म हुआ। इस सन्नान्ति के इतिहास में बैंक ऑव इंगलैण्ड की स्थापना का बहुत महत्व समझा जाता है।^२ ऊपर जिन परिस्थितियों का उल्लेख किया जा चुका है उन्हें दृष्टिगत रखकर बैंक ऑव इंगलैण्ड को

1. Southgate, op. cit., p 297.

2. "In the history of this transition the incidents of most importance are the success of the House of Commons in the Constitutional struggle, and the establishment of the Bank of England."
— Meredith, op. cit., p. 207.

स्थापना का महत्व समझना सरल है परन्तु जैसा कि मेरेडिथ ने लिखा है उसके वैधानिक स्वत्वों (चार्टर) का विकास व्यापार-जगत की सेवाओं के लिए उतना नहीं जितना कि राजकीय आवश्यकताओं के कारण किया गया।^१ सन् १६६४ में राजकीय व्यय के संतुलन के लिए १२ लाख पौण्ड की आवश्यकता थी। विलियम पेटर्सन (स्कॉटलैण्ड के एक व्यक्ति) ने एक स्कीम सुभाई जिसमें बिना कुछ अधिक संशोधन किए क्रियान्वित किया गया और परिणामतः सन् १६६४ में बैंक ऑव इंग्लैण्ड की स्थापना हुई। इस संस्था को इतनी अधिक सफलता मिली कि इसके अधिकार बहुत अधिक बढ़ा दिए गए।

बैंक ऑव इंग्लैण्ड की कम्पनी तथा उसके गवर्नर ने सरकार को १२ लाख पौण्ड की धन राशि उधार देने का दायित्व लिया। उसको दिये जाने वाले मुख्य अधिकार ये थे :

- (१) नोट निर्गमन करना,
- (२) धातु में विनिमय सौदे करना तथा बिलो (bills) का बट्टा,
- (३) ऋण प्रदान करना, तथा

(४) जमाएँ (deposits) प्राप्त करना। मुद्रा के टंकण में उसने सरकार को सहयोग प्रदान किया। सन् १६६६ में उसे कुछ विशेष अधिकार दिए गये तथा सन् १७०८ में एक अधिनियम के द्वारा संयुक्त-पूँजी वाले बैंको में उसे नोट निर्गम के लिए एकाधिकार दिया गया जिसके अनुमार छः से अधिक साझेदारों वाला कोई अन्य ऐसा बैंक स्थापित नहीं किया जा सकता था जिसे नोट निर्गम का अधिकार दिया जाय। सन् १७५१ में राष्ट्रीय ऋण (National Debt) का प्रबन्ध पूर्णतया बैंक ऑव इंग्लैण्ड को सौंप दिया गया। ऐसे संयुक्त पूँजी वाले बैंकों के निर्माण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था जो जमाएँ स्वीकार करने के लिए ही स्थापित हो परन्तु ऐसी बैंकों की स्थापना भी सन् १८२६ के पूर्व तक नहीं हुई। वस्तुतः उस समय बैंकिंग व्यवसाय चलाने के लिए नोट निर्गम का कार्य अत्यावश्यक समझा जाता था।

बैंक ऑव इंग्लैण्ड के प्रारम्भिक काल में बैंकिंग व्यवसाय में उससे स्पष्टां

1. "The Bank of England owed its charter less to a deliberate cognisance by the Government of the services which such an institution could perform to the business world than to pressing necessities of State." —Meredith, op. cit., p. 215.

लेने वाली कोई अधिकोपण संस्था नहीं थी परन्तु उन स्वर्णकारों ने जिनके तेन-देन पर प्रभाव पड़ा था ईर्ष्यावश उसकी आलोचना की। कुछ अन्य व्यक्तियों को भी यह सन्देह था कि यह बैंक जो कुछ सेवा कर रही थी उससे अधिक अपने अधिकारों का लाभ उठा रही थी। आरम्भ में स्वर्णकारों ने बैंक ऑफ इंग्लैण्ड को संकट में डालने के लिए काफी मात्रा में उसके नोट एकत्रित करके भुगतान के लिए प्रस्तुत किये।^१ बैंक के पास इस मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नगदी नहीं थी। बैंक ने दृढ़ता से काम लिया और कुछ नोटों पर १५ प्रतिशत अदायगी की; ऐसे नोटों का भुगतान स्थगित कर दिया जो स्पष्ट रूप में बैंक को कठिनाई में डालने के लिए ही पेश किए थे। इसी बीच में टंकमाल से पर्याप्त मात्रा में सिक्के आ गये और कुछ ही सप्ताहों में संकट काल समाप्त हो गया।

अठाहरवीं शताब्दी में ब्रिटिश अधिकोपण की विशेषताएँ

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, १८ वीं शताब्दी में संयुक्त-पूँजी के अधिकोपण में बैंक ऑफ इंग्लैण्ड का एकाधिकार था। निजी बैंकों के रूप में वे स्वर्णकार थे जिन्होंने इंग्लैण्ड में अधिकोपण को जन्म दिया था, कुछ अन्य शक्ति भी यह काम करने लगे थे। नोट निर्गम का कार्य बैंकिंग व्यवसाय के लिए आवश्यक समझा जाता था और क्योंकि वैधानिक रूप में यह अधिकार बैंक ऑफ इंग्लैण्ड के लिए सीमित रखा गया था, अन्य संयुक्त-पूँजी वाले बैंकों का विकास नहीं हुआ। उनका एकाधिकार न तो उसके स्थायित्व के लिए आवश्यक ही था और न ही वह अधिकोपण के विकास के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। बैंक ऑफ इंग्लैण्ड के सम्मुख उसकी शाखाएँ खोलने के लिए प्रस्ताव रखा गया था, यदि स्पर्धा होती तो शायद शाखाएँ चलाई जाती।^२ परन्तु उनके

१. निर्गम करने वाला बैंक परिवर्तनीय नोटों के प्रस्तुत किये जाने पर चालू प्रणाली के अनुरूप चलन अथवा सिक्के इत्यादि देने की प्रतिज्ञा करना है। व्यवहार में यह निर्गमित नोटों के अनुपात में कम नगदी कोष रखकर भी संभव होता है क्योंकि जनता बैंक पर विश्वास रखती है और भुगतान के लिए बहुत कम नोट प्रस्तुत किए जाते हैं। परन्तु यदि जनता का विश्वास टूट जाए अथवा जान बूझकर बैंक को संकट में डालने का विचार उत्पन्न हो तो बहुत अधिक नोट भुगतान के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

२. प्रारम्भिक अवस्था में बैंक ऑफ इंग्लैण्ड ने अपना कार्यक्षेत्र सन्दन में ही सीमित रखा। इसीलिए एशटन ने कहा, *It was the Bank of London, rather than of England.*—Ashton, T.S., op. cit., p. 101.

अभाव में प्रान्तीय नगरों में अधिकोपण मुविधाएँ प्राप्त नहीं हो सकीं। यह कहा जाता है कि स्पर्द्धा की दशाओं पर रोक लगाकर अधिकोपण के विकास में रकावट डाल दी गई थी।

१८ वीं शताब्दी के मध्य तक अर्थात् औद्योगिक क्रान्ति के पूर्व तत्कालीन आवश्यकताओं की दृष्टि में अपर्याप्त नहीं बही जा सकती परन्तु १७५० ई० के उपरान्त औद्योगिक विकास के काल में अधिकोपण क्रिया में वृद्धि हुई। यदि संयुक्त पूँजी वाले बैंकों के निर्माण पर प्रतिबन्ध न होते तो अधिकोपण व्यवसाय का विकास का मुहूर्त रूप सम्भव हो सकता था। इस काल के कुछ बैंक मुचालित थे परन्तु अधिकोपण कार्य में लगे अधिकदाय व्यक्तियों के साधन संमित थे और वे प्रायः निम्न स्थिति के थे।

सन् १७६३ में फ्रेंच युद्ध छिड़ने पर सन् १८२५ तक (सन् १८१५ में युद्ध समाप्त होने के बाद भी) ब्रिटिश अधिकोपण व्यवसाय पर संकट छाया रहा। सन् १७६७ में सरकार ने बैंक ऑफ इंग्लैंड को अधिकार दिया कि वह नोटों का भुगतान बन्द कर दे और लगभग बीस वर्षों तक परिवर्तनीय नोटों के बदले में स्वर्ण देना बन्द रहा। इनको निजी बैंकों का दिवाला निकल गया। सन् १८२१ में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने नोटों के बदले में स्वर्ण देना प्रारम्भ कर दिया था। सन् १८२४ तक व्यापार में समृद्धि की दशाएँ आ गई थी। विद्वत्स बढ चला था और अत्यधिक मात्रा में नोट निर्गमित हुए और परिणाम यह हुआ कि सन् १८२५ में ७० से आ अधिक बैंकों को दिवालिया होना पड़ा।

उन्नीसवीं शताब्दी के बैंकिंग अधिनियम तथा अधिकोपण का विकास

सन् १८२३ में बैंक ऑफ इंग्लैंड के सम्मुख सरकार ने प्रस्ताव रखा कि यदि वह अपना एकाधिकार लन्दन और उसके आस-पास सभी और ६५ मील के क्षेत्र तक सीमित रखने के लिए सहमति दे तो उसका अधिकार पत्र (चार्टर) सन् १८४३ तक के लिए बढ़ा दिया जाय। इस विषय पर बैंक ऑफ इंग्लैंड की सहमति लेना आवश्यक इसलिए था कि उसको सन् १८३२ तक के लिए पहले ही अधिकार दिये जा चुके थे।^१

सन् १८२६ में एक बैंकिंग अधिनियम पारित हुआ जिसके द्वारा यह व्यवस्था हुई कि लन्दन से ६५ मील बाहर कहीं भी संयुक्त पूँजी वाले बैंक

1. See Meredith, op. cit., p. 313.

स्थापित किये जा सकते थे जिन्हें नोट-निर्गम का अधिकार रहेगा। परन्तु पाँच पौण्ड में कम के नोटों का निर्गम निषिद्ध कर दिया गया था। देश का अधिकतर वित्तीय व्यापार लन्दन में केन्द्रित होने के कारण इस अधिनियम द्वारा बैंक ऑफ इंग्लैण्ड के एकाधिकार पर कोई गम्भीर प्रभाव नहीं पड़ा।। उसके अन्य संयुक्त पूँजी वाले बैंकों से सम्बन्ध भी सन्तोषजनक नहीं हो सके क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैण्ड को लन्दन के ६५ मील के बाहर बैंकिंग कार्य करने का अधिकार था, अतः प्रान्तीय नगरों में वह अन्य बैंकों के साथ स्पर्धा करता था।

सन् १८३३ के बैंकिंग अधिनियम द्वारा बैंक ऑफ इंग्लैण्ड के अधिकारों में कुछ परिवर्तन किये गये। यह उल्लेख किया गया कि लन्दन के आस पास ६५ मील के घेरे में भी संयुक्त पूँजी वाले बैंक व्यापार कर सकते थे परन्तु उन्हें उतनी परिधि में नोट निर्गम करने का अधिकार नहीं होगा। वस्तुतः यह नई बात नहीं थी, ऐसा तो पहले भी किया जा सकता था।^१ केशव उसे वैधानिक रूप में उल्लेख कर दिया गया था। संयुक्त पूँजी वाले बैंक, यदि नोटों का निर्गम लन्दन के ६५ मील के घेरे के बाहर हुआ है, अपने निर्गमित नोटों को अपने लार्न ऑफिस में शोपनीय (payable) रख सकते थे। सन् १८३३ की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था यह थी कि बैंक ऑफ इंग्लैण्ड के नोट विधिग्राह्य (legal tender) कर दिए परन्तु वह स्वयं अपने नोटों का परिशोधन (redemption) अपने ही नोटों द्वारा नहीं कर सकता, अन्य बैंक अपने नोटों का शोधन बैंक ऑफ इंग्लैण्ड के नोटों द्वारा कर सकते थे।

सन् १८३३ के अधिनियम के पदवात् सन् १८३४ में दो लन्दन एण्ड बैस्टमिनिस्टर बैंक और सन् १८३६ में दो लन्दन ज्वाइन्ट स्टॉक बैंक की स्थापना हुई। सन् १८३६ में यूनियन बैंक और दो लन्दन एण्ड काउन्टी बैंक की स्थापना हुई। अन्य संयुक्त पूँजी वाले बैंक भी स्थापित हुए। इन बैंकों के साथ बैंक ऑफ इंग्लैण्ड शत्रुता का सा व्यवहार करना था, उनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ना था। सन् १८५४ के पूर्व उन्हें समाशोधन गृह (clearing house) के लाभ से वंचित रखा गया। लन्दन के क्षेत्र में नोट निर्गम का

1. Ibid, p. 313. "In 1823 a pamphlet was published by Mr. Joplin in which it was maintained that the privilege of the Bank of England only precluded the formation of joint stock banks of issue, and did not bar corporations which restricted themselves to deposit banking."

अधिकार न होने के कारण नये संयुक्त पूँजी वाले बैंको को अधिकोपण के निक्षेप पक्ष (deposat side) पर आश्रित होना पड़ा और चेकों (cheques) का उपयोग करने के लिए अपने ग्राहकों को प्रोत्साहन दिया। कटना न होगा कि तदुपरान्त यह प्रणाली लोकप्रिय और अधिकोपण की प्रमुख विशेषता हो गई है।

सन् १८४४ के पूर्व इंग्लैंड में बैंकिंग संगठन के अनेक दोष थे, निजी बैंक दुर्बल थे और बैंक ऑफ इंग्लैंड के नोट निर्गमन का प्रबन्ध भी दोषपूर्ण था। परन्तु यह कहा जा सकता है कि प्रयोगात्मक ढंग पर जो कुछ कानूनी उपाय अपनाये गए थे उनका इसी दृष्टि से महत्व था। अधिकोपण सम्बन्धी कानून (legislation) में दो बातें स्पष्ट होगी : पहली तो यह कि संयुक्त पूँजी अधिकोपण में बैंक ऑफ इंग्लैंड का एकाधिकार धीरे धीरे समाप्त किया गया; और नोट निर्गमन के ऊपर प्रतिबन्ध बढ़ता गया—यह अधिकोपण व्यवसाय की सुदृढ़ प्रणाली के लिए उतना ही आवश्यक था जितना कि जनता की सुरक्षा की दृष्टि से।

सन् १८४४ का बैंक चार्टर एक्ट आगम अधिकोपण पद्धति के इतिहास में प्रगति का नया अध्याय खोलता है। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य नोट-निर्गमन पद्धति को सुदृढ़ बनाना था। इस एक्ट के द्वारा बैंक ऑफ इंग्लैंड को दो विभागों में बाँट दिया गया :

(१) निर्गमन विभाग (Issue Department), और

(२) अधिकोपण विभाग (Banking Department)।

निर्गमन विभाग को प्रतिभूतियों की आठ में १४० लाख पौण्ड (चौदह मिलियन पौण्ड) तक के नोट निर्गमित करने की आज्ञा प्रदान की गई, इससे अधिक मूल्य के नोटों का निर्गम करने के लिए शत प्रतिशत स्वर्ण कोष रखना आवश्यक कर दिया गया। उस समय के वर्तमान बैंकों को सीमित राशियों तक नोट निर्गम के अधिकार दिये गये परन्तु लन्दन में कोई अन्य बैंक नोट-निर्गमन नहीं कर सकता था। लन्दन के बाहर स्थित जिन बैंकों को नोट निर्गमित करने के अधिकार दिए उन पर कई प्रतिबन्ध लगाये गए। उदाहरणार्थ, वे बैंक किसी अन्य बैंक के साथ सम्मेलन करें, अथवा लन्दन में ऑफिस खोलें, अथवा कुछ दिनों के लिए नोट निर्गमन स्थगित करें इत्यादि, तो उनसे निर्गमन का अधिकार छीन लिया जायगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड के अतिरिक्त अन्य बैंकों को नोट निर्गम का कुल अधिकार लगभग ८६ लाख पौण्ड मूल्य तक था और यह

व्यवस्था की गई थी कि यदि कोई बैंक किसी कारण से अपना नोट निर्गमन का अधिकार खो बैठे तो बैंक ऑफ इंग्लैंड अपना विश्वासाश्रित नोट निर्गमन उमके दो तिहाई मूल्य तक बढ़ा सकता था। सन् १८४४ के एक्ट ने व्यवस्था की कि कोई नया बैंक नोट निर्गमन नहीं कर सकता था। उद्देश्य यह था कि नोट-निर्गमन का अधिकार धीरे धीरे अन्य बैंकों से छिन जाये और चैको (cheques) का उपयोग बढ़े। नोट-निर्गमन की सीमा निर्धारित कर दी गई थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड के निर्गमन विभाग से निश्चित दशाओं के अनुसार कोई भी व्यक्ति नोटों के बदले स्वर्ण अथवा स्वर्ण के बदले नोट माँग सकता था। उसके लिए यह भी आवश्यक कर दिया गया कि प्रति सप्ताह एक विवरण प्रकाशित किया जाये जिसमें प्रचलन में नोटों का मूल्य तथा स्वर्ण कोपी का व्यौरा दिया जाये।

सन् १८४४ के एक्ट से यह भाशा की गई थी कि भविष्य में वित्तीय संकट नहीं आयेगे परन्तु यह धारणा गलत सिद्ध हुई। सन् १८४७, १८५७ और १८६६ में गंभीर संकट (crisis) आये। तत्पश्चात् जो सुधार हुआ वह कानूनी उपाय के कारण नहीं बल्कि अधिकोपण व्यापार में अनुभव तथा संगठन की सुदृढ़ता के कारण हुआ। सन् १८६६ के बाद कोई संकट (सन् १९१४ तक) नहीं आया इसका मुख्य कारण यह था कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के प्रबन्ध में बहुत सुधार हुआ था।

आधुनिक काल

बैंक ऑफ इंग्लैंड :

सन् १८४४ के अधिनियम ने यह कल्पना नहीं की थी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड केन्द्रीय बैंक (central bank) हो जायेगा। यह पहले ही बताया जा चुका है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड प्रारम्भ में नई बैंकों से शत्रुता का सा भाव रखता था। परन्तु नई बैंकों ने विकास की दृष्टि में स्थिति के अनुकूल चलने का उपाय अपनाया। लन्दन राजधानी और वित्तीय सेवाओं का केन्द्र था। १३० वर्षों तक समुक्त पूँजी अधिकोपण में एकाधिकार रहने के कारण लन्दन के मुद्रा बाजार में बैंक ऑफ इंग्लैंड की केन्द्रीय स्थिति हो गई थी। कटुता रहने

१. विश्वासाश्रित निर्गम (fiduciary issue) के लिए छाड़ में स्वर्ण नहीं रखना पड़ता, प्रतिभूतियाँ रखकर नोट निर्गमन किया जाता है।

पर भी व्यवहार में निजी बैंक उमके प्रति भुके । वे अपने कोष जमाओं के रूप में बैंक ऑफ इंग्लैण्ड में रखते थे । उन्हें कठिनाई के समय उसी का सहारा लेना पड़ता था । सन् १८४४ के अधिनियम के द्वारा बैंक ऑफ इंग्लैण्ड के नोट निर्गमन सम्बन्धी अधिकारों से उसकी स्थिति और भी मुहृष्ट हुई । परिणामतः, बैंक ऑफ इंग्लैण्ड बैंकों का बैंक बन गया । सन् १७५१ में ही राष्ट्रीय ऋण (National debt) का पूर्ण प्रबन्ध उसे सौंपा जा चुका था । वित्तीय नीति के मामलों में वह ब्रिटिश सरकार को सलाहकारी सेवाएँ प्रदान करता है । बैंकों के कोष बैंक ऑफ इंग्लैण्ड में जमा रहने के कारण अग्नित वित्तीय प्रणाली में स्थायित्व आया है । सन् १९२८ में बैंक ऑफ इंग्लैण्ड को नोट-निर्गम संबंधी और भी अधिकार दिया गया ।

सन् १९३१ में वित्तीय सकट आया और स्वर्णमान का परित्याग कर दिया गया । सन् १९३२ में विनिमय समता कोष (Exchange Equalisation Fund) की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य स्टर्लिंग के उच्चावचनों को रोकना था । सितम्बर १९३६ में युद्ध छिड़ने के समय बैंक ऑफ इंग्लैण्ड का लगभग समस्त स्वर्ण कोष विनिमय समता कोष को स्थानान्तरित कर दिया गया तथा-नोट निर्गम की विस्वासाश्रित सीमा बढ़ती गई । बैंक ऑफ इंग्लैण्ड और ट्रेजरी के सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ हो चुके थे । सन् १९४६ में बैंक ऑफ इंग्लैण्ड एक्ट के द्वारा उसका राष्ट्रीयकरण कर लिया गया, वह राजकीय संस्था हो गई । व्यवहार में वह पहले ही इस रूप में प्रतिष्ठित था अतः कोई परिवर्तन हुआ प्रतीत नहीं हुआ ।

व्यापारिक बैंक (Commercial Banks)

यह पहले बताया जा चुका है कि बैंक ऑफ इंग्लैण्ड दीर्घकाल तक व्यापारिक बैंक की भाँति कार्य करता रहा और उसने अन्य बैंकों से स्पर्धा रखी परन्तु कालान्तर में वह केन्द्रीय बैंक बन गई ।

सन् १८३४ के पूर्व सीमित दायित्व (limited liability) का सिद्धान्त व्यवहार में नहीं आया था और बैंकों के हिस्सेदार (शेयर होल्डर) फर्म के साझेदारों की तरह थे जिनका दायित्व असीमित होता था । सीमित दायित्व के सिद्धान्त को वास्तुकी मान्यता सन् १८५५ में मिली और अधिकोपण में इस सिद्धान्त का व्यवहार सन् १८५८ में आरंभ हुआ । नई संयुक्त पूँजी वाली सीमित दायित्व की बैंकिंग कम्पनियाँ स्थापित हुईं और पुरानी बैंकों में से अधिकांश या तो सीमित दायित्व वाली बैंकिंग कम्पनियों में मिल गईं अथवा

उन्होंने रूप बदल लिया। जो पुरानी निजी बैंकें बची वे प्रायः सीमित दायित्व लाली नई बड़ी बड़ी कम्पनियों की स्पर्धा में न ठहर सकी और समाप्त हो गईं। छोटी छोटी बैंको ने सम्मेलन द्वारा बड़ो का रूप ग्रहण किया।

आधुनिक व्यापारिक बैंको की विशेषताएँ—

ग्रेट ब्रिटेन की वर्तमान अधिकोपण प्रणाली में व्यापारिक बैंको की निम्न लिखित मुख्य विशेषताएँ दृष्टव्य है :—

(१) ग्रेट ब्रिटेन का अधिकोपण व्यापार करने वाली अधिकांश बैंकें सीमित दायित्व वाली कम्पनियाँ हैं जो सीमित दायित्व वाली कम्पनियों से संबंधित कानून के अंतर्गत आती हैं।

(२) देश का अधिकांश अधिकोपण व्यापार बैंक ग्रैंड इंग्लैण्ड के प्रतिरिक्त पाँच बड़ी संस्थाओं लॉयड्स, वालरेंज, मिडलैंड्स, वेस्टमिनिस्टर और नेशनल प्रोविन्शियल के द्वारा संचालित होता है। ये पाँच बड़ी बैंकें छोटी बैंको के सम्मेलन से बनी हैं। विलियम्स और कन्स बैंक अन्य महत्वपूर्ण बैंको में से एक है।

(३) अपेक्षाकृत थोड़ी सी बैंको की शाखाएँ बहुत अधिक हैं। सन् १९५८ में ब्रिटिश बैंकर्स एसोसिएशन के ५० के ० के कुल सदस्यों की सहाय २९ थी जिनकी १२,५०० शाखाएँ थी और कुल संपत्ति (assets) आठ अरब पाँच (£ 8000 millions) से भी अधिक थी।^१ अधिक शाखाओं वाली इन बड़ी बैंको में संकट का सामना करने की सामर्थ्य है और प्रारम्भिक काल की छोटी बैंको से निश्चय ही अधिक स्थिरता है।

(४) ग्रेट ब्रिटेन में प्रत्येक बैंक (Cheque) पर २ पैसे स्टाम्प छपूरी देनी पड़ती है तो भी बैंको का उपयोग बहुत अधिक किया जाता है।^२

(५) समाशोधन गृह का विकास ब्रिटिश अधिकोपण प्रणाली का प्रमुख अंग है। इसका प्रारम्भ १८वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध भाग में हुआ। उस समय विभिन्न बैंको के क्लर्क चेन्ज ऐले में बैंको का विनिमय करने के लिए मिला करते थे, वेवल वाली (balances) का भुगतान स्वयं में होता था।

1. Britain : An Official Handbook, 1959, p. 417.

2. The average daily value of cheques, drafts, bills and bankers' effects cleared in 1957 through the London and Provincial Clearing Houses was £ 562 millions; and many cheques do not, for various reasons, pass through Clearing Houses.
—Britain, 1959, p. 417

सन् १७७५ में समाशोधन कार्य (Clearing Business) के लिए एक कमरा किराये पर लिया गया। उन्नीसवीं शताब्दी में समाशोधन गृह महत्वपूर्ण एवं आवश्यक हो गया। अब समाशोधन गृह के सदस्य बैंक पाँच बड़े बैंकों के प्रति-रिक्त् मार्टिन्स, बूट्स, ग्लिन मिल्स (Glyn Mills), नेशनल, डिस्ट्रिक्ट तथा विलियम डीवन्स हैं। अन्य बैंकों को इन्हीं में से किसी बैंक की मारफ़्त काम कराना पड़ता है। समाशोधन का कार्य सन्दन तथा बड़े बड़े नगरी में होता है।^१

(६) यूनाइटेड किंगडम के मुख्य बैंक अपनी कुल जमाओं (deposits) के लगभग = प्रतिशत नकद कोष रखते हैं।

(७) स्कॉटलैण्ड तथा उत्तरी आयरलैण्ड के कुछ बैंकों को अभी तक नोट निर्गम के सीमित अधिकार मिले हुए हैं।

ऐसी अनेक बैंकों के दफ्तर लन्दन में हैं जो राष्ट्रकुल (Commonwealth) के देशों तथा अन्य देशों में ही मुख्यतया कार्य करती हैं। इनके प्रतिरिक्त् सैंविंग्स बैंकों तथा सहकारी बैंकों, इत्यादि का स्थान भी महत्वपूर्ण है।

राजस्व

ग्रट ब्रिटेन के आर्थिक विकास के अध्ययन में राजस्व के विकास का बर्णन बहुतसा प्रनीत होता है परन्तु वास्तव में ऐसा है नहीं। पुराने जमाने में ब्रिटेन में इस प्रकार के विचार प्रचलित थे कि सरकार का व्यय कम से कम होना चाहिए और जनता से कर वसूल करने में अविनगत्त निजी जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिये। परिस्थितियों के अनुसार नीति में परिवर्तन होता रहा (जिसका उल्लेख पिछले अध्याय में तथा अन्यत्र यथास्थान किया गया है) और प्रशासन व्यय बढ़ने लगे। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि राजस्व का आकार बढ़ा है बल्कि यह है कि राजकीय आय और व्यय के व्यापक आर्थिक प्रभावों की दृष्टि से औचित्य का विचार रखकर उनके भिन्न भिन्न साधनों (sources) तथा मदों (items) को महत्व दिया गया। कहना न होगा कि सामाजिक सुरक्षा तथा जन-स्वास्थ्य की दृष्टि से ही नहीं अपितु उद्योग तथा

1. Southgate, op. cit., p. 305. Clearing business in London is now organised in two sections. The Town Clearing concerns only banks within a short distance of the Clearing Houses. The General Clearing deals with cheques from anywhere in England and Wales outside the Town clearing area. Provincial clearings take place in large towns to deal with local business.

व्यापार के विकास और नियमन की दिशा में भी राजस्व का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है।

सत्रहवीं शताब्दी में सम्राट् की आय के परम्परागत साधन अपर्याप्त हो चले थे।^१ सन् १६८८-८९ की क्रान्ति राजनीतिक इतिहास में प्रसिद्ध है जिसके उपरान्त देश की सर्वोच्च सत्ता पार्लियामेंट हो गई। सम्राट् और राजाशा के ऊपर पार्लियामेंट एवं कानून की जीत का राजस्व पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। स्टुअर्ट काल से वैधानिक संघर्ष सन् १६८९ के अधिकार पत्र (Bill of Rights) द्वारा समाप्त हो गये थे। इसके पश्चात् राजकीय आय को मनमाने ढंग से व्यय करने का सम्राट् का अधिकार नहीं रहा और हाउस ऑफ कॉमन्स (House of Commons) ने व्यय के नियन्त्रण की प्राधुनिक प्रणाली का विकास किया। करारोपण के सम्बन्ध में हाउस ऑफ कॉमन्स का निम्नण सत्रहवीं शताब्दी में ही प्रभावपूर्ण होगया था परन्तु व्यय के सम्बन्ध में नियन्त्रण उन्नीसवीं शताब्दी में ही प्रभावपूर्ण हो सका।

१८ वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में सर रॉबर्ट वालपोल ने राजस्व संबंधी ग्रन्थ सुधार किये। उसने अनुभव किया था कि देश का अर्थव्यवस्था तथा व्यापार और वाणिज्य का विकास सैकड़ों वस्तुओं के आयात और निर्यात पर कर लगाकर नहीं, बल्कि उनमें कमी करके किया जा सकता था। सन् १७५६ में सप्त वर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ जिसके अन्त में वालपोल के सुधार संबंधी विचारों को मुला दिया गया। सन् १७५६ में राष्ट्रीय ऋण ७२० लाख पौण्ड था, १७६३ में बढ़कर १६०० लाख पौण्ड हो गया।

सन् १७७६ में एडम स्मिथ का ग्रन्थ 'वैल्य ऑफ नेशनस' प्रकाशित हुआ जिसके प्रभावस्वरूप पिट ने (१७८३-१७८२ के शासि काल में) अपने प्रारंभिक प्रशासन काल में कर प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार किये, ड्यूटी की दरें घटाई, सरलता लाई गई। इस काल में राष्ट्रीय ऋण घटा। सन् १७८२ के पश्चात् फ्रेंच युद्ध के कारण व्यय में वृद्धि हुई और राष्ट्रीय ऋण बढ़ा। सन् १७९७ तक करो में कोई गंभीर परिवर्तन नहीं हुआ (मेरेडिथ के दान्तों में,

१. सोलहवीं शताब्दी तक राजकीय आय का मुख्य साधन भूमि और सम्राट् की निजी सम्पत्ति थी, कुछ वस्तुओं और कुछ प्रकार के विदेशी व्यापार पर कर लगाये गए थे तथा जुमानों, उपहारों एवं ऋणों इत्यादि का महत्व था। युद्धों पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए आय के पर्याप्त साधनों की आवश्यकता अनुभव की गई।

लगता है पिट ने युद्ध को कम महत्व दिया)। परन्तु सन् १७९७ से करो में बहुत वृद्धि की गई। करारोपण की दिशा में नये प्रयोग किये गये। आयकर आरोपित किया गया, जो आगे राजस्व का महत्वपूर्ण अंग बन गया।^१ उसने ऋण बढ़ाने लिए जिसकी भारी आलोचना हुई।

सन् १८१५ में शान्ति लौटने पर सन् १८१६ में आयकर (income tax) समाप्त कर दिया गया। कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की। उनका कहना था कि जब तक ऋण घटकर युद्ध पूर्व स्तर पर नहीं आजाता आयकर बालू रहने चाहिए थे परन्तु अधिक लोग आयकर समाप्त करने के पक्ष में ही थे। आयकर समाप्त होने के कारण सरकारी धाय को कमी परीक्ष करो में वृद्धि करके पूरी की गई जिसका निचैन वर्ग पर बुरा प्रभाव पड़ा।

सन् १८२३ में हस्किंसन व्यापार मण्डल (Board of Trade) के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुआ। उसने अपने कार्यकाल में (१८२३-२७) कर नीति में जो परिवर्तन किये वे स्वतंत्र व्यापार आन्दोलन का आरम्भ रहे जा सकते हैं (यद्यपि प्रधान मंत्री पिट अपने शक्तिशालीन प्रशासन में इसकी शुरुआत कर चुका था) हस्किंसन ने निर्यातों के ऊपर दी जाने वाली आर्थिक सहायता (bounties) समाप्त कर दी और अनेक वस्तुओं के ऊपर ट्यूटी की दरें कम कर दी। आन्तरिक करो में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया।

सन् १८४१ में जब पील प्रधान मंत्री बना तो उसने संपूर्ण राजस्व प्रणाली में सुधार किये। उसने ऐसी अधिकतर वस्तुओं पर से आयात कर हटा दिया जो कच्चे माल की श्रेणी में आती थी; निर्मित और अर्द्ध-निर्मित वस्तुओं की आधी से भी अधिक सख्या पर आयात कर घटा दिए; अनेक निर्मित वस्तुओं पर से कर समाप्त कर दिये, और इन सबमे होने वाली आय की कमी की आशिक पूर्ति के लिए उनमें कुछ वर्षों के लिए आय-कर लगाने का प्रस्ताव रखा। पील का विचार था कि आयात और निर्यात पर कर कम कर देने से व्यापार में जो वृद्धि होगी उससे करो में की जाने वाली कमी पूरी हो जायेगी परन्तु कुछ वर्षों तक आय में कमी होना निश्चित था, इसलिए आयकर लगाया गया। परन्तु बाद में आयकर हटाया नहीं, आगे के

1. "It is doubtful whether Peel could have levied an income-tax in time of peace if Pitt had not previously done so in time of war."
—Meredith, op. cit., p. 325.

लिये बढ़ा दिया और उसके बजाय निर्यात कर तथा कच्चे माल पर आयात कर समाप्त कर दिए गये। सन् १८४६ में रसेल (Russell) प्रधान मंत्री हुआ। उसने अपने कार्यकाल में उपनिवेशों से तथा अन्य देशों से आयात होने वाली चीनी पर लगे आयात करों के अंतर को समाप्त करके समान स्तर पर ला दिया।^१ सन् १८५३ में लॉर्ड एबरडीन के मंत्रिमंडल में ग्लेड्स्टन वित्तमंत्री बना। उसने अनेक आयातकर समाप्त कर दिए और अनेक कम कर दिए, मृत्यु कर (legacy duties) का महत्व उसने बढ़ा दिया। उसने आयकर में शून्य, शून्य, कमी करके अततोगात्वा उसे समाप्त करने की योजना बनाई थी परन्तु बीघ में प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाने के कारण यह संभव नहीं हो सका।^२ सन् १८५५ में सर जार्ज ल्यूइस वित्त-मंत्री बना। उसने आयकर तथा कुछ आयात करों में वृद्धि की; राष्ट्रीय ऋण में भी वृद्धि हुई। सन् १८६० में ग्लेड्स्टन दुबारा वित्तमंत्री बना^३ और उसने सभी प्रकार के करों का संरक्षणात्मक स्वभाव समाप्त करके स्वतंत्र व्यापार की स्थापना की, सरकारी आय की दृष्टि से कुछ कर रहने दिये। सन् १८६० से १८७५ तक राजस्व संबंधी नीति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ।

सन् १८६४ में हार्कोर्ट (Harcourt) ने मृत्यु कर की दरें बढ़ा दी। सन् १९०७ के बजट में आयकर को सरकारी आय का सामान्य तरीका मान लिया, अर्जित और अनुपार्जित (earned and unearned) आयों में अंतर किया गया तथा अनुपार्जित आय पर कर की दर अधिक रखी गई। सन् १९१४ में करों में विशेषकर आय कर में बहुत वृद्धि कर दी गई। सुपर टैक्स भी लगाया गया। युद्धकाल में अतिरिक्त लाभ कर (excess profits tax) भी लगाये गये और ऋण में बहुत वृद्धि हुई। सन् १९२६-२७ के मंदी काल

१. उस समय उपनिवेशों से आने वाली चीनी पर कर १४ शिलिंग प्रति हंड्रेडवेट था, जब कि अन्य देशों से आने वाली चीनी पर कर की दर बहुत अधिक थी। रसेल ने पहले उसे घटाकर २१ शि० और पाँच वर्ष बाद १४ शि० प्रति हंड्रेडवेट कर दिया।

२. प्रतिकूल परिस्थितियाँ ये थी : त्रिमियन युद्ध (१८१४) भारतीय राजनीतिक क्रान्ति (१८१७) चीन और फारस के युद्ध तथा फ्रान्स के साथ युद्ध की आशंका (१८५६)।

३. इस बार ग्लेड्स्टन पामरस्टन के मंत्रिमण्डल में वित्तमंत्री बना था।

में स्थिति इस प्रकार की हो गई थी कि ऋणों की अदायगी स्थगित करनी पड़ी। द्वितीय महायुद्ध काल में राजकीय व्यय बहुत बढ़ा, अतः आयकर में भी वृद्धि की गई। द्वितीय विश्व युद्ध काल के ब्रिटेन में राष्ट्रीय बचन योजना को बहुत महत्व दिया गया है।

सरकारी आय-व्यय

यूनाइटेड किंगडम के सरकारी आय-व्यय के मुख्य पदों की जानकारी अगले पृष्ठ पर दिए हुए बजट में प्राप्त की जा सकती है।

प्रश्न

1. What were the reasons which led to the suspension of cash payment in England in 1797 ?
2. Review critically the growth of the English Banking system from the establishment of the Bank of England in 1694 upto passing of the Bank Charter Act of 1844. What were the immediate repercussions of this piece of legislation ?
3. Give a brief account of the developments in British banking system since the middle of the 18th century.
4. What were the main features of finance in Great Britain in 18th century. Describe the later developments.

United Kingdom Budget
1957-58 out-turn and 1958-59 Estimates¹
(after 1958-59 Budget changes)
£ million

Revenue	Above the Line			Expenditure	1957-58 out-turn	1958-59 Estimate
	1957-58 out-turn	1958-59 Estimate				
Inland Revenue ²	2,355	2,970	Interest on Debt	663	695	
Customs and Excise	2,150	2,189	Sinking Funds	37	38	
Motor duties	101	104	Northern Ireland	72	74	
			Miscellaneous	10	10	
Total Tax Revenue	5,106	5,263	Total consolidated Fund Service	782	816	
Post office (net receipt)	8	2	Supply Defence (net)	1,430	1,418	
Broadcast licences	31	34	Civil (including cost of tax collection)	2,708	2,841	
Sundry loans	32	30				
Miscellaneous	166	110				
Total Revenue	5,343	5,439	Total supply	4,138	4,259	
			Total Expenditure	4,920	5,075	
			Surplus	423	364	
	5,343	5,439		5,543	5,439	

1. Britain: An Official Handbook, 1959, p. 413.

2. Inland Revenue includes Income Tax, Surtax, Profits Tax, Estate Duty, etc.

Below the Line

Receipts			Payments		
Interest outside Budget	169	205	Interest outside Budget	169	205
Local Authorities Repayments	47	52	Post-war credits	18	18
Nationalised Industries (other than National Coal Board) Repayments	13	29	War Damage	22	20
Other items	32	37	Loans to Local Authorities	92	65
			Loans for New Towns		
			Development	29	31
			Post Office Capital		
			expenditure	79	38
			Overseas Resources		
			Colonial Development	3	12
			Nation Coal Board		
			capital expenditure (net)	81	76
			Loans to other nationalized industries		
			Transport (Railway	295	370
			Finances) loans		
			Other items	66	61
				42	27
Total Receipts	261	323	Total Payments	896	923
Net sum borrowed or net from surplus	635	600			
	896	923		896	923
Total Receipts	5,604	5,762		5,816	5,998

ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्था पर विश्व-युद्धों का प्रभाव तथा द्वितीय विश्व-युद्धोत्तरकालीन आर्थिक समस्याएँ

[प्रथम महायुद्ध के प्रभाव, द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रभाव, युद्धोत्तर-कालीन आर्थिक समस्याएँ, प्रश्न ।]

पिछले अध्यायो मे ब्रिटेन के आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं, जैसे कृषि उद्योग व्यापार और यातायात पर विचार करते हुए युद्धों का प्रभाव प्रसंगानुक्रम बताया जा चुका है । सन् १९१४ के पूर्व ग्रेट ब्रिटेन औद्योगिक उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुँच चुका था, प्रथम महायुद्ध (१९१४-१८) ने उसकी आर्थिक स्थिति को जो क्षति पहुँचाई वह द्वितीय विश्व-युद्ध तक ठीक भी नहीं हो पाई थी कि उसे दूसरे विश्व युद्ध की कठिन अग्नि परीक्षा में होकर निकलना पड़ा । निश्चय ही ब्रिटेन ने परिस्थितियों के अनुकूल नीति अपना कर आर्थिक गठन, साहस और प्रशासन-कुशलता का परिचय दिया परन्तु यह प्रकट सत्य है कि द्वितीय विश्व-युद्ध ने ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति को जो आघात पहुँचाया और संसार में जो नई परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं उनमें लगता है कि ब्रिटेन के लिए पूर्वकालीन अभ्युदय प्राप्त करना असंभव नहीं तो दुष्कर अवश्य है । इस अध्याय में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों के प्रभावों तथा द्वितीय विश्व युद्धोत्तरकालीन आर्थिक समस्याओं पर संक्षेप में विचार किया जायगा ।

प्रथम महायुद्ध के प्रभाव

प्रथम महायुद्ध का ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा था । इन प्रभावों का अध्ययन मोटे तौर पर सुविधा की दृष्टि से इन शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है . (१) व्यापार का प्रभाव, (२) कृषि पर प्रभाव (३) उद्योगों पर प्रभाव तथा (४) अन्य क्षेत्रों में प्रभाव (राजनीतिक, मुद्रा संबन्धी , पूँजी विनियोग, यातायात, बैंकिंग, इत्यादि पर प्रभाव) ।

व्यापार— सन् १९१४ तक ब्रिटेन के निर्यात उत्तरोत्तर बढ़े थे परन्तु युद्ध छिड़ने के उपरान्त उन्हें बढ़ाना तो दूर रहा उनको चालू रखना कठिन हो गया

क्योंकि उत्पादन के साधनों जहाजों, शक्ति इत्यादि को युद्ध की दिशा में लगा देना पड़ा । युद्ध काल में ब्रिटिश वस्तुओं की पूर्ति न होने के कारण ग्राहक देशों ने अपने उद्योग स्थापित और विकसित कर लिये । सन् १९१३ में ब्रिटिश निर्यातों का मूल्य लगभग ५२३ करोड़ पाउण्ड था, सन् १९१८ में घटकर ५० करोड़ पाउण्ड के लगभग रह गया जब कि कीमतों में १२६ प्रतिशत वृद्धि हुई थी । मुख्यतया सूती वस्त्र, कोयले तथा लौह-इस्पात के निर्यात में भारी कमी हुई । युद्धोपरान्त समृद्धि व ल (Boom) आया तो सन् १९२० में ब्रिटिश निर्यातों का मूल्य १३३ ८० करोड़ पाउण्ड हो गया, परन्तु शीघ्र ही मन्दी न आ घेरा और सन् १९२१ में ही निर्यात घट कर ७० करोड़ पाउण्ड मूल्य के रह गये ।

कृषि—जहाजों की कमी के कारण कृषि-वसाधों का आयात बहुत कम हो जाने के कारण युद्ध काल (१९१४-१८) में खाद्यान्नों के मामले में स्वावलम्बी होने के लिए द्रुत गति कृषि का विकास करने के निवाय ब्रिटेन के सम्मुख और कोई उपाय नहीं रह गया । परती जर्मनों और शरणाग्रों में भी भन्न उगाया जाने लगा तथापि कृषि श्रमिकों की कमी के कारण कई प्रकार की फसलों के क्षेत्रफल में कमी हुई । खाद्यान्नों के कारण देश में नियन्त्रण और रेशनिंग की व्यवस्था करनी पड़ी । कृषि द्वारा भन्न की उपज बढ़ाने की दृष्टि से खाद्य-उत्पादन विभाग की स्थापना की गई । कुछ घाटों के मिलों पर सरकारी अधिकार कर लिया गया । सन् १९१७ में भन्न उत्पादन कानून के द्वारा वस्तुओं का न्यूनतम मूल्य तथा श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरियाँ निर्धारित कर दी गई । परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन बढ़ा । तीस लाख एकड़ भूमि नये सिरे से कृषियोग्य बनाई गई । सन् १९१४ की रूपेक्षा १९१८ में चालीस लाख टन अधिक खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ । युद्धोपरान्त भी कृषि की उन्नति के लिए प्रयत्न जारी रहे गये परन्तु सन् १९२० के पश्चात् सरकारी नियन्त्रण और न्यूनतम मूल्य की नीति का परित्याग कर दिया गया ।^१

उद्योग—उद्योगों पर सामान्यतया युद्ध का यह प्रभाव पड़ा कि श्रम और पूँजी तथा अन्य साधनों के युद्ध संबंधी उद्योगों में लग जाने के कारण औद्योगिक उत्पादन घटा । यातायात की कठिनाइयाँ तथा विदेशी व्यापार में कमी हो जाने का भी उद्योगों पर दुःप्रभाव पड़ा क्योंकि एक ओर कई उद्योगों के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल नहीं मिल सका और दूसरे निर्मित माल को निर्यात करना कठिन हो गया था ।

युद्धकाल में सूती वस्त्र का उत्पादन बहुत घटा क्योंकि कपास और जहाजी यातायात की भारी कमी हो गई थी। युद्धकाल में वारीक कपड़े का अधिक उत्पादन किया गया। युद्धोपरान्त पूर्वी देशों की बढ़ते हुई माँग को पूरा करने के कारण ब्रिटिश सूती उद्योग को अधिक लाभ हुए परन्तु सन् १९२० के बाद फिर पतन होने लगा। सन् १९२४ में सन् १९१२ की अपेक्षा सूत का उत्पादन ३० प्रतिशत और कपड़े का उत्पादन २३ प्रतिशत घटा। युद्धकाल में कपड़े पर नियन्त्रण और राशनिय लागू किये गये थे।

कोयला उद्योग पर भी युद्ध का गहरा प्रभाव पड़ा। धमिकों की कमी के कारण गहरी खानों की खुदाई विल्कुल बन्द हो गई। निर्यात न हो सकने के कारण भी कोयला खान उद्योग को हानि पहुँची। प्रथम महायुद्ध काल में सोहा-इस्पात उद्योग की उन्नति हुई। युद्धकाल में इस्पात उद्योग के मशीन (मेचर) के मूल्यों, अनाधारियों के लाभानों तथा धमिकों की मजदूरियों सभी में वृद्धि हुई। सरकार ने इस्पात के मूल्यों पर नियन्त्रण रखा। युद्धोपरान्त इस्पात की माँग गिरी और उत्पादन भी घटा।

युद्ध का उद्योग के ढाँचे (Structure) तथा संगठन (Organisation) पर भी प्रभाव पड़ा : (क) समोच्च आन्दोलन प्रारम्भ हुआ तथा क्षैतिज (horizontal) और उदय (Vertical) दोनों प्रकार के संयोग (Combinations) व्यवहार में आये।^१ स्पर्धा की हानियों से बचने के लिए युद्धोत्तर काल में सममिलन (amalgamations) और मर्जर (merger) बहुत हुए। (ख) उत्पादन की तकनीकी में महत्वपूर्ण सुधार किए गए, तथा (ग) उद्योगों को संरक्षण देने की नीति एवं साम्राज्यीय अधिमान नीति (Imperial preference policy) अपना कर युद्ध-पूर्व काल की आर्थिक समृद्धि पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया गया।

व्यापार, कृषि तथा उद्योग के अतिरिक्त मुद्रा, बैंकिंग, रोजगार, विनियोग, यातायात एवं अन्य क्षेत्रों पर भी युद्ध का गम्भीर प्रभाव पड़ा। विदेशी विनिमय सम्बन्धी कठिनाइयाँ उत्पन्न हुईं। युद्धोपरान्त राजनीतिक सीमाओं में संशोधन, हर्जाने वसूल करने इत्यादि के सम्बन्ध की अनेक समस्याएँ उत्पन्न हुईं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि प्रथम महायुद्ध ने ब्रिटेन की अर्थ-व्यवस्था की उन्नति के चिरने और सरल मार्ग पर भारी विघ्न उपस्थित कर दिये।

१. इस पुस्तक के अध्याय ६ में वाणिज्य क्रान्ति की विशेषताओं के अन्तर्गत देखिए।

उसने जो क्षति हुई उसे पूरा करना ब्रिटेन के लिए बहुत अधिक कठिन सिद्ध हुआ ।

द्वितीय विश्व-युद्ध के प्रभाव

द्वितीय विश्व-युद्ध ने ब्रिटेन की अर्थ-व्यवस्था को भारी क्षति पहुँचाई जिसे वह युद्धोपरान्त दस वर्षों में भी पूरा न सका । कृषि, उद्योगों तथा यातायात पर पड़ने वाले द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रभावों का उल्लेख इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में दयास्थान किया जा चुका है ।^१ द्वितीय विश्वयुद्ध के मुख्य कुप्रभाव निम्नलिखित पड़े :—

१. युद्ध के कारण ब्रिटेन की लगभग ३०० करोड़ पौण्ड के मूल्य की संपत्ति, जैसे, जहाजों, मकानों, सड़कों इत्यादि की हानि हुई ।

२. समुद्र पार संपत्ति की हानि (Loss of overseas assets) :— विदेशों में लगे लगभग १०० करोड़ पौण्ड के विनियोगों को युद्ध सामग्री खरीदने के लिए बेचना पड़ा । इनमें लगभग ४३ करोड़ पौण्ड के विनियोग उत्तरी अमेरिका में लगे सम्मिलित हैं ।

३. नए विदेशी ऋण (New overseas debts) :—लगभग ३०० करोड़ पौण्ड कीमत के नये विदेशी ऋण संवित हो गये [इनमें भारतवर्ष के पौण्ड पावने (Sterling balances) भी सम्मिलित हैं] ।

४. व्यापार की शर्तें (Terms of trade)—आयात होने वाले कच्चे-माल की कीमतें युद्धोपरान्त तेजी से बढ़ी और सन् १९४८ में १९३८ की तुलना में उनसे ही माल का आयात करने के लिए २० प्रतिशत अधिक माल (goods) निर्यात करने पड़े ।

५. निर्यातों में कमी (Reduced exports):—युद्ध के कारण निर्यात होने वाले माल की मात्रा (volume) घटी । सन् १९४४ में १९३८ की अपेक्षा एक-तिहाई में भी कम निर्यात (मात्रा में) हुए थे ।

६. कोषों में कमी (Smaller reserves) :—युद्ध-पूर्व काल की तुलना में स्वर्ण और डालर कोषों के मूल्य आधे के लगभग रह गए ।

७. डालर-संकट (Dollar shortage) :—युद्ध में हुई बर्बादियों के कारण ब्रिटेन तथा अन्य स्टर्लिंग क्षेत्रों (और अन्य कई देशों का भी) उत्तरी अमेरिका में काफी अधिक मात्रा में वस्तुएँ खरीदनी पड़ी । इनका

१. कृषि के लिए अध्याय ५, उद्योगों के लिए अध्याय ४, और यातायात के लिए अध्याय ६ देखिए ।

मूल्य चुकाने के लिए गैर-डालर देशों की डालर आयें (dollar earnings) बहुत कम थी।

युद्धोत्तरकालीन आर्थिक समस्याएँ

सन् १८३६ में युद्ध के प्रारम्भ के समय आर्थिक उद्योग तथा अर्थ-व्यवस्था युद्ध के लिए तैयार न थे तथापि प्रथम महायुद्ध के अनुभवों के आधार पर अर्थ-व्यवस्था के ढाँचे में शीघ्र ही परिवर्तन करने का प्रयत्न किया गया। युद्ध में मित्र-राष्ट्रों की विजय के लिए पूरा ध्यान दिया गया। देश के घरेलू तथा विदेशी व्यापार, उद्योग-धन्धों, यातायात, कृषि वस्तुओं की कीमतों इत्यादि अनेक दिशाओं में सरकार ने नियन्त्रण की नीति अपनाई। युद्ध समाप्त होते ही ब्रिटेन के सम्मुख युद्ध-कालीन अर्थ-व्यवस्था को शांति-कालीन अर्थ-व्यवस्था में बदलने की समस्या उपस्थित हुई।

युद्धोत्तरकालीन ब्रिटेन की मुख्य आर्थिक समस्याएँ निम्नलिखित थी—

- (१) डालर की कमी की समस्या,
- (२) भारत और मिस्र के पौण्ड-पावनों के निपटारे की समस्या,
- (३) उद्योग-धन्धों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न,
- (४) साम्राज्य और उपनिवेशों में कमी तथा व्यापार क्षेत्रों का संकुचन,
- (५) प्रतिरक्षा के लिए बढ़े हुए व्यय,
- (६) पुनर्वसन एवं विकास कार्य क्रम,
- (७) विदेशी विनिमय की कठिनाइयाँ, डालर और स्वर्णकोषों का ह्रास,
- (८) मुद्रा-स्फोषित, साक्षाभाव तथा अन्य कठिनाइयाँ।

डालर संकट—युद्ध के द्वारा ब्रिटेन के कारखानों, मकानों, जहाजों इत्यादि का जो भारी विनाश हुआ उसके कारण ब्रिटेन के हथियार और अदृश्य निर्यातों में भारी कमी हो गई। इसकी अपेक्षा ब्रिटेन को आयात अधिक मात्रा में करने पड़े। अपने आर्थिक पुनर्गठन के लिए ब्रिटेन को डालर क्षेत्रों से यन्त्रों, साधन सामग्री तथा कच्चे माल का आयात करना पड़ा परन्तु बढ़ने में निर्वात करने के लिए सामान की कमी थी। ब्रिटेन का डालर संकट कई वर्षों तक चला रहा। सन् १९४६ में ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार से पौने चार करोड़ डालर का ऋण लिया। इस ऋण के साथ दो दुर्भाग्यपूर्ण घटते जुड़ी थी। पहली, यह कि ब्रिटेन अमेरिका से अपनी खरीद (क्रय) में कमी नहीं करेगा और दूसरी, यह कि १५ जुलाई, १९४७ के उपरान्त ब्रिटेन विश्व के सभी देशों के हतु डालर स्थानिय विनिमय करेगा। भासा यह थी कि अमरीकी ऋण द्वारा ब्रिटेन को अर्थ-व्यवस्था पूर्णतया पुनः स्थापित हो सकेगी परन्तु वह राशि

शीघ्र ही समाप्त हो गई। स्टर्लिंग क्षेत्रों तथा राष्ट्र कुल (कॉमनवैलथ) के डालर साधनों को एकत्रित किया गया तथापि वे न्यून पड़े।

सन् १९४३ के वसन्त में ब्रिटेन को संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों में कमी करना नितान्त आवश्यक हो गया। इसी वर्ष १५ जुलाई ने दूसरी शर्त के पालन में और भी अधिक कठिनाई हुई। अतः अगस्त १९४७ में स्टर्लिंग का डालर विनिमय भी स्थगित करना पड़ा। ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका की आयात-निर्यात बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व-बैंक से भा ऋण लिए। जुलाई १९४६ में राष्ट्र कुल (कॉमनवैलथ) के वित्त मन्त्रियों का सम्मेलन लन्दन में बुलाया गया तथा महत्वपूर्ण निर्णय हुए। सन् १९४६ में १८ सितम्बर को पौण्ड का प्रबन्धन किया गया (पौण्ड का मूल्य ४.०३ डालर से घटाकर २.८० किया गया था)। इसका उद्देश्य भी डालर सकट को परास्त करना था। मार्शल योजना (Marshall Aid Plan) के अन्तर्गत प्राप्त तथा कनाडा से प्राप्त ऋण ने भी ब्रिटेन को डालर सकट पार करने में सहायता मिली तथापि सन् १९५८ के मध्यकाल में ही ब्रिटेन की डालर स्थिति सतोषजनक हो सकी है।

पौण्ड पावनों के निपटारे की समस्या—युद्धकाल में ब्रिटेन को युद्ध लड़ने के लिए भारत, मित्र, इत्यादि देशों से ऋण लेने पड़े जो पौण्ड पावनों (Sterling Balances) के रूप में संचित होते गए थे। युद्ध समाप्त होने पर भारत और मित्र ने यन्त्रों तथा अन्य पूँजीगत वस्तुओं इत्यादि की खरीदने के लिए पौण्ड पावनों की राशि को लेना चाहा परन्तु ब्रिटेन के लिए उन्हें एक-दम चुकाना सम्भव नहीं था। भारत सरकार ने यह भी चाहा था कि उसके पौण्ड पावनों का डालरों में परिवर्तन हो जाए ताकि डालर क्षेत्रों से आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर पूँजीगत वस्तुओं का आयात सम्भव हो सकता। ब्रिटेन और भारत के बीच बातचीत चलती रही और भारत अपने स्टर्लिंग ऋण को मनमाने ढंग से बमूल नहीं कर सका। अगस्त १९४७, फरवरी १९४८ और जुलाई १९४८ में भारत और ब्रिटेन के मध्य जो समझौते हुए वे उनके अनुसार भारत को क्रमशः ६५० लाख, १८० लाख और ८०० लाख पौण्ड की राशियाँ उपयोग करने के लिए प्राप्त हो सकी थी।

उद्योगों का राष्ट्रीयकरण—युद्धकाल में ब्रिटेन में सन् १९३५ में निर्वाचित संसद चलता रहने दिया था, चर्चिल के बाद सन् १९४५ के नामान्वय निर्वाचनों के द्वारा एटली के नेतृत्व में श्रम दली सरकार बनी। सन् १९४६ में कोयला उद्योग राष्ट्रीयकरण स्वीकृत हुआ। सन् १९४७ में बिजली उद्योग, सन् ४८ में गैस उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया। सन् १९४६ में लोहा-इस्पात विधान के अनुसार ब्रिटेन के अधिकांश लोहा-इस्पात के कारखानों को सरकारी अधिकार में कर लिया गया और उनके प्रबन्ध के लिए सन् १९५१ में एक लोहा-इस्पात निगम की स्थापना की गई। परन्तु अक्टूबर १९५१ में जब फिर चर्चिल सरकार बनी तो लोहा-इस्पात उद्योग निजी पूँजीपतियों को दे दिया गया।

भारतवर्ष का स्वतन्त्र होना—युद्धोत्तर काल में सन् १९४७ में भारत को स्वतंत्रता मिली। साम्राज्य और उपनिवेशों में कमी होने के कारण ब्रिटेन के व्यापार क्षेत्रों में संकुचन हुआ। यों कहना अधिक ठीक होगा कि ब्रिटेन को कच्चा माल खरीदने और निर्मित माल बेचने के लिए बाजारों का युद्ध-पूर्व जैसा लाभ न रहा।

प्रतिरक्षा पर व्यय—ब्रिटेन ने युद्धोत्तर काल में बजट में प्रतिरक्षा (defence) पर अधिक व्यय किए हैं। इसके मुख्य कारण ये हैं, (क) पश्चिमी और पूर्वी राष्ट्रों में, विशेषकर तीन बड़े पश्चिमी राष्ट्रों तथा सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चलते रहना तथा तृतीय विश्व युद्ध की संभावना; (ख) एशिया में साम्यवादी लहर को दबाना। इन व्ययों के कारण, ब्रिटेन को आर्थिक पुन-रुत्थान के लिए कम राशि मिल सकी।

पुनरुत्थान कार्य-क्रम—युद्ध से विनष्ट उद्योगों, जहाजों, मकानों, इत्यादि का फिर से निर्माण और पुनरुत्थान करने का ब्रिटेन के सम्मुख भारी कार्य था। इसके लिए ब्रिटेन को समुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इत्यादि से अधिक सहामता मिली। ब्रिटेन ने युद्ध के पश्चात् कुछ ही वर्षों में विकास कार्य-क्रम में आश्चर्यपूर्ण सफलता प्राप्त की यद्यपि युद्ध-पूर्व काल की ही स्थिति तो नहीं प्राप्त हो सकी है।

अन्य कठिनाइयाँ—ब्रिटेन को युद्धोत्तर काल में जिन अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनमें मुद्रा-स्थिति और खाद्याभाव मुख्य थी। विदेशी विनिमय की कठिनाइयों के कारण डॉलर तथा स्वर्ण कोषों का पतन हुआ।

प्रश्न

1. Describe and account for the changes in the structure and organization of British Industry after the war of 1914-18.

2. Discuss the effects of the Second World War on the British economy.

3. What were the main problems facing Great Britain in the post-war period? How did she overcome them?

विस्तृत अध्ययन के लिए पुस्तकों की नामावली

[BIBLIOGRAPHY]

1. Allen : British Industries and their Organisation.
2. Ashley : Economic Organisation of England.
3. Ashley : The Tariff Problem.
4. Ashton, T. S. : The Industrial Revolution (1760-1830).
5. Ashworth, W. : An Economic History of England.
6. Bhir & Pradhan : Modern Economic Development
7. Briggs & Jordon : An Economic History of England
8. Burn, Duncan (Edited by) : The Structure of British Industry, a symposium, Vol. I, 1938.
9. Clapham, Sir John : An Economic History of Modern Britain.
10. Clapham, Sir John : The Bank of England, A History.
11. C. O. I, London : Britan, an official handbook.
12. Cole, G. D. H. : British Social Services.
13. Court, W. H. B. : A Concise Economic History of Britain from 1750 to Recent Times.
14. Crosland, C. A. R. : Britain's Economic Problems.

15. **Cunningham, W. :** The Growth of English Industry and Commerce.
16. **Dubey, R. :** Economic Development of England
17. **Egerton** Short History of British Colonial Policy.
18. **Fay, C. R. :** Great Britain from Adam Smith to the Present Day.
19. **Flanders, Allan :** Trade Unions.
20. **Hadley** Railroad Transportation.
21. **Hobhouse, L. T. :** The Labour Movement.
22. **H. M. S. O. :** British System of Taxation.
23. **H. M. S. O :** Everybody's Guide to National Insurance, 1958.
24. **Jackman :** Transportation in Modern England
25. **John Price :** British Trade Unions.
26. **Jones, G. P. & Pool, A. G. :** A Hundred Years of Economic Development in Great Britain (1840-1940).
27. **Knowles :** Economic Development of Great Britain during the 19th century.
28. **Knowles** Industrial and Commercial Revolutions.
29. **Marsh, David C.** National Insurance and Assistance in Great Britain (Pitman).
30. **Meredith, H. O. :** Economic History of England (Pitman).
31. **Ogg & Sharp :** Economic Development of Modern Europe.
32. **Pigou, A. C. :** Economic Position of Great Britain.
33. **Panandikar, Dr. S. G. :** The Economic Development of Great Powers.

34. Rees : Short Fiscal and Financial History of England 1815-1918).
35. Ross : British Railways.
36. Sarkar, D. S. : Modern Economic Development of Great Powers.
37. Srivastava, C. P. : Economic Development of England
38. Southgate, G. W. : English Economic History.
39. Webb : History of Trade Unionism.
-